GEO IAS

It's about quality

April 2024

जियो दैनिक

डेली करंट अफेयर्स

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET

Contents

सामान्य अध्ययन I 11

INDIAN SOCIETY 11

1. दक्षिण एशिया, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश नष्ट होने का जोखिम: विश्व बैंक -द हिंदू 11
2. भारत में युवा आत्महत्या का विषय- द हिन्दू 12

HISTORY, ART & CULTURE 13

3. NCERT ने 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब में बदलाव किया -द हिंदू 13
4. कोयंबटूर में 3,000 साल पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले -द हिंदू 13
5. स्टैच्यू ऑफ वेलोर: अहोम गौरव का प्रतिनिधित्व करता है - द हिंदू 14
6. अंबेडकर जयंती: महाड़ सत्याग्रह का महत्व - इंडियन एक्सप्रेस 14
7. भगवान महावीर के दर्शन सिद्धांत का महत्व - द हिंदू 15

GEOGRAPHY 15

8. माउंट एटना ज्वालामुखी से धुएं के वलय (Rings) निकले - द हिन्दू 15
9. इस मानसून सीजन में बारिश 'सामान्य से अधिक' होने की संभावना:IMD- इंडियन एक्सप्रेस 16
10. लक्षद्वीप सागर में मछली की तीन नई प्रजातियाँ की खोज - द हिंदू 17
11. पूर्ण सूर्य ग्रहण नाजरा उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा - द हिंदू 17
12. लिथियम प्रसंस्करण: चीन पर निर्भरता कम करने हेतु भारत की विभिन्न देशों के साथ चर्चा - इंडियन एक्सप्रेस 18
13. ग्लोबल वार्मिंग पर अल नीनो के सुपरपोजिशन के कारण अपेक्षा से अधिक गर्म - द हिंदू 19

सामान्य अध्ययन II 20

POLITY & GOVERNANCE 20

14. वीवीपैट पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस- द हिंदू 20
15. ED 'किसी भी जानकारी' के लिए किसी को भी समन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट- द हिंदू 20
16. सुप्रीम कोर्ट एकतरफा तलाक पर केरल हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा -इंडिया टुडे 21
17. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रणाली- द हिन्दू 22
18. भारत की शिक्षा प्रणाली में अंतराल से सम्बंधित मामला - द हिंदू 22
19. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा कानून को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई -द हिंदू 23
20. सुप्रीम कोर्ट VVPAT पर्चियों के सत्यापन की याचिका पर सुनवाई करेगा - द हिंदू 24

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

21. उम्मीदवारों को मतदाताओं से निजता का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू.................................. 24

22. SC ने औद्योगिक अल्कोहल नियंत्रण पर केंद्र के सख्त रुख पर सवाल उठाए - द हिन्दू................. 25

23. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को खारिज किया - द हिंदू.. 26

24. सुप्रीम कोर्ट ने DMRC की क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूरी दी -... 26

25. चुनावी उम्मीदवारों को प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट - द हिन्दू 27

26. हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति लेनी होगी: गुजरात सरकार - - द हिन्दू...................... 27

27. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत 'एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी - इंडियन एक्सप्रेस 28

28. नींद का अधिकार एक "मूलभूत मानवीय आवश्यकता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता: बॉम्बे HC - इंडिया टुडे 29

29. असाधारण मामला: SC ने 30 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी - इंडियन एक्सप्रेस 29

30. सरकार को 'भ्रामक विज्ञापनों का उपयोग करने वाली FMCG कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए: SC - द हिंदू 30

31. अमेरिकी रिपोर्ट: भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है - द हिंदू... 31

32. दीफू लोकसभा क्षेत्र: संविधान का अनुच्छेद 244A का निर्वाचन क्षेत्र में महत्व - इंडियन एक्सप्रेस.. 31

33. निजी संपत्ति पुनर्वितरित करने की याचिका पर SC में सुनवाई शुरू- इंडियन एक्सप्रेस 32

34. सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को पुनर्जीवित करने वाली याचिका को खारिज किया - द हिंदू...................... 33

35. NCW अध्यक्ष, सदस्यों की किसी राजनीतिक दल से संबद्धता नहीं - द हिंदू.................................. 34

INTERNATIONAL RELATION 34

36. भारत-अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया-द हिंदू....... 34

37. भारत UNHRC में गाजा युद्धविराम के आह्वान पर मतदान से अनुपस्थित रहा -द हिंदू 35

38. इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अग्रणी योजनाओ को अपनाने हेतु भारत का दौरा किया - द हिंदू. 36

39. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUKUS के विस्तार को लेकर चर्चा - द हिंदू.................... 36

40. उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की - इंडियन एक्सप्रेस 37

41. EV और ग्रीन तकनीक उत्पादन, अमेरिकी-चीन व्यापार संघर्ष में फ्लैशप्वाइंट बना - द हिन्दू......... 37

42. भारत अफ्रीका के कई देशों के लिए नए डिफेंस अटैचेस भेजेगा - द हिंदू.. 38

43. म्यांमार संघर्ष: भारत ने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को स्थानांतरित किया - द हिंदू............. 38

44. तालिबान अफगान हिंदुओं, सिखों को भूमि अधिकार बहाल करेगा - द हिंदू 39

45. ईरान-इज़राइल संघर्ष: एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय - इंडियन एक्सप्रेस 40

46. IPC रिपोर्ट: गाजा उच्च स्तर पर भूख संकट का सामना कर रहा है - न्यूयॉर्क टाइम्स 41

47. इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर विवाद - द हिंदू 41

48. सोलोमन द्वीप के चुनाव में चीन का प्रभाव - द हिंदू 42

49. ईरान ने भारतीय अधिकारियों को चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी 43

50. श्रीलंका जल्द ही बॉन्ड धारकों के साथ फिर से बातचीत शुरू करेगा -द हिंदू 44

51. चीन के साथ वार्ता के बीच अमेरिकी नौसेना ने ताइवान जलडमरूमध्य से विमान उड़ाए - द हिंदू 44

52. विदेश मंत्रालय OCI हेतु आवेदन करने के लिए पुर्तगाली नागरिकता रद्द करने के आदेश को स्वीकार करेगा- द इंडियन एक्सप्रेस 45

53. भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार: ऑस्ट्रेलिया- द हिंदू 46

54. दोनों देशों द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित होने के बाद प्रोटोकॉल DTAA में संशोधन करेगा: मॉरीशस'- द हिंदू 46

55. रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेगा 47

56. संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय GANHRI भारत के मानवाधिकारों की समीक्षा करेगा - द हिंदू 47

57. G-7 मंत्री कोयले का चरणबद्ध तरीके से बंद करने करने पर सहमत हुए- द हिंदू 48

GOVERNMENT SCHEMES 49

58. लोकसभा चुनाव: सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए- टाइम्स ऑफ इंडिया 49

59. सरकार ने बागवानी सब्सिडी वितरण के लिए CDP-SURAKSHA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस 50

60. केंद्र ने आंगनबाड़ियों के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा जारी की - द हिंदू 50

ECONOMY 51

61. जनसांख्यिकीय लाभांश हेतु भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य में अधिक निवेश करना चाहिए: IMF- द हिंदू 51

INTERNAL SECURITY 52

62. भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप सौंपी- द हिंदू 52

63. नक्सल विरोधी अभियान: सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर निर्णायक प्रहार किया - द इंडियन एक्सप्रेस 53

सामान्य अध्ययन III 54

INTERNAL SECURITY 54

64. रक्षा निर्यात ₹21000 करोड़ से अधिक; पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि - द हिंदू 54

65. परमाणु ऊर्जा भारत के विकास की कुंजी है: IIM अहमदाबाद रिपोर्ट -द हिंदू 55

ENVIRONMENT 56

66. IMD की चेतावनी: अप्रैल-जून के बीच 10-20 दिन लू चलने की आशंका -द हिंदू 56

67. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने केंद्र पर आपदा राहत कोष में देरी का आरोप लगाया- द हिंदू 56

68. भारत ने झींगा हैचरी में एब्यूसिव स्थितियों पर रिपोर्ट को खारिज किया - द हिंदू 57

69. EV सब्सिडी: ओला इलेक्ट्रिक एवं अन्यों को MHI से मैन्युअल प्रारूप में प्रमाण पत्र मिले - द हिंदू 58

70. जलवायु संकट नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस 58

71. 'ब्लैक स्वान' इवेंट्स के लिए तैयार रहें, अप्रत्याशित की अपेक्षा करें: सेना प्रमुख - इकोनॉमिक टाइम्स 59

72. भारत की जलवायु नीति UNFCCC के मूलभूत सिद्धांतों से प्रेरित- इंडियन एक्सप्रेस 59

73. समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हेतु मेडागास्कर में बाओबाब पेड़ों पुनर्वनीकरण प्रयास - डाउन टू अर्थ .. 60

74. इनवेसिव एलियन स्पीशीज किसी पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती है?- इंडियन एक्सप्रेस 61

75. मछलियों से मूंगों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल पेय स्ट्रॉ का उपयोग-द हिंदू 61

76. विक्टोरिया न्यानज़ा झील का स्तर -द हिंदू 62

77. केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स में बदलाव किया- द हिंदू 64

78. एवियन इन्फ्लूएंजा: केरल कुट्टनाड में संक्रमित पक्षियों को मारा जाएगा - द हिंदू 64

79. NGT ने चेन्नई जल निकायों में रसायनों पर चिंता व्यक्त की - द हिंदू 65

80. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नए नियम- द हिंदू 66

81. पानी के बढ़ते तापमान से ब्लीचिंग के कारण कोरल चट्टानों को खतरा - इंडियन एक्सप्रेस 67

82. विश्व पृथ्वी दिवस 2024: थीम, इतिहास, विषय और महत्व - इंडियन एक्सप्रेस 67

83. कर्नाटक को सूखे से राहत देने हेतु SC ने केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया- द हिंदू 68

84. वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता कनाडा में आयोजित होगी - द इंडियन एक्सप्रेस 68

85. मानव-वन्यजीव संघर्षों से प्रकृति को भारी नुकसान की संभावना: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू 69

86. विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण रॉटरडैम (नीदरलैंड) में आयोजित किया गया - पीआईबी 70

87. सौर विकिरण की उपलब्धता वाले स्थानों को सौर पैनलों द्वारा बिजली घरों में परिवर्तित किया जा सकता है: IMD 70

88. हिंद महासागर का तापमान बढ़ने की संभावना: IIT पुणे - द हिंदू 71

DEFENCE 72

89. तेजस Mk-1A ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान भरी - द प्रिंट 72

90. भारतीय सेना ने आकाशतीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया -द हिंदू 72

91. DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण - द हिंदू 73

92. DRDO ने LCA तेजस Mk1A का एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल HAL को सौंपी- पीआईबी 73

93. IAF ने Su-30 MKI से एक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल ROCKS का परीक्षण किया- द प्रिंट 74

94. मिशन ISHAN: एक राष्ट्र, एक हवाई क्षेत्र परियोजना- द प्रिंट 74

SCIENCE & TECH 75

95. खगोलशास्त्री चंद्रमा की कक्षा में भारत की प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन को लगायेंगे - द हिंदू 75

96. सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के पीछे की तकनीक- द हिन्दू 75

97. इसरो के PSLV ने जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज़ मिशन पूरा किया - द हिंदू 76

98. 'गॉड पार्टिकल' की भविष्यवाणी करने वाले नोबेलिस्ट पीटर हिग्स का निधन - न्यूयॉर्क टाइम्स 77

99. वायरल हेपेटाइटिस पर WHO का अलर्ट - द हिंदू 77

100. सुप्रीम कोर्ट रेलवे मंत्रालय द्वारा उठाए गए रेलवे सुरक्षा उपायों की सराहना की- द हिंदू 78

101. मेटा 'कोर्ट' डीपफेक के मामलों का विश्लेषण करेगा - द हिंदू 79

102. एमपॉक्स वायरस विकसित होने के लिए 'जीनोमिक अकॉर्डियन' का उपयोग - द हिन्दू 79

ECONOMY 80

103. भारत का पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का सामरिक भंडारण - द हिंदू 80

104. RBI ने लगातार सातवीं बार रेपो दरों को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा -द हिंदू 80

105. RBI नकद जमा सुविधा के लिए UPI को सक्षम करेगा -द हिंदू 81

106. अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स GST में तत्काल सुधार की आवश्यकता: केलकर - द हिंदू 81

107. Apple ने 'मर्सनरी स्पाईवेयर' हमले के बारे में चेतावनी दी - द मिंट 82

108. वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना: WTO- इकोनॉमिक टाइम्स 83

109. भारत को विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सरल टैरिफ नीति की आवश्यकता है: ADB 83

110. IPC ने प्रतिकूल प्रभाव को लेकर दर्दनिवारक दवा निमेसुलाइड पर अलर्ट जारी किया- इकोनॉमिक टाइम्स 84

111. भारत की महत्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना का 80% काम पूरा हुआ - द हिंदू 85

112. आयातित मुद्रास्फीति: आयात लागत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकती है- द हिंदू 85

113. छोटे पैमाने के किसान खेतों पर पेड़ों से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ? - द हिंदू 86

114. भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए स्थायी समाधान चाहता है- द हिंदू 87

115. वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ने का अनुमान: UNCTAD - द हिंदू 88

116. IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां खरीदने हेतु आयु सीमा को समाप्त किया- द हिंदू 88

117. FSSAI भारत में बिकने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेगा - इंडियन एक्सप्रेस 89

118. नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 का अनावरण किया- द हिंदू 90

119. PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिली - इंडियन एक्सप्रेस 91

120. RBI डेटा: REITs, InvITs ने चार वर्षों में ₹1.3 लाख करोड़ जुटाए - द हिंदू 91

121. इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और कैसे काम करता है - इंडियन एक्सप्रेस 92

122. यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु SFB की कीमत 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए: RBI -इंडियन एक्सप्रेस 93

123. वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने से निर्यात पर असर पड़ सकता है: FIEO - द हिंदू 93

INTERNATIONAL RELATION 94

124. IP: अमेरिका ने भारत को 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया -द हिंदू 94

125. भारत अपने मध्य पूर्व संबंधों में वृद्धि हेतु ओमान के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार- द हिंदू 95

126. भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की - इंडियन एक्सप्रेस 96

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर 98

127. दक्षिण भारत में जल संकट से सम्बंधित मामला 98

128. अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के लिए भारत के प्रयास - द प्रिंट 98

129. भारत और श्रीलंका के बीच कच्चाथीवू द्वीप विवाद - द हिंदू 99

130. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से सम्बंधित मामला - द हिंदू 100

131. उत्तराखंड सरकार GLOF के जोखिम का मूल्यांकन करेगी -इंडियन एक्सप्रेस 101

132. भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वाहन परियोजना -द हिंदू 101

133. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से सम्बंधित मामला - द हिंदू 102

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

134. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विनियमन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण - द हिन्दू 103
135. जलवायु परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को बढ़ाता - द हिन्दू 103
136. सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का भारत का विनियमन- द हिंदू 104
137. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से सम्बंधित मामला - द हिंदू 105
138. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडो-पैसिफिक हेतु महत्वपूर्ण -इंडियन एक्सप्रेस 105
139. भारत - चीन के बीच सीमा विवाद - इंडियन एक्सप्रेस 106
140. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफ़ारी से सम्बंधित मामला - द हिंदू 107
141. भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष से सम्बंधित मामला- डाउन टू अर्थ 108
142. हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, निष्कर्षण विधियां- द हिंदू 108
143. भारत के हितों के लिए आर्कटिक क्षेत्र का महत्व - द हिंदू 109
144. एशियाई देशों में प्रजनन क्षमता का स्तर - द हिन्दू 110
145. तमिलनाडु का विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण मॉडल- इंडियन एक्सप्रेस 110
146. मतदान प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता- द हिंदू 111
147. दुबई में मूसलाधार बारिश का कारण क्या है - इंडियन एक्सप्रेस 112
148. दक्षिण चीन सागर में भारत का दृष्टिकोण - द हिन्दू 113
149. निजी निवेश में गिरावट से सम्बंधित मामला - द हिन्दू 114
150. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से रोका - द हिंदू 114
151. पर्यावरण और उद्योग के बीच संतुलन - इंडियन एक्सप्रेस 115
152. ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया - द हिंदू 116
153. जलवायु परिवर्तन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान- द हिंदू 116
154. भारत में आय और धन असमानता - द हिंदू 117
155. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी(PMAY-U) - द हिंदू 118
156. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) - द हिंदू 118
157. महिलाओं के लिए चाइल्डकैअर अवकाश एक संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस .. 119
158. वैश्विक शिपिंग उद्योग में भारतीय नाविकों की भूमिका - द हिंदू 120
159. इसरो ने हिमनद झीलों का विश्लेषण करने हेतु उपग्रह रिमोट-सेंसिंग का उपयोग किया - इंडियन एक्सप्रेस 121
160. वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता - इंडियन एक्सप्रेस 122

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

161. उत्तराखंड में दावानल से सम्बंधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस 122

162. भारत में असमानता और धन का संकेंद्रण से सम्बंधित मामला - द हिंदू 123

फैक्ट फटाफट 124

1. व्हाइट रैबिट (WR) 124
2. लम्पी स्किन डिजीज 124
3. न्यायालय की अवमानना 124
4. जापान सागर 125
5. पुनेट स्क्वायर 125
6. पैरा फसल प्रणाली 126
7. स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH) 126
8. पर्पल स्ट्राइप्ड जेलिफ़िश 126
9. वाशिंगटन संधि 126
10. वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) 127
11. मंगल पांडे 127
12. सतपुला बांध 127
13. ओशनिक नीनो इंडेक्स 127
14. टीसैट (TSAT)-1A 128
15. जेनु कुरुबा समुदाय 128
16. रम्फिकार्पा फिस्टुलोसा 128
17. राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट 128
18. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) 128
19. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत 129
20. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (WWS) 129
21. सनग्राज़िंग धूमकेतु 129
22. फ्रैक्टल 129
23. खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 130
24. फोर्ट इमैनुएल 130
25. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) 130

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

26. जियाधल नदी 130

27. ऑपरेशन मेघदूत 131

28. प्रीकोशनरी सिद्धांत 131

29. कुदसिया बाग 131

30. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 131

31. करिबा झील 132

32. यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज (UNPFII) 132

33. कवच सिस्टम 132

34. वीरानम झील 132

35. वोस्त्रो अकाउंट 133

36. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) 133

37. लीफ लिटर फ्रॉग 133

38. मैनिंजाइटिस 133

39. शोम्पेन जनजाति 134

40. वासुकी इंडिकस 134

41. माउंट रुआंग 134

42. माउंट अपो 134

43. पन्हाला दुर्ग 134

44. बिटकॉइन हाल्विंग 135

45. दीर्घायु भारत पहल 135

46. रैम्पेज मिसाइल 135

47. आर्टेमिस समझौते 135

48. माउंट एरेबस 135

49. राष्ट्रीय बायोमटेरियल सेंटर (राष्ट्रीय ऊतक बैंक) 136

50. हेडलाइन इन्फ्लेशन 136

51. कोर इन्फ्लेशन 136

52. बैंडेड क्रेट 136

53. वोयाजर 1 अंतरिक्ष यान 136

54. क्रिस्टल मेज़ 2 137
55. टीना (TINA) फैक्टर 137
56. मारबर्ग वायरस डिजीज (MVD) 137
57. बैथिमेट्री 137
58. Phi-3-Mini 138
59. ATACMS 138
60. इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन 138
61. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (GRFC) 2024 138
62. बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्थान(NIEPID) 139
63. नेफ्रोटिक सिंड्रोम 139
64. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क (CTCN) 139
65. Chang'e-6 139
66. बांबी बकेट 140
67. ग्रीन टैक्सयोनोमय 140

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन I

INDIAN SOCIETY

1. दक्षिण एशिया, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश नष्ट होने का जोखिम: विश्व बैंक -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- जनसांख्यिकीय विभाजन
- TFR

समाचार:
- **विश्व बैंक** ने चेतावनी दी है कि **भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र** अपने **जनसांख्यिकीय लाभांश** का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में **रोजगार सृजन** की गति बढ़ रही है।
- इससे कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि कम हो जाएगी, भले ही उसने अपने **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय** अपडेट, **जॉब्स फॉर रेजिलिएंस** में इस क्षेत्र के लिए **वर्ष 2024-25** के लिए **6.0-6.1%** की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया था।

मुख्य बिंदु
- यह देखते हुए कि **वर्ष 2000-23** की अवधि में **भारत की रोजगार वृद्धि** इसकी कामकाजी आयु आबादी में औसत वृद्धि से काफी नीचे थी
- **बहुपक्षीय ऋणदाता** ने कहा कि परिणामस्वरूप **वर्ष 2022** तक नेपाल को छोड़कर क्षेत्र के किसी भी अन्य देश की तुलना में देश के रोजगार अनुपात में अधिक गिरावट आई है।
- यह देखते हुए कि **भारत की अर्थव्यवस्था** को **वित्त वर्ष 2013/24** में **7.5%** की "**मजबूत वृद्धि**" दर्ज करने की उम्मीद थी, ऋणदाता ने कहा कि **श्रीलंका और पाकिस्तान** में रिकवरी के साथ यह वृद्धि, बड़े पैमाने पर **दक्षिण एशियाई क्षेत्र** के लिए मजबूत संख्या को बढ़ा रही थी।
- फिर भी, इस क्षेत्र में **16%** अधिक उत्पादन वृद्धि हो सकती है यदि इसकी **कामकाजी उम्र** की आबादी का हिस्सा जो कार्यरत था वह अन्य **EMDE** के बराबर था
- **दक्षिण एशिया** अभी अपने **जनसांख्यिकीय लाभांश** का पूरी तरह से लाभ उठाने में विफल हो रहा है, यह एक चूक गया अवसर है
- क्षेत्र में कमजोर रोजगार रुझान **गैर-कृषि क्षेत्रों** में केंद्रित थे
- नौकरी में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने **अर्थव्यवस्था में महिलाओं** की भागीदारी का समर्थन करने, व्यापार में खुलापन बढ़ाने और शिक्षा में सुधार करने की सिफारिश की है।

जनसांख्यिकीय विभाजन
- जैसा कि **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** द्वारा परिभाषित किया गया है, यह "**आर्थिक विकास** क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है, मुख्य रूप से जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के **गैर-कामकाजी** उम्र के हिस्से (14 और उससे कम उम्र, और 65 और उससे अधिक उम्र)" से बड़ा होता है

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति और चुनौतियाँ
- लैंसेट रिपोर्ट एक संदेश है कि भारत का **जनसांख्यिकीय लाभांश** हमेशा के लिए नहीं है।
- वैश्विक अनुभव देश के नीति निर्माताओं के लिए उदाहरण हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, चीन में, कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात **वर्ष 1987** में **50 प्रतिशत** को पार कर गया और पिछले दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंच गया।
- यही वह अवधि थी जब देश ने प्रभावशाली आर्थिक विकास दर्ज किया था।

- पिछले साल तक, चीन की **TFR रिकॉर्ड निचले स्तर** पर आ गई थी और इसकी कामकाजी उम्र की आबादी में **40 मिलियन** से अधिक की कमी आई थी।
- चीनी सरकार के जनसंख्या-वृद्धि समर्थक उपाय काम करते नहीं दिख रहे हैं।
- वास्तव में, **विकसित देशों** के पिछले **60 वर्षों** के इतिहास से पता चलता है कि एक बार **प्रजनन दर** प्रतिस्थापन दर से नीचे आ जाए, तो उसे वापस स्थापित करना लगभग असंभव है।
- 1.9 पर, भारत का **TFR वर्तमान** में **प्रतिस्थापन दर** से ठीक नीचे है, और **UNPF** गणना के अनुसार, देश की कामकाजी आयु की आबादी का हिस्सा **वर्ष 2030** के अंत में, **वर्ष 2040** के दशक की शुरुआत में चरम पर होगा।
- इसलिए, नीति निर्माताओं को **भारत** के **जनसांख्यिकीय लाभांश** को अधिकतम करने के लिए इस **विंडो** का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि **चीन** ने **वर्ष 1980** के दशक के अंत से लेकर पिछले दशक के शुरुआती वर्षों तक किया था।
- कौशल की कमी को दूर करने और **ज्ञान अर्थव्यवस्था** में कमियों को दूर करने के उपाय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
- चुनौती कृषि के बाहर **नौकरियां पैदा** करने की भी होगी, वे कम वेतन वाले **अनौपचारिक क्षेत्र** में नहीं होनी चाहिए।
- आगे बढ़ते हुए, नीति निर्माताओं को बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए पर्याप्त **सामाजिक सुरक्षा** और **स्वास्थ्य** देखभाल प्रावधान भी सुनिश्चित करने होंगे और उनके **कौशल** का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अवसर प्रदान करने होंगे।

2. भारत में युवा आत्महत्या का विषय- द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति

समाचार:
- **आत्महत्या मानव जीवन** की **दुखद और असामयिक** हानि है, और भी अधिक विनाशकारी और हैरान करने वाली है क्योंकि यह एक **जानबूझकर** किया गया कृत्य है।
- भारत को विश्व में सबसे अधिक आत्महत्याएँ होने का संदिग्ध स्थान प्राप्त है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की रिपोर्ट है कि **वर्ष 2022** में **1.71 लाख** लोग आत्महत्या से मर गए।
- आत्महत्या की दर बढ़कर **12.4 प्रति 1,00,000** हो गई है जो भारत में अब तक की सबसे ऊंची दर है।

मुख्य बिंदु
- **विश्व** में सर्वाधिक **आत्महत्याओं** के मामले **भारत** में **हार्ट ब्रेकिंग क्राइसिस** का सामना कर रहे हैं।
- **वर्ष 2022** में, रिकॉर्ड संख्या में **1.7 लाख** से अधिक लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई, जिसमें **चिंताजनक** रूप से **उच्च दर युवा लोगों (30 वर्ष से कम)** में हर **8 मिन**ट में एक थी।

यह चिंताजनक प्रवृत्ति कई खतरे पैदा करती है
- कम अनुमानित संख्याएँ वास्तविक आंकड़े संभवतः और भी अधिक हैं।
- यंग लाइव्स लॉस्ट सुसाइड युवा भारतीय महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है।

युवा आत्महत्या समस्या का कारण
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे** : आधे से अधिक (54%) युवा आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हैं।
- **शैक्षणिक दबाव:** प्रतियोगी परीक्षाएं, माता-पिता की अपेक्षाएं और शैक्षणिक तनाव सभी इसमें योगदान करते हैं।
- **मादक द्रव्यों का सेवन:** शराब और नशीली दवाओं का उपयोग ज्ञात जोखिम कारक हैं।
- **लड़कियों के लिए सामाजिक मुद्दे** : व्यवस्थित विवाह, शीघ्र मातृत्व, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता सभी भूमिका निभाते हैं।
- **मीडिया का प्रभाव:** आत्महत्याओं की सनसनीखेज रिपोर्टिंग, विशेष रूप से मशहूर हस्तियों से जुड़ी, नकलची व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है।

समाधान
- **युवाओं की मदद करना:** समस्या-समाधान कौशल सिखाना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना (जिम्मेदारी से इंटरनेट के उपयोग सहित) महत्वपूर्ण हैं।
- **शैक्षिक सुधार:** वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियाँ परीक्षा के तनाव को कम कर सकती हैं।

- **सामाजिक परिवर्तन:** मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कलंक और भेदभाव का मुकाबला करना आवश्यक है।
- **वर्ष 2022** में शुरू की गई एक **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति** का लक्ष्य **वर्ष 2030** तक **आत्महत्याओं** को **10%** तक कम करना है।
- यह **रणनीति मानसिक कल्याण** को बढ़ावा देने और **मादक द्रव्यों** के सेवन को कम करने के लिए **स्कूलों, युवा क्लबों** और **छात्र स्वास्थ्य राजदूतों** का लाभ उठाने पर केंद्रित है।

HISTORY, ART & CULTURE

3. NCERT ने 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब में बदलाव किया -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- राखीगढ़ी
- मोहनजोदड़ो

समाचार:
- **नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT)** ने **12वीं कक्षा** के छात्रों के लिए इतिहास की किताब में विशेष रूप से **हड़प्पा सभ्यता** की उत्पत्ति और गिरावट के संबंध में संशोधन किया है।

हड़प्पा की सभ्यता
- **सिंधु घाटी सभ्यता** (**IVC**) के उद्गम से शुरू होता है , जिसे **हड़प्पा सभ्यता** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह लगभग 2,500 ईसा पूर्व, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फला-फूला।
- सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की **चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं** में से **सबसे बड़ी** सभ्यता का घर थी।
- **वर्ष 1920** के दशक में, **भारतीय पुरातत्व विभाग** ने **सिंधु घाटी** में खुदाई की, जिसमें **दो पुराने शहरों**, **मोहनजोदड़ो और हड़प्पा** के **खंडहरों** का पता चला।
- वर्ष 1924 में ASI के **महानिदेशक जॉन मार्शल** ने दुनिया के सामने **सिंधु घाटी** में एक **नई सभ्यता** की खोज की घोषणा की है ।
- **राखीगढ़ी** एक **पुरातात्विक स्थल** है जो **घग्गर-हकरा नदी** के **मैदान** में, **हिसार** जिले (हरियाणा) में स्थित है।

राखीगढ़ी
- यह **भारतीय उपमहाद्वीप** का सबसे बड़ा **हड़प्पाकालीन** स्थल है
- यह एक **परिपक्व हड़प्पा चरण** है और इसे एक **नियोजित टाउनशिप** द्वारा दर्शाया गया है जिसमें **उचित जल निकासी व्यवस्था** के साथ **मिट्टी-ईंट** के साथ-साथ **पकी हुई ईंट** के घर भी हैं।
- एक **बेलनाकार मुहर** जिसके एक तरफ **पांच हड़प्पा** के **पात्र और दूसरी** तरफ एक **एलीगेटर** का **प्रतीक** है, इस साइट से एक महत्वपूर्ण खोज है।
- **सिरेमिक उद्योग** का **प्रतिनिधित्व लाल बर्तन** द्वारा किया जाता था, जिसमें **डिश-ऑन-स्टैंड, फूलदान, छिद्रित** जार और अन्य शामिल थे।

4. कोयंबटूर में 3,000 साल पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- कुमिट्टीपति पेंटिंग

समाचार:
- **कोयंबटूर शहर** से लगभग **30 किमी** दूर एक गांव **कुमिट्टीपथी** में **पथिमलाई** में **रॉक कला स्थल** पर **सफेद रंग** से रंगा हुआ प्रमुख **दांतों वाला एक हाथी** सबसे पहले **आगंतुकों** का ध्यान आकर्षित करता है।
- लगभग **3,000 साल** पुरानी मानी जाने वाली ये **गुफा पेंटिंग कोंगु क्षेत्र** की महत्वपूर्ण **रॉक कलाओं** में से एक हैं।

कुमिट्टीपति पेंटिंग
- **भारत** के **तमिलनाडु** में एक **गुफा** के अंदर **3,000** साल **पुराने** शैल चित्र हैं।
- कला के ये महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के शुरुआती निवासियों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं।
- चित्रों में एक **हाथी,** एक संभावित **रथ या मोर** और दैनिक जीवन के दृश्य दर्शाए गए हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि **कलाकारों** ने **गुफा की दीवारों** पर अपनी कृतियों को बनाने के लिए **सफेद रंगद्रव्य** और **प्राकृतिक गोंद** के मिश्रण का उपयोग किया।

- **तमिलनाडु** में **संरक्षित चट्टानों** पर पाए जाने वाले अधिकांश **शैल चित्रों** के विपरीत, **कुमिट्टीपति पेंटिंग** एक गुफा के भीतर छिपी हुई हैं, जो उनके **मिस्ट्री और इंट्रीगय** को दर्शाती हैं।

5. स्टैच्यू ऑफ वेलोर: अहोम गौरव का प्रतिनिधित्व करता है - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- जोरहाट
- अहोम

समाचार:
- **मेलेंग-होलोंगापार** के सबसे नए ऐतिहासिक स्थल **स्टैच्यू ऑफ वेलोर** का उद्घाटन किया जाएगा।
- **125 फुट ऊंची** इस प्रतिमा में **वर्ष 1671** में **मुगल सेना** को **असम** पर **कब्जा** करने से रोकने के लिए **सरायघाट** की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित **अहोम जनरल लाचित बोरफुकन** को दर्शाया गया है।

मुख्य बिंदु
- **पार्क** में **मैदाम**, या **मिट्टी** का **पिरामिड** शामिल है, जहां उसे **युद्ध** के बाद **दफनाया** गया था।
- **जोरहाट शहर, गुवाहाटी** से लगभग **300 किमी पूर्व** में, आसपास के **बागानों** के कारण **असम** की **चाय की राजधानी** कहा जाता है।
- यह पार्क **NH-715** के साथ शहर के **पूर्वी किनारे** से लगभग उतना ही दूर है जितना **सुखफा समन्नय क्षेत्र** इसके **पश्चिमी किनारे** से है।
- **स्वर्गदेव (या सम्राट) सुकाफा** को समर्पित, जो **अहोम राजवंश** की स्थापना के लिए **चीन के युन्नान** से आए थे, जिन्होंने **वर्ष 1800** के **दशक** में **ब्रिटिश अधिग्रहण** तक **600 वर्षों** तक **असम** पर शासन किया था।
- यह **लाचित प्रतिमा पार्क** जितना ही **अहोम गौरव** का प्रतिनिधित्व करता है।

लाचित बोरफुकन
- **24 नवंबर, 1622** को **जन्मे बोरफुकन** को वर्ष 1671 में **सरायघाट की लड़ाई** में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसमें **मुगल सेना** द्वारा अ**सम पर कब्जा** करने के **प्रयास को विफल** कर दिया गया था।
- **सरायघाट की लड़ाई** वर्ष 1671 में **गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र** के तट पर लड़ी गई थी।
- इसे नदी पर हुए **महानतम नौसैनिक युद्धों** में से एक माना जाता है जिसके **परिणामस्वरूप मुगलों** पर **अहोमों** की जीत हुई।
- वह अपनी **प्रभावशाली नौसैनिक रणनीतियों** के कारण **भारत की नौसेना** को मजबूत करने और **अंतर्देशीय जल परिवहन** को **पुनर्जीवित** करने और इससे जुड़े **बुनियादी ढांचे** के निर्माण के पीछे प्रेरणास्रोत थे।
- **लाचित बोरफुकन** स्वर्ण पदक **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी** के **सर्वश्रेष्ठ कैडेट** को प्रदान किया जाता है।
- इस पदक की स्थापना **वर्ष 1999** में **रक्षा कर्मियों** को **बोरफुकन की वीरता** और **बलिदान का अनुकरण** करने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई थी।

6. अंबेडकर जयंती: महाड़ सत्याग्रह का महत्व - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- डॉ अम्बेडकर
- पूना पैक्ट

समाचार:
- **महाड सत्याग्रह** को **दलित आंदोलन** की '**मूलभूत घटना**' माना जाता है।
- यह पहली बार था कि **समुदाय** ने **सामूहिक रूप** से **जाति व्यवस्था** को **अस्वीकार** करने और अपने **मानवाधिकारों** पर जोर देने का **संकल्प प्रदर्शित** किया।

हाड़ सत्याग्रह -1927
- **भारत** में **समानता की लड़ाई** में यह एक **निर्णायक क्षण** था।
- **अधूरे वादे: वर्ष** 1923 में, दलितों (अछूतों) को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया गया था। हालाँकि, यह परिवर्तन वास्तविकता में परिलक्षित नहीं हुआ।
- **डॉ. बीआर अंबेडकर** को **महाड में दलितों** के लिए एक **सम्मेलन** का **नेतृत्व** करने के लिए **आमंत्रित** किया गया था, हालांकि शुरुआत में इसे एक सम्मेलन का नाम दिया गया था, लेकिन यह एक शक्तिशाली विरोध में बदल गया।
- **परंपराओं की अवहेलना:** लगभग 2,500 दलितों ने अपने बहिष्कार को चुनौती देते हुए एक सार्वजनिक पानी की टंकी तक मार्च किया।
- डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं जल को अवज्ञा का एक प्रतीकात्मक कार्य बताया।
- **प्रतिक्रिया का सामना:** ऊंची जाति के हिंदुओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तालाब का शुद्धिकरण किया, जिससे व्याप्त भेदभाव उजागर हुआ।

- **आंदोलन प्रज्वलित** : बिना किसी डर के, डॉ. अंबेडकर ने बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया।।
- यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, इस आंदोलन ने **जाति व्यवस्था** को खुले तौर पर चुनौती दी।
- **स्थायी विरासत:** महाड़ सत्याग्रह को भारत में दलित आंदोलन की नींव के रूप में देखा जाता है।
- **डॉ. अम्बेडकर** के **नेतृत्व** में **समान अधिकारों** की **मांग** करने वाला यह **पहला संगठित** प्रयास था।
- इस विरोध ने **जातिगत भेदभाव** के खिलाफ **भविष्य के संघर्षों** के लिए एक खाका तैयार किया और **डॉ. अंबेडकर** को **उत्पीड़ितों के नेता** के रूप में स्थापित किया।

7. भगवान महावीर के दर्शन सिद्धांत का महत्व - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- जैन धर्म
- भगवान महावीर दर्शन सिद्धांत

समाचार :
- महावीर ने अपने दर्शन के मूल सिद्धांत के रूप में स्वतंत्र इच्छा (भाग्य जैसे बाहरी प्रभावों से मुक्ति) के महत्व पर दृढ़ता से जोर दिया।

भगवान महावीर के दर्शन के मूल सिद्धांत:
- **भगवान महावीर** ने अपने दर्शन के **मूल सिद्धांत** के रूप में **स्वतंत्र इच्छा** के महत्व पर दृढ़ता से जोर दिया।
- उनके अनुसार जीवन "**नियति" (भाग्य)** और "**पुरुषार्थ"** (स्वतंत्र इच्छा पर आधारित कार्य) का एक संयोजन है और भाग्य हमेशा **पुरुषार्थ (पिछले कर्म)** का परिणाम होता है।
- **भगवान महावीर** ने किसी के **जीवन** को **निर्धारित** करने में "**आत्मा**" की सर्वोच्चता का उपदेश दिया। वह **आत्मा** को "**परमात्मा" (सर्वोच्च)** मानते थे।
- **भगवान महावीर** घोषणा करते हैं कि केवल वही जो स्वीकार करता है कि **वास्तव** में, **वह स्वयं** अपने भाग्य का **स्वामी** है, वह "**आत्मवाद**" (चेतना और सर्वोच्च क्षमता की विशेषता वाली आत्माओं में विश्वास) के उनके **सिद्धांतों** का **सच्चा अनुयायी** है।

जैन धर्म:
- जैन धर्म **छठी शताब्दी ईसा पूर्व** में प्रमुख हो गया, इसका **प्रचार महावीर** ने किया।
- जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से **भगवान महावीर** अंतिम तीर्थंकर थे।
- नई कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार से इसकी उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- जैन धर्म के **तीन रत्नों या त्रिरत्नों में सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म** शामिल हैं।
- जैन धर्म का **सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य** के इर्द-गिर्द घूमता है।
- ब्रह्मचर्य (संयम का पालन) का पांचवां सिद्धांत महावीर द्वारा पेश किया गया था।

GEOGRAPHY

8. माउंट एटना ज्वालामुखी से धुएं के वलय (Rings) निकले - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- माउंट एटना
- ज्वालामुखीय भंवर वलय (Rings)

समाचार:
- **माउंट एटना , यूरोप** का सबसे बड़ा **ज्वालामुखी** और दुनिया के **सबसे सक्रिय** और **प्रतिष्ठित ज्वालामुखियों** में से एक, हवा में **धुएं के वलय (Rings)** भेज रहा है।
- **वलय (Rings)** एक **दुर्लभ घटना** है जिसे वैज्ञानिक **ज्वालामुखीय वोर्टेक्स** के **वलय (Rings)** के रूप में संदर्भित करते हैं, जो मोटे तौर पर **धुएं के वलय (Rings)** के **समान ही उत्पन्न** होते हैं

माउंट एटना:
- माउंट एटना, **भूमध्य सागर** के सबसे बड़े द्वीप **सिसिली** के **पूर्वी तट** पर एक **सक्रिय ज्वालामुखी** है।
- एटना की चोटी **आल्प्स** के **दक्षिण** में **इटली** में **सबसे ऊंची** है, और यह **यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों** में से एक है।
- एटना **वर्ष 2013** से एक **विश्व धरोहर स्थल** रहा है, और **यूनेस्को** के अनुसार, **ज्वालामुखी के विस्फोट** का **इतिहास 500,000 साल पुराना** है, इस गतिविधि के कम से कम **2,700 साल पुराने दस्तावेज़** में दर्ज किए गए हैं।

ज्वालामुखीय भंवर वलय (Rings) :

- **वोर्टेक्स रिंग्स** तब उत्पन्न होते हैं जब **गैस, मुख्य रूप से जल वाष्प** , **क्रेट**र में एक **वेंट** के माध्यम से तेजी से छोड़ी जाती है।
- एटना के क्रेटर में जो **वेंट खुला** है वह लगभग **पूर्णतः गोलाकार** है।
- हालाँकि **ज्वालामुखीय भंवर वलय (Rings)** अलास्का में रिडाउट, इक्वाडोर में तुंगुरहुआ, ग्वाटेमाला में पकाया, आइसलैंड में आईजफजल्लाजोकुल और हेक्ला, इटली में स्ट्रोमबोली, जापान में एसो और सकुराजिमा जैसे ज्वालामुखियों में देखे गए हैं।

9. इस मानसून सीजन में बारिश 'सामान्य से अधिक' होने की संभावना:IMD- इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- अल नीनो
- ला- नीना

समाचार:
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग** (**IMD**) ने सीज़न के लिए अपने पहले **दीर्घकालिक पूर्वानुमान** में कहा है की भारत में इस मानसून में **"सामान्य से अधिक" बारिश** होने की संभावना है ।
- इसमें कहा गया है कि पूरे देश में **लंबी अवधि के औसत** की **106 फीसदी बारिश** होने की उम्मीद है।

समुद्री तापमान और भारतीय मानसून वर्षा:
- अल नीनो **प्रशांत महासागर** में **समुद्र की सतह** के **तापमान को सामान्य** से अधिक **गर्म** कर देता है, जिससे **भारत** के **मानसून** के **मौसम में कम** बारिश हो सकती है।
- दूसरी ओर, **ला नीना प्रशांत महासागर** को ठंडा करता है और **भारत में अधिक मानसूनी बारिश** से जुड़ा है।
- जब न तो **अल नीनो** और न ही **ला नीना** हो रहा होता है, तो चीजें तटस्थ होती हैं, समुद्र की सतह का तापमान औसत के आसपास होता है।

हिंद महासागर डिपोल (IOD):
- यह **हिंद महासागर** में एक **जलवायु पैटर्न** है जहां **पूर्वी और पश्चिमी किनारों** के बीच स**मुद्र की सतह** के तापमान में **अंतर महत्वपूर्ण** है।
- एक **सकारात्मक IOD** का अर्थ है **पूर्व में ठंडा पानी** और **पश्चिम में गर्म पानी** और यह **भारतीय मानसून वर्षा** को भी प्रभावित कर सकता है।
- नकारात्मक IOD इसके विपरीत है, जिसमें गर्म पूर्वी जल और ठंडा पश्चिमी जल होता है।

मानसून पूर्वानुमान 2024:
- **भारत की मौसम सेवा (IMD)** का अनुमान है कि **वर्ष 2024** में **देश के अधिकांश हिस्सों** में **औसत** से **अधिक बारिश** होगी।
- **सामान्य वर्षा** को **दीर्घकालिक औसत** (पिछले 50 वर्षों में औसत वर्षा) के **96%** से **104%** के बीच माना जाता है।
- इस साल देश में **दीर्घकालिक औसत** की **106% बारिश** होने की उम्मीद है।

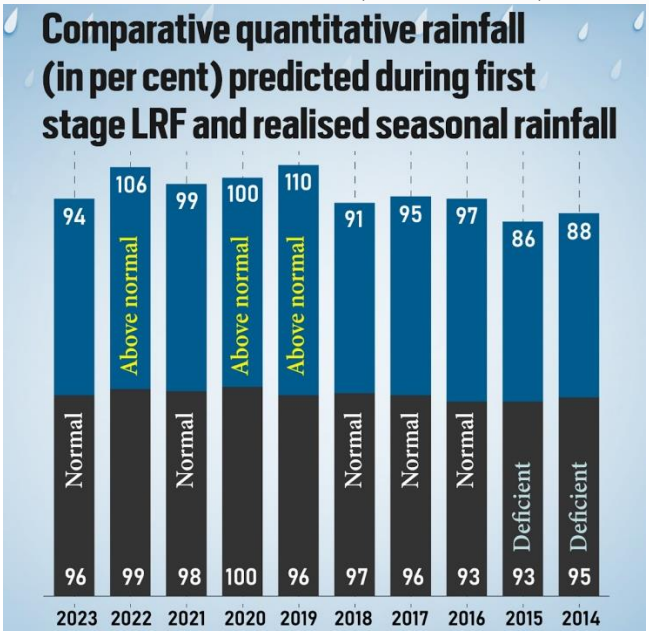

10. लक्षद्वीप सागर में मछली की तीन नई प्रजातियाँ की खोज - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- लक्षद्वीप द्वीप समूह
- मूंगा

समाचार:
- **लक्षद्वीप सागर** में **मछली** की **तीन प्रजातियाँ औजारों** का उपयोग करने में सक्षम पाई गई हैं।
- उन्होंने **समुद्री अर्चिन** के कठोर खोल को तोड़ने के लिए **जीवित** या **मृत मूंगा संरचनाओं** का उपयोग निहाई के रूप में किया ताकि वे **अंदर खाने योग्य टुकड़ों** तक पहुंच सकें।
- **प्राइमेट्स** के विपरीत, **पक्षी, ऊदबिलाव, ऑक्टोपस** और कई अन्य जानवर जिनके बारे में वैज्ञानिक जानते हैं कि वे टूल्स चलाने में सक्षम हैं

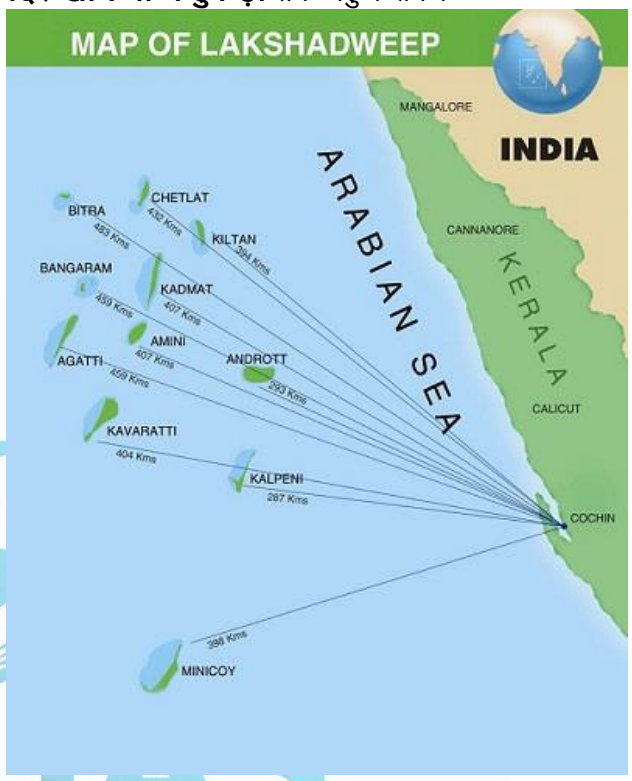

लक्षद्वीप द्वीप समूह:
- **भारत** का **सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश,** लक्षद्वीप एक द्वीपसमूह है जिसमें **32 वर्ग किमी क्षेत्रफल** वाले **36 द्वीप** हैं।
- इसमें **12 एटोल, तीन चट्टानें, पांच जलमग्न द्वीप** और **दस बसे हुए द्वीप** शामिल हैं।
- सभी द्वीप **केरल** में **कोच्चि के तट** से **220** से **440 किमी** दूर **अरब सागर** में हैं।
- यह **प्रशासक** के माध्यम से सीधे **केंद्र** के **नियंत्रण** में होता है।
- द्वीपों के **तीन प्रमुख** समूह हैं:
  - अमिनदीवी द्वीप समूह
  - लैकाडिव द्वीप समूह
  - मिनिकॉय द्वीप
- **अमिनदीवी द्वीप** सबसे **उत्तरी** है जबकि **मिनिकॉय** द्वीप **सबसे दक्षिणी** है।
- सभी **प्रवाल मूल (एटोल)** के छोटे द्वीप हैं और **किनारे पर चट्टानों** से घिरे हुए हैं।
- **मिनिकॉय** को छोड़कर सभी द्वीपों में **मलयालम** बोली जाती है, जहां लोग महल बोलते हैं जो **दिवेही लिपि** में लिखी जाती है।
- **लक्षद्वीप** में साल भर **उष्णकटिबंधीय जलवायु** (27-32 डिग्री सेल्सियस) रहती है।

11. पूर्ण सूर्य ग्रहण नाजरा उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रहण (एक्लिप्स)
- पेनुमब्रल एक्लिप्स

समाचार:
- हाल ही में, **पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका** और **कनाडा** से होकर गुजरेगा।
- इस प्रकार का **सूर्य ग्रहण** किसी भी स्थान विशेष के लिए एक दुर्लभ घटना है।
- **रॉयल म्यूज़ियम ग्रीनविच** के अनुसार, एक बार जब **पृथ्वी** पर कोई **स्थान पूर्ण सूर्य ग्रहण** देख लेता है, तो उस भाग में अगला **सूर्य ग्रहण** देखने में लगभग **400 वर्ष** लगेंगे।

रेयर सोलार एक्लिप्स (दुर्लभ सूर्यग्रहण)
- अधिकांश **कैलेंडर** वर्षों में **दो चंद्र ग्रहण** होते हैं, कुछ वर्षों में **एक या तीन या कोई** भी नहीं होता है।
- सूर्य ग्रहण **साल में दो से पांच बार होते हैं ।**
- **वर्ष 1935** में **पांच सूर्य ग्रहण** हुए थे और **वर्ष 2206** में फिर होंगे।
- एक सदी में कुल **सूर्य ग्रहणों** की **औसत संख्या 66** है।
- पृथ्वी पर कोई भी **बिंदु, औसतन**, **तीन से चार शताब्दियों** में एक से **अधिक पूर्ण सूर्य ग्रहण** का अनुभव नहीं कर सकता है।

चंद्र ग्रहण:

- चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है।
- पृथ्वी को सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच होना चाहिए, और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है
- **चंद्र ग्रहण के प्रकार:**
  - **पूर्ण चंद्र ग्रहण** : पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है और चंद्रमा पर छाया डालती है।
  - **आंशिक चंद्र ग्रहण** : सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अपूर्ण संरेखण के परिणामस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी की छाया के केवल एक भाग से होकर गुजरता है।
  - **उपछाया ग्रहण (पेनुमब्रल एक्लिप्स)** : चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया या उसकी छाया के हल्के बाहरी हिस्से से होकर गुजरता है।
  - चंद्रमा इतना हल्का धुंधला हो जाता है कि उसे नोटिस करना मुश्किल हो सकता है।

सूर्यग्रहण:

- **सूर्य ग्रह**ण तब होता है जब **चंद्रमा सूर्य** और **पृथ्वी** के बीच से गुजरता है, जिससे **पृथ्वी** पर छाया पड़ती है जो कुछ क्षेत्रों में **सूर्य के प्रकाश** को पूरी तरह या **आंशिक रूप से अवरुद्ध** कर देती है।
- **सूर्य ग्रहण के प्रकार**
  - **पूर्ण सूर्य ग्रहण:** पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब नया चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और अपनी छाया का सबसे काला हिस्सा, उपछाया, पृथ्वी पर डालता है।
  - **वलयाकार सूर्य ग्रहण:** चंद्रमा एक बड़ी, चमकीली डिस्क के ऊपर एक अंधेरी डिस्क के रूप में दिखाई देता है, जो चंद्रमा के चारों ओर एक वलय जैसा दिखता है।
  - **आंशिक सूर्य ग्रहण:** सूर्य का केवल एक भाग ही ढका हुआ दिखाई देगा, जिससे इसे अर्धचंद्राकार आकार मिलेगा
  - **हाइब्रिड सूर्य ग्रहण:** पृथ्वी की सतह घुमावदार है, कभी-कभी ग्रहण वलयाकार और पूर्ण के बीच स्थानांतरित हो सकता है क्योंकि चंद्रमा की छाया दुनिया भर में घूमती है।

12. लिथियम प्रसंस्करण: चीन पर निर्भरता कम करने हेतु भारत की विभिन्न देशों के साथ चर्चा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे

- कोबाल्ट
- लिथियम

समाचार:

- मामले से परिचित **चार सूत्रों** ने कहा कि **भारत** अपने **नवजात लिथियम खनन** और **इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों** को मजबूत करने और चीन पर भरोसा करने से बचने के लिए **लिथियम प्रसंस्करण** पर **तकनीकी** मदद के लिए साझेदारी की तलाश में कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- **भारत** के **खान मंत्रालय** ने पिछले वर्ष **ऑस्ट्रेलिया** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ **चर्चा** शुरू की थी
- **भारत सरकार** और कुछ **निजी कंपनियों** ने **बोलीविया, ब्रिटेन, जापान** और **दक्षिण कोरिया** से भी मदद मांगी है।
- एक **लिथियम खनन उद्योग** विकसित करने के लिए जो अपने **घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** उद्योग के लिए **बैटरी** के लिए **रासायनिक फीडस्टॉक** प्रदान कर सकता है जो इसके **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** और **तेल निर्भरता** में कटौती करने में मदद कर सकता है।
- **भारत** को **लिथियम** को **संसाधित** करने के लिए **प्रौद्योगिकी** की **आवश्यकता** है और हम **अन्य देशों** के साथ **सहयोग** करना चाहते हैं जिनके पास कुछ अनुभव है
- **प्रसंस्करण संयंत्रों** के अभाव में, **भारतीय कंपनियाँ** संभवतः **लिथियम अयस्कों** को **चीन** ले जाएंगी और **संसाधित धातु** को **भारत** वापस लाएँगी
- **पड़ोसी** और **प्रतिद्वंद्वी चीन** दुनिया की **लिथियम प्रसंस्करण क्षमता** का लगभग **दो-तिहाई हिस्सा** है।
- **सरकार** के शीर्ष नीति **थिंक-टैंक नीति आयोग** ने **लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की सिफारिश की है।
- **नीति आयोग** के अनुसार, **भारत** के **बैटरी उद्योग** को **वर्ष 2030** तक वार्षिक **56,000 मीट्रिक टन लिथियम** कार्बोनेट की आवश्यकता होगी।

महत्वपूर्ण खनिज:

- **पहचान** : भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और उर्वरक सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है।
- **महत्व** : ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग इन संसाधनों की बड़े पैमाने पर जरूरतों को उत्पन्न करती है।
- **वैश्विक मांग** : जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक मांग आसमान छूने की उम्मीद है, जिससे भारत के लिए सामरिक योजना और संसाधन सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- **एकाग्रता** : महत्वपूर्ण खनिज भंडार कुछ देशों, मुख्य रूप से चीन, में भारी मात्रा में केंद्रित हैं, जो असमान वितरण और प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियां पैदा कर रहे हैं।
- **चीनी प्रभुत्व** : महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी को परिष्कृत करने में चीन का प्रभुत्व अपने एकाधिकार के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी प्रगति को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **डिपेंडेंसी रिस्क**: भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य विशेष रूप से बैटरी निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- अन्य देशों के साथ समझौतों के माध्यम से संसाधनों को सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे घरेलू उद्योगों और तकनीकी प्रगति के लिए चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

13. ग्लोबल वार्मिंग पर अल नीनो के सुपरपोजिशन के कारण अपेक्षा से अधिक गर्म - द हिंदू

समाचार:

- **प्री-मॉनसून** समाप्ति के दौरान **भारतीय ईस्टरली जे**ट पर **एल नीनो** का प्रभाव एक **मजबूत और अधिक** लगातार **एंटीसाइक्लोन** का उत्पादन करता है जो लंबे समय तक चलने वाली और तीव्र गर्मी की लहरों का कारण बनता है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- एंटीसाइक्लोन
- साइक्लोन

मुख्य बिंदु:

- मार्च में, **उत्तरी हिंद महासागर** के ऊपर **एंटीसाइक्लोन परिसंचरण** के कारण **ओडिशा** में **असामान्य वर्षा** हुई।
- **ग्लोबल वार्मिंग स्थानीय स्तर** पर **अनूठी विशेषताएं** बनाती है जो ठंडे **पृष्ठभूमि तापमान** के **शीर्ष पर गर्मी** की लहरों को नियंत्रित करती है।
- इस मौसम में **भारत में गर्म लहरें विशेष** चिंता का विषय रही हैं
  - कुछ लगातार **परिसंचरण पैटर्न गर्मी** की लहरें पैदा कर रहे हैं और यह **पैटर्न भविष्यवाणियों** में सुधार के लिए **केंद्र बिंदु** के रूप में कार्य करता है।

एंटीसाइक्लोन:

- **एंटीसाइक्लोन स्थितियों** में **हवाएँ दक्षिणावर्त दिशा** में चलती हैं , जिसके बीच में **हवा नीचे** की ओर बहती है । जमीन से टकराते ही **हवा संपीड़ित** और **गर्म** हो जाती है और एक **उच्च दबाव ताप गुंबद** बना सकती है।
- **प्री-मानसून सीज़न के दौरान,**
  - ऊपरी स्तर का **इंडियन ईस्टर्नली जेट (IEJ**) अरब सागर, **प्रायद्वीपीय** भारत और बंगाल की खाड़ी के पार, **ऊपरी वायुमंडल** में आकार लेना शुरू कर देता है।
  - उत्तर में एक सशक्त पश्चिमी जेट मौजूद है।
- **मानसून** के **मौसम** के दौरान **पश्चिमी जेट** को **उत्तर** की ओर धकेल दिया जाता है और **IEJ भारतीय उपमहाद्वीप** पर हावी रहता है।
- इन दोनों के द्वारा **हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप** पर **एंटीसाइक्लोन स्थितियाँ** उत्पन्न हो सकती हैं।
- एक मजबूत **एंटीसाइक्लोन** भारत के कई हिस्सों में **शुष्क और गर्म मौसम** ला सकता है जबकि एक कमजोर **एंटीसाइक्लोन** हल्का मौसम पैदा कर सकता है।

आगे की राह:

- भारत की पूर्वानुमान प्रणाली और पूर्व अलर्ट प्रणालियों में सुधार हुआ है।
  - हालाँकि, भारत में हर स्थान पर मौसम के प्रक्षेप पथ की बेहतर भविष्यवाणी करके भविष्य के लिए रेसिलिएंस बनाने की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- इसे निरंतर सफल बनाने के लिए **सरकारों, उ**नके **विभागों** और **बड़े पैमाने** पर **लोगों को प्रशिक्षित** करने और इसमें शामिल होने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन II

POLITY & GOVERNANCE

14. वीवीपैट पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- EVM
- ECI

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **चुनाव आयोग (EC)** को नोटिस जारी कर सभी मतदाता सत्यापन योग्य **पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** पर्चियों की गिनती करके डाले गए वोटों के साथ **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** में गिनती को अनिवार्य रूप से **क्रॉस-सत्यापित** करने का निर्देश देने की मांग की है।

पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

- यह **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** से जुड़ी एक स्वतंत्र **सत्यापन प्रिंटर मशीन** है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया गया है।
- जैसे ही मतदाता **EVM पर बटन दबाता है, VVPAT मशीन** लगभग **7 सेकंड** के लिए उस **पर्ची को प्रिंट** करती है जिसमें उस **पार्टी का नाम और प्रतीक** होता है जिसे उन्होंने वोट दिया है।
- **VVPAT मशीनें** पहली बार **भारत में 2014** के **लोकसभा** चुनावों में पेश की गईं और पारदर्शिता बढ़ाने और **EVM** की सटीकता के बारे में संदेह को खत्म करने के लिए पेश की गईं।
- **VVPAT मशीनों** तक केवल **मतदान अधिकारी** ही पहुंच सकते हैं।
- **ECI** के अनुसार, **EVM** और **VVPAT** अलग-अलग इकाइयां हैं और किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जो मतदाता को उम्मीदवार की प्रत्येक पसंद के लिए एक बटन देने में सक्षम बनाती हैं।
- इसमें दो **इकाइयाँ कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट** शामिल हैं।
- इसका उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां बिजली नहीं है।
- नियंत्रण इकाई **चुनाव आयोग द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के पास है।**
- **बैलेटिंग यूनिट मतदान** अनुभाग में है जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के **नाम और हस्ताक्षर** के सामने बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालने के लिए प्रवेश करते हैं।

15. ED 'किसी भी जानकारी' के लिए किसी को भी समन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रवर्तन निदेशालय
- FERA

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** की व्यापक शक्तियों का समर्थन किया
- इसमें कहा गया है कि **केंद्रीय एजेंसी** "किसी भी जानकारी के लिए किसी को भी बुला सकती है" हालांकि उसने **तमिलनाडु** के **चार जिला कलेक्टरों** को **मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निकाय** द्वारा जारी किए गए समन के जवाब में **व्यक्तिगत रूप** से उपस्थित होने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।

PMLA की धारा 50(2)

- इसने **ED** को "**किसी भी व्यक्ति**" को बुलाने का अधिकार दिया, जिसकी उपस्थिति क़ानून के तहत **"किसी भी जांच या कार्यवाही"** के दौरान साक्ष्य देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक मानी जाती थी।

धारा 50(3)

- यह अनिवार्य है कि बुलाया गया व्यक्ति "**व्यक्तिगत रूप** से या **अधिकृत एजेंटों** के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य है" और उसे सच्चे बयान देने और आवश्यक दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** एक **बहु-विषयक संगठन** है जिसे **मनी लॉन्ड्रिंग** के **अपराधों और विदेशी मुद्रा** कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है।
- यह **वित्त मंत्रालय** के **राजस्व विभाग** के अंतर्गत कार्य करता है।
- इस **निदेशालय** की उत्पत्ति **1 मई, 1956** से हुई, जब **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)**, **1947** के तहत **विनिमय नियंत्रण कानूनों** के उल्लंघन से निपटने के लिए **आर्थिक मामलों** के विभाग में एक '**प्रवर्तन इकाई**' का गठन किया गया था।
- इसका **मुख्यालय दिल्ली** में था, जिसका **नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक** के रूप में एक **कानूनी सेवा अधिकारी** करता था।
- इसकी बम्बई और कलकत्ता में दो शाखाएँ थीं।

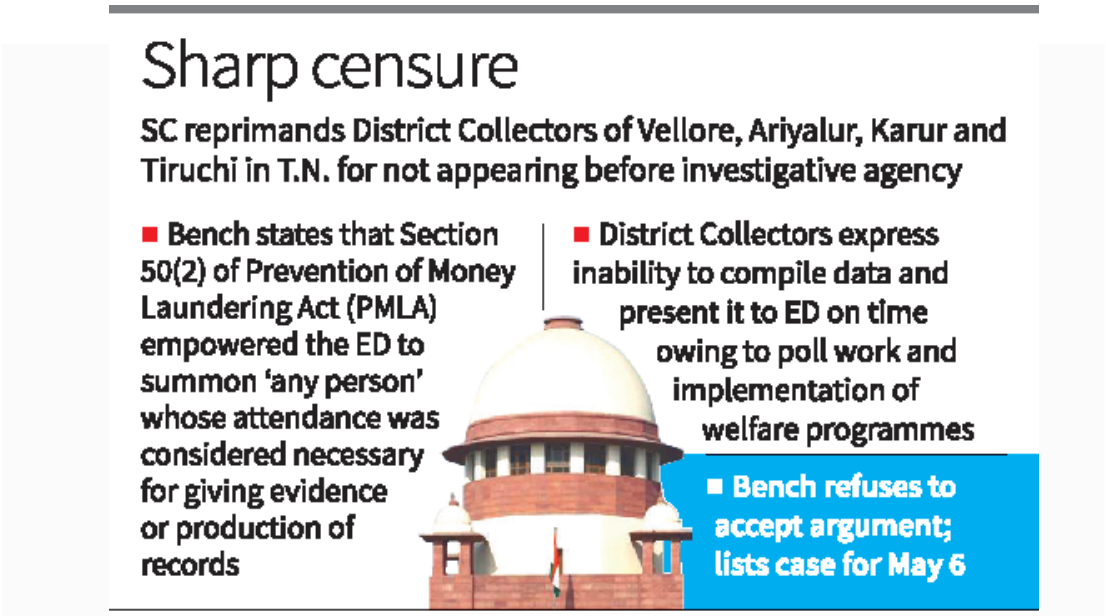

16. सुप्रीम कोर्ट एकतरफा तलाक पर केरल हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा - इंडिया टुडे

प्रीलिम्स टेकअवे

- तलाक
- खुला

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट **केरल हाई कोर्ट** के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें **मुस्लिम महिलाओं** को 'खुला' के जरिए तलाक लेने का पूरा अधिकार दिया गया था।
- इस्लामी कानून विवाह समाप्त करने के **खुला और तलाक** दो मुख्य तरीके प्रदान करता है।

खुला: तलाक शुरू करने का एक महिला का अधिकार

- कुरान में उल्लिखित खुला, महिलाओं को अदालत में अपने पतियों से अलग होने की मांग करने का अधिकार देता है।
- दुरुपयोग, उपेक्षा या बस असंगत होने जैसे वैध कारणों का हवाला दिया जा सकता है।
- समझौते के तहत पत्नी अपना दहेज (मेहर) वापस कर सकती है।
- खास बात यह है कि खुला तलाक के बाद बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति पर ही रहती है।

तलाक: तलाक की पहल पति द्वारा की जाती है

- इसके विपरीत, तलाक पतियों को अदालत की मंजूरी या कारण बताए बिना अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार देता है।
- जबकि दहेज और पत्नी के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति वापस की जानी चाहिए, यह प्रक्रिया कम संरचित है।

- यह प्रणाली दोनों पति-पत्नी को एक नाखुश विवाह को समाप्त करने की क्षमता देती है, लेकिन खुला महिलाओं को अधिक नियंत्रण देती है और प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा करती है।

17. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रणाली- द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- चुनाव चिह्न
- ECI

समाचार:
- **नाम तमिलर काची (NTK)** जिसने **वर्ष 2019** और **वर्ष 2021** में **तमिलनाडु** में **क्रमशः 3.9%** और **6.5% वोट** हासिल किए, को एक नया **सामान्य प्रतीक (माइक)** आवंटित किया गया है।
- **वर्ष 2019** और **वर्ष 2021** में **1.09% और 0.99% वोट** हासिल करने वाली **विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK)** को एक **सामान्य प्रतीक (Pot)** से वंचित कर दिया गया है।
- इससे '**पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों**' को चुनाव **चिन्ह आवंटन** पर सवाल खड़े हो गए हैं।

नियम
- **भारत** के **चुनाव आयोग (ECI)** द्वारा **चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** (प्रतीक आदेश) के प्रावधानों के तहत एक पार्टी को **'राष्ट्रीय'** या **'राज्य' पार्टी** के रूप में मान्यता दी जाती है।
- राज्य स्तर पर मान्यता के मानदंड शामिल हैं
  - प्रत्येक 25 सीटों या 3% विधान सभा सीटों के लिए एक लोकसभा सीट जीतना या
  - 6% वोटों के साथ एक लोकसभा या दो विधानसभा सीटें जीतना
  - आम चुनाव में डाले गए 8% वोट हासिल करना।
- **ECI** द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार **राजनीतिक दलों** और **चुनाव लड़ने** वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।
- **सबसे बड़े लोकतंत्र** में जहां एक बड़ी आबादी अभी भी निरक्षर है, मतदान प्रक्रिया में **प्रतीक महत्वपूर्ण** भूमिका निभाते हैं।
- एक मान्यता प्राप्त **राजनीतिक दल** का एक **आरक्षित प्रतीक** होता है जो किसी भी **निर्वाचन क्षेत्र** में किसी अन्य **उम्मीदवार** को आवंटित नहीं किया जाता है।
- पंजीकृत लेकिन **गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** के लिए, **चुनाव** के दौरान **मुफ्त प्रतीकों** में से एक को सामान्य प्रतीक के रूप में आवंटित किया जाता है
  - यदि वह पार्टी **दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों** में या किसी राज्य की **विधानसभा** में **5% सीटों** पर, जैसा भी मामला हो, चुनाव लड़ती है।

मौजूदा मामला क्या है?
- प्रतीक आदेश के नियम **10 B** में प्रावधान है कि एक सामान्य **मुक्त प्रतीक** की रियायत **दो आम चुनावों** के लिए 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी' को उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा, एक पार्टी किसी भी बाद के **आम चुनाव** में एक **सामान्य प्रतीक** के लिए पात्र होगी यदि उसने पिछले अवसर पर राज्य में **कम से कम 1%** वोट हासिल किए थे जब पार्टी ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।
- हालाँकि ऐसी **गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी** को हर बार निर्धारित प्रारूप में **प्रतीक चिन्ह** के लिए आवेदन करना चाहिए।
- यह आवेदन **लोकसभा या राज्य विधानसभा** के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय किया जा सकता है।
- उसके बाद प्रतीकों को '**पहले आओ-पहले पाओ**' के आधार पर आवंटित किया जाता है।

18. भारत की शिक्षा प्रणाली में अंतराल से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ASER
- ILO

समाचार:
- **जनवरी** में जारी **ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स**' **शीर्षक** से **शिक्षा** की **वार्षिक स्थिति** रिपोर्ट में पाया गया कि आधे से अधिक लोगों को बुनियादी **गणित** में संघर्ष करना पड़ा, एक ऐसा कौशल जिसमें उन्हें कक्षा 3 और 4 में महारत हासिल करनी चाहिए थी।
- **नागरिक समाज संगठन** प्रथम द्वारा 1**4 से 18 वर्ष** की आयु के **ग्रामीण छात्रों** के बीच एक **सर्वेक्षण** किया गया था।

मुख्य बिंदु

- **26 राज्यों** के **28 जिलों** में किए गए **घरेलू सर्वेक्षण** में **30,000** से अधिक छात्रों की मूलभूत **पढ़ने** और **अंकगणित क्षमताओं** का आकलन किया गया और पता चला कि इस **आयु वर्ग** के लगभग **25% छात्र** अपनी **स्थानीय भाषा** में **कक्षा 2 स्तर** का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।
- जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, **पढ़ाई छोड़ने** की दर बढ़ती गई।
- जबकि **14 साल** के **3.9%** बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, **18 साल** के बच्चों के लिए यह **आंकड़ा** बढ़कर **32.6%** हो गया।
- इसके अलावा, केवल **5.6%** ने **व्यावसायिक प्रशिक्षण** या **अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों** का विकल्प चुना था।
- मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार हालिया भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 सहित बाद के **सर्वेक्षणों** से पता चलता है कि हालांकि सभी **सामाजिक** समूहों के लिए **शिक्षा** तक पहुंच में सुधार हुआ है,
  - लेकिन **सामाजिक समूहों** के बीच पदानुक्रम कायम है, **अनुसूचित जनजातियां** अभी भी सबसे अधिक वंचित हैं।"
- **प्राथमिक** से **उच्च प्राथमिक** और **माध्यमिक विद्यालय** में **परिवर्तन दर** महत्वपूर्ण **ड्रॉपआउट** दिखाती है और **लैंगिक अंतर** भी अधिक है।
- **ST बच्चों** को प्रदान की जाने वाली **शिक्षा** की **गुणवत्ता** में सुधार के लिए, **"सुधारित शिक्षाशास्त्र"** की आवश्यकता है
  - मातृभाषा में शिक्षा और जनजातीय बोलियों में सहायक सामग्री।
- स्कूल की **गतिविधियों और विद्यार्थियों** के जीवन के बीच **तालमेल** होना जरूरी है

लैंगिक और अन्य असमानताएँ

- लैंगिक, जाति, अमीर/गरीब, **शहरी/ग्रामीण** विभाजन जो शिक्षा में कायम है। कई गाँव के स्कूलों में खराब **गुणवत्ता वाली शिक्षा** के बारे में लिखते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण सेवाओं** को लागू करने के लिए, **नौकरशाहों** को **जटिल समस्याओं** को हल करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है, "

19. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा कानून को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
• अनुच्छेद 29
• अनुच्छेद 14

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसने **मदरसों** को **विनियमित** करने वाले उत्तर प्रदेश के **20 साल पुराने कानून** को रद्द कर दिया और उनके छात्रों को नियमित **स्कूलों में स्थानांतरित** करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

- **भारत** के **मुख्य न्यायाधीश** की अध्यक्षता वाली **तीन-न्यायाधीशों** की पीठ ने एक अंतरिम आदेश में **22 मार्च** के **उच्च न्यायालय** के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया।
  - हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने न्याय का निर्णय को "स्वीकार" कर लिया है।
- राज्य ने **उच्च न्यायालय** में **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004** के अस्तित्व के लिए जी-जान से लड़ने का दावा किया है।
- हालाँकि, यह अब **उच्च न्यायालय** के दृष्टिकोण से सहमत हो गया है कि **अधिनियम धर्मनिरपेक्षता** के **सिद्धांतों** को खतरे में डालता है और **संविधान की मूल संरचना** का उल्लंघन करता है।
- "इसका उपाय **मदरसा बोर्ड अधिनियम** को रद्द करना नहीं होगा
  - लेकिन **मदरसों** में अपनी **शिक्षा** प्राप्त करने वाले छात्रों को अन्य **संस्थानों** में **राज्य** द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा की **गुणवत्ता** तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए **उपयुक्त** निर्देश जारी करने के लिए, **मुख्य न्यायाधीश** ने **खंडपीठ** के लिए आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस **अधिनियम** का उद्देश्य **उत्तर प्रदेश राज्य** में **मदरसों** (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को **विनियमित और नियंत्रित** करना है।

- इसने पूरे **उत्तर प्रदेश** में **मदरसों** की स्थापना, मान्यता, **पाठ्यक्रम और प्रशासन** के लिए एक **रूपरेखा** प्रदान किया।
- इस **अधिनियम** के तहत, राज्य में **मदरसों की गतिविधियों** की **देखरेख और पर्यवेक्षण** के लिए **उत्तर प्रदेश** मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।

20. सुप्रीम कोर्ट VVPAT पर्चियों के सत्यापन की याचिका पर सुनवाई करेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- VVPAT
- ECI

समाचार:
- **19 अप्रैल** को होने वाले पहले चरण के मतदान के साथ, **सुप्रीम कोर्ट (SC)** ने पिछले हफ्ते कहा था कि **वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** पर्चियों के **100% सत्यापन** की मांग करने वाली याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी।
- **मार्च 2023** में **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स** ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी
- इसमें कहा गया है कि **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित** करने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों** (EVM) के मिलान को **VVPAT** से सत्यापित किया जाना चाहिए।

VVPAT कैसे काम करता है
- VVPAT मशीनें **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग** के लिए **रसीद प्रिंटर** की तरह हैं।
- जब आप **EVM** पर वोट करते हैं, तो आपके चुने हुए उम्मीदवार को दर्शाने वाली एक पर्ची कांच की खिड़की के पीछे **सात सेकंड** के लिए निकलती है।
- इससे आप अपने वोट को **सुरक्षित बॉक्स** में गायब होने से पहले **सत्यापित** कर सकते हैं।
- आप पर्ची घर नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ बेतरतीब ढंग से चुने गए **मतदान केंद्रों** में **इलेक्ट्रॉनिक** परिणामों की जांच करने के लिए इसे सहेजा जाता है।

VVPAT क्यों?
- **चुनाव आयोग (EC)** द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग** को और अधिक पारदर्शी बनाने के तरीकों की मांग के बाद 2013 में **VVPAT** की शुरुआत हुई।
- **परीक्षणों** और **फीडबैक** के बाद, उन्हें **वर्ष 2017** तक देश भर में लागू कर दिया गया।

VVPAT पर कानूनी लड़ाई
- VVPAT के इस्तेमाल को अदालत में चुनौती दी गई है।
- **वर्ष 2013** में, **सुप्रीम कोर्ट** के एक मामले में फैसला सुनाया गया कि **पेपर ट्रेल्स** आवश्यक थे और **VVPAT** के लिए **फंडिंग** का आदेश दिया गया था।
- अदालत ने अंततः **VVPAT** को सत्यापित करने के लिए **पांच-स्टेशनों** पर **पुनर्मतगणना** का पक्ष लिया।

21. उम्मीदवारों को मतदाताओं से निजता का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- RPA 1950
- RPA 1951

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में कहा कि एक **चुनावी उम्मीदवार** को **मतदाताओं से निजता** का अधिकार है
- यह माना गया कि मतदाताओं को अपने **निजी जीवन और संपत्ति, अतीत और वर्तमान** के प्रत्येक टुकड़े को **आवर्धक कांच** से जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुख्य बिंदु
- किसी उम्मीदवार द्वारा उन मामलों पर अपनी गोपनीयता बनाए रखने का विकल्प, जो मतदाताओं के लिए कोई चिंता का विषय नहीं थे या **सार्वजनिक पद** के लिए उसकी उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक थे, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की **धारा 123** के तहत '**भ्रष्ट आचरण**' की श्रेणी में नहीं आता है।
- इस तरह का **गैर-प्रकटीकरण 1951 अधिनियम की धारा 36(4)** के तहत "**महत्वपूर्ण प्रकृति का दोष**" नहीं माना जाएगा।
- "यह आवश्यक नहीं है कि एक **उम्मीदवार चल संपत्ति** के प्रत्येक **आइटम की घोषणा** करे जो उसके या उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के पास है
- जब तक कि ये आइटम इतने मूल्य के न हों कि अपने आप में एक बड़ी **संपत्ति का गठन** करें या उनकी **जीवनशैली और प्रकटीकरण** की आवश्यकता के संदर्भ में उनकी उम्मीदवारी को प्रतिबिंबित करें।

- अदालत ने कहा कि मतदाताओं को उस जानकारी का खुलासा करने का अधिकार है जो उस उम्मीदवार को चुनने के लिए आवश्यक है जिसे वोट दिया जाना चाहिए।

RPA - 1951 की धारा 123

- यह '**भ्रष्ट गतिविधियों**' को परिभाषित करता है जिसमें **रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी** और भारत के **नागरिकों के विभिन्न वर्गों** के बीच "**शत्रुता या घृणा** की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास" शामिल है।
  - चुनाव में अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक उम्मीदवार द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर।
- **धारा 123 (2)** '**अनुचित प्रभाव**' से संबंधित है जिसे यह "उम्मीदवार या उसके एजेंट, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप** करने का प्रयास" के रूप में परिभाषित करता है।
  - **उम्मीदवार** या उसके **चुनाव एजेंट** की सहमति से, किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के साथ।"
- इसमें चोट पहुंचाने की धमकी, **सामाजिक बहिष्कार** और किसी **जाति या समुदाय** से निष्कासन भी शामिल हो सकता है।
- धारा 123 (4) "**भ्रष्ट गतिविधियों**" के दायरे को झूठे बयानों के **जानबूझकर प्रकाशन** तक बढ़ाती है जो **उम्मीदवार के चुनाव** के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

22. SC ने औद्योगिक अल्कोहल नियंत्रण पर केंद्र के सख्त रुख पर सवाल उठाए - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- संघ सूची
- राज्य सूची

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** की **नौ-न्यायाधीशों** की **संविधान पीठ** ने **औद्योगिक शराब** पर **विशेष नियंत्रण** के लिए **केंद्र** की **कठोर स्थिति** पर सवाल उठाया है।
- इसने **केंद्र** से **राज्यों** को **मानव उपभोग** के लिए **पीने योग्य शराब के प्रवाह** और **गुप्त रूपांतरण** को **विनियमित** करने का अवसर दिए बिना **सार्वजनिक स्वास्थ्य** के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के बारे में भी सवाल उठाया है।

मुख्य बिंदु

- **"मानव उपभोग** के उद्देश्य से विकृत **स्पिरिट या औद्योगिक अल्कोहल** का दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है।
- राज्य **सार्वजनिक स्वास्थ्य** का **संरक्षक** है राज्य अपने **अधिकार क्षेत्र** में होने वाली **शराब त्रासदियों** के बारे में चिंतित हैं।
- दूसरी ओर, केंद्र एक असंबद्ध इकाई है।
- **केंद्र** ने दावा किया कि **औद्योगिक शराब** एक संसदीय कानून के तहत जनहित में **केंद्र सरकार** द्वारा नियंत्रित एक "**उद्योग**" था।
- ऐसे उद्योग को **संविधान** की **सातवीं अनुसूची** में **संघ सूची की प्रविष्टि 52** द्वारा कवर किया गया था।
- हालाँकि ऐसे **उद्योगों** के उत्पादों के **व्यापार** और **वाणिज्य, आपूर्ति, वितरण और उत्पादन** को **समवर्ती सूची** की प्रविष्टि **33 (A)** के रूप में शामिल किया गया था,

क्षमताओं की सीमा

- हालाँकि, **केरल, महाराष्ट्र, पंजाब** जैसे **राज्यों** और यहां तक कि **उत्तर प्रदेश** की एक **याचिका** ने **नशीली शराब** बनाने के लिए **औद्योगिक अल्कोहल** के इस्तेमाल के बारे में चिंता जताई है।

संविधान में औद्योगिक शराब फ्रेमवर्क

- **राज्य सूची (प्रविष्टि 8):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित है।
- **संघ सूची (प्रविष्टि 52)** : संसद को सार्वजनिक हित में समीचीन समझे जाने वाले उद्योगों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

- **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 33)** : यह राज्यों और केंद्र दोनों को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते है।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** औद्योगिक अल्कोहल उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) के अंतर्गत आता है, जो इसे विनियमन के विषय के रूप में सूचीबद्ध करता है।
- संसद का यह अधिनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक शराब को विनियमित करने की क्षमता प्रदान करता है।

23. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को खारिज किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एड) एक्ट , 1954

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने स्वयंभू योग **गुरु बाबा रामदेव**, **पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड** की दूसरे दौर की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु
- शीर्ष अदालत ने **नवंबर 2023** में दिए गए एक वचन का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी कि वे **वर्ष 1954 अधिनियम** के उल्लंघन में "**इलाज**" का विज्ञापन करने से बचेंगे।
- सुनवाई के दौरान **अदालत** ने **भ्रामक विज्ञापनों** पर आंखें मूंद लेने के लिए **उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग** प्राधिकरण पर नाराजगी जताई।

ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एड) एक्ट , 1954
- यह **दवाओं** के **विज्ञापन** को नियंत्रित करने और उपचारों में **मैजिक गुणों** के **दावों** को **प्रतिबंधित** करने के लिए एक विधायी ढांचा है।
- इसमें **लिखित, मौखिक और दृश्य माध्यमों** सहित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत, "**दवा**" शब्द का तात्पर्य मानव या **पशु उपयोग** के लिए **इच्छित दवाओं, रोगों के निदान** या **उपचार** के लिए **पदार्थों** और **शरीर** के **कार्यों** को प्रभावित करने वाले लेखों से है।
- उपभोग के लिए बनाई गई वस्तुओं के अलावा, इस **अधिनियम** के तहत "**मैजिक रेमेडीज** " की परिभाषा **तावीज़, मंत्र** और **ताबीज** तक भी फैली हुई है, जिनमें कथित तौर पर **उपचार या शारीरिक कार्यों** को प्रभावित करने के लिए **चमत्कारी शक्तियां** होती हैं।
- यह **दवाओं** से **संबंधित विज्ञापनों** के प्रकाशन पर सख्त नियम लागू करता है।
- यह उन विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो ग़लत धारणाएँ देते हैं, झूठे दावे करते हैं, या अन्यथा भ्रामक हैं।
- इन प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दोषी पाए जाने पर **कारावास** या **जुर्माना सहित दंड** हो सकता है।
- अधिनियम के तहत शब्द "**विज्ञापन**" सभी नोटिस, लेबल, रैपर और मौखिक घोषणाओं तक फैला हुआ है।

24. सुप्रीम कोर्ट ने DMRC की क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूरी दी -

प्रीलिम्स टेकअवे
- पुनर्विचार याचिका

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने फैसला सुनाया कि **दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन** (**DMRC**) को **दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL)** को लगभग **8,000 करोड़ रुपये** का भुगतान नहीं करना होगा।

क्यूरेटिव पिटीशन
- जैसा कि **भारत के संविधान** में उल्लिखित और वादा किया गया है, लोगों के लिए न्याय पाने के लिए **क्यूरेटिव पिटीशन** अंतिम और अंतिम विकल्प है।
- अंतिम दोषसिद्धि के खिलाफ स**मीक्षा याचिका खारिज** होने के बाद **सुधारात्मक याचिका** दायर की जा सकती है।
- **उद्देश्य**: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय में कोई गड़बड़ी न हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

- **अदालत** ने फैसला सुनाया कि यदि **याचिकाकर्ता** यह स्थापित करता है कि **प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो **सुधारात्मक याचिका** पर विचार किया जा सकता है और **आदेश पारित** करने से पहले **अदालत** ने उसकी बात नहीं सुनी थी।
- यह भी स्वीकार किया जाएगा जहां एक **न्यायाधीश** उन तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा जो **पूर्वाग्रह** की आशंका पैदा करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि **सुधारात्मक याचिकाएं नियमित** होने के बजाय दुर्लभ होनी चाहिए और उन पर **सोच-समझकर** विचार किया जाना चाहिए।
- एक **उपचारात्मक याचिका** के साथ एक **वरिष्ठ वकील** द्वारा **प्रमाणीकरण** किया जाना चाहिए, जिसमें इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार बताए जाएं।

25. चुनावी उम्मीदवारों को प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- RPA, 1951
- ECI

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में कहा कि **उम्मीदवारों** को अपने **चुनावी हलफनामे** में हर जानकारी और **संपत्ति का खुलासा** करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वह पर्याप्त प्रकृति की न हो।

कानूनी प्रावधान:
- **RPA 1951:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम) की धारा 33, चुनाव नियमों के नियम 4A के साथ पढ़ी जाती है, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक शपथ पत्र के साथ चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करना आवश्यक है।
- **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2002)** :
  - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, आय और संपत्ति के साथ-साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार है।
  - इस निर्णय के परिणामस्वरूप धारा 33A को RP अधिनियम में जोड़ा गया जिसके लिए चुनावी हलफनामे का हिस्सा होने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड के विवरण की आवश्यकता होती है।
- **RPA** की **धारा 125A** में प्रावधान है कि आवश्यक **जानकारी देने में विफल** रहने, **गलत जानकारी** देने या **नामांकन पत्र या हलफनामे** में कोई **जानकारी छिपाने** पर **छह महीने** तक की **कैद या जुर्माना** या **दोनों** से **दंडनीय** होगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)** में यह निर्देश दिया गया था कि **उम्मीदवारों** के साथ-साथ **राजनीतिक दलों** को भी **उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड** के बारे में घोषणा करनी होगी।
  - चुनाव से पहले कम से कम तीन बार, स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घोषणा करनी होगी।।

चुनाव आयोग और विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में सिफारिशें:
- **झूठा हलफनामा** दाखिल करने के लिए **दोषी ठहराए** जाने पर कम से कम **2 साल** की **कैद** होनी चाहिए और यह **अयोग्यता** का आधार होना चाहिए।
- ऐसे मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर की जानी चाहिए
- जिन व्यक्तियों पर **सक्षम न्यायालय** द्वारा **कम से कम 5 वर्ष** के **कारावास** की **सजा वाले अपराध** का आरोप लगाया गया है, उन्हें **चुनाव लड़ने** से रोक दिया जाना चाहिए, बशर्ते **मामला चुनाव** से **कम से कम 6 महीने** पहले **दायर** किया गया हो।

26. हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति लेनी होगी: गुजरात सरकार - - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मौलिक अधिकार

समाचार:
- **गुजरात सरकार** ने एक **परिपत्र जारी** कर **बौद्ध धर्म** को एक **स्वतंत्र धर्म** के रूप में मान्यता देने की बात स्पष्ट की है।
- इसमें कहा गया है कि **हिंदू धर्म** से **बौद्ध धर्म, जैन धर्म** या **सिख धर्म** में रूपांतरण के लिए **गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003** के अनुसार संबंधित **जिला मजिस्ट्रेट** से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

भारत में धर्मांतरण से सम्बंधित कानून

- **अनुच्छेद 25 (मौलिक अधिकार):** लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
- धार्मिक समूहों को भी अपने **धार्मिक मामलों** को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक वे **सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य** और **व्यवस्था का पालन** करते हैं।
- वर्तमान में **भारत** में **धार्मिक रूपांतरण** पर कोई **राष्ट्रीय प्रतिबंध** या **नियम** नहीं हैं।
- कई **राज्यों** ने पिछले **कुछ वर्षों** में **जबरन, धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण** पर रोक लगाने के लिए **"धर्म की स्वतंत्र**ता" कानून बनाए हैं।
- सामान्य तौर पर, भारत में **धर्मांतरण विरोधी कानूनों** के तहत ऐसे **व्यक्तियों** को पहले से **सरकारी अनुमति प्राप्त** करने की आवश्यकता होती है जो **दूसरे धर्म में परिवर्तित** होना चाहते हैं।
- कु**छ राज्यों में दूसरों** की **तुलना** में **सख्त कानून** हैं, और **कुछ कानून विशेष** रूप से कुछ **धार्मिक समूहों** या **गतिविधियों** को लक्षित करते हैं।

एस पुष्पाबाई बनाम सीटी सेल्वराज:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने पुष्टि की कि बशर्ते **रूपांतरण वास्तविक** और **स्वैच्छिक** हो, **व्यक्तियों** को **दूसरे धर्म** में **परिवर्तित होने** का अधिकार है
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि **धार्मिक रूपांतरण** के **संबंध** में किसी भी प्रकार की **जबरदस्ती** या **गलत बयानी धर्म** की **स्वतंत्रता का उल्लंघन** करती है।

27. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत 'एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- UAPA
- PMLA

समाचार:

- **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)** के तहत **निर्णायक प्राधिकरण** ने समाचार पत्र समुदाय से संबंधित **751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति** की **कुर्की** की पुष्टि की है।

एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी

- यह **भारत सरकार** द्वारा नियुक्त किया जाता है, **180 दिनों** के भीतर **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** द्वारा जब्त की गई संपत्ति की समीक्षा करता है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) **मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों** से जुड़ी होने के संदेह में **संपत्ति जब्त** कर सकती है।
- मुकदमे से पहले संपत्ति के गायब होने को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) **6 महीने (180 दिन)** के लिए संपत्ति को जब्त कर लेती है।
- एक **एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी** यह तय करता है कि क्या जब्ती वैध है यदि नहीं, तो **संपत्ति मालिक** के पास वापस चली जाती है।
- यदि **प्राधिकरण जब्ती** को मंजूरी दे देता है, तो मालिक कई **अदालतों के माध्यम** से फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
- कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक संपत्ति जमी रहती है।
- सबसे खराब स्थिति में, यदि दोषी ठहराया जाता है, तो **मालिक सरका**र को **अपनी संपत्ति स्थायी** रूप से खो देता है।
- इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं, जिससे जब्त की गई संपत्ति **अनुपयोगी और संभावित रूप** से **क्षतिग्रस्त** हो जाएगी।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

- यह **भारत** की **संसद** का **एक अधिनियम** है जो **मनी लॉन्ड्रिंग** को रोकने और **मनी लॉन्ड्रिंग** से प्राप्त **संपत्ति की जब्ती** का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
- धारा **45 मनी लॉन्ड्रिंग** के आरोप में जमानत का प्रावधान करती है।

- कानून में यह प्रावधान, **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)** में कड़े जमानत मानक की तरह, **आरोपी** पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।
- हालाँकि, **जमानत मानक** में एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
- कानून कहता है कि बशर्ते कि को**ई व्यक्ति**, जो **सोलह वर्ष** से **कम उम्र** का है या **महिला** है या **बीमा**र या **अशक्त** है, उसे **जमानत पर रिहा** किया जा सकता है, यदि **विशेष अदालत** ऐसा निर्देश दे।
- यह अपवाद महिलाओं और नाबालिगों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत छूट के समान है।

28. नींद का अधिकार एक "मूलभूत मानवीय आवश्यकता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता: बॉम्बे HC - इंडिया टुडे

समाचार:

- **बॉम्बे हाई कोर्ट** ने कहा कि **नींद का अधिकार** एक "**मूलभूत मानवीय आवश्यकता**" है और इसे **प्रदान न करना** किसी व्यक्ति के **मानवाधिकारों** का उल्लंघन है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- अनुच्छेद 21

मुख्य बिंदु

- अदालत ने **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** को बयान दर्ज करने के लिए "**सांसारिक समय**" बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश दिया
  - जब एजेंसी द्वारा **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत समन जारी किया जाता है।
- एक अदालत ने एक **व्यापारी की गिरफ़्तारी** की शिकायत खारिज कर दी, लेकिन पूरी रात उससे पूछताछ करने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया।
- इससे उनके **सोने** के **अधिकार** का उल्लंघन हुआ, जिसे **भारतीय संविधान** के तहत **सम्मान** के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा माना जाता है।
- हालाँकि इसकी **कुछ सीमाएँ** हैं कि आप कहाँ, **कब और कैसे सो** सकते हैं (जैसे कि सार्वजनिक रूप से नग्न होकर नहीं सोना!), कोई भी आपको **अनुचित** रूप से अच्छी रात का आराम पाने से नहीं रोक सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

- **सईद मकसूद अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2001):** मध्य प्रदेश HC ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सभ्य वातावरण में रहने का अधिकार है और रात में शांति से सोने का अधिकार है।
- **पुनः-रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव (2012)** : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी है, जो अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू है। यह भारतीय संविधान का एक अपरिहार्य अधिकार है।

29. असाधारण मामला: SC ने 30 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी - इंडियन एक्सप्रेस

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **यौन उत्पीड़न** की **14 वर्षीय पीड़िता** को लगभग **30 सप्ताह** के **गर्भ** को **समाप्त** करने की अनुमति दे दी है।
- एक बेंच ने कहा कि यह "एक बहुत ही असाधारण मामला है जहां हमें उसकी (लड़की की) रक्षा करनी है"।

प्रीलिम्स टेकअवे
- MTP अधिनियम 1971

भारत में गर्भपात कानून

- **वर्ष 1971** से **भारत** का **गर्भपात कानून** (MTP अधिनियम) (2021 में संशोधित) **महिलाओं** को **गर्भावस्था** को समाप्त करने की अनुमति देता है।
- **20 सप्ताह** तक, एक **डॉक्टर** की मंजूरी पर्याप्त है।
- **20-24 सप्ताह** तक, इसे केवल **विशेष स्थितियों** (जैसे बलात्कार या युवा लड़कियों) में ही अनुमति दी जाती है और इसके लिए **दो डॉक्टरों** से **अनुमोदन** की आवश्यकता होती है।
- 24 सप्ताह के बाद चीजें जटिल हो जाती हैं।

- विशेष **क्लीनिक** यह तय कर सकते हैं कि **गर्भपात** की **अनुमति** है या नहीं, लेकिन केवल तभी जब **भ्रूण** में कोई **गंभीर समस्या** हो (यह देखने के लिए "व्यवहार्यता परीक्षण" द्वारा जांच की जाती है कि क्या यह गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है)।
- यह **परीक्षण विवादास्पद** है क्योंकि यह कुछ हद तक **पुरानी समय-सीमा (24 सप्ताह)** पर आधारित है।
- अदालतें कभी-कभी बाद में भी गर्भपात की अनुमति दे सकती हैं।
- उदाहरण के लिए, हाल के एक मामले में एक **14 वर्षीय लड़की** को संभावित **मानसिक** और **शारीरिक** क्षति के कारण अपनी **गर्भावस्था समाप्त** करने की अनुमति दी गई।

MTP एक्ट 2021

- **अधिनियम** उन **स्थितियों** को **नियंत्रित** करता है जिनके तहत **गर्भावस्था** को **समाप्त** किया जा सकता है।
- यह उस **समयावधि** को बढ़ाता है जिसके भीतर **गर्भपात** किया जा सकता है।
- वर्तमान में, **गर्भपात** के लिए एक **डॉक्टर** की राय की आवश्यकता होती है यदि यह गर्भधारण के **12 सप्ताह** के भीतर किया जाता है और यदि यह **12 से 20 सप्ताह** के बीच किया जाता है तो **दो डॉक्टरों** की राय की आवश्यकता होती है।
- यह **20 सप्ताह** तक एक **डॉक्टर** की सलाह पर और **20 से 24 सप्ताह** के बीच **कुछ श्रेणियों** की **महिलाओं** के मामले में **दो डॉक्टरों** की सलाह पर **गर्भपात** कराने की अनुमति देता है।
- यह यह तय करने के लिए **राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड** का गठन करता है कि भ्रूण में पर्याप्त **असामान्यताओं** के मामलों में **24 सप्ताह** के बाद **गर्भावस्था** को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।

30. सरकार को 'भ्रामक विज्ञापनों का उपयोग करने वाली FMCG कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए: SC - द हिंदू

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने कहा कि **केंद्र** को **फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)** कंपनियों के खिलाफ "खुद को सक्रिय" करना चाहिए, अगर ये **विश्वसनीय उपभोक्ताओं** को लक्षित करने के लिए अपने उत्पादों के बारे में "**भ्रामक विज्ञापन**" देते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954

मुख्य बिंदु

- FMCG के भ्रामक विज्ञापन जनता, विशेषकर परिवारों को धोखा देते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के **मंत्रालय** ने **भारतीय खाद्य सुरक्षा** और **मानक प्राधिकरण (FSSAI)** से अग्रणी **FMCG** के खिलाफ आरोपों की जांच करने को कहा है।

अवमानना का मामला

- अदालत पतंजलि आयुर्वेद, इसके **सह-संस्थापक** और **योग गुरु बाबा रामदेव** और उनके **सहयोगी आचार्य बालकृष्ण** के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** को दिए गए वचन के बावजूद **ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट** का उल्लंघन करके अपनी **आयुर्वेदिक दवाओं** का विज्ञापन जारी रखने के लिए अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी।

तेजी से बढ़ते उपभोक्ता

- ये ऐसे उत्पाद हैं जो तेजी से बिकते हैं और आम तौर पर धीमी गति से चलने वाले सामानों की तुलना में कम कीमत पर बेचे जाते हैं।
- इन वस्तुओं में भोजन, पेय, टूथपेस्ट, घरेलू सफाई उत्पाद और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो तीन साल से कम समय में समाप्त हो जाती हैं या उपभोग की जाती हैं।

ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954

- यह दवाओं के **विज्ञापन को नियंत्रित** करने और उपचारों में **जादुई गुणों** के दावों को **प्रतिबंधित** करने के लिए एक **विधायी** ढांचा है।
- इसमें **लिखित**, **मौखिक** और **दृश्य माध्यमों** सहित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन शामिल हैं।

- अधिनियम के तहत, "**दवा**" शब्द का तात्पर्य **मानव या पशु उपयोग** के लिए **इच्छित दवाओं, रोगों** के **निदान या उपचार** के लिए **पदार्थों और शरीर** के **कार्यों** को प्रभावित करने वाले लेखों से है।
- उपभोग के लिए बनाई गई **वस्तुओं** के अलावा, इस अधिनियम के तहत "**मैजिक रेमेडीज़**" की परिभाषा तावीज़, मंत्र और **ताबीज** तक भी फैली हुई है, जिनमें कथित तौर पर उपचार या **शारीरिक कार्यों** को प्रभावित करने के लिए चमत्कारी शक्तियां होती हैं।
- यह दवाओं से **संबंधित विज्ञापनों** के **प्रकाशन पर सख्त नियम** लागू करता है।
- यह उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो ग़लत धारणाएँ देते हैं, **झूठे दावे** करते हैं, या **अन्यथा भ्रामक** हैं।
- इन प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दोषी पाए जाने पर **कारावास या जुर्माना सहित दंड** हो सकता है।
- अधिनियम के तहत शब्द **"विज्ञापन" सभी नोटिस, लेबल, रैपर और मौखिक घोषणाओं** तक फैला हुआ है।

31. अमेरिकी रिपोर्ट: भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- UDHR
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

समाचार:
- **अमेरिकी विदेश विभाग** ने अपनी **मानवाधिकार रिपोर्ट (HRR) - 2023** जारी की, जो **मानवाधिकार गतिविधियों** का देश-वार संकलन है।
- इसने भारत में एक दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के **मानवाधिकारों के हनन** की "**विश्वसनीय रिपोर्ट**" को चिह्नित किया है।

मुख्य बिंदु:
- रिपोर्ट में **कुकी और मैतेई जातीय समूहों** के बीच **जातीय संघर्ष** के फैलने पर प्रकाश डाला गया।
- रिपोर्ट में **गैर-न्यायिक हत्याएं, जबरन गायब करना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या हिरासत** में लेना, **जुर्म कबूल** कराने के लिए यातना देना, बार-बार **इंटरनेट** बंद करना शामिल है।
- देश में **वर्ष 2016-2022** के बीच **न्यायेतर हत्या**ओं के **813 मामले** दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले **छत्तीसगढ़** में दर्ज किए गए, इसके बाद **उत्तर प्रदेश** का स्थान है।

UDHR
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा:** 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, आदि।
- भारत ने UDHR के प्रारूपण में सक्रिय भाग लिया है।
- UDHR एक संधि नहीं है , इसलिए यह सीधे तौर पर देशों के लिए कानूनी दायित्व नहीं बनाता है।
- UDHR, **नागरिक** और **राजनीतिक अधिकारों** पर **अंतर्राष्ट्रीय वाचा** और **आर्थिक, सामाजिक** और **सांस्कृतिक अधिकारों** पर अं**तर्राष्ट्रीय वाचा** के साथ मिलकर तथाकथित **अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों** का विधेयक बनाता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC):
- भारत में **मानवाधिकारों** की र**क्षा और प्रचार** के लिए स्वतंत्र **वैधानिक निकाय** की स्थापना की गई।
- यह **मानवाधिकार उल्लंघनों** की समीक्षा करने और उन्हें **संबोधित** करने तथा **मानवाधिकारों** की सुरक्षा और संवर्धन के लिए **सिफारिशें** करने के लिए जिम्मेदार है।
- **NHRC** की स्थापना **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA)**, 1993 के तहत की गई थी।
- यह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है।
- पेरिस सिद्धांतों (1991) के अनुरूप है

32. दीफू लोकसभा क्षेत्र: संविधान का अनुच्छेद 244A का निर्वाचन क्षेत्र में महत्व - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 244(A)

- छठवीं अनुसूची

समाचार:

- **असम** के **आदिवासी-बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र** में, उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त '**राज्य** के भीतर **राज्य**' बनाने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 244 (A)** के कार्यान्वयन का वादा किया है।
- इसमें असम के **तीन आदिवासी**-बहुल पहाड़ी जिलों **कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग** और **दिमा हसाओ** में **विधान सभा क्षेत्र** शामिल हैं।
- **राज्य** और **केंद्र** में **सरकारों** का रवैया अधिक **स्वायत्तता** देने का नहीं बल्कि **शक्तियां** वापस लेने का प्रयास करने का रहा है।

अनुच्छेद 244(A):

- **अनुच्छेद 244 (A) को संविधान** (बाईसवाँ संशोधन) **अधिनियम, 1969** द्वारा शामिल किया गया था , जिसने संसद को **"असम राज्य** के भीतर **कार्बी आंगलोंग** सहित एक **स्वायत्त राज्य बनाने"** के लिए एक **अधिनियम पारित** करने में सक्षम बनाया गया है।
- इस **स्वायत्त राज्य** की अपनी **विधानमंडल** या **मंत्रिपरिषद** या दोनों होंगी।
- यह प्रावधान **छठवीं अनुसूची** के तहत **प्रावधानों** की तुलना में अधिक **स्वायत्तता** देता है, जो इन क्षेत्रों में पहले से ही लागू हैं।

छठवीं अनुसूची:

- **भारतीय संविधान** की **छठवीं अनुसूची** के उद्देश्य हैं:
  - पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में **आदिवासी क्षेत्रों** के **प्रशासन** के लिए प्रावधान करना।
  - **आदिवासी भूमि** और **संसाधनों** की रक्षा करना और ऐसे **संसाधनों** को **गैर-आदिवासी व्यक्तियों** या **समुदायों** को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना।
  - यह सुनिश्चित करना कि **जनजातीय समुदायों** का **गैर-आदिवासी आबादी** द्वारा **शोषण** या हाशिए पर न रखा जाए और उनकी **सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान** को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए।
- **छठवीं अनुसूची** के तहत **स्वायत्त परिषदों** ने इन **आदिवासी क्षेत्रों** के अधिक **विकेन्द्रीकृत शासन** के लिए प्रतिनिधियों को चुना है।
- उनके पास **सीमित विधायी शक्तियाँ** हैं, कानून और व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं है, और उनके पास केवल **सीमित वित्तीय शक्तियाँ** हैं।

33. निजी संपत्ति पुनर्वितरित करने की याचिका पर SC में सुनवाई शुरू- इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- DPSP
- मौलिक अधिकार

प्रसंग:

- **सुप्रीम कोर्ट (SC)** ने एक असंबंधित मामले की सुनवाई शुरू की कि क्या सरकार **निजी स्वामित्व** वाली **संपत्तियों का अधिग्रहण** और **पुनर्वितरण** कर सकती है यदि उन्हें संविधान के **अनुच्छेद 39 (b)** में उल्लिखित "**समुदाय के भौतिक संसाधन**" के रूप में माना जाता है।

मुख्य बिंदु

- संविधान के भाग IV के अंतर्गत आने वाले शीर्षक "राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत" (DPSP) है
  - DPSP के तहत आने वाला अनुच्छेद 39 (b) राज्य पर "समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह से वितरित करने के लिए नीति बनाने का दायित्व रखता है कि वह आम लोगों की भलाई के लिए सबसे अच्छा हो।
- DPSP का उद्देश्य कानूनों के अधिनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, लेकिन ये किसी भी अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं हैं।

कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी

- विशेष रूप से, कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) में शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर अनुच्छेद 39 (b) की व्याख्या पर विचार किया है ।
- इस मामले में सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4:3 के बहुमत से यह माना कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के दायरे में नहीं आते हैं।
- हालाँकि, यह न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अल्पमत राय थी जो आने वाले वर्षों में प्रभावशाली हो जाएगी।

- मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1996) के नौ-न्यायाधीशों की खंडपीठ के मामले में न्यायमूर्ति परिपूर्णन की सहमति वाली राय में कहा गया था कि "अनुच्छेद 39 (b) में आने वाले 'भौतिक संसाधन' शब्द प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों और चल या अचल संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लेंगे।"
  - इसमें भौतिक जरूरतों को पूरा करने के सभी निजी और सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कि केवल सार्वजनिक संपत्ति तक ही सीमित रहेंगे।"

अधिगृहीत संपत्तियों का विवाद

- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला मुंबई में 'सेस्ड' संपत्तियों के मालिकों द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 (MHADA) में 1986 के संशोधन को चुनौती देने के बाद सामने आया है।
- MHADA को वर्ष 1976 में शहर की पुरानी, जीर्ण-शीर्ण इमारतों में असुरक्षित होने के बावजूद किरायेदारों के आवास की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए अधिनियमित किया गया था।
- MHADA ने इमारतों के रहने वालों पर एक उपकर लगाया, जिसका भुगतान मरम्मत और बहाली परियोजनाओं की देखरेख के लिए मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड (MBRRB) को किया गया।
- 1986 में, अनुच्छेद 39 (b) को लागू करते हुए, भूमि और भवनों के अधिग्रहण की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए MHADA में धारा 1A डाली गई थी।
  - ताकि उन्हें "ज़रूरतमंद व्यक्तियों" और "ऐसी भूमि या इमारतों के कब्ज़ेदारों" को हस्तांतरित किया जा सके।
- संशोधन ने कानून में अध्याय VIII-A को भी शामिल किया, जिसमें राज्य सरकार को अधिगृहीत इमारतों (और जिस भूमि पर वे बने हैं) का अधिग्रहण करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं, यदि 70% रहने वाले ऐसा अनुरोध करते हैं।
- सात-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हमें इस व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने में कुछ कठिनाई है कि अनुच्छेद 39 (b) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन निजी स्वामित्व वाली चीज़ों को कवर करते हैं।
  - और MHADA के अध्याय VIII-A की चुनौती को नौ-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया जो अब मामले की सुनवाई कर रही है।
- हालाँकि, अदालत ने माना कि DPSP को आगे बढ़ाने में बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है -
  - उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 31C ("कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत") के अनुसार समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है।

34. सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को पुनर्जीवित करने वाली याचिका को खारिज किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- NJAC
- कोलेजियम प्रणाली

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री** ने **न्यायिक नियुक्तियों** की **कॉलेजियम प्रणाली** को समाप्त करने और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** को **पुनर्जीवित** करने की **याचिका** को **स्वीकार** करने से **इनकार** कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **सुप्रीम कोर्ट** के **रजिस्ट्रार** ने कहा कि **कॉलेजियम प्रणाली** को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, जबकि **NJAC** को **संविधान पीठ** ने **अक्टूबर 2015** में रद्द कर दिया था।
  - इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका को भी अदालत ने **वर्ष 2018** में खारिज कर दिया था।

कॉलेजियम प्रणाली:

- यह **न्यायाधीशों** की **नियुक्ति और स्थानांतरण** के लिए बनाया गया एक तंत्र है।
- यह **द्वितीय** और **तृतीय न्यायाधीशों** के मामले के निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- ऐसा कोई **कानून** या **संवैधानिक** प्रावधान नहीं है जो कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख या परिभाषित करता हो।
- सुप्रीम कोर्ट **कॉलेजियम** का नेतृत्व **भारत** के **मुख्य न्यायाधीश** करते हैं और इसमें **सुप्रीम कोर्ट** के **चार** अन्य **वरिष्ठतम न्यायाधी**श शामिल होते हैं।
- इस बीच, **उच्च न्यायालय कॉलेजियम** का नेतृत्व उसके **मुख्य न्यायाधीश** और उस **उच्च न्यायालय** के **चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश** करते हैं।

NJAC :

- 99वें **संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014** और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम, 2014** में एक **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** बनाने का प्रस्ताव किया गया।
  - **NJAC** को **उच्च न्यायपालिका** में **न्यायाधीशों** की नियुक्ति के लिए **कॉलेजियम प्रणाली** को बदलने के लिए एक **स्वतंत्र आयोग** माना जाता था।
- **NJAC** ने **न्यायिक नियुक्तियों** में **सरकार** को **बराबर** की भूमिका दी आयोग में **6 सदस्यों** को शामिल करने का प्रस्ताव था:
  - पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे
  - पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
  - नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।

35. NCW अध्यक्ष, सदस्यों की किसी राजनीतिक दल से संबद्धता नहीं - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- सूचना का अधिकार

समाचार:

- **सूचना अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** ने कहा है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसके **अध्यक्ष और सदस्य** किसी **राजनीतिक दल** के सदस्य हैं या नहीं।

मुख्य बिंदु:

- **राष्ट्रीय महिला आयोग** की जिम्मेदारी केंद्र **और राज्य सरकारों** के तहत **महिलाओं** के **विकास की प्रगति** का मूल्यांकन करना है।
  - यह **आदेश** होने के नाते, **अध्यक्ष या सदस्य** को **तटस्थता** के **सिद्धांत** को बनाए रखने और बिना किसी डर या **पक्षपात** के **सेवा करने** के लिए कम से कम अपने कार्यकाल के लिए किसी भी **राजनीतिक दल** का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- उपलब्ध कोई भी जानकारी सीधे तौर पर **पारदर्शिता और जवाबदेही** पर बड़े सवाल खड़े करेगी, **निर्णयों** पर सवाल उठाएगी और चाहे ये **राजनीतिक पूर्वाग्रह** के बिना सेवा कर रहे हों।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

- **NCW महिला** एवं **बाल विकास मंत्रालय** द्वारा **NCW अधिनियम, 1990** के तहत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **आयोग** के **अध्यक्ष** और **सदस्यों** को **भारत सरकार** द्वारा **नामित** किया जाता है।
- **आयोग के कार्य**
  - महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना
  - उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना
  - शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना
  - महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- NCW महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उन विभिन्न कठिनाइयों पर **सरकार** को **समय-समय** पर **रिपोर्ट** भी देता है जिनके तहत महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं।
- इसके अलावा, **अधिनियम** में **संदर्भित** किसी भी मामले की **जांच** करते समय **आयोग** के पास **सिविल अदालत** की सभी **शक्तियां** होंगी।

INTERNATIONAL RELATION

36. भारत-अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया-द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- HADR
- NDMA

समाचार:
- **भारत और अमेरिका** के बीच **द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता** और **आपदा राहत (HADR) उभयचर अभ्यास**, **टाइगर ट्रायम्फ 2024**, हाल ही में आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य **संयुक्त HADR संचालन** में **सर्वोत्तम प्रथाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं** को साझा करना है

HADR
- ये वे अभ्यास हैं जो **भारतीय सशस्त्र बल** और **आपदा प्रतिक्रिया बल नागरिकों** को बचाने या ऐसे अभियान चलाने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए करते हैं।
- **गृह मंत्रालय** आमतौर पर **रक्षा मंत्रालय** के साथ इनका समन्वय करता है।

भारत में आपदा प्रबंधन:
- भारत में, NDMA आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।
- इसका औपचारिक गठन **27 सितंबर 2006** को **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के अनुसार **प्रधान मंत्री** की **अध्यक्षता** में किया गया था।
- मुख्यालय **इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS)** के तत्वावधान में **भारतीय रक्षा बल** देश के भीतर और साथ ही देश के बाहर भी **HADR ऑपरेशन** कर रहे हैं।
- क्षति के आकलन, निकासी में उनकी विशेषज्ञता के कारण रक्षा बल विभिन्न HADR आकस्मिकताओं के दौरान काम कर सकते हैं
  - राहत बुनियादी ढांचे की स्थापना, संचार बहाल करना और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, राशन आपूर्ति, कपड़े आदि वितरित करना।

37. भारत UNHRC में गाजा युद्धविराम के आह्वान पर मतदान से अनुपस्थित रहा -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- हथियार प्रतिबंध
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

समाचार:
- भारत ने **मानवाधिकार परिषद** में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें **इज़राइल** से **गाजा** में तत्काल **युद्धविराम** का **आह्वान** किया गया था और **राज्यों** से **हथियार प्रतिबंध** लागू करने का आह्वान किया गया था, जिसे **47-सदस्यीय मानवाधिकार परिषद** ने अपनाया था।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद (UNHRC)
- यह एक **अंतरराष्ट्रीय संगठन** है जो **दुनिया** भर में **मानवाधिकारों** की **रक्षा** के लिए काम करता है।
- यह इसे **जिनेवा, स्विट्जरलैंड** में **वर्ष 2006** में स्थापित किया गया था।
- **UNHRC** में **47 सदस्य देश** हैं जो **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा चुने जाते हैं।
- ये देश **मानवाधिकार** के मुद्दों पर चर्चा करने और **मानवाधिकारों** के हनन की जांच के लिए साल में **तीन बार** मिलते हैं।
- परिषद के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों की निगरानी करना
  - मानवाधिकारों के हनन की जांच करना
  - संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा (यूनिवर्सल पीरियोडिक समीक्षा)
  - विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों की जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करना
- भारत ने **मानवाधिकारों** के **हनन** के लिए **इज़राइल की आलोचना** करने वाले और **फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का आह्वान** करने वाले प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, लेकिन **इज़राइल पर हथियार प्रतिबंध** लगाने के प्रस्ताव से दूर रहा क्योंकि उसने ह**मास की निंदा** नहीं की।

हथियार प्रतिबंध
- UNSC ने **वर्ष 2022** में **हैती** पर **हथियार प्रतिबंध** लगाया था ।
- इसने व्यक्तियों और संस्थाओं को हथियारों और संबंधित सामग्री की सभी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया।
- वर्ष 2023 में इसे सभी **गैर-सरकारी व्यक्तियों** और **संस्थाओं पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध** में संशोधित किया गया था।
- **प्रतिबंध का समय सीमित है ।**

38. इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अग्रणी योजनाओ को अपनाने हेतु भारत का दौरा किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मिड-डे मील योजना

समाचार :
- **इंडोनेशिया**, हाल ही में संपन्न चुनावों के बाद**, राष्ट्रपति** के तहत नई **सामाजिक-आर्थिक पहल** शुरू करना चाहता है और **मिड-डे मील योजना** और **डिजिटल समावेशन** में सर्वोत्तम गतिविधियों को अपनाने के लिए भारत से संपर्क किया है।

मिड-डे मील योजना
- **भारत का विशाल स्कूल लंच कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम, जिसे अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है, अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- यह कक्षा 1 से 8 तक के लाखों बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर दिन गर्म भोजन प्रदान करता है।
- **बच्चों की मदद करने का एक लंबा इतिहास:** यह कार्यक्रम वर्ष 1925 में वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू हुआ था।
- यह वर्ष 1995 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया और इसमें कुछ नाम परिवर्तन किए गए।
- **स्वस्थ भविष्य के लिए लक्ष्य:** कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों, विशेषकर वंचित परिवारों के बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना और उन्हें स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करना है।
- यह भूख से लड़ने, बच्चों के **पोषण में सुधार** और विभिन्न **जातियों** के बीच **सामाजिक संपर्क** को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है।
- **इसे साकार करने हेतु मिलकर काम करना** : प्रत्येक राज्य विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए समितियाँ गठित करता है।
- संघीय सरकार राज्यों के साथ लागत साझा करती है, कुछ क्षेत्रों में अधिक योगदान होता है।

39. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUKUS के विस्तार को लेकर चर्चा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- AUKUS
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- **अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया** अपने **AUKUS सुरक्षा समझौते** में **नए सदस्यों** को लाने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वाशिंगटन **चीन के खिलाफ निवारक** के रूप में **जापान** को शामिल करने पर जोर दे रहा है।

मुख्य बिंदु
- ये पहले स्तंभ का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिसे **ऑस्ट्रेलिया** में **परमाणु-संचालित** हमलावर पनडुब्बियों को वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **वर्ष 2021** में तीन देशों द्वारा गठित AUKUS, **इंडो पैसिफिक क्षेत्र** में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ पीछे हटने के उनके प्रयासों का हिस्सा है।
- **चीन** ने **AUKUS** समझौते को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे **क्षेत्रीय हथियारों** की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है।

ऑकस ग्रुपिंग
- यह **ऑस्ट्रेलिया, यूके** और **यूएस (AUKUS)** के बीच **इंडो-पैसिफिक** के लिए एक **त्रिपक्षीय सुरक्षा** साझेदारी है जिस पर **वर्ष 2021** में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण **अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी** को **ऑस्ट्रेलिया** के साथ साझा करना है।
- इसका **इंडो-पैसिफिक झुकाव** इसे **दक्षिण चीन सागर** में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन बनाता है।
- इसमें **तीन देशों** के बीच बैठकों और जुड़ाव की एक नई **वास्तुकला** के साथ-साथ उभरती **प्रौद्योगिकियों** (अनुप्रयुक्त एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और समुद्र के नीचे की क्षमताओं) में सहयोग शामिल है।

40. उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- PMLA
- UAPA

समाचार:
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** में कड़े जमानत प्रावधानों में **महिलाओं** के लिए एक अपवाद है
- **दिल्ली** की एक अदालत **दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला** मामले में इस आधार पर जमानत के लिए भारत **राष्ट्र समिति नेता** की याचिका पर फैसला करने के लिए तैयार है।

PMLA में जमानत का प्रावधान
- धारा 45 **मनी लॉन्ड्रिंग** के आरोप में जमानत का प्रावधान करती है।
- कानून में यह प्रावधान, **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)** में कड़े जमानत मानक की तरह, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।
- हालाँकि, जमानत मानक में एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
- कानून कहता है, "बशर्ते कोई व्यक्ति, जो **सोलह वर्ष से कम उम्र** का है या **महिला** है या **बीमार या अशक्त** है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे।"
- यह **अपवाद महिलाओं और नाबालिगों** के लिए **भारतीय दंड संहिता** के तहत छूट के समान है।

कानूनी मिसाल क्या है?
- **HC** ने कहा कि **PMLA** या **संविधान** एक घरेलू महिला, एक **व्यवसायी महिला** या एक **राजनीतिक** व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है।

41. EV और ग्रीन तकनीक उत्पादन, अमेरिकी-चीन व्यापार संघर्ष में फ्लैशप्वाइंट बना - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- इलेक्ट्रिक वाहन
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- चीन में **इलेक्ट्रिक कारों** और अन्य **ग्रीन प्रौद्योगिकियों** का बढ़ता उत्पादन नई **अमेरिकी-चीन व्यापार** लड़ाई में एक **फ्लैशप्वाइंट** बन गया है, जिस पर **ट्रेजरी सचिव** ने अपनी **पांच दिवसीय चीन यात्रा** के दौरान प्रकाश डाला है।

मुख्य बिंदु
- व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन फिर से भिड़ रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई **इलेक्ट्रिक कारों, सोलर पैनल** और अन्य **ग्रीन प्रौद्योगिकियों** को लेकर है।
- चीन इन उद्योगों में पैसा लगा रहा है और अब वह **घरेलू स्तर** पर जितना बेच सकता है उससे कहीं अधिक उत्पादन कर रहा है।
- यह सस्ती प्रतिस्पर्धा अ**मेरिकी कंपनियों और सरकार** को चिंतित करती है, जो चिंतित हैं कि इससे **अमेरिकी नौकरियों** को नुकसान हो सकता है।
- चीन का तर्क है कि अमेरिका अपनी **स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी** के साथ भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन **अमेरिका** का कहना है कि वे **अमेरिकी उपभोक्ता मांग** को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो **चीन** ने उतना नहीं किया है।
- अमेरिका-चीन **ग्रीन तकनीकी व्यापार ल**ड़ाई का अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं है।
- अमेरिका चाहता है कि **चीन** उसकी **चिंताओं** का समाधान करे, लेकिन चीन का तर्क है कि उसके सस्ते उत्पाद पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं।

हालाँकि, दोनों पक्षों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है:
- **चीन** के पास विनिर्माण की बहुतायत है और उन्हें **नए बाजारों** की आवश्यकता है, साथ ही उनकी अपनी **अर्थव्यवस्था घरेलू खर्च** को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है।
- **अमेरिका** अपने **उद्योगों की रक्षा** करना चाहते हैं लेकिन **कम कीमत वाली ग्रीन तकनीक** से भी लाभ उठाना चाहते हैं।

संभावित समाधान:
- **चीन**: क्षमता से अधिक उत्पादन को कम करने और ग्रीन उत्पादों की घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजना।
- **अमेरिका:** चीन की प्रगति से लाभ उठाते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के तरीके खोजना।

42. भारत अफ्रीका के कई देशों के लिए नए डिफेंस अटैचेस भेजेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- लाल सागर

समाचार:
- सैन्य कूटनीति पर ध्यान बढ़ाने के संकेत में, **भारत अफ्रीका** में अपने कई मिशनों के लिए **डिफेंस अटैचेस** (**DA**) भेजने के लिए तैयार है, पहली बार यहां के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

मुख्य बिंदु
- यह कदम **महाद्वीपों** और **क्षेत्रों** में फैले **भारतीय मिशनों** में **DA** के एक बड़े समायोजन का हिस्सा है और इसे लागू किया जा रहा है क्योंकि **भारत इंडो-पैसिफिक**, **लाल सागर-हिंद महासागर** और **यूरेशिया** में **गतिशील स्थितियों** से निपट रहा है।
- **अफ्रीका** के **चार देशों** के अलावा **पोलैंड** में **भारतीय दूतावास** को नया **DA** मिलने वाला है।
- वर्तमान में **चेक गणराज्य** में **भारतीय दूतावास** में **DA** समवर्ती रूप से **वारसॉ** में **भारतीय मिशन** के लिए कार्य करता है।
- कई क्षेत्रों में **DA** के पद पर पुनर्समायोजन **भारत की उभरती आवश्यकताओं** का हिस्सा है जो **रक्षा उत्पादन और सहयोग** से लेकर **संकट की स्थितियों** से निपटने तक फैला हुआ है जो तत्काल लामबंदी पर निर्भर है।
- इसी तरह की नई नियुक्तियां और **DA** के पद पर बदलाव **यूनाइटेड किंगडम, रूस, फिलीपींस, आर्मेनिया** में **भारतीय मिशनों** में भी होने की उम्मीद है।
- जबकि **फिलीपींस और आर्मेनिया** पहली बार भारतीय **DA** की मेजबानी करेंगे, **रूस** के मामले में, अटैचियों की संख्या कम होने की उम्मीद है।

43. म्यांमार संघर्ष: भारत ने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को स्थानांतरित किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- इम्बैक
- कलादान

समाचार:
- **विदेश मंत्रालय** का कहना है कि **म्यांमार** के **रखाइन राज्य** की स्थिति को देखते हुए **सितवे** में **भारतीय वाणिज्य दूतावास** ने **कर्मचारियों** को **स्थानांतरित** कर दिया है

मुख्य बिंदु:
- **विदेश मंत्रालय** ने कहा कि **म्यांमार** के **सैन्य शासन** और **जातीय सशस्त्र संगठनों (EAO)** के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर भारत ने **रखाइन प्रांत** के **बंदरगाह शहर सिटवे** में अपने **वाणिज्य दूतावास** से कर्मचारियों को '**अस्थायी रूप से स्थानांतरित**' कर दिया है।

- **करेन नेशनल यूनियन,** एक **जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह** ने दावा किया है कि उसने **दक्षिण-पूर्वी शहर म्यावाडी** में आखिरी बचे **सैन्य अड्डे** को जब्त कर लिया है।

भारत म्यांमार संबंध
- म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है।
- **दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार** होने के कारण इसका **भू-राजनीतिक महत्व** :
  - **म्यांमार दक्षिण एशिया** को दक्षिण **पूर्व एशिया** से जोड़ने वाले एक **भूमि पुल** के रूप में कार्य करता है।

- **भार**त के पूर्वोत्तर **राज्यों** से **म्यांमार** की निकटता एक **सामरिक संबंध** स्थापित करती है और **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी** के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भारत** और **म्यांमार बंगाल** की खाड़ी में **समुद्री सीमा साझा** करते हैं जो मछली पकड़ने और **नेविगेशन** में **समुद्री सहयोग** के अवसर प्रदान करता है।
- क्षेत्र में **चीन** के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए **म्यांमार** के साथ **भारत की सक्रिय भागीदारी** महत्वपूर्ण है।
- वर्ष **2021-22** में **1.03 बिलियन अमेरिकी डॉल**र का **द्विपक्षीय व्यापार दर्ज** करते हुए **भारत म्यांमार** के **पांचवें** सबसे **बड़े व्यापारिक भागीदार** के रूप में स्थान पर है।
- **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट** : जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता के बंदरगाह से जोड़ना है।
- **भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास** (IMBAX) **दोनों सेनाओं** के बीच **घनिष्ठ संबंधों** का **निर्माण** और **प्रचार** कर रहा है।
- **भारत** ने **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का आसान ऋण दिया है। **भारत** ने **म्यांमार** को **निर्देशात्मक** के बजाय उन क्षेत्रों में **विकासात्मक सहायता प्रदान** की है जो वह चाहता है।
- **भारत** और **म्यांमार बौद्ध विरासत** और **ब्रिटिश उपनिवेशवाद** के साझा इतिहास के संदर्भ में **सांस्कृतिक** संबंध साझा करते हैं।
- **म्यांमार** में **भारतीय मूल** के लोग कुल **जनसंख्या** का लगभग **4%** हैं।

44. तालिबान अफगान हिंदुओं, सिखों को भूमि अधिकार बहाल करेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- डेलाराम ज़रांज हाईवे
- सेल्मा/हाजिगाक

समाचार
- **भारत** ने **अफगानिस्तान** के **अल्पसंख्यक सिखों** और **हिंदुओं** की **संपत्ति बहाल** करने की **तालिबान** की पहल का स्वागत किया है।

मुख्य बिंदु:
- **अफगानिस्तान** के **प्रमुख शहरों** को **साफ- सफाई (स्वच्छता**) करने के प्रयास में हाल ही में **काबुल** में **तालिबान प्रशासन** के **'न्याय मंत्रालय'** ने **बड़े पैमाने** पर कार्रवाई शुरू की है |
- **अफगानिस्तान** के एक **सिख नेता नरेंद्र सिंह खालसा तालिबान** द्वारा उन्हें और **अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों** के **अन्य सदस्यों** को आश्वासन देने के बाद **काबुल** लौट आए हैं कि उनके **संपत्ति अधिकारों** की रक्षा की जाएगी।
- **सिखों**, **हिंदुओं** और अन्य **अफ़गानों** की **संपत्ति** को **बहाल** करने जैसे कदमों के साथ, जिन्होंने **सोवियत कब्जे** और **सरदार संस्कृति** से शुरू होने वाले **दशकों** में संपत्ति खो दी थी

- **तालिबान तर्कसंगत अभिनेता** के रूप में देखा जाना चाहता है और बड़े पैमाने पर **दुनिया** को एक संदेश देना चाहता है जिसने अब तक उन्हें काली सूची में डाल दिया है

भारत-अफगानिस्तान संबंध:
- **हड़प्पा सभ्यता** के **समय** से ही **भारत अफगानिस्तान** के साथ **समृद्ध ऐतिहासिक संबंध साझा** करता रहा है।
- **हिंदू-कुश क्षेत्र** के **पर्वतीय दर्रे** सदियों से **भारतीय उपमहाद्वीप** का प्रवेश द्वार रहे हैं।

- **वर्तमान परिदृश्य** में **भारत दक्षिण एशिया** में एक **महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार** के रूप में **अफगानिस्तान** के साथ **सौहार्दपूर्ण** संबंध चाहता है, और **शांति, स्थिरता** और **विकास की दिशा** में **अफगानिस्तान** के **प्रयासों** का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसने महत्वपूर्ण **परियोजनाओं** का **वित्त पोषण और निर्मा**ण किया है जैसे:
  - डेलाराम जरांज राजमार्ग, संसद भवन, भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध/सेल्मा बांध
  - अफगान निर्यात के लिए एयर फ्रेट कॉरिडोर, काबुल तक ट्रांसमिशन लाइनें, 800 मेगावाट बिजली संयंत्र और सेल द्वारा 6 मीट्रिक टन स्टील प्लांट।
- हालाँकि, **तालिबान शासन** के **पुनरुद्धार** के साथ **भारत की प्रमुख चिंता आतंकवाद** (हक्कानी नेटवर्क) के **पुनरुद्धार** के साथ-साथ **अफगानिस्तान** में **वित्तीय और सामरिक निवेश** का खतरा है।
- हालाँकि, **अफगानिस्तान** के लोग **भारतीयों** के प्रति बहुत **सम्मान** करते हैं, यही वजह है कि **तालिबान भारत सरकार** से समर्थन हासिल करने से पीछे नहीं हटते हैं।
- भारत **नई दिल्ली** में नए शासन के **अफगान राजनयिकों** को **प्रशिक्षण** दे रहा है, **भारत** ने **अफगानिस्तान** में **विकास प्रयासों** के लिए **3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की प्रतिबद्धता भी जताई है।

45. ईरान-इज़राइल संघर्ष: एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- दो सप्ताह पहले **सीरिया** के **दमिश्क** में अपने **वाणिज्य दूतावास** पर हुए **इजरायली हमले** के जवाब में, ईरान ने **14 अप्रैल** को **इजरायल** की ओर **सैकड़ों ड्रोन** और **मिसाइलें** दागीं।
- हालाँकि माना जाता है कि **इज़राइल** को शुरुआत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन **ईरान** ने चेतावनी दी थी कि **इज़राइल** के सैन्य कदम का बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी।

ईरान-इजरायल टकराव पर भारत का रुख

- **इजराइल** के खिलाफ **ईरान** के जवाबी हमले के बाद **भारत** ने **टकराव** कम करने का आह्वान किया।
- यह दृष्टिकोण **हमास** द्वारा **7 अक्टूबर** के **आतंकवादी हमले** के तुरंत बाद **उच्चतम राजनीतिक** स्तर पर **इज़राइल** के साथ **भारत** की तत्काल एकजुटता की अभिव्यक्ति के विपरीत है।

ईरान-इज़राइल टकराव पर भारत के दृष्टिकोण का महत्व

- ईरान-इज़राइल टकराव के बाद से भारत एक मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है।
- **दो देशों** (जैसे ईरान और इज़राइल) के बीच **लड़ाई** और एक **गैर-राज्य समूह** (जैसे हमास) द्वारा **आतंकवाद** के बीच एक बड़ा अंतर है।
- भारत चाहता है कि **दोनों पक्ष शांत** रहें (संयम दिखाएं) क्योंकि उसके **दोनों देशों** के साथ अ**च्छे संबंध** हैं
- यदि ये **भारत** को एक **दृष्टिकोण का पक्ष** लेते हुए देखते हैं तो इससे क्षेत्र में **शांति को नुकसान** पहुंच सकता है।

क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता

- **इज़राइल और ईरान** के बीच टकराव कम करने का **भारत का आह्वान क्षेत्र** की **राजनीति की जटिलता** को पहचानने के बारे में है।
- **मध्य पूर्व** में **अंतर-राज्य** और **अंतर-राज्य संघर्ष** गहरे और व्यापक हैं।
- भारत को प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों **मिस्र, ईरान, इज़राइल, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** के साथ अपने जुड़ाव को हमेशा संतुलित रखना होगा।
- इन देशों के रुझान और हित अलग-अलग हैं और अक्सर संघर्ष में रहते हैं।

इस क्षेत्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण में बदलाव

- अतीत में, **भारत** की **क्षेत्रीय नीति पश्चिम** और **मध्य पूर्व** के बीच **विरोधाभासों** के संदर्भ में तैयार की गई थी।
- उदाहरण के लिए **अमेरिका-ईरान टकराव** के परिणामों को प्रबंधित करने के लिए भारत के कदम।
- आज दिल्ली क्षेत्र के **आंतरिक अंतर्विरोधों** पर ध्यान देती है।
- जैसे, ईरान **इजराइल** मुद्दा, **इजराइल-फिलिस्तीन** मुद्दा आदि पर भारत का रुख।

- मध्य पूर्व से निपटने के लिए धर्म प्रमुख कारक नहीं हो सकता
- संघर्ष कम करने के लिए **भारत का आह्वान** यह भी रेखांकित करता है कि **मध्य पूर्व** से निपटने में धर्म और संबंधित **वोट-बैंक** की **राजनीति प्रमुख** कारक नहीं हो सकती है।

मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते कदम

- खाड़ी के साथ भारत के संबंध सिर्फ तेल और जनशक्ति से परे हैं।
- **सऊदी अरब** और **संयुक्त अरब अमीरात** जैसे देश अब **भारत** के **प्रमुख आर्थिक** और **राजनीतिक** भागीदार हैं।
- यह सहयोग सिर्फ व्यापार से कहीं अधिक व्यापक है, जो पूरे **हिंद महासागर क्षेत्र** को प्रभावित करता है।
- ये साझेदारियाँ **भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर (IMEC)** बनाने की भारत की योजना के लिए आवश्यक हैं, जो इसकी **अंतर्राष्ट्रीय रणनीति** का एक प्रमुख हिस्सा है।

46. IPC रिपोर्ट: गाजा उच्च स्तर पर भूख संकट का सामना कर रहा है - न्यूयॉर्क टाइम्स

समाचार:

- **संयुक्त राष्ट्र** के एक अधिकारी ने कहा, "**खाद्य उत्पादन प्रणाली** पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और थोड़े समय के भीतर **आपातकालीन सहायता** की पहुंच में कमी के कारण **भारी गिरावट** आई है।"

प्रीलिम्स टेकअवे

- मानचित्र आधारित प्रश्न
- एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC)।

मुख्य बिंदु

- एक औपचारिक अकाल घोषणा **संयुक्त राष्ट्र** यानी **द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन (IPC)** के साथ काम करने वाले एक समूह से आती है।
- तीन मुख्य शर्तें हैं:
  - गंभीर भोजन की कमी से कई घर प्रभावित हो रहे हैं
  - बच्चों के एक बड़े हिस्से में कुपोषण,
  - उच्च मृत्यु दर
- **वर्ष 2004** में अपनी स्थापना के बाद से **IPC** ने **सोमालिया** में **दो अकाल** घोषित किए हैं**, पहला वर्ष 2011** में दशकों के **संघर्षपूर्ण सूखे** और **ध्वस्त अर्थव्यवस्था** के कारण, **दूसरा दक्षिण सूडान** में वर्षों के **सूखे** के कारण **गृह युद्ध** ने **देश** की **अर्थव्यवस्था** को **नष्ट** कर दिया और विद्रोहियों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया।
- मौजूदा युद्ध से पहले ही **गाजा मिस्र** द्वारा समर्थित **इजरायली नाकेबंदी** के अधीन था।
- जिसके तहत, **खाद्य और वाणिज्यिक आयात** सहित **मानवीय सहायता** को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- लेकिन **हमास** के हमले के बाद, **इज़राइल** ने घेराबंदी कर दी और ऐसी किसी भी चीज़ को रोककर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बारे में उसका मानना है कि इससे हमास को प्रवेश करने में संभावित रूप से फायदा हो सकता है।
- इसने भोजन के **वाणिज्यिक आयात** को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसने **गाजा की दुकानों** और **बाजारों** को भर दिया था, **गाजा के बंदरगाह** और **क्षेत्रीय खेतों** पर **बमबारी** की और **मछली पकड़ने** पर **प्रतिबंध** लगा दिया।
- **हवाई हमलों** और **लड़ाई** के कारण विस्थापन के साथ-साथ **व्यवसायों** के **विनाश और कीमतों** में वृद्धि के कारण **परिवारों** के लिए अपना **पेट भरना मुश्किल** हो गया है।

47. इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर विवाद - द हिंदू

समाचार:

- हाल ही में **क्विटो** में **मेक्सिको दूतावास** पर **इक्वाडोर** की **छापेमारी राजनयिक संबंधों** पर वियना **कन्वेंशन** का गंभीर उल्लंघन है जिसके आधार पर **राष्ट्र विदेशी भूमि** में अपने **मिशन संचालित** करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- ICJ
- भारत-दक्षिण अमेरिका

- यह छापेमारी **वामपंथी प्रशासन** के एक **पूर्व उपराष्ट्रपति** और **पूर्व राष्ट्रपति** को गिरफ्तार करने के लिए थी, जिन्हें **भ्रष्टाचार** के आरोप में सजा सुनाई गई है।
- मेक्सिको ने कहा कि उसकी **संप्रभुता** का उल्लंघन किया गया है, अब उसने **इक्वाडोर को संयुक्त राष्ट्र** से निष्कासित करने की मांग करते हुए **नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** का रुख किया है।

भारत-इक्वाडोर संबंध:

- **राजनयिक स्थापना:** भारत और इक्वाडोर के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 19 सितंबर 1969 को स्थापित हुए, जिसने निरंतर राजनयिक जुड़ाव की नींव रखी।

आर्थिक सहयोग:

- **व्यापार और निवेश:** द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सकारात्मक रहा है।
- दोनों देश आपसी लाभ पर जोर देते हुए व्यापार में सुधार के अवसर सक्रिय रूप से तलाश रहे हैं।
- वर्ष 2021 के दौरान, इक्वाडोर ने खनिज उत्पादों ($569M), लकड़ी के उत्पादों ($64.5M), और कीमती धातुओं ($17.3M) के निर्यात में भारत के साथ बड़ा शुद्ध व्यापार किया था। वर्ष 2021 के दौरान, भारत ने परिवहन ($93.9M), रासायनिक उत्पाद ($92.1M), और धातु ($44.1M) के निर्यात में इक्वाडोर के साथ बड़ा शुद्ध व्यापार किया।।

प्रमुख समझौते:

- **समझौता ज्ञापन (MoUs):** पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:**
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत और इक्वाडोर दोनों नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास गतिविधियों के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** : भारत-इक्वाडोर साझेदारी दक्षिण-दक्षिण सहयोग की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि दोनों देश वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के हितों की वकालत करने वाले मंचों और गठबंधनों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय:

- **ICJ**, जिसे **विश्व न्यायालय** के रूप में भी जाना जाता है, **संयुक्त राष्ट्र (UN)** का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना **जून 1945** में **संयुक्त राष्ट्र के चार्टर** द्वारा की गई और **अप्रैल 1946** में काम शुरू हुआ।
- न्यायालय की सीट **हेग (नीदरलैंड) में पीस पैलेस** में है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- ICJ की सुनवाई हमेशा सार्वजनिक होती है।
- **आधिकारिक भाषाएँ**: फ्रेंच और अंग्रेजी
- **शक्तियाँ और कार्य:** न्यायालय दो प्रकार के मामलों पर विचार करता है:
- **सबसे पहले**, यह "**विवादास्पद मामलों**" कहे जाने वाले मामलों में दो सदस्य राज्यों के बीच विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य कर सकता है।
- **दूसरा,** यह संयुक्त राष्ट्र निकाय या विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न पर एक सलाहकार राय जारी करने के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।
- इसमें **15 न्यायाधीश** शामिल होते हैं, जो सभी **अलग-अलग देशों** से होते हैं, जो **संयुक्त राष्ट्र महासभा** और **सुरक्षा परिषद** में बहुमत से **नौ साल** के लिए चुने जाते हैं।
- न्यायाधीश, जिनमें से **एक-तिहाई हर तीन साल** में चुने जाते हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं।

48. सोलोमन द्वीप के चुनाव में चीन का प्रभाव - द हिंदू

समाचार:

- **सोलोमन द्वीपवासी** हाल ही में चुनावों में उतरेंगे, एक ऐसे चुनाव में **मतदान** करेंगे जो **चीन** की **क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं** को बढ़ावा देने या कुंद करने का वादा करता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- सोलोमन द्वीप
- क्वाड

- यह द्वीपसमूह, **दुनिया** के सबसे कम विकसित देशों में से एक, **चीन** को **पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों** के खिलाफ खड़ा करने वाली **कूटनीतिक लड़ाई** का असंभावित केंद्र बिंदु है।

मुख्य बिंदु

- **सोलोमन** द्वीप **प्रधानमंत्री मनश्शे सोगावरे** के तहत **चीन** की कक्षा में घुस गया है, जिन्होंने **वर्ष 2022** में **बीजिंग** के साथ एक **सुरक्षा समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जिससे **पारंपरिक साझेदार ऑस्ट्रेलिया** और **अमेरिका** को आश्चर्य हुआ।
- **चीनी सहायता** और **निवेश** की एक लहर आई, जिसमें एक अ**त्याधुनिक चिकित्सा केंद्र** और **10,000 सीटों** वाले **एथलेटिक्स स्टेडियम** के लिए **करोड़ों डॉलर** शामिल थे।

सोलोमन द्वीप:

- **सोलोमन** द्वीप **पापुआ न्यू गिनी** के पूर्व में **मेलानेशिया** में एक **राष्ट्र** है , जिसमें **990** से अधिक द्वीप शामिल हैं।
- इसकी **राजधानी होनियारा** है, जो **गुआडलकैनाल द्वीप** पर स्थित है।
- सोलोमन द्वीप समूह में **चोईसेउल, शॉर्टलैंड द्वीप समूह, न्यू जॉर्जिया द्वीप समूह, सांता इसाबेल, रसेल द्वीप समूह, फ्लोरिडा द्वीप समूह** छह प्रमुख द्वीप समूह शामिल हैं।
- पूर्व **ब्रिटिश उपनिवेश** ने **वर्ष 1978** में **स्वतंत्रता** प्राप्त की और **ताइवान** के साथ अपने शुरुआती विदेशी साझेदारों में से एक के रूप में **राजनयिक संबंध** स्थापित किए।
- इसमें **मेलानेशिया** में **ज्वालामुखीय द्वीपों** और **मूंगा एटोल** की दोहरी श्रृंखला शामिल है।
- यह **प्रशांत महासागर** में द्वीपों की एक **महत्वपूर्ण श्रृंखला** है। हाल ही में हुई क्वाड बैठक में **अमेरिका** ने कहा है कि वह "स्वतंत्र और खुले, जुड़े, समृद्ध, सुरक्षित और लचीले" **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** के लिए प्रतिबद्ध है।

49. ईरान ने भारतीय अधिकारियों को चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी

प्रीलिम्स टेकअवे

- फरजाद-B गैस क्षेत्र
- उत्तर-दक्षिण गलियारा

समाचार:

- **विदेश मंत्री** का कहना है कि उन्होंने **ईरान** और **इजराइल दोनों** के **विदेश मंत्रियों** से तनाव कम करने के लिए कहा, क्योंकि दोनों **पश्चिम एशियाई देशों** के साथ **भारत** के मजबूत **रणनीतिक संबंधों** को देखते हुए **नई दिल्ली ईरानी** हमलों पर अधिक तटस्थ स्थिति अपनाती है।

भारत ईरान संबंध:

- **मध्य एशिया** और **रूस** के साथ **व्यापार** के लिए **ईरान भारत** का सबसे **व्यवहार्य पारगमन विकल्प** बनकर उभरा है।
- **भारत, रूस** और **ईरान** ने **2000 में 'उत्तर-दक्षिण गलियारे'** के माध्यम से **ईरान के माध्यम** से **भारतीय कार्गो** को **रूस भेजने** के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
- भारत ने **ईरान में तेल** और **गैस, पेट्रोकेमिकल** और **उर्वरक परियोजनाओं** में **20 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का निवेश करने की योजना बनाई है। **मई 2016** में, **पीएम मोदी** ने **ईरान** का दौरा किया, जहां **ऐतिहासिक चाबहार बंदरगाह** समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **वित्त वर्ष 2022-23** के दौरान **भारत-ईरान द्विपक्षीय** व्यापार **$2.33 बिलियन** था, जो साल-दर-साल **21.76%** की वृद्धि दर्ज करता है।
- **फरजाद-B गैस क्षेत्र:** भारत ने ऊर्जा सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए फरजाद-बी गैस क्षेत्र को विकसित करने में रुचि व्यक्त की है।

- ईरानी तेल पर भारत की निर्भरता विवाद का विषय रही है, खासकर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव वाली भू-राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे **भू-राजनीतिक दबावों** के साथ **ऊर्जा जरूरतों** को **संतुलित** करना, **ईरान** के साथ **भारत के संबंधों** के लिए एक चुनौती है।

50. श्रीलंका जल्द ही बॉन्ड धारकों के साथ फिर से बातचीत शुरू करेगा -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- पेरिस क्लब
- भारत-श्रीलंका संबंध

समाचार:
- **श्रीलंका** पहले ही **भारत** और **पेरिस क्लब** के सदस्यों सहित अपने **द्विपक्षीय ऋणदाताओं** के साथ एक **समझौते** पर पहुंच चुका है।
- **श्रीलंकाई सरकार** जो अपने **निजी ऋणदाताओं** के साथ **ऋण उपचार** योजना को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है, **विश्व बैंक** की **वसंत बैठक** के बाद लंदन में उनके साथ बातचीत फिर से शुरू करेगी।
- **श्रीलंका** पर अपने **नवीनतम विकास अपडेट** में, **विश्व बैंक** ने नोट किया है कि **श्रीलंका** की **अर्थव्यवस्था** ने **राजकोषीय** और **बाह्य संतुलन** में सुधार के साथ "**स्थिरता** के **शुरुआती संकेत**" दिखाए हैं।

पेरिस क्लब के सदस्य:
- पेरिस क्लब **ऋणदाता देशों** का एक **अनौपचारिक समूह** है जो **वित्तीय कठिनाइयों** का सामना करने वाले **देशों**, मुख्य रूप से **ऋण चुकाने** के लिए **संघर्ष** कर रहे **देशों का समर्थन** करने के लिए मिलकर काम करता है।
- **इसकी स्थापना वर्ष 1956** में स्थापित की गई थी जिसका मुख्यालय **पेरिस** में है।
- समूह का लक्ष्य देशों की **व्यापक आर्थिक** और **वित्तीय स्थिति** को स्थिर करने और **सतत आर्थिक विकास** को बढ़ावा देने में मदद करना है।
- भारत **पेरिस क्लब** में **पर्यवेक्षकों** में से एक है

श्रीलंका के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता
- श्रीलंका के मामले में, **भारत, चीन और जापान** सबसे **बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता** हैं।
- **श्रीलंका पर भारत** का कर्ज़ उसके **कुल कर्ज़** का **12%** है।
- **भारत** ने **जनवरी 2023** में **श्रीलंका** के साथ अपनी **द्विपक्षीय वार्ता** शुरू की है।
- **भारत** ने **द्वीप-राष्ट्र** पर **वित्तीय बोझ** को कम करने में मदद करने के लिए **श्रीलंका** को अपना कर्ज चुकाने के लिए **12 साल** तक की अनुमति देने की योजना बनाई है, जो कि **$1.6 बिलियन** है।

51. चीन के साथ वार्ता के बीच अमेरिकी नौसेना ने ताइवान जलडमरूमध्य से विमान उड़ाए - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ताइवान जलडमरूमध्य
- दक्षिण चीन सागर

समाचार:
- क्षेत्रीय तनाव को कम करने के प्रयास में **अमेरिकी और चीनी रक्षा प्रमुखों** की वार्ता के एक दिन बाद **अमेरिकी नौसेना** के **पोसीडॉन विमान** ने **ताइवान जलडमरूमध्य** से उड़ान भरी।

मुख्य बिंदु
- **गश्ती** और **टोही विमान** ने "**ताइवान जलडमरूमध्य** को **अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र** में पार किया।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून** के अनुसार **ताइवान जलडमरूमध्य** के भीतर **संचालन** करके, **संयुक्त राज्य अमेरिका** सभी देशों के **नौवहन अधिकारों** और **स्वतंत्रता** को बरकरार रखता है।

ताइवान जलडमरूमध्य:
- यह जलडमरूमध्य **160 किलोमीटर** चौड़ा है और **चीन को स्वशासित द्वीप लोकतंत्र ताइवान** से विभाजित करता है।
- इसे **फॉर्मोसा जलडमरूमध्य** भी कहा जाता है, यह **जलडमरूमध्य ताइवान** के नियंत्रण में **पेस्काडोरेस** द्वीपों से युक्त है।
- मुख्य बंदरगाह **मुख्य भूमि चीन** में **अमॉय** और **ताइवान** में **काओ-हसिउंग हैं।**

- हालाँकि यह **अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र** में स्थित है, **चीन** इसके माध्यम से **विदेशी सैन्य विमानों और जहाजों** के पारित होने को अपनी **संप्रभुता** के लिए चुनौती मानता है।
- **चीन ताइवान** द्वीप पर दावा करता है और **द्वीप** के लिए **अमेरिकी सैन्य समर्थन** के बावजूद आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक इसकी **रक्षा** करने की धमकी देता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान:

- **ताइवान द्वीपों** की एक श्रृंखला का आधार है जिसके **अमेरिका** के **अनुकूल क्षेत्र** हैं
- **सेमीकंडक्टर उपकरणों** के उत्पादन में अपनी क्षमता के कारण **ताइवान** में **अमेरिका** की बहुत अधिक आर्थिक रुचि है।
- **अमेरिका** इसे **चीन** की **विस्तारवादी योजनाओं** का मुकाबला करने के लिए **उत्तोलन** के स्थान के रूप में भी उपयोग करने की **योजना** बना रहा है।
- **अमेरिका** के **ताइवान** के साथ **आधिकारिक राजनयिक संबंध** नहीं हैं, लेकिन **द्वीप** को अपनी **रक्षा** के साधन प्रदान करने के लिए **अमेरिकी कानून (ताइवान संबंध अधिनियम, 1979)** के तहत बाध्य है।
- यह **ताइवान** का सबसे बड़ा **हथियार डीलर** भी है और '**रणनीतिक अस्पष्टता**' का पालन करता है।

भारत और ताइवान

- दोनों देशों के **बीच 1995** से ही **औपचारिक राजनयिक संबंध** नहीं हैं
- **दोनों पक्षों** ने एक-दूसरे की **राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय** बनाए हुए हैं जो **वास्तविक दूतावासों** के रूप में कार्य करते हैं।

52. विदेश मंत्रालय OCI हेतु आवेदन करने के लिए पुर्तगाली नागरिकता रद्द करने के आदेश को स्वीकार करेगा- द इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- पुर्तगाली शासन
- भारत के प्रवासी नागरिक

समाचार:

- **विदेश मंत्रालय भारत** में **पूर्ववर्ती पुर्तगाली क्षेत्रों** (गोवा और दमन और दीव) के लोगों को **राहत प्रदान** कर सकता है, जिनके **भारतीय पासपोर्ट पुर्तगाली नागरिकता** प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिए गए थे।
- **विदेश मंत्रालय** ने देश में **पासपोर्ट अधिकारियों** को अनिवार्य रूप से "**निरस्तीकरण आदेश**" जारी करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों ने **विदेशी राष्ट्रीयता** प्राप्त करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने के लिए **गोवा** के उन लोगों के **पासपोर्ट** रद्द करना शुरू कर दिया, जिन्होंने **पुर्तगाली नागरिकता** हासिल कर ली थी।
- **सरकार** ने **पुर्तगाली राष्ट्रीयता कानून** के अनुसार **पुर्तगाली राष्ट्रीयता** हासिल करने वालों के लिए **'निरस्तीकरण प्रमाणपत्र'** स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
- पुर्तगाली कानून के अनुसार यह **19 दिसंबर, 1961** से पहले **गोवा में पैदा** हुए **लोगों को**, जिस दिन **गोवा पुर्तगाली शासन** से **मुक्त** हुआ था और **दो भावी पीढ़ियों** को **पुर्तगाली नागरिक** के रूप में **पंजीकरण** करने का विकल्प प्रदान करता है।

भारत में पुर्तगाली:

- पुर्तगाली भारत **वर्ष 1505 से वर्ष 1961** तक **भारतीय उपमहाद्वीप** के भीतर एक **औपनिवेशिक राज्य** था।
- पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ **भारतीय समुद्र तट** पर **व्यापारिक चौकियाँ** और **किले स्थापित** किए थे।
- उनका प्रभाव सीमित था, **अंग्रेजों के विपरीत** जिन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ाया।
- **वर्ष 1961** में, **भारत सरकार** ने **पुर्तगाली क्षेत्रों** पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे **भारत में पुर्तगाली शासन का** अंत हो गया।
- **वर्ष 1843** में **राजधानी** को **पणजी** में **स्थानांतरित** कर दिया गया, फिर इसका नाम बदलकर **नोवा गोवा** कर दिया गया , यह **पुर्तगाली भारत** की **प्रशासनिक सीट** बन गई।
- **दिसंबर 1961** में , **भारतीय सेना ने गोवा** पर आक्रमण शुरू किया।
- गोवा में **450 वर्षों** के **पुर्तगाली शासन** का **अंत** हुआ

- केंद्र शासित प्रदेश **दमन और दीव (D&D)** और **दादरा और नगर हवेली (DNH),** जो कि पूर्व **पुर्तगाली** क्षेत्र भी थे, का विलय **वर्ष 2019** में हुआ।

53. भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार: ऑस्ट्रेलिया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- COP26 मीटिंग
- शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता

समाचार:
- पिछले सप्ताह जारी नई रा**ष्ट्रीय रक्षा रणनीति-2024** में कहा गया है कि **भारत ऑस्ट्रेलिया** के लिए एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है
- **ऑस्ट्रेलिया और भारत** के बीच **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** के माध्यम से, **सरकार व्यावहारिक** और **ठोस सहयोग** को **प्राथमिकता** देना जारी रख रही है जो सीधे तौर पर **भारत-प्रशांत स्थिरता** में योगदान देता है।

मुख्य बिंदु
- **वर्ष 2024 एकीकृत निवेश कार्यक्रम (IIP)** भी जारी किया गया जो उन **विशिष्ट रक्षा क्षमताओं** को निर्धारित करता है जिनमें **ऑस्ट्रेलिया NDS** को प्रभावी बनाने के लिए निवेश करेगा।
- **NDS** ने कहा, **ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया** और **प्रशांत क्षेत्र** के साथ-साथ **हिंद महासागर** और **उत्तरी एशिया क्षेत्रों** में **भागीदारों** के साथ हमारे **रक्षा संबंधों** को गहरा करने में भी निवेश करेगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध
- **भारत** और **ऑस्ट्रेलिया** का सम्बन्ध बहुत पुराना है, जिसकी शुरुआत **भारत** की **आजादी** से भी पहले **सिडनी** में स्थापित एक व्यापार कार्यालय से हुई थी।
- वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद सम्बन्धों मे कई उतार-चढ़ाव आए हैं।
- दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की परंपराओं और बढ़ती आर्थिक साझेदारी को साझा करते हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया** में **भारतीय मूल** की बड़ी आबादी के साथ, मजबूत **सांस्कृतिक संबंध** भी हैं ।
- **वर्ष 2020** में, देशों ने अपनी साझेदारी को " **व्यापक रणनीतिक साझेदारी**" में उन्नत किया।
- इसमें जलवायु परिवर्तन (COP26 बैठक) और रक्षा (संयुक्त सैन्य अभ्यास और समझौते) जैसे मुद्दों पर घनिष्ठ सहयोग शामिल है।
- **शैक्षिक योग्यता** की **पारस्परिक मान्यता के लिए तंत्र (MREQ)** पर **मार्च 2023** में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे **भारत और ऑस्ट्रेलिया** के बीच **छात्रों** की **आवाजाही** में सुविधा होगी।

54. दोनों देशों द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित होने के बाद प्रोटोकॉल DTAA में संशोधन करेगा: मॉरीशस'- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- डबल टैक्सेशन एवोइडेंस एग्रीमेंट (DTAA)

समाचार:
- **मॉरीशस राजस्व प्राधिकरण (MRA)** ने पिछले सप्ताह कहा था कि आधार **क्षरण** और **लाभ स्थानांतरण न्यूनतम मानकों** का अनुपालन करने के लिए **मॉरीशस-भारत डबल टैक्सेशन एवोइडेंस एग्रीमेंट (DTAA)** में **संशोधन** करने वाले **प्रोटोकॉल** को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है।
- **MRA** ने कहा कि **दोनों देशों** द्वारा **अनुमोदित** और **अधिसूचित** होने के बाद **प्रोटोकॉल DTAA** में संशोधन करेगा।
- "**प्रोटोकॉल** इन **अधिसूचनाओं** के बाद की **तारीख** से लागू होगा।
- **प्रोटोकॉल** के **अनुसमर्थन** से पहले, **हितधारकों** को **मॉरीशस-भारत DTAA** में लाए जा रहे **संशोधनों** पर स्पष्ट **जानकारी प्रदान** की जाएगी।
- **भारत** और **मॉरीशस** ने **7 मार्च** को **DTAA** में एक **संशोधन** पर **हस्ताक्षर किए** और **समझौते** में एक **प्रमुख उद्देश्य परीक्षण** शामिल किया ताकि यह **सुनिश्चित** किया जा सके कि संधि का लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए दिया जाता है।

भारत और मॉरीशस के बीच दोहरा कर बचाव समझौता (DTAA):
- **भारत और मॉरीशस** की **सरकारें डबल टैक्सेशन** से बचने के संबंध में **वर्ष 1983 में** एक **सर्वसम्मत निर्णय** पर पहुंचीं है।
- यह **भारत** और **मॉरीशस** के बीच **डबल टैक्सेशन एवोइडेंस एग्रीमेंट एवोइडेंस एग्रीमेंट** या **DTAA** है।
- **भारत** और **मॉरीशस** के बीच हस्ताक्षरित **DTAA** के समझौते एक या **दोनों अनुबंधित राज्यों** के निवासियों पर लागू होंगे।

उद्देश्य:

- **टैक्स निश्चितता** प्रदान करके और **टैक्स बाधाओं** को कम करके **भारत और मॉरीशस** के बीच **द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों** और निवेश को बढ़ावा देना।

संशोधन का प्रभाव:

- संशोधन के बाद, चिंताएं थीं कि **मॉरीशस के माध्यम** से आने वाले **विदेशी पोर्टफोलियो** निवेश को **टैक्स अधिकारियों** द्वारा बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ेगा।
- साथ ही, ऐसी आशंकाएं भी थीं कि **पिछले निवेशों** को **संशोधित प्रोटोकॉल** द्वारा **कवर** किया जा सकता है।
- इसके कारण **12 अप्रैल, 2024** को भारत के **बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स** और **निफ्टी** में 1 **प्रतिशत** की गिरावट आई है।

55. रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेगा

प्रीलिम्स टेकअवे

- शंघाई सहयोग संगठन
- शंघाई फाइव

समाचार:

- **भारतीय प्रतिनिधिमंडल शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के **सदस्य देशों** के **रक्षा मंत्रियों** की **वार्षिक बैठक** के लिए **कजाकिस्तान** के **अस्ताना** गया है
- बैठक में **रक्षा सहयोग** पहल सहित **SCO** के भीतर **क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों** की **समीक्षा** की जाएगी।
- **भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग** के मुद्दों पर चर्चा के लिए **SCO** के **मित्र देशों** के **रक्षा मंत्रियों** के साथ बैठक करेगा।

शंघाई सहयोग ऑपरेशन:

- **शंघाई सहयोग संगठन** एक ऐसा संगठन है जो यूरेशिया में **राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** और रक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भौगोलिक कवरेज और जनसंख्या के मामले में इसे सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन होने का गौरव प्राप्त है।
- यह **शंघाई फाइव** के **उत्तराधिकारी** के रूप में उभरा, जिसे **वर्ष 199**6 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था।
- **उज्बेकिस्तान** के साथ ये देश **15 जून 2001** को **शंघाई** में **राजनीतिक** और **आर्थिक सहयोग** को गहरा करने के उद्देश्य से एक नए संगठन के गठन की घोषणा करने के लिए एक साथ आए।
- समय के साथ, **संगठन** ने **आठ राज्यों** को शामिल करते हुए अपनी **सदस्यता** का विस्तार किया, जिसमें **2017** में **भारत** और **पाकिस्तान** भी शामिल हो गए।

SCO का महत्व-

- **सुरक्षा पर सहयोग**
  यह **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS)** जैसी पहलों के माध्यम से मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और आतंकवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करता है।
- **सैन्य गतिविधियाँ**
  यह आतंकवाद और बाहरी खतरों के खिलाफ **सहयोग और समन्वय** बढ़ाने के लिए **संयुक्त सैन्य अभ्यास** आयोजित करता है।
- **आर्थिक सहयोग**
  इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना है।
- **सांस्कृतिक सहयोग**
  सांस्कृतिक सहयोग और आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए **शंघाई सहयोग संगठन** के **संस्कृति मंत्री** नियमित रूप से मिलते हैं।

56. संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय GANHRI भारत के मानवाधिकारों की समीक्षा करेगा - द हिंदू

समाचार:

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** अपनी **"ए स्टैटस"** को बरकरार रखने के लिए संयुक्त **राष्ट्र-मान्यता प्राप्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** की बैठक में सरकार की **मानवाधिकार प्रक्रियाओं** का बचाव करने की तैयारी कर रहा है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- GANHRI
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- पेरिस सिद्धांत

मुख्य बिंदु:

- **वर्ष 2023** में **चिंताओं** को लेकर **NHRC** की रेटिंग रोक दी गई थी
  - संरचना प्रक्रिया
  - मानवाधिकार जांच में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति
  - लैंगिक और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव।
- **NHRC** को **A** या **B** रेटिंग दी जाती है या नहीं, इससे **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** और कुछ **UNGA निकायों** में मतदान करने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी।
- यह बैठक **114 सदस्यीय गठबंधन** के **प्रत्येक सदस्य** के लिए **पांच साल** की **सहकर्मी समीक्षा** के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएगी।
- **वर्ष 1999** में मान्यता प्राप्त होने के बाद से **भारत** ने **वर्ष 2006** और **वर्ष 2011** में अपनी A रैंकिंग बरकरार रखी, जबकि **वर्ष 2016** में इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई और एक साल बाद बहाल कर दी गई।

GANHRI

- **मानवाधिकारों** के **प्रचार** और **संरक्षण** के लिए **राष्ट्रीय संस्थानों** की **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति** के रूप में **वर्ष 1993** में स्थापना की गई
  - **वर्ष 2016** में इसने अपना नाम बदलकर **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** कर लिया है
- यह **सदस्य-आधारित नेटवर्क संगठन** बनाने के लिए दुनिया भर से **NHRI** को इकट्ठा करता है
- यह **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली** का एक सम्मानित भागीदार है।
- **GANHRI** के **वकालत कार्य** का उद्देश्य **NHRI** की आवाज़ और अनुभवों को **वैश्विक चर्चाओं** में लाकर **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र** और **प्रक्रियाओं** के वास्तविक परिणामों को **सकारात्मक** रूप से प्रभावित करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र पेरिस सिद्धांतों और गंहरि क़ानून** के अनुसार , मान्यता के लिए निम्नलिखित वर्गीकरण:
  - A. पेरिस सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से अनुपालन;
  - B. आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप।

पेरिस सिद्धांत:

- ये **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं** की स्थिति से संबंधित सिद्धांत हैं
  - उन्होंने **न्यूनतम मानक निर्धारित** किए हैं जिन्हें **विश्वसनीय** माने जाने और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए **NHRI** को पूरा करना होगा।
- **पेरिस सिद्धांतों** के प्रमुख स्तंभ **बहुलवाद**, **स्वतंत्रता** और **प्रभावशीलता** हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:

- **भारत** का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) **वर्ष 1993** में स्थापित किया गया था।
- यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है।
- NHRC **मानवाधिकारों** के **प्रचार** और **संरक्षण** के लिए **भारत** की चिंता का प्रतीक है।
- इसकी स्थापना **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993** के तहत की गई है, जिसे मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) **अधिनियम, 2006** द्वारा संशोधित किया गया है।
- आयोग में एक अध्यक्ष, **पांच पूर्णकालिक सदस्य** और **सात मानद सदस्य** होते हैं।
  - अध्यक्ष **भारत** का **पूर्व मुख्य न्यायाधीश** या **सर्वोच्च न्यायालय** का **न्यायाधीश** होता है।
- **क़ानून आयोग** के **अध्यक्ष** और **सदस्यों** की **नियुक्ति** के लिए **योग्यताएँ निर्धारित** करता है।

57. G-7 मंत्री कोयले का चरणबद्ध तरीके से बंद करने करने पर सहमत हुए- द हिंदू

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- G - 7
- COP-28

- **G-7 ऊर्जा मंत्रियों** ने **कोयले** से चलने वाले **बिजली संयंत्रों** को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए एक समय सीमा पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि **जलवायु परिवर्तन** पर **साहसिक कार्रवाई** करने में विफल रहने के **बहाने स्वीकार्य** नहीं हैं।

मुख्य बिंदु:

- **संयुक्त राष्ट्र** के **COP-28** जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया द्वारा **कोयला, तेल और गैस** से दूर जाने की प्रतिज्ञा के बाद **सात देशों** का समूह समझौता पहला **बड़ा राजनीतिक सत्र** है।
- इसकी समय-सीमा देशों के **नेट ज़ीरो पाथवे** के अनुरूप, पहुंच के भीतर **1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान** वृद्धि की सीमा रखने के अनुरूप है।

G7 समूह

- **सात औद्योगिक लोकतंत्रों** का एक **अनौपचारिक समूह** जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** और **ऊर्जा नीति** जैसे **पारस्परिक हित** के मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करने के लिए की गई थी।
- **G7** बिना किसी **औपचारिक चार्टर** या **सचिवालय** के संचालित होता है और इसकी **अध्यक्षता** प्रत्येक वर्ष **सदस्य देशों** के बीच बदलती रहती है।
- **G7** की उत्पत्ति **वर्ष 1973** के **तेल संकट** के बाद हुई, जिसके कारण **वैश्विक आर्थिक मंदी** आई और अधिक **अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

G-7 और भारत

- चूँकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी **अर्थव्यवस्थाओं** में से एक है, इसलिए भारत को अपने **आर्थिक** और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए G7 के साथ जुड़ने में रुचि है।
  - **आर्थिक:** G7 देश भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं, और घनिष्ठ आर्थिक सहयोग से भारत को अपने बाजारों का विस्तार करने और अपनी आर्थिक वृद्धि में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
  - **प्रौद्योगिकी:** भारत G7 की तकनीकी सहायता से लाभान्वित हो सकता है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में।
  - **जलवायु परिवर्तन:** G7 के साथ सहयोग से भारत को अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने में मदद मिल सकती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** : G-7 के साथ सहभागिता से उसे अपने रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने तथा अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **वर्ष 2023** में 49वें **G7 शिखर सम्मेलन** में, **भारत** के **प्रधान मंत्री** ने **जापान** के **हिरोशिमा** में **महात्मा गांधी** की एक प्रतिमा का अनावरण किया।

GOVERNMENT SCHEMES

58. लोकसभा चुनाव: सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए- टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रीलिम्स टेकअवे

- सुविधा पोर्टल
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI)

समाचार:

- **चुनाव आयोग** ने रविवार को कहा कि **लोकसभा चुनाव** की घोषणा के बाद से उसके **सुविधा पोर्टल** पर विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति मांगने के लिए **73,000** से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सुविधा पोर्टल

- इसे स्वतंत्र, **निष्पक्ष** और **पारदर्शी चुनावों** के **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए **भारतीय चुनाव आयोग (ECI)** द्वारा विकसित किया गया है।
- इसने **चुनाव अवधि** के दौरान राजनीतिक दलों और **उम्मीदवारों** से **अनुमति और सुविधाओं** के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर **कार्रवाई** करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
- यह फर्स्ट इन **फर्स्ट आउट सिद्धांत** पर **पारदर्शी रूप** से विभिन्न प्रकार के **अनुमति अनुरोधों** को पूरा करता है।

- **राजनीतिक दल और उम्मीदवार** किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति **अनुरोध ऑनलाइन** जमा कर सकते हैं।
- ऑफ़लाइन सबमिशन विकल्प उपलब्ध हैं।
- यह रैलियों के आयोजन, **अस्थायी पार्टी कार्यालय** खोलने, **घर-घर जाकर** प्रचार करने, वीडियो वैन, **हेलीकॉप्टर**, **वाहन परमिट** प्राप्त करने, **पर्चे बांटने** की अनुमति प्रदान करता है।
- यह एक मजबूत **आईटी प्लेटफॉर्म** द्वारा समर्थित है, जिसका प्रबंधन विभिन्न **राज्य विभागों** के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- इसमें एक **सहयोगी ऐप** भी है जो आवेदकों को **वास्तविक समय** में उनके **अनुरोधों** की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, **पोर्टल** पर उपलब्ध अनुमति **डेटा चुनाव व्यय** की जांच के लिए एक **मूल्यवान संसाधन** के रूप में कार्य करता है, जो **चुनावी प्रक्रिया** में अधिक जवाबदेही और अखंडता में योगदान देता है।

59. सरकार ने बागवानी सब्सिडी वितरण के लिए CDP-SURAKSHA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- CDP-SURAKSHA
- GVA

समाचार:
- सरकार **क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP)** के तहत **बागवानी किसानों** को **सब्सिडी** देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है।
- यह बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल है।
- इस प्लेटफॉर्म को **CDP-SURAKSHA (CDP - सुरक्षा)** के नाम से जाना जाता है।

मुख्य बिंदु
- इस कदम का उद्देश्य भारत के **बागवानी क्षेत्र** के विकास को बढ़ावा देना है, जो **कृषि सकल मूल्यवर्धन (GVA)** में लगभग **एक तिहाई** योगदान देता है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- हाल के वर्षों में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन भी बढ़ा है।
- जहां **वर्ष 2010-11** में यह **240.53 मिलियन** टन था, वहीं **वर्ष 2020-21** में यह संख्या बढ़कर **334.60 मिलियन टन** हो गई।
- **SURAKSHA** (एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली) मूलतः एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है।
- यह **प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया** (**NPCI**) से **e-RUPI वाउचर** का उपयोग करके किसानों को उनके **बैंक खाते** में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति देगा।
- **CDP-SURAKSHA** में पीएम-किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, **NIC** से **क्लाउड-आधारित सर्वर स्पेस**, **UIDAI** सत्यापन, **eRUPI एकीकरण** , स्थानीय सरकार निर्देशिका **(LGD), सामग्री प्रबंधन प्रणाली, जियोटैगिंग** और **जियो-फेंसिंग** जैसी विशेषताएं हैं।

60. केंद्र ने आंगनबाड़ियों के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा जारी की - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- आधारशिला
- आंगनवाड़ी

समाचार :
- **महिला** एवं **बाल विकास मंत्रालय** (**MWCD**) द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और **शिक्षा** के लिए **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024** 'आधारशिला' जारी किया गया।

मुख्य बिंदु
- **केंद्र सरकार** ने **तीन से छह साल** के बच्चों को पढ़ाने के लिए यह पाठ्यक्रम जारी किया है।
- पाठ्यक्रम का ध्यान देश भर की **14 लाख आंगनबाड़ियों** में **प्री-स्कूल शिक्षा** पर केंद्रित है।
- लगभग **पांच वर्षों** तक **प्राथमिक कक्षा** तक के **42000 भारतीय बच्चों** पर किए गए एक **अनुदैर्ध्य शोध** से यह संकेत मिला है
  - जिन बच्चों ने **प्रारंभिक बाल्यावस्था** की शिक्षा प्राप्त की है, उनसे स्कूल में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है और वे उन लोगों की तुलना में **मनोवैज्ञानिक** रूप से बेहतर **अनुकूलित** होते हैं जिन्होंने **छह साल** की उम्र से पहले कोई **औपचारिक शिक्षा** प्राप्त नहीं की थी।

- बच्चे पढ़ना-लिखना सीखे बिना ही स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जिससे **गणित और भाषा कौशल** जैसे **आयु-उपयुक्त** सीखने के स्तर हासिल करने में बाधा आ सकती है।

आधारशिला:

- पाठ्यक्रम में **कहानी सुनाना, कला** और **शिल्प, खोज, मुक्त खेल,** बातचीत आदि जैसी **शैक्षणिक** और पाठ्येतर गतिविधियों का मिश्रण शामिल है।
- यह पाठ्यक्रम तीन से **छह वर्ष** की आयु के बच्चों में **प्री-स्कूल शिक्षा** को बढ़ावा देगा
- पाठ्यक्रम **बच्चों** में **कौशल विकसित** करके **ग्रेड 1** में आसानी से प्रवेश करने में मदद करेगा।
- यह **रूपरेखा बच्चों** की चुनौतियों से निपटने के समाधान के रूप में देखे जाने वाले अपने स्वयं के **सांस्कृतिक रूप** से उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए **राज्यों के लिए एक आधार** के रूप में काम करेगी।

ECONOMY

61. जनसांख्यिकीय लाभांश हेतु भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य में अधिक निवेश करना चाहिए: IMF- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट

समाचार:

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** (**IMF**) ने सुझाव दिया है कि **भारत** को **शिक्षा और स्वास्थ्य** में भारी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी बढ़ती युवा आबादी को **पर्याप्त रोजगार** मिले।

मुख्य बिंदु

- **IMF** की 'जुड़वां' बहुपक्षीय संस्था **विश्व बैंक** ने कहा था कि **भारत** और अन्य **दक्षिण एशियाई देश** अपने **जनसांख्यिकीय लाभांश** को बर्बाद कर रहे हैं।
- **AI** और ऐसी अन्य चुनौतियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए **श्रम बल** के पास सही **कौशल** होना आवश्यक है
- **IMF** ने युवाओं में **बेरोजगारी** की **उच्च दर** के बावजूद **वित्त वर्ष 2024/25** में **भारत की अर्थव्यवस्था** के लिए **6.8%** की **वृद्धि दर** का अनुमान लगाया है।
  - जो कि कुछ अनुमानों के अनुसार **वर्ष 2022-23 में 40%** से थोड़ा ऊपर था।
- भारत में विकास का नेतृत्व **सार्वजनिक निवेश और निजी उपभोग** ने किया
- जबकि **सार्वजनिक पूंजीगत व्यय** (उदाहरण के लिए बुनियादी ढांचे) का विकास पर "बहुत **लाभकारी**" प्रभाव पड़ा था
- IMF अधिकारी ने कहा कि मुद्दा यह था कि क्या निजी निवेश में भीड़ थी।

IMF:

- IMF एक **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन** है जिसकी स्थापना निम्न बिन्दुओं के लिए की गई है
  - वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना
  - सुरक्षित वित्तीय स्थिरता
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना
  - उच्च रोजगार को बढ़ावा देना
  - सतत आर्थिक विकास
  - दुनिया भर में गरीबी कम करें।
- **वर्ष 1944** में **विश्व बैंक** के साथ **ब्रेटन वुड्स विनिमय प्रणाली** के एक भाग के रूप में **IMF** की योजना बनाई गई थी।
- भारत **27 दिसंबर 1945** को **IMF** में शामिल हुआ था।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** का प्राथमिक उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों** की प्रणाली और **अंतर्राष्ट्रीय भुगतान** की स्थिरता सुनिश्चित करना है जो देशों को एक-दूसरे के साथ लेनदेन करने में सक्षम बनाता है।

SDR

- SDR एक **अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति** है **SDR** एक मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका मूल्य **अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग** पांच मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है।
- जब **वर्ष 1973** में निश्चित विनिमय दरें समाप्त हो गईं, तो **IMF** ने **SDR** को **विश्व मुद्राओं** की एक बास्केट के मूल्य के बराबर के रूप में फिर से परिभाषित किया। **SDR** स्वयं एक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक परिसंपत्ति है जिसे धारक

जरूरत पड़ने पर मुद्रा के लिए विनिमय कर सकते हैं। SDR **IMF** और **अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के** खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है।

IMF द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट :

- वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण।

INTERNAL SECURITY

62. भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप सौंपी- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ब्रह्मोस
- फिलिपींस

समाचार:

- **भारत** ने **फिलीपींस** को **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों** की पहली खेप पहुंचाई।
- **फिलीपींस** ने **ब्रह्मोस** के **एंटी-शिप संस्करण** के लिए **भारत** के साथ **375 मिलियन डॉलर** का सौदा किया, जो भारत और रूस के बीच **संयुक्त उद्यम मिसाइल** के लिए **पहला निर्यात ग्राहक** बन गया।

मुख्य बिंदु:

- पहला बैच **भारतीय वायु सेना** के एक प**रिवहन विमान** में पहुंचाया गया जो **फिलीपींस** में उतरा है
- यह **डिलीवरी दक्षिण चीन सागर** में **फिलीपींस** और **चीन** के बीच तनातनी के बीच हुई है और **सिस्टम चालू** होने के बाद **फिलीपींस सशस्त्र बलों** की **रक्षात्मक मुद्रा** में काफी वृद्धि होगी।

ब्रह्मोस:

- **ब्रह्मोस** एक **लंबी दूरी** की **परमाणु-सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** सिस्टम है।
- इसमें हवा, समुद्र और जमीन सहित कई **प्लेटफार्मों** से तैनात होने की क्षमता है।
- यह **मैक 3** तक की गति से यात्रा करने में सक्षम है और यह **दुनिया** की सबसे **तेज़ क्रूज़ मिसाइलों** में से एक है।
- इसे **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** द्वारा विकसित किया गया था और **वर्ष 2001** में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था।
- ब्रह्मोस का नाम **ब्रह्मपुत्र** और **मोस्कवा (रूस) नदियों** के नाम पर रखा गया है। **ब्रह्मोस एक शक्तिशाली आक्रामक मिसाइल हथियार सिस्टम** है जिसे पहले ही **सशस्त्र बलों** में शामिल किया जा चुका है।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस:

- **वर्ष 1990** के दशक के **खाड़ी युद्ध** के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि देश को एक **क्रूज़ मिसाइल सिस्टम** की आवश्यकता है।
- परिणामस्वरूप, **वर्ष 1998** में **भारत** और **रूस** ने **मास्को** में एक **अंतर-सरकारी** समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इसने **भारत** के **रक्षा अनुसंधान** और **विकास संगठन (DRDO)** और **रूस** के **NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM)** के बीच एक संयुक्त उद्यम, **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

फिलीपींस के साथ भारत के संबंध :

- **भारत और फिलीपींस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** में **दो लोकतांत्रिक** देश हैं जो **इंडो-पैसिफिक** के प्रति एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो एक **स्वतंत्र**, **खुले और स्थिर क्षे**त्र के महत्व पर जोर देते हैं।
- **राजनीतिक संबंध**: भारत और फिलीपींस ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को दोनों देशों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद राजनयिक संबंध (1946 में फिलीपींस और 1947 में भारत) स्थापित किए।
- जब भारत ने **वर्ष 1992** में पूर्व की ओर देखो **नीति शुरू** की और **दक्षिण पूर्व एशियाई देशों** के संगठन (आसियान) के साथ साझेदारी तेज की, तो इसके परिणामस्वरूप **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संदर्भ** में फिलीपींस के साथ संबंध भी मजबूत हुए।

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014)** के साथ, **फिलीपींस** के साथ संबंध **राजनीतिक-सुरक्षा व्यापार और उद्योग** आदि में और अधिक विविध हो गए हैं।
- **आर्थिक संबंध**: भारत वर्तमान में फिलीपींस का पंद्रहवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका वर्ष 2022 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होगा।
- इसके अलावा, फिलीपींस भारत के साथ माल व्यापार में शुद्ध आयातक रहा है

फिलीपींस:

- **फिलीपींस दक्षिण** पूर्व **एशिया** में स्थित एक **द्वीपसमूह** है, जिसकी सीमा पूर्व में **फिलीपीन सागर,** पश्चिम में **दक्षिण चीन सागर** और **दक्षिण** में सेलेब्स सागर से लगती है।
- इसमें **7,641 द्वीप** हैं, जिनमें **लूज़ोन और मिंडानाओ** सबसे बड़े हैं।
- राजधानी **मनीला** है, जो **लुज़ोन द्वीप** पर स्थित है।

63. नक्सल विरोधी अभियान: सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर निर्णायक प्रहार किया - द इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे

- वामपंथी उग्रवाद
- समाधान (SAMADHAN)

समाचार :

- छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर निर्णायक प्रहार किया है।
- **BSF और जिला रिजर्व गार्ड** के **संयुक्त बल** ने **तीन वरिष्ठ कमांडरों** सहित उनमें से **29** को मार डाला।

मुख्य बिंदु:

- **बस्तर** में किसी एक **ऑपरेशन** में **माओवादियों** के हताहत होने की यह सबसे बड़ी संख्या थी।
- माओवादी आंदोलन **वर्ष 2010** में अपने चरम पर पहुंच गया था जब **20 राज्यों के 223 जिले** कुछ हद तक हिंसा से प्रभावित थे।
- **हिंसा** और उसके **परिणामस्वरूप** होने वाली **मौतों** में **वर्ष 2010** के **उच्चतम स्तर** से **73 प्रतिशत** की गिरावट आई है।

वामपंथी उग्रवाद:

- **वामपंथी उग्रवाद (LWE)**, जिसे **वामपंथी आतंकवाद** के रूप में भी जाना जाता है, उन **राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों** को संदर्भित करता है जो **क्रांतिकारी तरीकों** के माध्यम से **सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन** की वकालत करते हैं।
- **भारत** में **वामपंथी उग्रवाद आंदोलन** की शुरुआत **वर्ष 1967** में **पश्चिम बंगाल** के **नक्सलबाड़ी** में हुए विद्रोह से हुई थी।
- वर्ष 2006 की **डी बंदोपाध्याय समिति** ने **आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों** में **आदिवासियों** के **खिलाफ शासन संबंधी अंतराल और सामाजिक भेदभाव** को नक्सलवाद के प्रसार के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचाना।
- **स्वतंत्रता** के बाद **भूमि सुधारों** और **भूमि पुनर्वितरण** की **विफलता उग्रवाद** में वृद्धि का एक और कारण है।
- पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना खनन, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं द्वारा जबरन विस्थापन किया गया ।
- FRA, 2006 के तहत **पारंपरिक भूमि अधिकारों** का **गैर-नियमितीकरण, आदिवासियों** को भूमि अनुदान अस्वीकार करना ।

सरकारी पहल:

- **'वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015** : व्यापक दृष्टिकोण जिसमें शासन, सुरक्षा और विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** : यह अधिनियम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **समाधान(SAMADHAN):** यह वामपंथी उग्रवाद समस्या के लिए एकमात्र समाधान है। विभिन्न स्तरों पर अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तैयार की जाती है

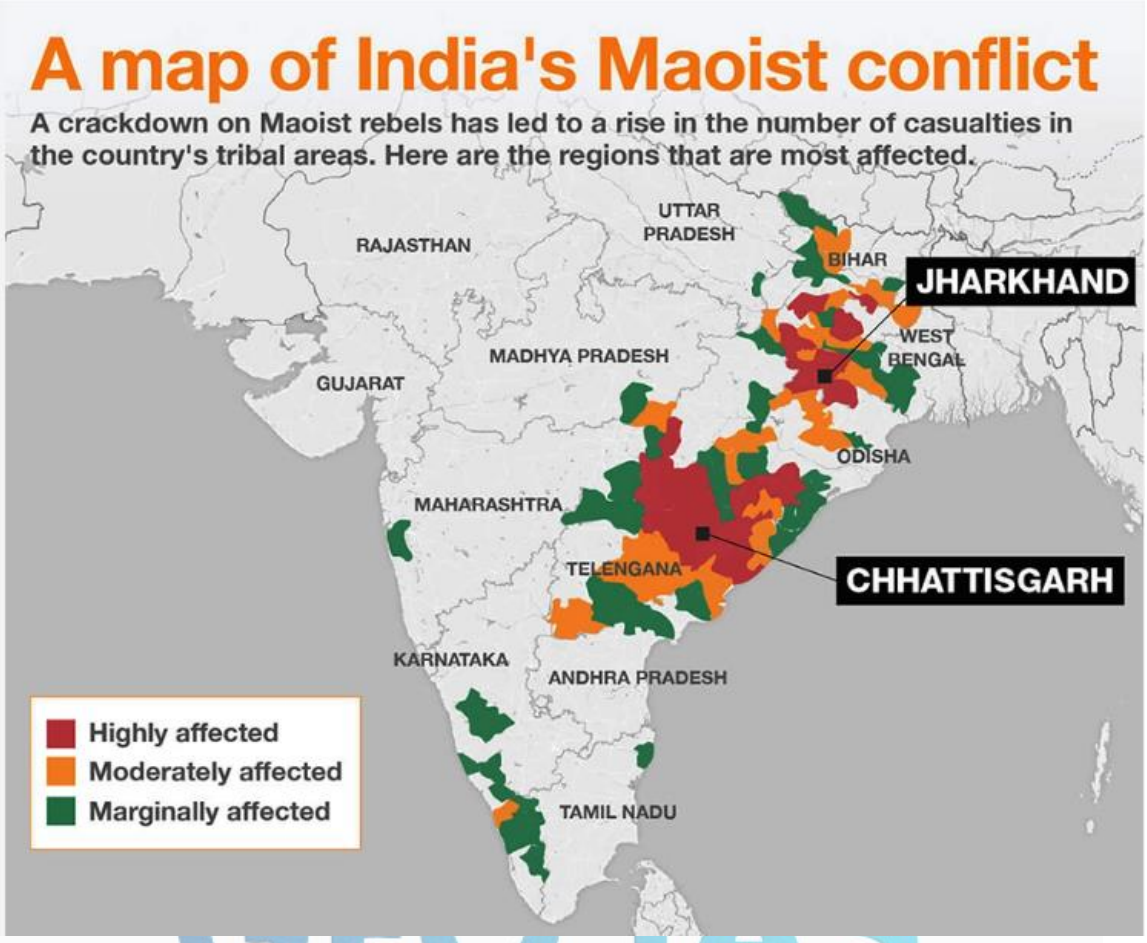

सामान्य अध्ययन III

INTERNAL SECURITY

64. रक्षा निर्यात ₹21000 करोड़ से अधिक; पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि - द हिंदू

समाचार:

- **रक्षा मंत्री** ने कहा कि **भारत** का **रक्षा निर्यात** पहली बार **₹21,000 करोड़** को पार कर गया।

प्रीलिम्स टेकअवे

- आकाश मिसाइल
- ध्रुव हेलीकाप्टर

- **रक्षा मंत्रालय** ने कहा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि **वित्त वर्ष 2013-14** की तुलना में पिछले **10 वर्षों** में **रक्षा निर्यात 31 गुना** बढ़ गया है।
- "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि **रक्षा निर्यात** अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और **स्वतंत्र भारत** के इतिहास में पहली बार **₹21,000 करोड़** का आंकड़ा पार कर गया है।"

प्रमुख निर्यात:

- **वित्तीय वर्ष 2023-24** में **रक्षा निर्यात ₹21,083 करोड़** के स्तर तक पहुंच गया है, जो **पिछले वित्तीय वर्ष** की तुलना में **32.5%** की शानदार वृद्धि है।
- **भारत** ने **वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया** जैसे देशों को **ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों** का निर्यात किया है।
- **ध्रुव हेलीकॉप्टर** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (**HAL**) द्वारा विकसित एक **बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर** है।
- **नेपाल, मालदीव, इक्वाडोर और पेरू** सहित कई देशों में निर्यात किया गया है ।
- **आकाश मिसाइल प्रणाली** भारत के **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
- भारत ने **वियतनाम और म्यांमार** सहित कई देशों को **सोनार सिस्टम निर्यात** किया है।
- भारत ने **नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया** सहित कई देशों को **बुलेटप्रूफ जैकेट** निर्यात किए हैं।
- इन **जैकेटों** का उपयोग सैन्य और **कानून प्रवर्तन एजेंसियों** द्वारा अपने कर्मियों को **गोलियों और छर्रों** से बचाने के लिए किया जाता है।

65. परमाणु ऊर्जा भारत के विकास की कुंजी है: IIM अहमदाबाद रिपोर्ट -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- यूरेनियम
- नाभिकीय विखंडन
- बैकबॉन

समाचार:

- **भारत** को **वर्ष 2047** तक एक विकसित देश बनाने और **वर्ष 2070** तक **शुद्ध शून्य या प्रभावी** रूप से शून्य **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** हासिल करने की राह पर होना।
- **IIM, अहमदाबाद** के **शिक्षाविदों** के एक अध्ययन में कहा गया है कि इसे परमाणु ऊर्जा में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए और संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए।

मुख्य बिंदु

- परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, इसका मतलब है कि वर्ष 2030 तक **भारत** की **कुल ऊर्जा** में **परमाणु ऊर्जा** का योगदान **4%** होगा और **वर्ष 2050** तक तेजी से बढ़कर **30%** हो जाएगा।
- इसी परिदृश्य में, **सौर ऊर्जा** की हिस्सेदारी **वर्ष 2030** में **42%** से गिरकर **वर्ष 2050** में **30%** हो जाती है।

यूरेनियम उपलब्धता

- वर्तमान में, **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** के आंकड़े कहते हैं कि **भारत** की स्थापित **उत्पादन क्षमता** में **सौर ऊर्जा** का हिस्सा **16%** और **कोयले का 49%** है।
- **परमाणु ऊर्जा** के लिए इन **आदर्शवादी आंकड़ों** को प्राप्त करने के लिए निवेश के साथ-साथ **यूरेनियम** की धारणा को दोगुना करने की आवश्यकता होगी
- एक महत्वपूर्ण ईंधन, लेकिन **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध** द्वारा प्रतिबंधित, आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है।

- कोयला संभवतः **भारतीय ऊर्जा प्रणाली** की **"बैकबॉन** " होगा और अगर देश को अगले **तीन दशकों** में कोयले को चरणबद्ध तरीके से बंद करना होगा
- **नवीकरणीय ऊर्जा** के एकीकरण का समर्थन करने के लिए लचीले **ग्रिड बुनियादी ढांचे** और भंडारण के अलावा, **परमाणु ऊर्जा** जैसे **वैकल्पिक स्रोतों** के लिए **पर्याप्त बुनियादी ढांचे** का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

ENVIRONMENT

66. IMD की चेतावनी: अप्रैल-जून के बीच 10-20 दिन लू चलने की आशंका -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- गर्म तरंगें
- IMD

समाचार:
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने अप्रैल-जून के दौरान देश के अधिकांश क्षेत्रों में **कठोर और शुष्क** गर्मी की भविष्यवाणी की है, इस अवधि के दौरान **10 से 20 दिनों** तक लू चलने की उच्च संभावना है।

भारत का मौसम निगरानीकर्ता: IMD
- **IMD** एक सरकारी एजेंसी है जो **मौसम, भूकंप** पर नज़र रखती है और **मौसम संबंधी** डेटा एकत्र करती है।

फ़ंक्शन
- पूरे भारत में मौसम की स्थिति का अवलोकन करना
- मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियाँ प्रदान करना
- मौसम का रिकार्ड रखना
- मौसम अनुसंधान का संचालन करना

भारत में हीट वेव्स
- हीट वेव्स असामान्य रूप से गर्म मौसम का विस्तार हैं।
- ये आम तौर पर मार्च और जून के बीच भारत में आते हैं, कभी-कभी जुलाई तक रहते हैं।
- उत्तरी भारत में प्रति वर्ष लगभग पाँच या छह गर्म लहरें अनुभव होती हैं।
- जब तापमान विशिष्ट सीमा तक पहुँच जाता है तो गर्म लहरें घोषित की जाती हैं:
- मैदानी भाग: 40°C (104°F) या अधिक
- पहाड़ियाँ: 30°C (86°F) या अधिक
- गर्मी की लहर की गंभीरता इस बात से निर्धारित होती है कि तापमान सामान्य स्तर से कितना अधिक है या वास्तव में वे कितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं।
- गर्मी की लहरें खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि वे शरीर के लिए तापमान को नियंत्रित करना कठिन बना देती हैं, जिससे ऐंठन, थकावट और हीटस्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।

67. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने केंद्र पर आपदा राहत कोष में देरी का आरोप लगाया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मिचौंग
- चक्रवात

समाचार:
- **तमिलनाडु** ने **मुख्यमंत्री** द्वारा मांगे गए लगभग **₹38,000 करोड़** के **आपदा राहत कोष** को जारी करने में देरी करके **केंद्र सरकार** पर राज्य के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए **सुप्रीम कोर्ट** में एक मुकदमा दायर किया।

मुख्य बिंदु
- इसका उद्देश्य **चक्रवात मिचौंग और अप्रत्याशित बाढ़** की दोहरी आपदाओं से निपटने में मदद करना है।
- **तमिलनाडु** का मुकदमा **उच्चतम न्यायालय** में **केरल और कर्नाटक** के हालिया मुकदमे के बाद आता है।

- **केरल ने केंद्र** पर उसकी **नेट बोर्रोविंग लिमिट्स** में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जिससे **राज्य वित्तीय आपातकाल** के कगार पर पहुंच गया है।
- **कर्नाटक** ने **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष** के तहत **सूखा राहत** जारी करने के लिए **सुप्रीम कोर्ट** का रुख किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

- **वर्ष 2005** में **आपदा प्रबंधन अधिनियम** के अधिनियमन के साथ **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि** (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय **आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF)** कर दिया गया।
- इसे **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act)** की **धारा 46** में परिभाषित किया गया है।
- इसे **भारत सरकार** के "**सार्वजनिक खाते**" में **"ब्याज रहित आरक्षित निधि"** के अंतर्गत रखा जाता है।

पब्लिक अकाउंट:

- इसका गठन **संविधान** के **अनुच्छेद 266(2)** के तहत किया गया था।
- यह उन लेनदेन के लिए प्रवाह का हिसाब रखता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत आदि।
- ये धनराशि सरकार की नहीं है और इन्हें कुछ समय पर वापस भुगतान करना होगा।
- इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

चक्रवात मिचौंग

- चक्रवात दक्षिण **पश्चिम बंगाल की खाड़ी** में कम दबाव वाले क्षेत्र से विकसित हुआ।
- यह धीरे-धीरे एक गहरे **अवसाद, एक चक्रवाती तूफान** और अंत में एक **सुपर-चक्रवात तूफान** में तब्दील हो गया।
- उन्हें समुद्र की सतह के **गर्म तापमान और मैडेन-जूलियन दोलन** से सहायता मिली, जो मौसम की एक विसंगति है जो वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है।
- यह **उत्तर** की ओर **आंध्र प्रदेश तट** की ओर बढ़ गया, जबकि **उत्तरी तमिलनाडु** में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ आईं।
- इसने **बापटला जिले** के पास **भूस्खलन** किया, और भूमि पर एक **अवसाद** के रूप में कमजोर हो गया।
- **विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन** और **बंगाल की खाड़ी** और अ**रब सागर** के लिए **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक** और **सामाजिक आयोग** द्वारा तैयार किए गए नामों की सूची के बाद **म्यांमार** द्वारा **मिचौंग** नाम का सुझाव दिया गया था जो **ताकत और लचीलेपन** का प्रतीक है।

68. भारत ने झींगा हैचरी में एब्यूसिव स्थितियों पर रिपोर्ट को खारिज किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- झींगा पालन
- नीली अर्थव्यवस्था

समाचार:

- अमेरिका के पसंदीदा **समुद्री भोजन झींगा** के **सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता भारत** ने **शिकागो** स्थित **मानवाधिकार** समूह द्वारा लगाए गए **मानवाधिकारों और पर्यावरण** के **दुरुपयोग के आरोपों** का दृढ़ता से खंडन किया है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ष 2022-23** में, **भारत का समुद्री भोजन** निर्यात **$8.09 बिलियन** या **₹64,000 करोड़** रहा, और इन निर्यातों में **झींगा** की हिस्सेदारी **$5.6 बिलियन** थी।
- **भारत दुनिया** के सबसे **बड़े झींगा निर्यातकों** में से एक के रूप में उभरा है और **अमेरिकी बाजार** में इसकी हिस्सेदारी **वर्ष 2022-23** में **21%** से बढ़कर **40%** हो गई है, जो **थाईलैंड, चीन, वियतनाम** और **इक्वाडोर** जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे है।
- भारत के **झींगा निर्यात** के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** द्वारा प्रमाणित है और **विदेशी शिपमेंट** के बारे में ऐसी चिंताओं की कोई गुंजाइश नहीं है।
- **राज्य:** अकेले आंध्र प्रदेश में लगभग एक लाख झींगा फार्म भारत के झींगा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी** : माना जाता है कि इस क्षेत्र में लगभग 80 लाख नौकरियों में से 70% महिलाएं हैं, जिनमें से दो लाख हैचरी और एक्वाकल्चर फार्म में हैं, और बाकी प्रसंस्करण और फ्रीजिंग इकाइयों में हैं।
- **मंत्रालय अमेरिका** और **यूरोपीय संघ** जैसे **प्रमुख बाजारों** में चिंताओं को दूर करने के लिए **निर्यातकों को झींगा फार्मों** में काम करने की स्थितियों पर **स्वतंत्र अध्ययन** कराने की सलाह दे सकता है।

SAIME पहल

- **सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम (SAIME)** पहल के तहत, किसानों ने **पश्चिम बंगाल** में **30 हेक्टेयर** में **झींगा** की **खेती** शुरू की है।
- **मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र** को **झींगा की खेती** के साथ एकीकृत किया गया है, लेकिन जब **मत्स्य पालन** का अंदर की ओर विस्तार किया गया, तो **मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र** को बाहर कर दिया गया।
- मछली पकड़ना, विशेष रूप से **झींगा पालन, सुंदरबन** के लोगों के प्रमुख व्यवसायों में से एक है, जो **नदियों और निचले द्वीपों** का एक **जटिल नेटवर्क** है जो दिन में **दो बार ज्वार** की लहर का सामना करता है।

69. EV सब्सिडी: ओला इलेक्ट्रिक एवं अन्यों को MHI से मैन्युअल प्रारूप में प्रमाण पत्र मिले - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम
- इलेक्ट्रिक वाहन

समाचार:
- ओला इलेक्ट्रिक, TVS मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक **मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024** के तहत स**ब्सिडी प्राप्त** करने के लिए **हेवी इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय (MHI)** से **मैन्युअल प्रारूप** में प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं।

मुख्य बिंदु
- हालांकि **EMPS** के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए **ऑनलाइन पोर्ट**ल तैयार नहीं है, लेकिन कंपनियों को **हेवी इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय (MHI)** से मैन्युअल प्रारूप में 'आगे बढ़ने' का प्रमाण पत्र मिल रहा है।
- **कंपनियों** के बीच राहत है क्योंकि **3 अप्रैल** से निर्मित वाहन इस योजना के तहत **सब्सिडी** के लिए पात्र होंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024:
- **भारत सरकार** ने **इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e2W)** और **तिपहिया वाहनों (e3W)** की खरीद को बढ़ावा देने के लिए **EMPS 2024** पेश किया है।।
- **5 अरब** रुपये के बजट के साथ, यह **FAME-2 योजना** की जगह लेगी और **अप्रैल से जुलाई 2024** तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद इसे बदले जाने या बढ़ाए जाने की संभावना है।
- **मुख्य लक्ष्य सब्सिडी** पर उद्योग की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करते हुए **e2Ws और e3Ws** को अपनाना है।
- इस योजना में **इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e4Ws) और ई-बसें** शामिल नहीं हैं।

70. जलवायु संकट नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 14

समाचार:
- एक महत्वपूर्ण फैसले में, **सुप्रीम कोर्ट** ने "**जलवायु परिवर्तन** के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को शामिल करने के लिए **अनुच्छेद 14 और 21 के** दायरे का विस्तार किया है।

मुख्य बिंदु
- **"संविधान के अनुच्छेद 48A** में प्रावधान है कि **राज्य पर्यावरण** की **रक्षा और सुधार** करने और देश के **जंगलों और वन्यजीवों** की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A** के खंड (g) में कहा गया है कि **जंगलों, झीलों, नदियों** और **वन्यजीवों** सहित प्राकृतिक **पर्यावरण की रक्षा** और **सुधार करना** और **जीवित प्राणियों** के प्रति दया रखना **भारत** के **प्रत्येक नागरिक** का कर्तव्य होगा।
- **अनुच्छेद 21** जीवन और **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** के अधिकार को मान्यता देता है जबकि **अनुच्छेद 14** इंगित करता है कि सभी **व्यक्तियों** को **कानून के समक्ष समानता** और **कानूनों का समान संरक्षण** प्राप्त होगा।
- ये अनुच्छेद **स्वच्छ पर्यावरण** के **अधिकार और जलवायु परिवर्तन** के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं

सरकारी नीति
- बावजूद इसके कि **सरकारी नीति औ**र नियम-**कायदे जलवायु परिवर्तन** के प्रतिकूल प्रभावों को पहचान रहे हैं और इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं

- **स्वास्थ्य का अधिकार** (जो **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है) **वायु प्रदूषण,** वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल की विफलता के कारण **खाद्य आपूर्ति** में **कमी, तूफान** और **बाढ़** जैसे **कारकों** के कारण प्रभावित होता है।
- अदालत ने बताया कि **भारत** का लक्ष्य वर्ष **2022** तक **175 गीगावाट** (गीगावाट) की स्थापित **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** (बड़ी पनबिजली को छोड़कर) हासिल करना है, एक **लक्ष्य** जो **स्वच्छ ऊर्जा** अपनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और भविष्य का **लक्ष्य 2030** तक **450 गीगावॉट** स्थापित क्षमता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा** में निवेश न केवल इन तात्कालिक **पर्यावरणीय चिंताओं** का समाधान करता है, बल्कि बहुत सारे **सामाजिक-आर्थिक** लाभ भी देता है।

71. 'ब्लैक स्वान' इवेंट्स के लिए तैयार रहें, अप्रत्याशित की अपेक्षा करें: सेना प्रमुख - इकोनॉमिक टाइम्स

प्रीलिम्स टेकअवे
- ब्लैक स्वान

समाचार:
- **सेना प्रमुख जनरल** ने बल से '**ब्लैक स्वान' इवेंट्स** के लिए हमेशा तैयार रहने और "**अप्रत्याशित** की **उम्मीद**" करने का आह्वान किया, यहां तक कि उन्होंने **राष्ट्रों** के बीच **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा** के लिए प्रौद्योगिकी को नए क्षेत्र के रूप में पहचाना।

ब्लैक स्वान इवेंट्स
- **ब्लैक स्वान'** एक दुर्लभ, **अप्रत्याशित घटना** है जो **आश्चर्यचकित** करती है और **समाज या दुनिया** पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है
- ये दुर्लभ घटनाएँ एक आश्चर्य के रूप में सामने आती हैं, जो दुनिया पर एक बड़ी छाप छोड़ती हैं।
- **प्रभाव:** वे अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों और हमारे दैनिक जीवन को बाधित करते हैं।
- यह अवधारणा नसीम निकोलस तालेब की पुस्तक, "**द ब्लैक स्वान**" से आई है।

ब्लैक स्वान प्रभाव:
- **व्यवधान** : अर्थव्यवस्थाएं, उद्योग और समाज अराजकता में फंस सकते हैं।
- **अनिश्चितता:** उनकी भविष्यवाणी करना कठिन है, जिससे योजना बनाना एक चुनौती बन जाता है।
- **भेद्यता** : ये हमारे सिस्टम में कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें कहाँ अधिक तैयार रहने की आवश्यकता है।

आगे की राह
- **जोखिम पर पुनर्विचार:** हम जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, छिपे खतरों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं।
- **नए नियम** : सरकारें इसी तरह की घटनाओं को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए नए कानून बना सकती हैं।
- **व्यवहार परिवर्तन** : लोग और संगठन अपने खर्च, निवेश और जोखिम प्रबंधन के तरीके बदल सकते हैं।

उदाहरण:
- डॉट कॉम बबल बर्स्ट
- 9/11 आतंकवादी हमला
- वर्ष 2008 का वित्तीय संकट
- ब्रेक्सिट
- कोविड-19 महामारी
- ब्लैक स्वान घटनाएँ याद दिलाती हैं कि दुनिया अप्रत्याशित हो सकती है।
- लेकिन उन्हें समझकर, हम जीवन में आने वाले आश्चर्यों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं।

72. भारत की जलवायु नीति UNFCCC के मूलभूत सिद्धांतों से प्रेरित- इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNFCCC

समाचार:
- भारत की **जलवायु नीति सर्वांगीण आर्थिक** और **सामाजिक विकास** के लिए **समावेशी विकास**, गरीबी उन्मूलन, घटते **कार्बन बजट**, **UNFCCC** के मूलभूत सिद्धांतों का दृढ़ पालन और **जलवायु-अनुकूल जीवन** शैली के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ष 1990** का दशक **भारत** और **दुनिया** में बड़े **बदलाव** का समय था, जिसके कारण **पर्यावरण** सहित कई क्षेत्रों में नई नीतियां बनाई गईं।
- **वर्ष 1992** के **रियो शिखर सम्मेल**न में **जलवायु परिवर्तन** पर **संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन** (**UNFCCC**) और **जैविक विविधता और वन सिद्धांतों** पर **कन्वेंशन** का उदय हुआ।
- रियो के बाद, भारत के **तत्कालीन पर्यावरण** और **वन मंत्रालय** में **जलवायु परिवर्तन** और **जैव विविधता** का **विभाजन** धीरे-धीरे और तेजी से सामने आया।
- **UNFCCC** के लिए **भारत** की **दीर्घकालिक** कम **उत्सर्जन विकास रणनीति 2070** तक **शुद्ध शून्य** हासिल करने की **बहुपक्षीय प्रक्रिया** में उसके विश्वास को दर्शाती है।
- भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को **ग्रीनहाउस गैस** (**GHG**) उत्सर्जन से सफलतापूर्वक अलग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप **वर्ष 2005** और **वर्ष 2019** के बीच इसके **सकल घरेलू उत्पा**द की उत्सर्जन तीव्रता में **33%** की कमी आई है।
- यह **वर्ष 2020** से पहले की अवधि में **UNFCCC** के तहत कोई बाध्यकारी **शमन दायित्व** नहीं होने के बावजूद है।
- पिछले **10 वर्षों** में **भारत** की **सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना** से अधिक बढ़ गई है, और **पवन ऊर्जा क्षमता** दोगुनी से अधिक हो गई है।
- अब इसके पास **पवन** की **चौथी सबसे बड़ी** स्थापित क्षमता है, और **दुनिया में पांचवीं** सबसे **बड़ी सौर ऊर्जा** है, जिसने निर्धारित समय से **नौ साल पहले नवंबर 2021** में **गैर-जीवाश्म ईंधन** से **40%** स्थापित **विद्युत क्षमता** का लक्ष्य हासिल कर लिया है, और फिर **लक्ष्य** को बढ़ाकर **50%** कर दिया है।
- पक्का आवास, चौबीसों घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छ रसोई गैस जैसी **बुनियादी सेवाएं प्रदा**न करने पर भी अभूतपूर्व ध्यान दिया जा रहा है, जो **जलवायु परिवर्तन** के खिलाफ लड़ाई में एक अमिट छाप छोड़ेगा।
- **भारत** मानता है कि **विकास** और **पर्यावरण** एक ही **सिक्के** के **दो पहलू** हैं और **सर्वांगीण समग्र विकास** के लिए इन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए।
    - भारत के **सतत विकास मॉडल** को **विकसित देशों** द्वारा प्रस्तुत **आख्यानों का मुकाबला** करने के लिए **विकासशील देशों** के लिए एक रैली के रूप में कार्य करना चाहिए, **विज्ञान और साक्ष्य** को **नीति-निर्माण** में सबसे आगे लाना चाहिए।

73. समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हेतु मेडागास्कर में बाओबाब पेड़ों पुनर्वनीकरण प्रयास - डाउन टू अर्थ

प्रीलिम्स टेकअवे
- बाओबाब पेड़
- अफ्रीका

समाचार:

- एक अभूतपूर्व संरक्षण प्रयास में, **ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैंग्रोव्स** (**GSPBM**) ने प्रतिष्ठित **बाओबाब पेड़ों** को फिर से जीवंत करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।
- **वनों की कटाई** और **जलवायु परिवर्तन** से खतरे में पड़े इन **प्राचीन दिग्गजों** को अंकुर **प्रत्यारोपण** के माध्यम से **जीवन रेखा** मिल रही है।

द माइटी बाओबाब: ए सर्वाइवर इन ड्राई लैंड्स

- **अफ्रीका** के गर्म, **शुष्क सवाना** में पाया जाने वाला **बाओबाब पेड़** (**एडंसोनिया डिजिटाटा**) अस्तित्व का समर्थक है।
- **मेडागास्कर** में, ये **दिग्गज द्वीप** के **अद्वितीय वातावरण** के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **विशाल तने और गहरी जड़ों** के साथ,ये **विशाल जल टैंकों** की तरह काम करते हैं, जो **बरसात के मौसम** में कठोर सूखे के दौरान उन्हें और आस-पास के पौधों को देखने के लिए पानी जमा करते हैं।
- **कैक्टस** की तरह, **बाओबाब** एक **रसीला पौधा** है, जो बारिश होने पर पानी सोख लेता है।
- ये **प्रभावशाली पेड़ हजारों वर्षों** तक जीवित रह सकते हैं, **30 मीटर** तक ऊंचे और अविश्वसनीय **50 मीटर त**क पहुंच सकते हैं!
- **बाओबाब पोषक तत्वों** से **भरपूर फल** भी पैदा करता है, जो **दुनिया में सबसे अधिक पौष्टिक** में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि यह एकमात्र फल है जो प्राकृतिक रूप से शाखा पर सूख जाता है।

74. इनवेसिव एलियन स्पीशीज किसी पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती है?- इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत की इनवेसिव स्पीशीज
- जैविक विविधता सम्मेलन (CBD)

समाचार:
- **रॉस द्वीप** (आधिकारिक तौर पर **नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप** के रूप में जाना जाता है) में **चीतल** (चित्तीदार हिरण) की **बढ़ती आबादी** का **प्रबंधन** करने के लिए, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन** ने हाल ही में **भारतीय वन्यजीव संस्थान** से मदद मांगी है।

मुख्य बिंदु
- **भारत** की **मुख्य भूमि** के मूल निवासी **चीतल** को **20वीं सदी** की शुरुआत में **अंग्रेजों** द्वारा **छोटे से द्वीप (0.3** वर्ग किमी छोटा) में लाया गया था।
- कोई **प्राकृतिक शिकारी** या **प्रतिस्पर्धी** न होने और **अच्छे तैरा**क होने के कारण **चीतल** तेजी से **अंडमान** में फैल गया।

इनवेसिव एलियन स्पीशीज
- किसी **इनवेसिव एलियन स्पीशीज** (IAS) को परिभाषित करने के **दो तरीके** हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन** (CBD) का कहना है कि यह एक ऐसी **प्रजाति** है जो अपने **प्राकृतिक आवास** के **बाहर पनपती** है और **संसाधनों** के लिए **प्रतिस्पर्धा** करके **मूल प्रजातियों** को **नुकसान** पहुंचाती है।
- भारत में उदाहरणों में **अफ्रीकी कैटफ़िश** जैसी **मछलियाँ** और **लाल कान** वाले **स्लाइडर** जैसे कछुए शामिल हैं।
- हालाँकि, **भारत** के **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** की एक अलग परिभाषा है।
- इसमें कहा गया है कि **इनवेसिव एलियन स्पीशीज** (IAS) केवल एक **ऐसी प्रजाति** है जो भारत की **मूल निवासी** नहीं है।
- इसमें **चीतल** हिरण जैसी उन **प्रजातियों** को शामिल नहीं किया गया है जो भारत में ही **इनवेसिव** हो सकती हैं।

चीतल हिरण:
- **चीतल** मुख्य भूमि **भारत** के **मूलवासी** हैं, लेकिन **वर्ष 1900** के दशक की शुरुआत में अंग्रेज उन्हें **अंडमान द्वीप समूह** में ले आए।
- कोई **प्राकृतिक शत्रु** न होने और **अच्छे तैराक** होने के कारण, वे तेजी से फैलते हैं।
- हालाँकि वे **भारत में संरक्षित** हैं, लेकिन उन्हें **अंडमान में आक्रामक** के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे **स्थानीय पौधों** और **जानवरों** को नुकसान पहुँचाते हैं।

इनवेसिव स्पीशीज पारिस्थितिक तंत्र और अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुँचाती हैं:
- ये **खाद्य श्रृंखला** और **असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र** को बाधित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान** में **अफ्रीकी कैटफ़िश** देशी पक्षियों को खाती है।
- ये आर्थिक क्षति भी पहुंचाते हैं।

75. मछलियों से मूंगों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल पेय स्ट्रॉ का उपयोग-द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मूंगा - चट्टान
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र

समाचार:
- **प्रवाल भित्तियों** की **आबादी** में **गिरावट** को दूर करने के लिए **दुनिया भर** के **वैज्ञानिक वर्षों** से काम कर रहे हैं।
- **दक्षिण फ़्लोरिडा** और **फ़्लोरिडा कीज़** में **रीफ़ बचाव** समूह समुद्र के बढ़ते तापमान से **मूंगे** को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

मुख्य बिंदु
- मौजूदा **मूंगों को जीवित** रखने के लिए काम करने के अलावा, **शोधकर्ता प्रयोगशालाओं** में **नए मूंगे उगा** रहे हैं और फिर उन्हें **समुद्र में डाल** रहे हैं।

- यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि **प्रयोगशाला** में उगाया गया और **समुद्र में डाला** गया **मूंगा मछली** का भोजन न बन जाए।
- परिपक्व होने पर मछलियाँ अंततः मूंगे में रुचि खो देती हैं, लेकिन **वैज्ञानिकों** को इस बीच **मूंगे** की रक्षा करने की आवश्यकता होती है।
- अतीत में **प्रत्यारोपित मूंगे** के **चारों** ओर **स्टेनलेस स्टील** और **PVC पाइप अवरोध** स्थापित किए गए हैं, लेकिन उन बाधाओं को **शैवाल के विकास** से साफ करने और अंततः हटाने की आवश्यकता है।

मूंगे की चट्टानें :

- मूंगा चट्टान एक **जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र** है जो चट्टान बनाने वाले मूंगों की उपस्थिति से अलग होता है।
- प्रवाल भित्तियाँ उथले **उष्णकटिबंधीय** और **उपोष्णकटिबंधीय** जल में पाई जाती हैं।
- यह मूल रूप से **समुद्री जीवन** की एक विस्तृत **श्रृंखला** के साथ एक गतिशील **पारिस्थितिकी** तंत्र है, यहां तक कि **मैंग्रोव** और **समुद्री घास** को भी इनके द्वारा सूजन से बचाया जाता है।
- **चट्टान शैवाल, मछली** और **इचिनोडर्म** सहित कई अलग-अलग प्रजातियों के लिए **आवास और भोजन के स्रोत दो**नों के रूप में कार्य करती है ।
- ये चट्टानें **कैल्शियम कार्बोनेट** द्वारा एक साथ बंधे हुए **मूंगा पॉलीप्स** के समूहों से बनी हैं।

मूंगा चट्टानों का महत्व

- ये **तरंग क्रियाओं** और **उष्णकटिबंधीय तूफानों** के **हानिकारक प्रभावों** से **तटरेखाओं** की **रक्षा** करते हैं।
- ये कई **समुद्री जीवों** को **आवास** और **आश्रय प्रदान** करते हैं।
- ये **समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं** के लिए **नाइट्रोजन और अन्य** आवश्यक **पोषक तत्वों** का स्रोत हैं।
- ये कार्बन और नाइट्रोजन-फिक्सिंग हैं।
- ये **पोषक तत्वों** के **पुनर्चक्रण** में मदद करते हैं।
- **मछली पकड़ने का उद्योग भी मूंगा चट्टानों पर निर्भर करता है।**
- बहुत सारी मछलियाँ वहाँ अंडे देती हैं, और कोरल पर भोजन खोजने आती हैं।
- **ग्रेट बैरियर रीफ** मछली पकड़ने और पर्यटन से **ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था** के लिए **सालाना 1.5 बिलियन डॉलर** से अधिक का उत्पादन करता है।
- **मूंगे** की **चट्टानें वैश्विक पारिस्थितिकी** तंत्र के **स्वास्थ्य** के प्रमुख **संकेतक** भी हैं, ये क्षेत्र में **पारिस्थितिक** बदलाव के **शुरुआती चेतावनी** संकेत प्रदान करते हैं।

76. विक्टोरिया न्यानज़ा झील का स्तर -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- अफ्रीकी रिफ्ट घाटी
- विक्टोरिया झील

समाचार:

- वर्ष 1896 से वर्ष 1922 तक **विक्टोरिया झील** और **वर्ष 1904 से वर्ष 1922 तक अल्बर्ट झील** के **झील** स्तर में भिन्नता **वैज्ञानिकों** द्वारा देखी गई, जैसा कि **ज्वार गेज** द्वारा दर्ज किया गया था।
- चूंकि **अधिकांश** वर्षा **वाष्पीकरण** द्वारा हटा दी जाती है और **न्यूनतम सनस्पॉट** की अवधि के दौरान **वाष्पीकरण उच्चतम** होता है, इसलिए झील का स्तर सबसे कम होता है।

- यह स्तर **वर्ष 1917** में उच्चतम था, यह वर्ष **अधिकतम सनस्पॉट** का था और उच्च स्तर के कारण वर्षा में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

विक्टोरिया झील:

- विक्टोरिया झील, **अफ्रीका** की सबसे **बड़ी झील** और **नील नदी** का **प्रमुख जलाशय**, मुख्य रूप से **तंजानिया और युगांडा** में स्थित है, लेकिन **केन्या की सीमा** पर भी स्थित है।
- उत्तरी अमेरिका में **सुपीरियर झील** के बाद यह **दुनिया की दूसरी** सबसे **बड़ी मीठे** पानी की झील है।

- इसका पानी विशाल पठार के केंद्र में एक उथले अवसाद को भरता है जो पश्चिमी और पूर्वी दरार घाटियों के बीच फैला हुआ है।
- कई द्वीपसमूह झील के भीतर समाहित हैं, जैसे कई चट्टानें हैं, जो अक्सर साफ पानी की सतह के ठीक नीचे होती हैं।
- **विक्टोरिया झील** में **मछलियों** की **200** से अ**धिक प्रजातियाँ** हैं।

अल्बर्ट झील:

- अल्बर्ट झील, **पूर्व-मध्य अफ्रीका** में, **कांगो (किंशासा)** और **युगांडा** के बीच की **सीमा** पर, **पश्चिमी रिफ्ट घाटी** की सबसे उत्तरी झील है।
- इस झील का नाम **रानी विक्टोरिया** के **पति अल्बर्ट** के नाम पर रखा गया था
- **अल्बर्ट झील** पानी का एक **उथला शरीर** है, **सेमलिकी नदी झील** में **एडवर्ड झील, कांगो एस्केरपमेंट** और **बारिश** से **लथपथ रूवेनज़ोरी** रेंज का पानी लाती है, इस प्रक्रिया में एक बड़े जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है।
- **उत्तरी छोर** पर तराई का काफी विस्तार है, जहां **विक्टोरिया नील** एक दलदली डेल्टा में एक **सुस्त धारा** के रूप में प्रवेश करती है।
- लगभग तुरंत ही **झील संकीर्ण** होकर **अल्बर्ट नील नदी** में मिल जाती है, जिसके माध्यम से यह **व्हाइट नील** को पानी की आपूर्ति करती है। **पश्चिम और पूर्व** में, **झील जंगली चट्टानों** और **खड्डों से घिरी** हुई है।

77. केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स में बदलाव किया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रीन क्रेडिट
- ग्रीनवाशिंग
- मिशन लाइफ(LiFE)

समाचार:
- इस चिंता के बीच कि **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** वित्तीय लाभ के लिए **वृक्षारोपण** को प्रोत्साहित कर सकता है, **केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय** ने स्पष्ट किया है कि केवल **वृक्षारोपण** के बजाय **पारिस्थितिकी तंत्र** को **बहाल करने** को **प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु
- **13 राज्यों** के **वन विभागों** ने लगभग **10,983 हेक्टेयर मूल्य** की निम्नीकृत वन भूमि के **387 भूमि पार्सल** की पेशकश की है।
- इन वनों को "बहाल" करने के लिए भुगतान करने के लिए **व्यक्तियों** और **कंपनियों** द्वारा **भारतीय वानिकी अनुसंधान** और **शिक्षा परिषद** (**ICFRE**) को आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- वास्तविक **वनीकरण राज्य वन विभागों** द्वारा किया जाएगा।
- **रोपण** के **दो साल** बाद और **ICFRE** द्वारा मूल्यांकन के बाद, ऐसा प्रत्येक रोपा गया पेड़ एक '**ग्रीन क्रेडिट**' के लायक हो सकता है।
- इन **क्रेडिट** का बाद में **वित्तपोषण संगठन** द्वारा दावा किया जा सकता है
- इन संगठनों द्वारा **क्रेडिट का उपयोग दो तरीकों** से किया जा सकता है:
  - **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR)** आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **पर्यावरण, सामाजिक और शासन** नेतृत्व मानदंडों के तहत **रिपोर्टिंग** के लिए उपयोग किया जाता है।।

ग्रीन क्रेडिट:
- **ग्रीन क्रेडिट** प्रोत्साहन की एक इकाई है जो **पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव** डालने वाली **गतिविधियों** में लगे **व्यक्तियों और संस्थाओं** को प्रदान की जाती है ।
- **ग्रीन क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023** के तहत संचालित होता है जो **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023** के तहत **कार्बन क्रेडिट** से स्वतंत्र है।

ग्रीन ऋण कार्यक्रम:
- **ग्रीन क्रेडिट पहल** की शुरुआत **प्रधानमंत्री** द्वारा **COP 28** के मौके पर की गई थी।
- यह **पर्यावरण** के लिए **सरकार** की **जीवनशैली** या **मिशन लाइफ(LiFE** के तहत एक पहल है।
- **GCP** एक **अभिनव बाजार-आधारित तंत्र** है जिसे **व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र** के **उद्योगों** और **कंपनियों** जैसे **विभिन्न हितधारकों** द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में **स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों** को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस पहल में **निम्नीकृत बंजर भूमि** की एक सूची बनाना शामिल है, जिसका **उपयोग व्यक्तियों और संगठनों** द्वारा **रोपण** के लिए किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय रूप** से **सकारात्मक कार्य** करने वाले प्रतिभागियों को व्यापार योग्य **ग्रीन क्रेडिट** प्राप्त होंगे।

78. एवियन इन्फ्लूएंजा: केरल कुट्टनाड में संक्रमित पक्षियों को मारा जाएगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- इंफ्लुएंजा
- एवियन फ्लू

समाचार:
- पशुपालन विभाग **केरल** के **कुट्टनाड** के **एवियन फ्लू प्रभावित क्षेत्रों** में **पक्षियों** को **मारने का अभियान** चलाएगा।
- "केंद्र ने बीमारी के प्रकोप को अधिसूचित किया है।

एवियन इन्फ्लूएंजा:
- **एवियन इन्फ्लूएंजा**, जिसे अक्सर **बर्ड फ्लू** कहा जाता है, एक अत्यधिक **संक्रामक वायरल संक्रमण** है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से **जंगली पक्षियों** और **घरेलू मुर्गों** को प्रभावित करता है।
- **एवियन इन्फ्लूएंजा** का मानव संचरण कभी-कभी होता है, लेकिन संक्रमण को **एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति** में प्रसारित करना मुश्किल होता है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, जब लोग **संक्रमित** होते हैं, तो मृत्यु दर लगभग **60%** होती है।

- यह **बुखार**, **खांसी** और **मांसपेशियों** में दर्द सहित **हल्के फ्लू** जैसे **लक्षणों से लेकर निमोनिया, सांस** लेने में कठिनाई जैसी **गंभीर श्वसन समस्याओं** और यहां तक कि परिवर्तित मानसिक स्थिति और दौरे जैसी **संज्ञानात्मक समस्याओं** तक हो सकता है।

एवियन इन्फ्लुएंजा और भारत :

- **भारत** में अत्यधिक रोगजनक **एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI) H5N1** का प्रारंभिक प्रकोप **वर्ष 2006** में **नवापुर, महाराष्ट्र** में हुआ और इसके बाद वार्षिक प्रकोप हुआ।
- **H5N8** पहली बार भारत में **नवंबर 2016** में देखा गया था, जो मुख्य रूप से **पांच राज्यों** में **जंगली पक्षियों** को प्रभावित करता था, जिसमें **केरल** में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे।
- अत्यधिक **रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा** (**HPAI**) को नियंत्रित करने के लिए **भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लूएंजा** की रोकथाम, **नियंत्रण और रोकथाम** के लिए **राष्ट्रीय कार्य योजना (2021)** में उल्लिखित "**पता लगाने और मारने**" की नीति का पालन करता है।

इन्फ्लुएंजा:

- **HPAI** का अर्थ है अत्यधिक **रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा** और **LPAI** का अर्थ है कम **रोगजनक एवियन** इन्फ्लूएंजा

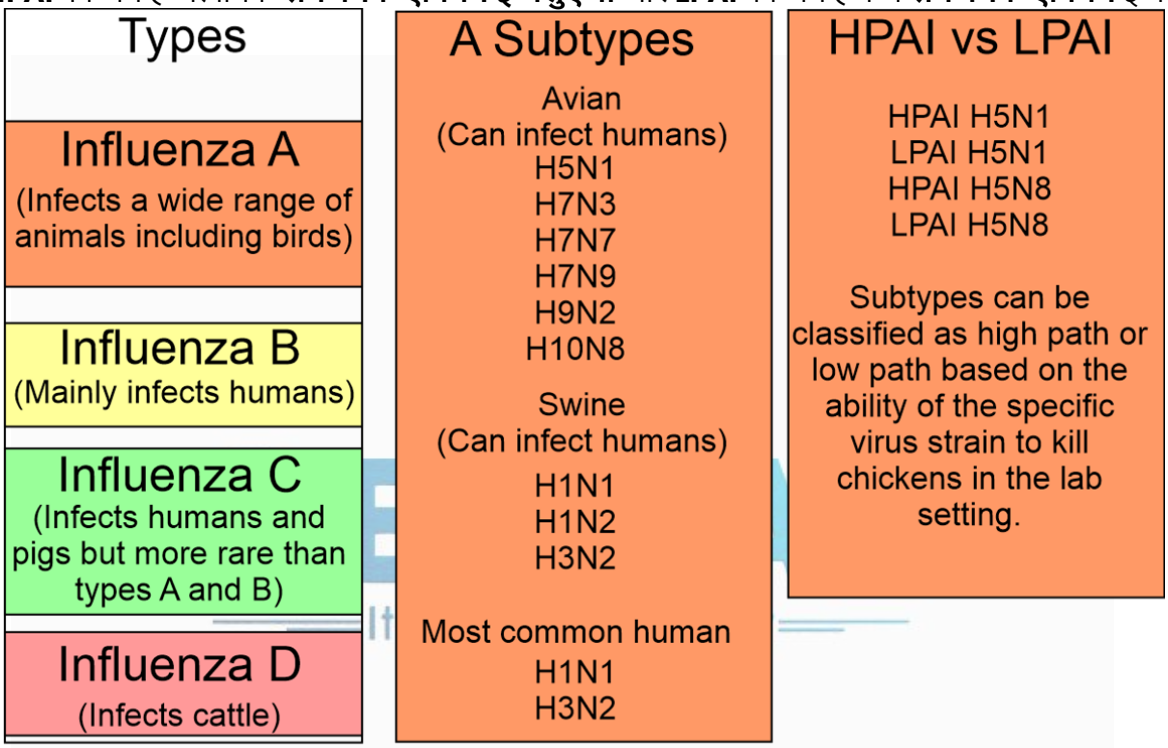

79. NGT ने चेन्नई जल निकायों में रसायनों पर चिंता व्यक्त की - द हिंदू

समाचार :

- हाल ही में, **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)** ने स्वत: संज्ञान लिया और **आईआईटी मद्रास** द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर **चेन्नई** के जल **निकायों** में **पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थों (PFAS)** की उपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ (PFAS)
- स्टॉकहोम कन्वेंशन

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में **जल निकायों** में **पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ (PFAS)** की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है
- अध्ययन से पता चला कि **पेरुंगुडी डंपयार्ड** के पास **भूजल** में **2.72 नैनोग्राम प्रति लीटर (ng/L) परफ्लूरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड (PFOS)** था जो **EPA** के 0.02 **ng/L** के **सुरक्षित स्तर** से काफी अधिक था।
- यह भी देखा गया, जब **सामान्य पानी** की तुलना में उपचारित पानी में **सभी आठ** लक्ष्य **PFAS** की सांद्रता बढ़ गई।
- चूंकि पारंपरिक **जल उपचार** केवल **PFAS** को अधिक प्रचलित बनाता है, इसलिए अध्ययन में उन्नत **पॉलिशिंग** उपचार प्रणाली की मांग की गई है।

पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ (PFAS):

- लंबे समय तक **पर्यावरण** में बने रहने की क्षमता के कारण **PFAS** को **फॉरएवर रसायन** के रूप में भी जाना जाता है ।
- ये **सिंथेटिक रसायन** हैं जो **पर्यावरण** को ख़राब करते हैं और उनका उपयोग **नॉन-स्टिक कुकवेयर, जल-विकर्षक कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन** और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है जो **पानी या तेल** को विकर्षित करते हैं।
- **PFAS** को **लीवर की क्षति, हार्मोनल असंतुलन, प्रतिरक्षा प्रणाली** के मुद्दों और कैंसर जैसे **प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों** के कारण जाना जाता है।

स्टॉकहोम कन्वेंशन:

- **स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य** और **पर्यावरण** को लगातार **जैविक प्रदूषकों (POP)** से बचाने के लिए एक **वैश्विक संधि** है।
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन** POP की रिलीज को खत्म करने या कम करने पर केंद्रित है।
- **152** से **अधिक देशों** ने **कन्वेंशन** का अनुमोदन किया और यह **17 मई 2004** को लागू हुआ तथा **भारत** ने **वर्ष 2006** में कन्वेंशन का अनुमोदन किया।

80. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नए नियम- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- कार्बन क्रेडिट
- मिशन लाइफ

समाचार:

- पहली पहल को नियंत्रित करने वाले नियम निर्धारित करने के बाद, **पर्यावरण मंत्रालय** ने अपने **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** पर आगे दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य बिंदु:

- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम** इसकी उत्पत्ति **मिशन लाइफ** में हुई है।
- **पर्यावरण संरक्षण** के लिए **स्वैच्छिक कार्यों** को प्रोत्साहित करने के लिए **GCP कार्यक्रम** खुद को एक अभिनव, बाजार-**आधारित तंत्र** के रूप में प्रस्तुत करता है।
- व्यक्तियों, संगठनों और सार्वजनिक और निजी कंपनियों को से लेकर **क्षेत्रों में निवेश करने** के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
  - वनरोपण जल संरक्षण, वायु-प्रदूषण को रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन, मैंग्रोव संरक्षण और बदले में ' **ग्रीन क्रेडिट** प्राप्त करने के पात्र बनें।
- एक स्वायत्त निकाय, **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE),** कार्यक्रम के प्रशासन का प्रभारी है।
  - ये निर्धारित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले ' **ग्रीन क्रेडिट** ' की गणना के लिए पद्धतियों को परिभाषित करेंगे।
  - **ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का** भी प्रबंधन करेंगे जिससे ऐसे क्रेडिट का कारोबार किया जा सके।

GCP के विवाद:

- **वनीकरण** के लिए **GCP कार्यक्रम** कहता है कि **कंपनियाँ प्रतिपूरक वनीकरण** के अनुपालन के लिए अपने **क्रेडिट** का **आदान-प्रदान** कर सकती हैं, जिससे भूमि के कुछ हिस्सों में **अत्यधिक वनों की कटाई** होगी।
- पेड़ लगाने से **पारिस्थितिकी तंत्र** को **स्वचालित** रूप से बढ़ावा नहीं मिलता है।
- गलत प्रकार के **पेड़** लगाने से **इनवेसिव प्रजातियाँ नष्ट** हो सकती हैं या एक **स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र** बाधित हो सकता है।
- यह भी ख़तरा है कि **प्राकृतिक वनों** को नष्ट किया जा सकता है और **इनवेसिव मोनोकल्चर** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- अंत में, **GCP** का यह भी कहना है कि **ग्रीन क्रेडिट** जिसके **परिणामस्वरूप कार्बन (पेड़ों से)** का भंडारण होता है, का उपयोग **कार्बन ट्रेडिंग** के लिए किया जा सकता है।
- यह फिर से विवादास्पद है क्योंकि इन **गतिविधियों** को बराबर करने वाला गणित स्पष्ट नहीं है।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- राज्यों को यह गणना करने के लिए इस पर भरोसा करना चाहिए कि ख़राब **वन परिदृश्य को पुनर्स्थापित** करने में कितनी लागत आएगी।
- स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी

- **कंपनियाँ** ग्रीन क्रेडिट का उपयोग करके **प्रतिपूरक वनीकरण** के तहत अपने सभी **दायित्वों** की भरपाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसके एक हिस्से का दावा कर सकती हैं।

81. पानी के बढ़ते तापमान से ब्लीचिंग के कारण कोरल चट्टानों को खतरा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- कोरल
- ग्रेट बैरियर रीफ

समाचार:
- **यूएस नेशनल ओशनिक** एंड **एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA)** ने कहा कि **चौथी वैश्विक** सयुक्त **प्रवाल ब्लीचिंग** घटना **असाधारण समुद्री तापमान** के कारण शुरू हुई है।
- इसके **समुद्री जीवन** और **लाखों लोगों** के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो **भोजन, नौकरियों और तटीय** सुरक्षा के लिए चट्टानों पर निर्भर हैं।

मुख्य बिंदु
- मूंगे **छोटे समुद्री जीव** हैं जो **विशाल कालोनियों** में एक साथ रहते हैं, समुद्र के नीचे संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें **रीफ** कहा जाता है।
- ये चट्टानें जीवन से भरपूर पानी के नीचे वर्षावनों की तरह हैं।
- **ग्रेट बैरियर रीफ** दुनिया की स**बसे बड़ी रीफ** है, जो **2,300 किलोमीटर** से अधिक तक फैली हुई है।
- स्वस्थ **महासागरों** के लिए **चट्टानें अत्यंत** आवश्यक हैं।
- ये **अनगिनत मछलियों** और **अन्य समुद्री जानवरों** को **भोजन** और **आश्रय** प्रदान करते हैं।
- ये समुद्री तटों को लहरों और तूफानों से भी बचाते हैं।
- आश्चर्य की बात है कि बढ़ते पानी के **तापमान से कोरल चट्टानों** को खतरा है।
- स्ट्रेस्ड होने पर, मूंगे अपने अंदर रहने वाले **रंगीन शैवाल** को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये सफेद हो जाते हैं। इसे **ब्लीचिंग** कहा जाता है।
- प्रक्षालित मूंगों के मरने की संभावना अधिक होती है।
- मूंगे छोटे जानवर हैं जो **बड़ी चट्टानों** का **निर्माण** करते हैं।
- कोरल चट्टानें समुद्री जीवन और **तटीय सुरक्षा** के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **पानी** के बढ़ते **तापमान** से **ब्लीचिंग** के कारण **कोरल चट्टानों** को खतरा है।

82. विश्व पृथ्वी दिवस 2024: थीम, इतिहास, विषय और महत्व - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- WWF
- पृथ्वी दिवस

समाचार:
- **विश्व पृथ्वी दिवस**, जिसे **अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस** के रूप में भी जाना जाता है, एक **विश्व स्तर** पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो जागरूकता बढ़ाने और हमारे **ग्रह की स्थिरता** को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

मुख्य बिंदु
- हर साल **22 अप्रैल** को मनाया जाने वाला **पृथ्वी दिवस** एक **वैश्विक आंदोल**न है जो **वर्ष 1970** में शुरू (वर्ष 2024 में इसके 54वें वर्ष को चिह्नित करते हुए) हुआ था।
- इसकी शुरुआत **अमेरिका** में **सांता बारबरा तेल रिसाव** जैसी घटनाओं से होने वाले **पर्यावरणीय नुकसान** के **विरोध** में **लाखों** लोगों द्वारा की गई।
- **संयुक्त राष्ट्र** ने **वर्ष 2009** में **आधिकारिक तौर** पर **पृथ्वी दिवस** को मान्यता दी गई।
- अब **192 देशों में** मनाया जाता है और **Earthday.org** द्वारा आयोजित किया जाता है

उद्देश्य
- इसका लक्ष्य **दुनिया** का सबसे बड़ा **पर्यावरण आंदोलन** बनना है।
- **पृथ्वी दिवस** का उद्देश्य **ग्रह** के **पारिस्थितिकी** तंत्र को ठीक करने, **जलवायु परिवर्तन** से लड़ने और पृथ्वी पर जीवन की **विविधता की रक्षा** करने के लिए सभी को मिलकर काम करने के लिए **प्रोत्साहित** करना है।
- इस **वैश्विक** प्रयास को सफलता मिली है, जैसे **पृथ्वी दिवस वर्ष 2016** पर **ग्रीनहाउस गैसों** को कम करने के लिए **पेरिस समझौते** पर **हस्ताक्षर** किए गए थे।

- इस वर्ष की थीम, **"प्लैनेट बनाम प्लास्टिक",** प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती **समस्या पर प्रकाश** डालती है, जो अब **दुनिया** भर में **प्रति वर्ष 380 मिलियन टन** से अधिक तक पहुँच जाती है।
- यह हमारे **ग्रह और स्वास्थ्य** के लिए **प्लास्टिक से उत्पन्न** खतरे पर जोर देता है और **वर्ष 2040** तक **प्लास्टिक** उत्पादन में **नाटकीय कमी** लाने का आह्वान करता है।

83. कर्नाटक को सूखे से राहत देने हेतु SC ने केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- सेंडाई फ्रेमवर्क
- NDMA

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **केंद्र** और **कर्नाटक** को **संघीय ढांचे** में उत्पन्न होने वाले **मतभेदों** को **सौहार्दपूर्ण** ढंग से हल करने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाया।
- **केंद्र सरकार** ने **आश्वासन** दिया कि एक सप्ताह के भीतर **कर्नाटक** की **सूखे** की **चिंताओं** को हल करने के लिए "कुछ किया जाएगा"।
- **राज्य** ने कहा कि केंद्र **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की **वैधानिक योजना** का उल्लंघन कर रहा है।
- **सूखा प्रबंधन** के लिए **मैनुअल** और **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष** और **NDRF** के प्रशासन पर दिशानिर्देश।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित करता है।
- **अधिनियम आपदा प्रबंधन प्रयासों** की **देखरेख और कार्यान्वयन** के लिए **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य** और **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** जैसे विभिन्न **प्राधिकरणों** और **समितियों की स्थापना** को अनिवार्य करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष **भारत** के **प्रधानमंत्री** होते हैं।
- NDMA ने भारत में **सूखे के उचित प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश (2010) जारी किए हैं**
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) 2016** में जारी की गई, यह **आपदा प्रबंधन** के लिए देश में तैयार की गई **पहली राष्ट्रीय योजना** है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना** (2016) के साथ, भारत ने अपनी **राष्ट्रीय योजना** को **आपदा जोखिम न्यूनीकरण वर्ष** 2015-2030 के लिए **सेंडाई फ्रेमवर्क** के साथ जोड़ दिया है।

केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263):
- राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना आवश्यक है
- प्रशासनिक मामलों में "सहकारी संघवाद" की संकल्पना।
- कुछ मामलों पर राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति

84. वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता कनाडा में आयोजित होगी - द इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्लास्टिक के प्रकार
- OECD रिपोर्ट

समाचार:
- वर्ष के अंत तक **प्लास्टिक प्रदूषण** को समाप्त करने के लिए एक **वैश्विक संधि** पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं ने कनाडा में मुलाकात की है।

मुख्य बिंदु:
- **वर्ष 2022** में संयुक्त राष्ट्र **पर्यावरण सभा** में, राष्ट्रों ने **विश्व** के **प्लास्टिक प्रदूषण संक**ट से निपटने के लिए **वर्ष 2024** के अंत तक एक कानूनी रूप से **बाध्यकारी समझौता विकसि**त करने पर सहमति व्यक्त की है।
- यह संधि **प्लास्टिक** को उसके संपूर्ण **जीवनचक्र के माध्यम** से संबोधित करने के लिए निर्धारित है
- सऊदी अरब, ईरान और चीन सहित कई **प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादक देशों,** जिन्हें सामूहिक रूप से समान **विचारधारा वाले देशों** के समूह के रूप में जाना जाता है, ने **उत्पादन सीमा** का उल्लेख करने का विरोध किया है।
- इस बीच, **60 देशों** का "**उच्च-महत्वाकांक्षा गठबंधन**", जिसमें **यूरोपीय संघ** के देश, **द्वीप राष्ट्र, जापान** और **संयुक्त अरब अमीरात** शामिल हैं, **वर्ष 2040** तक **प्लास्टिक प्रदूषण** को समाप्त करना चाहते हैं।

प्लास्टिक उपयोग:

- **पेट्रोकेमिकल उद्योग** (प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयुक्त) का कहना है कि **उत्पादन सीमा** से कीमतें बढ़ेंगी और संधि को इस पर ध्यान देना चाहिए:
  - प्लास्टिक का पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण , और प्लास्टिक को ईंधन के रूप में जलाने के लिए बाजार विकसित करना।

प्लास्टिक

- प्लास्टिक पॉलिमर हैं पॉलिमर कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना एक पदार्थ है ।
- प्लास्टिक को **दो भागों थर्मोप्लास्टिक्स** और **थर्मोसेट्स** में विभाजित किया जा सकता है।
- **थर्मोप्लास्टिक्स** को **ऐसे पॉलिमर** के रूप में **परिभाषित** किया जाता है जिन्हें लगभग **अनिश्चित काल** तक **पिघलाया और दोबारा** बनाया जा सकता है।
- **थर्मोसेट्स** एक बहुलक है जो गर्म होने पर अ**परिवर्तनीय रूप** से कठोर हो जाता है

भारत द्वारा किये गये प्रयास:

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 2022 तक चिन्हित एकल उपयोग वाली **प्लास्टिक वस्तुओं** पर प्रतिबंध लगाता है
- प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई व**र्ष 2021** में **50** से **बढ़कर 75 माइक्रोन** और 2022 से **120 माइक्रोन** हो गई है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022** दिशानिर्देश प्लास्टिक **पैकेजिंग क**चरे की **चक्रीय अर्थव्यवस्था** को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं
- प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देना
- व्यवसायों द्वारा सतत प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम प्रदान करें

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

- वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई:
- वैश्विक स्तर पर **21 मिलियन टन (MT)** प्लास्टिक पर्यावरण में लीक हो गया।

85. मानव-वन्यजीव संघर्षों से प्रकृति को भारी नुकसान की संभावना: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य
- मानव वन्यजीव संघर्ष

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** की **सीमाओं** के सीमांकन से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए चेतावनी दी कि **मानव-वन्यजीव संघर्ष जंगलों** और **वन्यजीवों** के अस्तित्व के लिए खतरा है।

मुख्य बिंदु

- **सुप्रीम कोर्ट** ने कहा, **जंगल को संरक्षित** करने के लिए **मानव और वन्यजीवों** के **अधिकारों** के बीच संतुलन होना जरूरी है।
- **असम** के **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** की **सीमाओं** के **सीमांकन** और **अभयारण्य** के भीतर रहने वाले **ग्रामीणों के अधिकारों** के निपटान से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां सामने आईं है।
- पीठ ने कहा कि **अभयारण्य** के संबंध में **राज्य के प्रस्तावों** को **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड** द्वारा मंजूरी दी जाएगी और **सुप्रीम कोर्ट** की जांच से भी गुजरना होगा।
  - अदालत ने **राज्यों** को आदेश दिया कि मुख्य **वन्यजीव वार्डन** और **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** के **फील्ड निदेशक** को **वन्यजीवों** की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष समिति का सदस्य बनाया जाए।
- अदालत ने अपने आदेश में कहा कि "मानचित्र के प्रथम दृष्टया अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि **राज्य वन्यजीव अभयारण्य** के छोटे क्षेत्रों को हटाने और एक बड़े क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव करता है ताकि बसने वालों की भूमि और गैंडों की बढ़ती आबादी के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जा सके।
- पिछले महीने **सुप्रीम कोर्ट** ने **पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य** को **डिनोटिफाई** करने के **असम सरकार** के फैसले पर भी रोक लगा दी थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव:

- **मनुष्यों** को **वित्तीय नुकसान** के साथ-साथ **स्वास्थ्य और सुरक्षा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा** और **संपत्ति** को भी खतरा होता है।
- **सड़क और रेलवे** आधारभूत संरचना में वृद्धि से **जानवरों** की **आकस्मिक मृत्यु** की संभावना बढ़ जाती है।
- **आवास की हानि** और **जानवरों** का **विस्थापन** जिसके कारण **जैव विविधता** की हानि या विलुप्ति होती है।

86. विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण रॉटरडैम (नीदरलैंड) में आयोजित किया गया - पीआईबी

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व ऊर्जा परिषद
- 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस
- COP28

समाचार :
- **नीदरलैंड** के **रॉटरडैम** में चल रहे **विश्व ऊर्जा कांग्रेस** के **26वें संस्करण** में **24 अप्रैल, 2024** को **मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन** आयोजित किया गया था।
- सम्मेलन में **COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन** सम्मेलन की सकारात्मकताओं पर चर्चा की गई।

मुख्य बिंदु
- **गोलमेज सम्मेलन** में **ऊर्जा नवाचार और सहयोग** , और उभरती ऊर्जा **त्रिलम्मा व्यापार-बंद** के **प्रबंधन** में निहितार्थ पर भी चर्चा हुई।
- सम्मेलन के दौरान, **केंद्रीय ऊर्जा सचिव** ने **वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन** में **नीति उत्प्रेरक** के रूप में इसके महत्व पर जोर देते हुए, **COP28** में **भारत** की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
  - उन्होंने **COP28 प्रतिबद्धताओं** के प्रति **अभिसरण** के निर्माण के लिए **भारत के प्रयासों** के प्रमाण के रूप में **G20** नई दिल्ली नेताओं की **घोषणा** पर भी प्रकाश डाला।
  - की **कार्बन कैप्चर**, **उपयोग** और **भंडारण** (**CCUS**) और हरित हाइड्रोजन पर जोर देने के साथ **कार्बन तटस्थता** की ओर संक्रमण **कीCOP28** मान्यता।
  - संशोधित **भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (IESS)** 2047 **डैशबोर्ड** जैसे उपकरणों के साथ **प्रौद्योगिकी परिनियोजन** और **सहयोग** की भूमिका, **सूचित निर्णय** लेने में सहायता करती है।
  - **पर्यावरणीय स्थिरता** और **रोजगार सृजन** को बढ़ावा देने वाली **पीएम-कुसुम योजना** और **सौर** छत कार्यक्रमों जैसी पहलों के साथ **ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता** को संतुलित करना।

26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस:
- **थीम** : लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना',
- यह सभा **विश्व ऊर्जा** में **विश्व ऊर्जा परिषद की शताब्दी** का प्रतीक है ।
- परिषद के अनुसार, **कांग्रेस विश्व संदर्भ** में **वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन** को आगे बढ़ाने में **कनेक्टेड ऊर्जा समाजों** की **भूमिका** का पता लगाना चाहती है जो कम पूर्वानुमानित, अधिक अशांत और तेजी से बदलाव वाला है।

विश्व ऊर्जा परिषद भारत:
- विश्व ऊर्जा परिषद **भारत विश्व ऊर्जा परिषद (WEC)** का एक **सदस्य** देश है
- यह ऊर्जा की **सतत आपूर्ति** और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **वर्ष 1923** में स्थापित एक **वैश्विक** निकाय है।
- WEC **भारत विश्व ऊर्जा परिषद** के शुरुआती सदस्यों में से एक है, यह **वर्ष 1924** में **परिषद** में शामिल हुआ था।
- **WEC** इंडिया **भारत सरकार** के **विद्युत मंत्रालय के संरक्षण** में और **कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा,** पेट्रोलियम एवं **प्राकृतिक गैस** और **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से कार्य करता है।

87. सौर विकिरण की उपलब्धता वाले स्थानों को सौर पैनलों द्वारा बिजली घरों में परिवर्तित किया जा सकता है: IMD

प्रीलिम्स टेकअवे
- SPV
- सौर ऊर्जा प्रतिबद्धता

समाचार:
- भारत **मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** का सुझाव है कि **भारत में कई स्थानों** पर उपलब्ध **सौर विकिरण** की मात्रा जिसे **आर्थिक रूप** से **सौर पैनलों** द्वारा **बिजली** में **परिवर्तित** किया जा सकता है, चिंताजनक रूप से घटती प्रवृत्ति दिखा रही है।

मुख्य बिंदु:

- **पृथ्वी** पर उपलब्ध **सूर्य** के **प्रकाश** को **अवरुद्ध** करने में **एरोसोल** की भूमिका **वर्ष 1980** के दशक से स्पष्ट है, कई अध्ययनों से पता चला है कि **समय और स्थान** दोनों के साथ इसमें भिन्नताएं हैं।
- **वैश्विक सौर विकिरण** में **वर्ष 1981-2006** तक आम तौर पर कमी की प्रवृत्ति देखी गई, **वर्ष 1971-2000** में **वर्ष 1981-2006** की तुलना में अधिक कमी देखी गई।
  - हालाँकि, कुल मिलाकर, **वर्ष 2001** के बाद रुझानों में **उलटफेर** हुआ और **सटीक** कारण स्पष्ट नहीं हुए।
- **SPV** क्षमता, जो **पैनलों** द्वारा **बिजली** में **परिवर्तित** करने के लिए **व्यावहारिक रूप** से **उपलब्ध विकिरण** की मात्रा है, ने अध्ययन किए गए **स्टेशनों** में **सामान्य गिरावट** देखी है।
- **भारत** के सबसे **बड़े सौर पार्क,** विशेष रूप से **गुजरात** और **राजस्थान**, भी **SPV क्षमता** में कमी दिखा रहे हैं।
- आज तक, **भारत** की स्थापित **सौर ऊर्जा क्षमता** लगभग **81 गीगावॉट** (1 गीगावॉट 1,000 मेगावाट है) या कुल स्थापित बिजली का लगभग **17%** है।

सौर विकिरण घटने के कारण:

- **एयरोसोल लोड में वृद्धि-**
  - कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन जलने, धूल और बादल से निकलने वाले बारीक कणों को इसके कारक कहा जाता है
- **एरोसोल सूर्य** के **प्रकाश** को **अवशोषित** करते हैं और इसे जमीन से दूर **विक्षेपित** कर देते हैं और वे घने **बादलों** का निर्माण भी कर सकते हैं जो फिर से **सूर्य** के **प्रकाश को अवरुद्ध** कर देते हैं।
  - **सौर पैनलों** की **कार्यक्षमता** उन पर पड़ने वाली **सूर्य** की **रोशनी** की मात्रा से काफी प्रभावित होती है।

सौर ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता:

- **भारत** की **वर्ष 2030** तक **गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों** से लगभग **500 गीगावॉट,** यानी अपनी बिजली की लगभग आधी आवश्यकता, प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना है।
- यह सुझाव देता है कि उस वर्ष तक **सौर ऊर्जा** से कम से कम 280 गीगावॉट या **वर्ष 2030 त**क सालाना कम से कम **40 गीगावॉट सौर क्षमता** जोड़ी जाएगी।
  - हालाँकि, पिछले **पाँच वर्षों** में, **सौर क्षमता मुश्किल** से **13 गीगावॉट** को पार कर पाई है।
- इस साल की **शुरुआत** में **सरकार** ने देश भर में कम से कम एक **करोड़ घरों** में छत पर **सौर ऊर्जा** स्थापित करने के लिए **वित्तपोषण** के लिए एक बड़ी पहल की भी घोषणा की है।

88. हिंद महासागर का तापमान बढ़ने की संभावना: IIT पुणे - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- मरीन हीटवेव
- ज़ेटा- जूल

समाचार:

- **IITM** पुणे के **वैज्ञानिकों** द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि **उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर** संभवतः लगभग **स्थायी हीटवेव स्थिति** में होगा।

मुख्य बिंदु:

- **वर्ष 1950** से **वर्ष 2020** तक **हिंद महासागर** 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है, और **जलवायु मॉडल** का अनुमान है कि **वर्ष 2020** से **वर्ष 2100** तक यह **1.7 डिग्री सेल्सियस** से **3.8 डिग्री सेल्सियस** तक और गर्म हो जाएगा।
- जब सतह से **2,000 मीटर** की गहराई तक मापा जाता है, तो **हिंद महासागर** की **गर्मी सामग्री** वर्तमान में **4.5 ज़ेटा-जूल प्रति** दशक की दर से बढ़ रही है, और **भविष्य** में **16-22 ज़ेटा-जूल** प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- मुख्य रूप से **ग्लोबल वार्मिंग** के लिए जिम्मेदार, यह घटना **प्रवाल विरंजन, समुद्री घास** के विनाश और समुद्री घास के जंगलों के नुकसान में तेजी लाएगी, जिससे **मत्स्य पालन क्षेत्र** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मरीन हीटवेव:

- **समुद्री ताप तरंगें असामान्य** अवधि होती हैं, जिसके दौरान समुद्र की सतह **बड़े क्षेत्रों** में कई **दिनों** से लेकर कई **महीनों** तक गर्म रहती है।
- हालाँकि समुद्र की **सतह** के **तापमान** में वृद्धि मुख्य संकेतक है, लेकिन इसका विस्तार गहरे **समुद्र** तक भी हो सकता है।
- इसके अलावा, पहले **अति, स्थानीयकृत** और **अस्थायी जलवायु संबंधी घटनाएं** होने के कारण, अब वे तेजी से तीव्र, लगातार, **लंबे समय** तक चलने वाली और **स्थानिक रूप** से व्यापक होती जा रही हैं।
- **IPCC** के अनुसार, **वर्ष 1980** के दशक के बाद से **समुद्री ताप तरंगों** की आवृत्ति दोगुनी हो गई है।

मरीन हीटवेव के कारण:

- जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है और इससे **समुद्री गर्म लहरें उत्पन्न** हो रही हैं।
- **इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC)** के अनुसार, **ग्लोबल वार्मिंग** से उत्पन्न **90% अतिरिक्त गर्मी महासागरों** द्वारा अवशोषित कर ली गई है।
  - परिणामस्वरूप, **प्राकृतिक रूप** से उत्पन्न होने वाली कोई भी **समुद्री गर्मी** अब और **अधिक गंभीर** हो जाएगी क्योंकि **वैश्विक औसत समुद्री तापमान** में वृद्धि जारी रहेगी।
- **जलवायु परिवर्तन** से **वायुमंडलीय स्थितियों** की आवृत्ति भी बढ़ रही है जो **हवाओं** को धीमा कर देती है
  - महासागरों के तापमान को नियंत्रित करने में हवा की गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - ये समुद्र का मंथन करते हैं, जिससे सतह पर गर्म पानी के साथ ठंडे गहरे पानी के मिश्रण को बढ़ावा मिलता है।
  - यदि हवा की गति कम हो जाए या पूरी तरह गायब हो जाए तो ऐसा होने की संभावना कम है।

DEFENCE

89. तेजस Mk-1A ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान भरी - द प्रिंट

प्रीलिम्स टेकअवे
- तेजस
- LCA प्रोग्राम

समाचार:
- **तेजस Mk-1A श्रृंखला** का **पहला विमान, LA 5033, बेंगलुरु** में **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड** (**HAL) सुविधा** से आसमान में उड़ गया, जो उस **लड़ाकू विमान** के लिए एक महत्वपूर्ण **महत्वपूर्ण उपलब्धि** है जिसका **भारतीय वायु सेना (IAF)** को बेसब्री से इंतजार है।

पृष्ठभूमि
- जब **LCA** कार्यक्रम पहली बार **वर्ष 1983** में शुरू किया गया था, तो योजना **वर्ष 1994** तक **पहला विमान** जारी करने की थी।
- लेकिन **LCA** का **प्रोटोटाइप परियोजना** शुरू होने के **18 साल** बाद वर्ष **2001** में ही उड़ा।
- **दिसंबर 2013** में, **तेजस** को **प्रारंभिक परिचालन** मंजूरी मिली और **वर्ष 2019** में, **IAF** को अंतिम मंजूरी के साथ पहला विमान दिया गया।
- तेजस **Mk-1A** में एक **उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध संचार प्रणाली, दृश्य सीमा** से परे मिसाइलों के साथ अतिरिक्त युद्ध क्षमता और बेहतर रखरखाव सुविधाएँ होंगी।

LCA Mk-1A विमान
- तेजस LCA Mk.1A का निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) है।
- तेजस LCA Mk 1A एवियोनिक्स, प्रदर्शन और हथियार क्षमताओं के मामले में LCA तेजस के पिछले वेरिएंट से बेहतर होगा।
- तेजस **LCA Mk 1A** विभिन्न प्रकार की **बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR)** मिसाइलें दागने में सक्षम होगा।
- यह साबित करता है कि **LCA तेजस Mk 1A** सुचारू **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकीकरण** के लिए पर्याप्त लचीला होगा, जो कि विभिन्न प्रकार की **BVR मिसाइलों** को ले जाने के लिए आवश्यक होगा, जो **भारतीय वायु सेना (IAF)** की सूची में उपलब्ध हैं।

90. भारतीय सेना ने आकाशतीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- आकाशतीर
- आत्मनिर्भर भारत

समाचार:
- **भारतीय सेना** ने अपनी **वायु रक्षा क्षमताओं** को बढ़ाने के लिए **'प्रोजेक्ट आकाशतीर'** के तहत **नियंत्रण** और **रिपोर्टिंग सिस्टम** को शामिल करने की पहल की है।
- इस परियोजना का उद्देश्य **मित्रवत विमानों** की **सुरक्षा सुनिश्चित क**रने और **प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्र** में **शत्रुतापूर्ण विमानों** को शामिल करने के लिए बल के लिए **अभूतपूर्व स्तर** की **स्थितिजन्य जागरूकता** और नियंत्रण प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट आकाशतीर
- यह भारत की **वायु रक्षा** के लिए **गेम-चेंजर** है।

- यह **उच्च तकनीक प्रणाली डिजिटल उपकरणों** का उपयोग करके **वायु रक्षा नियंत्रण** को स्वचालित करती है।
- यह **सेना** को **आकाश** में क्या हो रहा है (स्थितिजन्य जागरूकता) की **स्पष्ट तस्वीर प्रदान** करता है और उन्हें तुरंत नियंत्रण लेने देता है।
- यह **प्रणाली कम ऊंचाई** वाले **हवाई क्षेत्र** को ट्रैक कर सकती है और **जमीन-आधारित वायु रक्षा हथियारों** का प्रबंधन कर सकती है।
- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** द्वारा विकसित, **आकाशतीर भारत** की **आत्मनिर्भरता** (आत्मनिर्भर भारत) के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **तेज़ प्रतिक्रिया** और **कम अनुकूल गोलाबारी, कार्यों** को स्वचालित करके**, आकाशतीर सेना** को **खतरों** के प्रति तेज़ी से प्रतिक्रिया करने देता है और गलती से अपने ही विमान से टकराने के जोखिम को कम कर देता है।
- **स्पष्ट तस्वीर:** रडार और संचार प्रणालियों को जोड़कर, आकाशतीर सेना को हवाई क्षेत्र का पूरा दृश्य देता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को ढूंढना और उनसे निपटना आसान हो जाता है।
- **भविष्य-संरक्षित रक्षा** : प्रोजेक्ट आकाशतीर पूरी तरह से स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है, जो आने वाले वर्षों के लिए भारत की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

91. DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- DRDO
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल

समाचार:
- **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने **ओडिशा** के तट पर **चांदीपुर** में **एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR)** से "लंबी दूरी की **सबसोनिक स्वदेशी** रूप से विकसित **क्रूज मिसाइल**" का सफल उड़ान परीक्षण किया।
- **मिसाइल** ने **वेपॉइंट नेविगेशन** का उपयोग करके **वांछित पथ का अनुसरण** किया और **बहुत कम ऊंचाई** वाली **समुद्री-स्किमिंग** उड़ान का प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु
- **परीक्षण** के दौरान **सभी उपप्रणालियों** ने अपेक्षा के अनुरूप **प्रदर्शन** किया
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज़ मिसाइल** (**ITCM**) के प्रदर्शन की निगरानी उड़ान पथ की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए **ITR** द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो **ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम (EOTS)** और **टेलीमेट्री** जैसे कई रेंज सेंसर द्वारा की गई थी।
- **मिसाइल** की उड़ान की निगरानी **भारतीय वायु सेना** के **Su-30-Mk-I** विमान से भी की गई।"
- **मिसाइल** को अन्य **प्रयोगशालाओं** और घरेलू उद्योगों के योगदान के साथ बेंगलुरु स्थित **DRDO** प्रयोगशाला **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान** (**ADE**) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस सफल उड़ान परीक्षण ने **गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE**), **बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी** प्रणोदन प्रणाली के **विश्वसनीय** प्रदर्शन को भी स्थापित किया है।
- बेहतर और **विश्वसनीय** प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए **क्रूज़ मिसाइल** उन्नत **एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर** से भी लैस है

92. DRDO ने LCA तेजस Mk1A का एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल HAL को सौंपी-पीआईबी

प्रीलिम्स टेकअवे
- DRDO
- रक्षा प्रौद्योगिकी

समाचार:
- DRDO की **एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA)** ने **स्वदेशी लीडिंग एज एक्चुएटर्स** और **एयरब्रेक** कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** को सौंप दिया है।
- **वैमानिकी प्रौद्योगिकियों** में **आत्मनिर्भरता** की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए **HAL, लखन**ऊ ने मौजूदा **83 LCA** तेजस **Mk1A ऑर्डर** के लिए इन इकाइयों के उत्पादन की तैयारी पहले ही कर ली है।

मुख्य बिंदु
- **LCA-तेजस** का **सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल**, जिसमें **लीडिंग एज स्लैट्स** और **एयरब्रेक** शामिल हैं, अब **अत्याधुनिक सर्वो एक्चुएटर्स** और **कंट्रोल मॉड्यूल** का दावा करता है।
- इन महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन **सहायक उपकरण** प्रभाग, **HAL**, **लखनऊ** में चल रहा है, जो **भारत** की **एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं** को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

DRDO:

- **DRDO** का गठन **वर्ष 1958** में हुआ था।
- **DRDO** भारत सरकार के **रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास** शाखा है , जिसका लक्ष्य **अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों** के साथ भारत को सशक्त बनाना और महत्वपूर्ण **रक्षा प्रौद्योगिकियों** और **प्रणालियों** में **आत्मनिर्भरता** हासिल करना है।
- **तीनों सेनाओं** द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे **सशस्त्र बलों** को **अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों** से लैस करना।
- अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, मल्टी-बैरल रॉकेट लांचर, पिनाका, वायु रक्षा सिस्टम, आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि की एक विस्तृत श्रृंखला ने भारत की सैन्य शक्ति को क्वांटम उछाल दिया है, प्रभावी प्रतिरोध पैदा किया है और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है।
- "**बलस्य मूलं विज्ञानम्**" शक्ति का स्रोत **विज्ञान** ही **राष्ट्र को शांति और युद्ध** में चलाता है

93. IAF ने Su-30 MKI से एक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल ROCKS का परीक्षण किया- द प्रिंट

प्रीलिम्स टेकअवे

- बैलिस्टिक मिसाइल
- ROCKS

समाचार:

- हाल ही में, **भारतीय वायु सेना (IAF)** ने **Su-30 MKI** से एक **अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल - ROCKS** का परीक्षण किया।
- इसने **भारत** की अपनी **हवाई सीमा** को पार किए बिना **दुश्मन** के इलाके में अंदर तक निशाना लगाने की क्षमता में **उल्लेखनीय वृद्धि** दर्ज की।

मुख्य बिंदु

- यह **मिसाइल**, अगली **पीढ़ी** की विस्तारित **स्टैंड-ऑफ** हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है
  - **भारत की जरूरतों** को ध्यान में रखते हुए **इजरायली** रक्षा प्रमुख **राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स** द्वारा **डिजाइन और निर्मित** किया गया है।
- यह **मिसाइल स्पाइस श्रृंखला** की **मिसाइलों की क्षमताओं** का उपयोग करते हुए **हवा में लॉन्च** की जाने वाली **बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्यों** की **स्पैरो श्रृंखला** से एक **स्पिन-ऑफ** है।
- **मिसाइल** में इस्तेमाल होने वाले कई **घटकों** को **भारत से मंगाए** जाने के साथ, भारतीय वायुसेना **आत्मनिर्भर पहल** के तहत एक **बड़ा ऑर्डर** देने पर विचार कर रही है।
- **भारतीय वायुसेना** चाहती है कि **मिसाइलों** का **निर्माण** भारत में किया जाए।
- **अर्ध बैलिस्टिक** का मतलब है कि **मिसाइल नियमित हवा** से जमीन पर मार करने वाली **हथियार प्रणाली** की तरह फायर नहीं करती और काम नहीं करती।
- **विमान** का **पायलट मिसाइल** के **प्रक्षेप पथ** को **क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर** भी चुन सकता है।
- इसे जमीन के ऊपर, या **भूमिगत**, और **GPS-अस्वीकृत** क्षेत्रों में **पिनपॉइंट सटीकता** के साथ भारी **किलेबंद लक्ष्यों** पर **उच्च मूल्य वाले स्थिर** और **स्थानांतरित** करने योग्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसकी उड़ान की **बैलिस्टिक प्रकृति** के कारण, उड़ान के **अंतिम चरणों** के दौरान इसका **उच्च वेग** इसे लक्ष्य में गहराई तक घुसने में काफी मदद करेगा।
- संयोग से, इस **मिसाइल** का **इस्तेमाल इजरायली सेना** ने पिछले हफ्ते ईरान की **S-300 बैटरी** को निशाना बनाने के लिए किया था।
- स्वायत्त रूप से संचालन, और **भारी सुरक्षा** वाले सतह से हवा के **खतरों** के **क्षेत्रों** के बाहर एक विस्तारित **स्टैंड-ऑफ रेंज** पर **लॉन्च** किया गया
  - **ROCKS** में पारंपरिक **पोपाय** और **SPICE** हवा से सतह पर मार करने वाले **हथियारों** से **विरासत** में मिली **प्रौद्योगिकियों** को शामिल किया गया है।

94. मिशन ISHAN: एक राष्ट्र, एक हवाई क्षेत्र परियोजना- द प्रिंट

प्रीलिम्स टेकअवे

- AAI

समाचार:

- **भारत** ने **एयर ट्रैफिक कंट्रोल** को **सुव्यवस्थित** और बढ़ाने के लिए पूरे देश में फैले अपने **चार हवाई क्षेत्र क्षेत्रों** को एक में **एकीकृत** करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्य बिंदु

- **एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATM)** सेवाओं के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक इकाई, **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** ने पिछले महीने **अभिव्यक्ति पत्र (EoI)** आमंत्रित किए थे।
- इस कदम से न केवल **एयरलाइंस** को अधिक **निर्बाध संचालन** और **उड़ान प्रबंधन क्षमता** में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है
  - बल्कि यात्रियों को भी भीड़भाड़ और उड़ान के समय में कमी आएगी।
- यह हवाई क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार उड़ान सूचना क्षेत्रों (FIR) और गुवाहाटी में एक उप-उड़ान सूचना क्षेत्र के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
- "एक **सिंगल निरंतरता** FIR से सुरक्षा, दक्षता, उपयोगकर्ता संतुष्टि, कम कार्बन पदचिह्न और इष्टतम जनशक्ति उपयोग के मामले में बहुत सारे लाभ मिलेंगे
- AAI ने इस बात पर जोर दिया कि **नागपुर** में केंद्रित निरंतर हवाई क्षेत्र में **FIR** का **एकीकरण क्षेत्र** में **ATM** संचालन को परिष्कृत और मजबूत करने के लिए किया गया है।
  - **ISHAN** के कार्यान्वयन के लिए, वर्तमान और **अनुमानित हवाई यातायात** वृद्धि और बढ़े हुए हवाई **यातायात के प्रबंधन** से संबंधित चुनौतियों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

SCIENCE & TECH

95. खगोलशास्त्री चंद्रमा की कक्षा में भारत की प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन को लगायेंगे - द हिंदू

समाचार:

- खगोलविद चंद्रमा पर और उसके चारों ओर कक्षा में **उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीनें** तैनात करके **ब्रह्मांड** पर एक नई योजना पर काम करने की उम्मीद कर रहे हैं।
- **दुनिया** भर के **खगोलविदों** की ओर से ऐसा करने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं, जिनमें **भारत** का एक **प्रस्ताव** भी शामिल है जिसे **प्रत्यूष (PRATUSH)** कहा जाता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- कॉस्मिक रे
- प्रत्यूष (PRATUSH)

मुख्य बिंदु

- **RRI** और इसरो द्वारा निर्मित **भारत** की **प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन** का उद्देश्य **ब्रह्मांड** के शुरुआती दिनों के रहस्यों को उजागर करना है।
- पृथ्वी के हस्तक्षेप से बचने के लिए यह **रेडियो टेलीस्कोप चंद्रमा** के दूर की ओर स्थित होगा, **चंद्रमा** की ओर **प्रक्षेपित** होने से पहले यह **पहले पृथ्वी** की परिक्रमा करेगा।
- **प्रत्यूष (PRATUSH)** सबसे पहले **तारों और आकाशगंगाओं** से आने वाले **हल्के रेडियो संकेतों** को सुनेगा।
- इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये पहले तारे कब उभरे, वे कैसे थे, और ब्रह्मांड की **"कॉस्मिक डॉन "** के दौरान उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति क्या थी।
- **कॉस्मिक नोइज़** के बीच इन कमजोर संकेतों को पकड़ने के लिए **दूरबीन विशेष उपकरणों** से सुसज्जित है।
- इन उपकरणों में एक **वाइडबैंड एंटीना,** एक **सेल्फ-कैलिब्रेटिंग रिसीवर** और एक **डिजिटल सहसंबंधक** शामिल हैं।
- लक्ष्य कुछ **मिलीकेल्विन** की **संवेदनशीलता** प्राप्त करना है, जिससे **विकृतियों** के बिना स्पष्ट पता लगाना संभव हो सके।

96. सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के पीछे की तकनीक- द हिन्दू

समाचार:

- सेमीकंडक्टर **चिप निर्माण क्षमताएं वर्तमान** में दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों तक सीमित हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- सेमीकंडक्टर
- ताइवान

- **महामारी** और हालिया **भू-राजनीतिक तनाव** के दौरान **आपूर्ति श्रृंखला** में व्यवधान के साथ, भारत सहित कई **कंपनियों** और **देशों** ने चिप निर्माण **बुनियादी ढांचे** में निवेश के महत्व को महसूस किया है।

सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण कैसे होता है ?

- यह प्रक्रिया डाक टिकट बनाने जैसी है।
- **सैकड़ों चिप्स** एक **गोलाकार वेफर** पर उकेरे गए हैं, एक शीट के समान जिसमें कई टिकटें होती हैं।
- फिर इस **वेफर** को काटा जाता है, जिससे हमें **अलग-अलग चिप्स** मिलते हैं।
- प्रत्येक चिप को **बिजली, डेटा और सिग्नल** के लिए छोटे तारों के साथ एक सुरक्षात्मक आवरण की आवश्यकता होती है।

भारत का सेमीकंडक्टर दृश्य

- **TATA** समूह **भारत** में एक **अत्याधुनिक चिप फैक्ट्री** बनाने के लिए **ताइवान** की **PSMC** के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- यह सुविधा वर्ष 2026 तक 28nm चिप उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- चूंकि **चिप-निर्माण** में कई क्षेत्र शामिल हैं, यह प्रक्रिया **इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों** जैसे पेशेवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दरवाजे खोलता है।

97. इसरो के PSLV ने जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज़ मिशन पूरा किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे

- नासा
- PSLV

समाचार:

- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** ने कहा है कि उसके **PSLV-C58/XPoSat मिशन** ने पृथ्वी की कक्षा में **प्रैक्टिकल रूप** से **शून्य मलबा** छोड़ा है।

मुख्य बिंदु

- अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मिशन में इस्तेमाल किए गए **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** के अंतिम चरण को एक प्रकार के **कक्षीय स्टेशन** में बदल दिया गया, जिसे **PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल -3** (POEM-3) कहा जाता है।
  - इससे पहले कि मिशन पूरा होने के बाद इसे कक्षा में तैरने के **बजाय पृथ्वी** के **वायुमंडल** में फिर से प्रवेश करने के लिए छोड़ दिया गया था।

अंतरिक्ष प्रयोगों को किफायती बनाना

- इसरो के चतुर विचार ने **रॉकेट स्टेज** को **विज्ञान प्रयोगशाला** में बदल दिया!
- **PSLV रॉकेट** का अंतिम भाग **PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM)** बन गया, जो **अंतरिक्ष अनुसंधान** के लिए एक कम लागत वाला प्लेटफार्म है।
- **वर्ष 2022** में लॉन्च किया गया, **POEM वैज्ञानिकों** को किसी **नए उपग्रह** की आवश्यकता के बिना कक्षा में प्रयोग करने की सुविधा देता है।

POEM-3: एक स्वच्छ मिशन

- **वर्ष 2024** में, इसरो के **PSLV C-58 मिशन** ने एक उपग्रह को तैनात किया और फिर **चौथे चरण** को **POEM-3** में बदल दिया।
- अपने प्रयोगों को पूरा करने के बाद, **POEM-3** ने अंतरिक्ष मलबे को कम करते हुए, पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से पुनः प्रवेश किया।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष में **मलबे की** की समस्या बढ़ रही है, जो उपग्रहों से टकरा सकता है और टकराव की एक श्रृंखला बना सकता है।

अंतरिक्ष की सफ़ाई

- **निचली-पृथ्वी कक्षा** के मलबे की **सफाई** के लिए कोई **अंतरराष्ट्रीय कानून** नहीं हैं, लेकिन कई **अंतरिक्ष एजेंसियों** के पास दिशानिर्देश हैं।

- उदाहरण के लिए, **नासा** के पास एक **कक्षीय मलबा कार्यक्रम** है, और **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** का लक्ष्य **वर्ष 2030** तक **शून्य मलबा** का लक्ष्य है।
- यहां तक कि **भारत** में **मनास्तु स्पेस** जैसी **निजी कंपनियां** भी पुराने **उपग्रहों को हटाने** और उनका **जीवनकाल** बढ़ाने के तरीके विकसित कर रही हैं।

98. 'गॉड पार्टिकल' की भविष्यवाणी करने वाले नोबेलिस्ट पीटर हिग्स का निधन - न्यूयॉर्क टाइम्स

प्रीलिम्स टेकअवे
- गॉड पार्टिकल
- बोसॉन

समाचार:
- **पीटर हिग्स,** जिन्होंने एक **नए कण** के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया और एक साल बाद **नोबेल पुरस्कार** दिया गया, हाल ही में उनका निधन हो गया।

गॉड पार्टिकल
- हिग्स **बोसोन हिग्स** क्षेत्र का मूलभूत बल-वाहक कण है, जो **मूलभूत कणों** को उनका **द्रव्यमान प्रदान** करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र को पहली बार **साठ के दशक** के मध्य में **पीटर हिग्स** द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनके नाम पर इस कण का नाम रखा गया है।
- इस कण की खोज अंततः **वर्ष 2012** में **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)** के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी।
  - दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सीईआरएन, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- **LHC** ने **हिग्स क्षेत्र** और उस तंत्र के अस्तित्व की पुष्टि की जो **द्रव्यमान** को जन्म देता है और इस प्रकार **कण भौतिकी** का **मानक मॉडल** पूरा हुआ।
- यह उन **17 प्राथमिक कणों** में से एक है जो कण **भौतिकी** के **मानक मॉडल** को बनाते हैं, जो **ब्रह्मांड** के सबसे **बुनियादी निर्माण खंडों के व्यवहार** के बारे में वैज्ञानिकों का सबसे अच्छा सिद्धांत है।
- **हिग्स बोसोन उपपरमाण्विक** भौतिकी में इतनी मौलिक भूमिका निभाता है कि इसे कभी-कभी "**गॉड पार्टिकल**" भी कहा जाता है।
- **हिग्स बोसोन** का **द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट** है, अर्थात यह एक **प्रोटॉन** से **130 गुना** अधिक विशाल है।
- यह **शून्य स्पिन** के साथ **चार्जलेस** भी है, जो **कोणीय गति** के बराबर एक **क्वांटम यांत्रिक** है।
- यह एकमात्र **प्राथमिक कण** है जिसका कोई **चक्रण** नहीं है।

99. वायरल हेपेटाइटिस पर WHO का अलर्ट - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- हेपेटाइटिस
- WHO की रिपोर्ट

समाचार:
- हाल ही में जारी **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की **वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024** के अनुसार, **बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूसी संघ** और वियतनाम सामूहिक रूप से हे**पेटाइटिस** B और C के वैश्विक भार का लगभग **दो-तिहाई** हिस्सा वहन करते हैं।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि यह **बीमारी वैश्विक स्तर** पर मृत्यु का दूसरा **प्रमुख संक्रामक** कारण है, प्रति **वर्ष 1.3 मिलियन लोगों** की मृत्यु होती है, जो कि **तपेदिक** के समान है, जो एक **शीर्ष संक्रामक** हत्यारा है।

हेपेटाइटिस रोग:
- **हेपेटाइटिस यकृत** की सूजन है जो विभिन्न प्रकार के **संक्रामक वायरस** और **गैर-संक्रामक एजेंटों** के कारण होती है जिससे कई प्रकार की **स्वास्थ्य समस्याएं** होती हैं।
  - जिनमें से कुछ घातक हो सकते हैं **हेपेटाइटिस वायरस** के **पांच मुख्य प्रकार** हैं, जिन्हें प्रकार **A, B, C, D और E** कहा जाता है।

- **भारत असुरक्षित** है क्योंकि **बड़ी संख्या** में मामले अनजान हैं, **लक्षणों, जांच** और **उपचार** के बारे में **जागरूकता** की कमी और अच्छी **स्वच्छता गतिविधियों** तक पहुंच नहीं है।
- **हेपेटाइटिस B** और **C** सबसे व्यापक रूप से लोगों में पाए जाने वाले वायरस हैं, **हेपेटाइटिस B** को **टीकाकरण** के माध्यम से रोका जा सकता है, जबकि **हेपेटाइटिस C दवाओं से** ठीक हो सकता है।
- **क्रोनिक हेपेटाइटिस B** और सी संक्रमण का आधा भार **30-54 वर्ष** की आयु के लोगों में है, **12% 18 वर्ष** से **कम उम्र के बच्चों** में है।
- सभी मामलों में **58%** मामले **पुरुषों** के हैं।
- अधिकांश **नए संक्रमणों** के लिए **मां से बच्चे** में संचरण जिम्मेदार है, और **भारत में हेपेटाइटिस B** के उन्मूलन के लिए व्यापक उपचार **कवरेज, टीकाकरण और रोगियों** के खिलाफ किसी भी भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- **WHO** के आंकड़ों से पता चलता है कि **वर्ष 2030** तक **क्रोनिक हेपेटाइटिस B** और **हेपेटाइटिस C** से **पीड़ित 80%** लोगों के इलाज के वैश्विक लक्ष्य से परिणाम काफी नीचे हैं।

100. सुप्रीम कोर्ट रेलवे मंत्रालय द्वारा उठाए गए रेलवे सुरक्षा उपायों की सराहना की- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- कवच
- राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने **स्वदेशी एंटी कोलिशन सिस्टम कवच** के कार्यान्वयन सहित **ट्रेन दुर्घटनाओं** को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों को दर्ज किया और **मंत्रालय** द्वारा उठाए गए उपायों को स्वीकार किया।

मुख्य बिंदु
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **केंद्र** से **कवच प्रणाली** सहित **रेल सुरक्षा उपायों** पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
- कवच, जिसका शाब्दिक अर्थ कवच है, **वर्ष 2002** में **अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन** द्वारा **तीन भारतीय विक्रेताओं** के सहयोग से विकसित किया गया था।

रेल दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियाँ:** रेलवे का बुनियादी ढाँचा, जिसमें ट्रैक, पुल, ओवरहेड तार और रोलिंग स्टॉक शामिल हैं, अक्सर खराब रखरखाव के कारण ख़राब होते हैं।
- **निधि का अभाव:** रेलवे प्रणाली भी धन की कमी, भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त है, जो इसके विकास और रखरखाव में बाधा डालती है।
- **मानवीय त्रुटियाँ** : रेलवे कर्मचारी, जो ट्रेनों और पटरियों के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, थकान के कारण मानवीय त्रुटियों का शिकार होते हैं।
- **सिग्नलिंग विफलताएँ** : सिग्नलिंग प्रणाली, जो पटरियों पर ट्रेनों की गति और दिशा को नियंत्रित करती है, तकनीकी खराबी, बिजली कटौती या मानवीय त्रुटियों के कारण विफल हो सकती है।

दुर्घटनाओं कम करने के लिए रेलवे के प्रयास
- **राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष (RRSK)**
- **तकनीकी उन्नयन:** इसमें स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) कवच स्थापित करना भी शामिल है।
- **LHB डिज़ाइन कोच** : मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हल्के और सुरक्षित कोच।
- **GPS आधारित फॉग पास डिवाइस:** लोको पायलटों को कोहरे की स्थिति में नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक उपकरण।

- **आधुनिक ट्रैक संरचना:** मजबूत और अधिक टिकाऊ ट्रैक और पुल।

रेलवे की सुरक्षा की सिफ़ारिश से सम्बंधित समिति

- काकोडकर समिति (2012)
- बिबेक देबरॉय समिति (2014)

101. मेटा 'कोर्ट' डीपफेक के मामलों का विश्लेषण करेगा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- डीपफेक
- डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट 2023

समाचार:
- **मेटा** के **निरीक्षण बोर्ड** ने कहा कि वह **दो मामलों** के नजरिए से **सोशल मीडिया टाइटन** की **डीप फेक नीतियों** की जांच कर रहा था।
- **सामग्री मॉडरेशन विवादों** के लिए मेटा **"सुप्रीम कोर्ट"** के रूप में संदर्भित यह कदम स्पष्ट **AI-जनरेटेड छवियों** के व्यापक साझाकरण के कुछ ही महीनों बाद आया है।

डीपफेक:
- **डीपफेक** गलत सूचना फैलाने के लिए **मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम** के साथ **कृत्रिम छवियों** और **ऑडियो** का एक संकलन है और यह किसी **वास्तविक व्यक्ति** की उपस्थिति, **आवाज या दोनों** को बदल सकता है।
- **उत्पत्ति:** डीप फेक शब्द की उत्पत्ति **वर्ष 2017** में हुई जब एक गुमनाम Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को "डीपफेक" कहा।
- डीप फेक, **डीप सिंथेसिस** का एक हिस्सा है, जो **आभासी दृश्य** बनाने के लिए **टेक्स्ट , चित्र, ऑडियो** और **वीडियो** उत्पन्न करने के लिए **गहरी शिक्षा** और **संवर्धित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों** का उपयोग करता है।

भारत स्टैंड:
- भारत में ऐसे **विशिष्ट कानून या नियम** नहीं हैं जो **डीपफेक तकनीक** के उपयोग पर **प्रतिबंध या विनियमन** करते हों।
- हालाँकि, **भारत** ने **"नैतिक" AI उपकरणों** के विस्तार पर एक **वैश्विक ढांचे** का आह्वान किया है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की धारा 67 और 67A जैसे मौजूदा कानूनों में प्रावधान हैं
  - इसे **डीप फेक** के कुछ **पहलुओं** पर लागू किया जा सकता है, जैसे **मानहानि** और स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना।
- **भारतीय दंड संहिता (1860)** की **धारा 500** मानहानि के लिए **सजा का प्रावधान** करती है।
- **डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट 2023** व्यक्तिगत डेटा के **दुरुपयोग** के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।

102. एमपॉक्स वायरस विकसित होने के लिए 'जीनोमिक अकॉर्डियन' का उपयोग - द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्माल पॉक्स
- एमपॉक्स वायरस

समाचार:
- **वायरस** का **mpox** (एमपॉक्स) फैमिली चयनात्मक विकासवादी दबावों से बचने में सक्षम माना जाता है।
- एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने **एमपॉक्स जीनोम** के उस हिस्से के बारे में बताया जहां इस तरह के बदलाव होते हैं।

मुख्य बिंदु:
- पॉक्सवायरस एमपॉक्स **वर्ष 2022-2023** में तेजी से बढ़ते **वैश्विक प्रकोप** के बाद सुर्खियों में था।
  - **वर्ष 1958** में **बंदरों** से जुड़ी एक **अनुसंधान सुविधा** में फैलने की घटना के बाद इस वायरस को पहले **'मंकीपॉक्स'** कहा जाता था।
  - तथापि, **शोधकर्ताओं ने मनुष्यों के बीच** कई **आकस्मिक प्रकोपों** में **एमपॉक्स** की पहचान की है ।
- तत्काल हस्तक्षेप के बिना, यह **प्रकोप राष्ट्रीय** और यहां तक कि **महाद्वीपीय सीमाओं** पर तेजी से फैलने और एक अन्य **वैश्विक प्रकोप के रूप** में सामने आने की क्षमता रखता है।
  - इस उभरते खतरे को कम करने के लिए **विश्व** की **स्वास्थ्य सुरक्षा** के लिए कठोर **जीनोमिक जांच** और **समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों** की आवश्यकता है।

एमपॉक्स वायरस:

- **एमपॉक्स (मंकीपॉक्स)** एक **वायरल बीमारी** है जो **एमपॉक्स वायरस** के कारण होती है, जो **जीनस ऑर्थोपॉक्सवायरस** की एक प्रजाति है, **क्लैड I और क्लैड II** दो अलग-अलग समूह मौजूद हैं।
- **एमपॉक्स** का **उपचार सहायक** देखभाल के साथ किया जाता है। कुछ **परिस्थितियों** में **स्माल पॉक्स** के लिए विकसित **टीकों** और **उपचारों** को कुछ देशों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, जिनका उपयोग **एमपॉक्स** के लिए किया जा सकता है।
- **वर्ष 2022** में **118** से अधिक देशों में **एमपॉक्स** के प्रकोप के कारण **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने इसे **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल** घोषित किया।
  - इसका **प्रकोप IIb** नामक एक **क्लैड** (एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न वायरस के उपभेद) के कारण हुआ था।

ECONOMY

103. भारत का पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का सामरिक भंडारण - द हिंदू

समाचार:

- भारत किसी भी **आपूर्ति व्यवधान** के खिलाफ **बीमा** के रूप में **भंडार** को बढ़ाने के प्रयासों के तहत अपना पहला **वाणिज्यिक कच्चे तेल सामरिक भंडारण** बनाने की योजना बना रहा है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सामरिक पेट्रोलियम भंडार
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

मुख्य बिंदु

- **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL)**, देश में **सामरिक पेट्रोलियम भंडार** के निर्माण और संचालन के लिए **सरकार** द्वारा बनाई गई एक **SPV** है।
  - **कर्नाटक** के **पादुर** में **2.5 मिलियन टन भूमिगत भंडारण** के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं
- **ISPRL** ने पहले चरण में **तीन स्थानों** पर भूमिगत बिना लाइन वाली **चट्टानी गुफाओं** में एक **सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व** बनाया था।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)

- ये **कच्चे तेल** के भंडार हैं जो **भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान** के समय भी **कच्चे तेल** की स्थिर **आपूर्ति सुनिश्चित** करने वाले देशों द्वारा बनाए रखे जाते हैं।
- ये भूमिगत **भंडारण सुविधाएं** देश की **वृद्धि** और **विकास** के लिए **ऊर्जा संसाधनों** के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (I.E.P.)** समझौते की शर्तों के अनुसार, **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** से संबंधित प्रत्येक राष्ट्र को अपने **शुद्ध तेल आयात** के **न्यूनतम 90 दिनों** के बराबर तेल का आपातकालीन भंडार बनाए रखना आवश्यक है।
- वर्ष 2017 में, भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** के भीतर एक सहयोगी सदस्य का दर्जा हासिल किया।

104. RBI ने लगातार सातवीं बार रेपो दरों को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा -द हिंदू

समाचार:

- **भारतीय रिज़र्व बैंक** की **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** ने लगातार **सातवीं बैठक** में **प्रमुख रेपो दर** को **6.5 प्रतिशत** पर अपरिवर्तित रखा, क्योंकि इसका ध्यान **खुदरा मुद्रास्फीति** पर नियंत्रण रखने पर था, जो इसके **4 प्रतिशत** के लक्ष्य से ऊपर रही है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- MPC
- मुद्रा स्फ़ीति

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** की एक समिति है जो **रेपो दर** निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, वह ब्याज दर जिस पर **बैंक RBI** से उधार लेते हैं।
- **MPC** की स्थापना **वर्ष 2016** में हुई थी।
- मौद्रिक नीति रुख की समीक्षा के लिए **MPC साल में कम से कम चार बार बैठक** करती है। अपनी नवीनतम बैठक में, MPC ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।
- **MPC** ने **मुद्रास्फीति** को नियंत्रित करने के लिए **सिस्टम** से तरलता निकालने पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखा।
- **रेपो रेट** को **अपरिवर्तित रखने** का **MPC** का निर्णय उम्मीदों के अनुरूप था।

- विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि **आर्थिक विकास** में हालिया मंदी को देखते हुए **MPC** दर स्थिर रखेगी।
- **चलनिधि** वापस लेने पर **MPC** का ध्यान **मुद्रास्फीति** पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है, जो कई महीनों से **RBI** के **4%** के लक्ष्य से ऊपर चल रही है।
- **RBI** के **नवीनतम आर्थिक पूर्वानुमान** में भविष्यवाणी की गई है कि **सकल घरेलू उत्पाद** की **वृद्धि दर वर्ष 2023-24** में **8.7%** से धीमी होकर **वर्ष 2024-25** में **7%** हो जाएगी।
- यह **मंदी कई कारकों** से प्रेरित होने की उम्मीद है, जिसमें मौजूदा **वैश्विक आर्थिक मंदी** और **दुनिया भर** के **केंद्रीय बैंकों** द्वारा **मौद्रिक नीति** को कड़ा करना शामिल है।
- **RBI** ने **वर्ष 2024-25** के लिए अपने **मुद्रास्फीति पूर्वानुमान** को भी संशोधित कर **4.5%** कर दिया, जो पहले **4.2%** था।
- **MPC** की अगली बैठक **अगस्त 2024** में होनी है।
- उस बैठक में, **MPC नवीनतम आर्थिक आंकड़ों** की समीक्षा करेगी और **मौद्रिक नीति** के भविष्य के पाठ्यक्रम पर निर्णय लेगी।
- **MPC** के फैसले **भारतीय अर्थव्यवस्था** के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे **मुद्रास्फीति, ब्याज दरों** और **आर्थिक विकास** जैसे कारकों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **MPC** की कार्रवाइयों पर **व्यवसायों, निवेशकों और उपभोक्ताओं** द्वारा समान रूप से नजर रखी जाती है।

105. RBI नकद जमा सुविधा के लिए UPI को सक्षम करेगा -द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- FPI
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

समाचार:
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने ऐप की **लोकप्रियता** और **सुविधा** को देखते हुए नकद जमा के लिए **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिंदु
- अब **UPI** के उपयोग के माध्यम से **नकद जमा सुविधा** की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- **बैंकों द्वारा तैनात नकदी जमा मशीनें (CDM)** बैंक शाखाओं पर **नकदी-हैंडलिंग** भार को कम करते हुए ग्राहक सुविधा को बढ़ाती हैं।
- नकदी जमा करने की सुविधा अभी केवल **डेबिट कार्ड** के जरिए ही उपलब्ध है।
- **गवर्नर** ने कहा कि **नकद जमा सुविधा** के लिए **UPI** को सक्षम करने पर **परिचालन निर्देश शीघ्र** ही जारी किए जाएंगे।
- एक अन्य उपाय में, **सॉवरेन ग्रीन बांड (SGrB)** में व्यापक अनिवासी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए-
  - **RBI** ने **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र** में **पात्र विदेशी निवेशकों** को भी ऐसे **बांड में निवेश** करने की अनुमति देने का निर्णय लिया।
- **सरकार** और **IFSC प्राधिकरण** के परामर्श से **IFSC** में **पात्र विदेशी निवेशकों** द्वारा **SGrB** में **निवेश** और **व्यापार** के लिए एक योजना अलग से अधिसूचित की जा रही है।
- वर्तमान में, **सेबी** के साथ **पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** को **सरकारी प्रतिभूतियों** में **FPI** द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के तहत **SGrB** में निवेश करने की अनुमति है।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना
- **RBI** ने **नवंबर 2021** में शुरू की गई अपनी **रिटेल डायरेक्ट योजना** के लिए एक **मोबाइल ऐप** पेश करने का भी फैसला किया।
- यह योजना **व्यक्तिगत निवेशकों** को **RBI** के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और **सरकारी प्रतिभूतियों** में निवेश करने की सुविधा देती है।
- यह **योजना निवेशकों** को **प्राथमिक नीलामी** में **प्रतिभूतियां खरीदने** और **NDS-OM प्लेटफॉर्म** के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदने/बेचने में सक्षम बनाती है।

106. अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स GST में तत्काल सुधार की आवश्यकता: केलकर - द हिंदू

समाचार :

प्रीलिम्स टेकअवे
- GST
- GST परिषद

- **भारत** के **टैक्स सुधारों** के प्रमुख वास्तुकार और **तेरहवें वित्त आयोग** के अध्यक्ष **विजय केलकर** ने देश की अगली सरकार से "अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स" **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है।
- जैसे कि **12%** की **एकल टैक्स दर** पर स्विच करना और **स्थानीय सरकारों** और **नगर निगमों** के साथ राजस्व साझा करना।

तेरहवें वित्त आयोग विजय केलकर की सिफ़ारिश
- **जुलाई 2017** में लागू **अप्रत्यक्ष टैक्स** के लिए **सर्वोच्च निर्णय** लेने वाली संस्था **GST परिषद** के लिए एक स्वतंत्र **सचिवालय के निर्माण** पर भी विचार किया गया।
- चूँकि **सचिवालय** को संचालित करने वाली **केंद्र सरकार** की **वर्तमान व्यवस्था** को **राज्यों द्वारा समस्याग्रस्त** माना जा सकता है।
- **टैक्स दरें** निर्धारित करना "बड़े पैमाने पर **राजस्व तटस्थता** बनाए रखने के उद्देश्य से" जैसा कि **भारत** द्वारा किया गया है, "**प्रति-उत्पादक**" है

एकल GST दर की आवश्यकता
- **वर्तमान GST** धोखाधड़ी की उत्पत्ति **GST दरों** की संरचना में निहित है, क्योंकि **GST** की **उच्च दरें** धोखेबाजों के लिए टैक्स से बचने को आकर्षक बनाती हैं।
- **सरकार** और **केंद्र शासित प्रदेशों** के सभी स्तरों के साथ राजस्व को समान रूप से साझा करते हुए **12%** की **एकल GST दर** जल्द से जल्द पेश की जाए।
- **एकल दर** और **सरल GST** या **वैट कानून** वाले देश कर **राजस्व** को अनुकूलित करने और **टैक्स विवादों** को कम करने में सफल रहे हैं
- **GST** या **वैट प्रणाली** वाले देशों में से **80%** ने **एकल टैक्स दर** का विकल्प चुना है, जिसमें **सिंगापुर, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और जापान** शामिल हैं।
- यह कहते हुए कि **भारत** में **एकल GST** दर "**एक अधूरा लक्ष्य**" है, उन्होंने याद दिलाया कि **13वें वित्त आयोग** द्वारा "**GST** बहस में बहुत पहले" **12%** की **एकल दर** की सिफारिश की गई थी।
- **हाइड्रोकार्बन** जैसे कुछ **अवगुण वस्तुओं** पर **कार्बन टैक्स** जैसे अतिरिक्त गैर-वैट-योग्य टैक्स के साथ एकल GST दर की शुरूआत का क्रांतिकारी सुधार अब आवश्यक है।

GST को स्थानीय निकायों के साथ साझा करें'
- अनुभवी अर्थशास्त्री ने **GST राजस्व** को संविधान के **73वें और 74वें संशोधन** द्वारा बनाई गई **सरकार** के **तीसरे स्तर** के साथ साझा करने की भी वकालत की है।
- **तीसरे स्तर** के साथ **GST** की समान हिस्सेदारी हमारी **शहरी सरकारों** के **वित्तीय** आधार को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र और शासन को मजबूत** करने में काफी मदद करेगी।
- इसे सक्षम करने के लिए, हमें सबसे पहले **सरकार** के **तीसरे स्तर** के लिए **समेकित निधि** बनाने के लिए एक **संवैधानिक संशोधन** की आवश्यकता होगी

107. Apple ने 'मर्सनरी स्पाईवेयर' हमले के बारे में चेतावनी दी - द मिंट

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्पाइवेयर
- मैलवेयर

- कई **मीडिया रिपोर्टों** के अनुसार, **Apple** ने **भारत** और **91 अन्य देशों** में अपने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे "**मर्सनरी स्पाईवेयर**" हमले के शिकार हो सकते हैं।
- **Apple** ने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि उन पर **मर्सनरी स्पाईवेयर** द्वारा हमला किया जा रहा है जो उनके **iPhones** तक **रिमोट एक्सेस** हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

मुख्य बिंदु
- **जासूसी सॉफ़्टवेयर (स्पाइवेयर):** यह स्नीकी सॉफ़्टवेयर आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नज़र रखता है, जैसे कि आप जिन वेबसाइटों पर जाते हैं, जो चीज़ें आप टाइप करते हैं, और यहां तक कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी।

- यह आपके बिना यह जाने भी ऐसा करता है कि **स्पाइवेयर** अक्सर आपको अवांछित विज्ञापन दिखाने या यहां तक कि आपकी पहचान चुराने के लिए यह जानकारी चुरा लेता है।
- **मेलिशियस सॉफ्टवेर (मैलवेयर):** यह ब्रॉडर सॉफ़्टवेयर के लिए एक व्यापक शब्द है जो आपके कंप्यूटर को विभिन्न तरीकों से खराब कर सकता है।
- मैलवेयर में **वायरस, वॉर्म और रैंसमवेय**र जैसी सॉफ्टवेयर शामिल हो सकती हैं।
- मैलवेयर आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने, आपकी जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को ठीक से काम करने से रोकने का प्रयास कर सकता है।

सुपर स्नीकी स्पाइवेयर

- **सुपर-पावर्ड स्पाइवेयर हमला:** ये सुपर उन्नत हमले हैं जो बहुत सारे संसाधनों वाले विशिष्ट लोगों को लक्षित करते हैं।
- अधिकांश लोगों को मिलने वाले **मैलवेयर** की तुलना में वे अधिक गुप्त हैं।
- इन हमलों को बनाना महंगा है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, इसलिए ये ज्यादातर लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हैं।
- ये कुछ सबसे खतरनाक डिजिटल खतरे हैं और विशेषज्ञ अभी भी इनके बारे में सीख रहे हैं।
- **सुपर स्पाइवेयर का लक्ष्य:** यह स्पाइवेयर गुप्त रूप से आपके फोन या अन्य डिवाइस पर पहुंचने और आपकी जासूसी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह ट्रैक कर सकता है कि आप कहां जाते हैं, आप किससे बात करते हैं और आपकी **निजी जानकारी चुरा** सकते हैं।
- कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि **सरकारें** और **कानून प्रवर्तन** इस **स्पाइवेयर** का उपयोग कार्यकर्ताओं या **राजनीतिक विरोधियों** को निशाना बनाने के लिए करते हैं।

108. वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना: WTO- इकोनॉमिक टाइम्स

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व व्यापार संगठन
- मुद्रा स्फ़ीति

समाचार:

- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने एक पूर्वानुमान में कहा कि **वर्ष 2023** में संकुचन के बाद इस वर्ष **वैश्विक माल व्यापार** में धीरे-धीरे **वृद्धि** होने की उम्मीद है।
- **विश्व व्यापारिक व्यापार** की मात्रा **वर्ष 2023** में **1.2%** गिरने के बाद **वर्ष 2024** में **2.6%** और **वर्ष 2025** में **3.3%** बढ़नी चाहिए, लेकिन आगाह किया कि **क्षेत्रीय संघर्ष, भू-राजनीतिक तनाव** और **आर्थिक नीति अनिश्चितता** पूर्वानुमान के लिए पर्याप्त **नकारात्मक जोखिम** पैदा करते हैं।

विश्व व्यापार संगठन(WTO)

- **WTO** एक **अंतरराष्ट्रीय संगठन** है जो **देशों के बीच** व्यापार के लिए **नियम निर्धारित** करता है। इसकी शुरुआत **GATT** नामक एक पुराने **समझौते** से लेते हुए **वर्ष 1995** में हुई थी।
- WTO **टैरिफ और कोटेशन** जैसी बाधाओं को कम करने के लिए समझौते स्थापित करके देशों को **वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा** का व्यापार करने में मदद करता है।
- ये समझौते **सदस्य देशों** द्वारा किये जाते हैं और उनकी **सरकारों** द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।
- WTO में **164 सदस्य देश** हैं , जो लगभग **सभी वैश्विक व्यापार** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है।
- WTO **हर साल** एक **रिपोर्ट प्रकाशित** करता है जो **ट्रैक** करती है कि **दुनिया भर** में **व्यापार का संचालन** कैसा चल रहा है।
- उनकी नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि मुद्रास्फीति और अन्य मुद्दों के कारण **वर्ष 2023** में व्यापार धीमा हो गया, लेकिन **वर्ष 2024** और **वर्ष 2025** में इसके फिर से बढ़ने की उम्मीद है।
- भले ही **वर्ष 2023** में व्यापार धीमा हो गया, फिर भी यह महामारी से पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
- यात्रा और ऑनलाइन सेवाओं जैसी सेवाओं में व्यापार वास्तव में काफी अच्छा चल रहा है।
- कुल मिलाकर, WTO कठिन आर्थिक समय के दौरान भी **देशों के बीच व्यापार** को **सुचारू** रूप से चलाने में मदद करता है।

109. भारत को विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सरल टैरिफ नीति की आवश्यकता है: ADB

प्रीलिम्स टेकअवे
- एशियाई विकास बैंक
- टैरिफ बाधाएँ

समाचार:
- **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ने कहा कि **भारत** को अपनी **टैरिफ नीति** को सरल बनाने, अपनी व्यापार **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने** और **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं** के साथ अपने **'सीमित' एकीकरण** को दूर करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है।
- इसने इस बात पर भी जोर दिया कि यह उसके **विनिर्माण क्षेत्र** के लिए विशेष रूप से जरूरी है, जो मध्यम **अवधि में विकास पथ** को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु
- **भारत** की **विकास रणनीति पर्याप्त निर्यात वृद्धि** पर आधारित थी जिसे **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं** में एकीकरण के माध्यम से हासिल किया जा सकता था।
- **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ने अपनी **एशिया डेवलपमेंट आउटलुक** रिपोर्ट में कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित **वर्ष 2030** तक **2 ट्रिलियन डॉलर** के निर्यात लक्ष्य में काफी वृद्धि की आवश्यकता होगी।

'लॉजिस्टिक्स इन्फ्रा में सुधार'
- **"व्यापार और लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना** में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों के साथ-साथ एक **सरलीकृत टैरिफ नीति** की आवश्यकता है

एशियाई विकास बैंक (ADB)
- इसकी स्थापना **वर्ष 1966** में हुई थी, इसका मुख्य **कार्यालय मनीला (फिलीपींस)** में था। इसमें **एशिया प्रशांत क्षेत्र** से **67 सदस्य** हैं।
- इस बैंक को **विश्व बैंक** की तर्ज पर बनाया गया था।
- **ADB** में **15.677%** के साथ **जापान** की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसके बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका (15.567%), चीन (6.473%)** और **भारत (5.812%)** का स्थान है।
- **ADB** का उद्देश्य **समावेशी विकास, सतत विकास** और **क्षेत्रीय एकीकरण** के साथ **एशिया प्रशांत** में गरीबी को कम करके **सामाजिक विकास** करना है।
- यह **सार्वजनिक क्षेत्र** में **80% निवेश के माध्यम** से किया जाता है।
- **ADB आधारभूत संरचना** , स्वास्थ्य, **सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली** में निवेश करता है, जिससे राष्ट्रों को **जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव को कम करने और **प्राकृतिक संसाधनों** का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत
- भारत ने **वर्ष 1986** में **ADB** की सहायता लेना शुरू किया।
- **एशियाई विकास बैंक** का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में **भारत का समर्थन** करना है
  - औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता
  - रोजगार सृजन
  - कम आय वाले राज्यों की विकास गति में तेजी
  - पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन चुनौतियाँ

110. IPC ने प्रतिकूल प्रभाव को लेकर दर्दनिवारक दवा निमेसुलाइड पर अलर्ट जारी किया- इकोनॉमिक टाइम्स

प्रीलिम्स टेकअवे
- IP रिफरेन्स सब्सटेंस (IPRS)
- निमेसुलाइड (nimesulide)

समाचार:
- **फार्मा मानक** निकाय **भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC)** ने **निमेसुलाइड** पर **दवा सुरक्षा चेतावनी** जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह **गोली त्वचा** पर **चकत्ते (दवा का फटना)** पैदा कर सकती है।
- इसने **उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल** पेशेवरों से दवा के उपयोग की बारीकी से निगरानी करने और **IPC** के **भारत** के राष्ट्रीय समन्वय **केंद्र-फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम** को किसी भी **प्रतिकूल प्रतिक्रिया** की रिपोर्ट करने के लिए कहा है ।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग:
- भारत सरकार के **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** का एक स्वायत्त संस्थान है ।
- इसे देश में **दवाओं के मानक तय** करने के लिए बनाया गया है।

- इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित **बीमारियों** के इलाज के लिए आमतौर पर **आवश्यक दवाओं** के **मानकों को नियमित** रूप से **अद्यतन** करना है।
- यह **भारतीय फार्माकोपिया (IP)** के रूप में नए जोड़ने और मौजूदा **मोनोग्राफ** को **अद्यतन** करने के माध्यम से **दवाओं की गुणवत्ता** में सुधार के लिए **आधिकारिक दस्तावेज** प्रकाशित करता है।
- यह **नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया** को प्रकाशित करके **जेनेरिक दवाओं** के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- यह **मनुष्यों** और **जानवरों** के **स्वास्थ्य देखभाल** के **दृष्टिकोण** से आवश्यक दवाओं की **पहचान, शुद्धता** और **ताकत** के लिए मानक निर्धारित करता है।
- यह **IP रिफरेन्स सब्सटेंस (IPRS)** भी प्रदान करता है जो **परीक्षण** के तहत किसी **वस्तु की पहचान** और **IP** में निर्धारित उसकी **शुद्धता के लिए फिंगरप्रिंट** के रूप में कार्य करता है।

111. भारत की महत्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना का 80% काम पूरा हुआ - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- रेलवे
- DFC

समाचार:
- भारत का महत्वाकांक्षी **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) 80% पूरा हो चुका है** , रेलवे ने इसे अंतिम रूप देने का लक्ष्य **जून 2024** तक रखा है।
- इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव **18 साल** पहले रखी गई थी, लेकिन **वर्तमान सरकार** के तहत इसमें अधिक **पूंजीगत व्यय** और **निर्माण** की गति देखी गई है।
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**, एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर, **भारत** के लिए एक **गेमचेंजर** साबित होगा क्योंकि वर्तमान में **मालगाड़ियाँ आम रेल लाइनों** पर **यात्री ट्रेनों** के साथ-साथ चलती हैं, जो कि तेजी से बढ़ती **अर्थव्यवस्था** के लिए एक **आदर्श स्थिति** नहीं है, जिसका लक्ष्य एक **औद्योगिक महाशक्ति** बनना है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर:
- यह एक **उच्च गति** और **क्षमता** वाला **रेलवे कॉरिडोर** है जो विशेष रूप से **माल** (माल और वस्तुओं) के **परिवहन** के लिए है।
- DFC में बेहतर **आधारभूत संरचना** का **निर्बाध एकीकरण** शामिल है
- **रेल मंत्रालय** ने **दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** (DFC) अर्थात **लुधियाना से सोननगर (1337 किमी)** तक **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** और **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT)** से **दादरी (1506 किलोमीटर)** तक **वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)** का निर्माण शुरू किया है।
- **EDFC** का निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है और **WDFC** के 1506 किलोमीटर में से **1220 किलोमीटर** का काम पूरा हो चुका है और पूरे हो चुके खंडों पर ट्रेन परिचालन जारी है।
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए, **सरकार** ने समय पर धन का प्रावधान किया है और **राज्य सरकारों** के साथ **सीधे और विभिन्न मंचों** यानी **प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG)** आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय करके परियोजना **भूमि अधिग्रहण गतिविधियों** की निगरानी की है।
- एक बार जब **DFC** के सभी खंड पूरे हो जाएंगे, तो **दिल्ली-मुंबई** की अवधि कम होकर **48 घंटे** हो जाएगी।
- अभी तक मालगाड़ी की **औसत गति 20 से 25 किमी प्रति घंटा** है। **DFC** के साथ यह **60 किमी प्रति घंटे** तक हो जाएगी।
- **राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030-** लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 3,600 मिलियन टन (MT) कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए लॉजिस्टिक्स बाजार में रेल की मॉडल हिस्सेदारी को 40% -45% तक बढ़ाना है।
- **पीएम गति शक्ति-** रेलवे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रमुख चालकों में से एक है।
- रेल **मंत्रालय** ने **रेलवे बोर्ड** में एक बहु-विषयक गति **शक्ति निदेशालय** की स्थापना की है।
- सभी **68 डिविजनों** में **गति शक्ति इकाइयां** भी बनाई गई हैं।
- **पीएम गति** शक्ति **राष्ट्रीय मास्टर प्लान** ने **परियोजनाओं** की **शीघ्र मंजूरी, कार्यों** के **निष्पादन की निगरानी** और **अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों** के साथ समन्वय में मदद की है।

112. आयातित मुद्रास्फीति: आयात लागत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकती है- द हिंदू

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- मुद्रा स्फ़ीति
- अपस्फीति

- **आयातित मुद्रास्फीति** से तात्पर्य किसी देश में **वस्तुओं और सेवाओं** की कीमतों में वृद्धि से है जो देश में **आयात की कीमत** या **लागत में वृद्धि** के कारण होती है।
- ऐसा माना जाता है कि **इनपुट लागत** में वृद्धि उत्पादकों को अपने **स्थानीय ग्राहकों** से ली जाने वाली कीमत बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे **मुद्रास्फीति** बढ़ती है।

रुपये में गिरावट

- किसी **देश की मुद्रा** के **मूल्य** में **गिरावट** को आम तौर पर किसी **अर्थव्यवस्था** में **आयातित मुद्रास्फीति** के सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी देश की मुद्रा का मूल्यह्रास होता है तो -
  - देश के लोगों को किसी भी विदेशी सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा का अधिक भुगतान करना होगा।
  - जिसका अर्थ यह होगा कि वे प्रभावी रूप से किसी भी चीज के लिए अधिक भुगतान करेंगे जो वे आयात करते हैं।
- **एशियाई विकास बैंक** ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि **भारत** को **आयातित मुद्रास्फीति** का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि **पश्चिम** में **ब्याज दरों** में वृद्धि के बीच **रुपये में गिरावट** आ सकती है।
- **पश्चिम** में **ब्याज दरों** में वृद्धि से **विकासशील देशों** की मुद्राओं का **पश्चिमी मुद्राओं** के मुकाबले **मूल्यह्रास** हो जाता है
  - जिसके परिणामस्वरूप इन देशों के लिए **आयात लाग**त बढ़ सकती है।
- आगे यह तर्क दिया जा सकता है कि जब मुद्रा के **मूल्यह्रास** के कारण **आयात** लागत बढ़ती है, तब भी लागत में वृद्धि अंततः उ**पभोक्ताओं** के बीच अंतिम **आउटपुट** की मांग से प्रेरित होती है।
- दूसरे शब्दों में, **स्थानीय मुद्रा** के संदर्भ में **विदेशी मुद्रा** की **अधिक** मांग को **प्रतिबिंबित** करने के लिए **मुद्रा** की **विनिमय दर** में गिरावट आती है।
- इसलिए, **मूल्यह्रास** के कारण **आयात** लागत में वृद्धि को केवल **इनपु**ट की नाममात्र मांग में बदलाव के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है।
- सीधे शब्दों में कहें तो, यह मुद्रा का **मूल्यह्रास** नहीं है जिसके कारण **इनपुट लागत और अंतिम वस्तुओं** की कीमतें बढ़ रही हैं
  - बल्कि, मुद्रा का **मूल्यह्रास** केवल अंतिम **उपभोक्ताओं** से **आयातित वस्तुओं** की **उच्च नाममात्र मांग** का प्रतिबिंब है।

113. छोटे पैमाने के किसान खेतों पर पेड़ों से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ? - द हिंदू

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- कृषि वानिकी नीति
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- **कृषिवानिकी** का उपयोग **मध्यम या बड़ी जोत** वाले **किसानों** तक ही सीमित है।
- समस्या प्रासंगिक बनी हुई है और विशेष रूप से **छोटे भूमि धारकों** के लिए गंभीर है, जिन्हें **पानी सुरक्षित** करने के लिए **अतिरिक्त धन** की आवश्यकता होती है और ऐसा करने में उन्हें **अतिरिक्त कर्ज** उठाना पड़ता है।

मुख्य बिंदु

- **कृषि** एक विविध **भूमि-उपयोग** अभ्यास है, जिसमें **फसलों, पेड़ों और पशुधन** को **एकीकृत** किया जाता है, इस **तकनीक** को **मोटे** तौर पर **कृषि वानिकी** कहा जाता है।
- यह किसानों की **आजीविका और पर्यावरण** को बढ़ा सकता है और **हरित क्रांति** से प्रेरित **मोनोक्रॉपिंग** के दशकों के बाद धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
- **कृषि मंत्रालय** ने **वर्ष 2014** में **राष्ट्रीय कृषिवानिकी नीति** का **मसौदा** तैयार करते समय पानी की उपलब्धता को एक चुनौती के रूप में मान्यता दी।
- इसके अलावा, **पौधे** के उगने के **चरण** के दौरान **पानी** की **उपलब्धता** महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर पानी की कमी वाले **वातावरण** में **पेड़ पानी** के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो यह **लगातार चिंता** का विषय बना रहता है।
- इस बाधा को दूर करने का एक **तरीका** ऐसे पेड़ उगाना है जो पानी के लिए **फसलों से प्रतिस्पर्धा** न करें।
- हालाँकि, **किसान** उन **पेड़ प्रजातियों** की ओर **आकर्षित हो**ते हैं जो तेजी से बढ़ती हैं और **शाकाहारी जीवों** को दूर भगाती हैं

- लेकिन ऐसी **प्रजातियाँ** भी आम तौर पर **गैर-देशी** होती हैं और मिट्टी के **स्वास्थ्य और मानव कल्याण** के लिए **खतरा** होती हैं।

- **भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना 2023**, जो **कृषि वानिकी और लकड़ी-आधारित उत्पादों** को सतत के रूप में प्रमाणित करती है, में **किसानों और उद्योगों** के लिए **पात्रता मानदंडों** की एक विस्तृत सूची है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति:

- यह **उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता** और **पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता** को बढ़ाता है।
- यह देश की लगभग आधी ईंधन की प्लाईवुड लकड़ी की 70-80%, जरूरतों को पूरा करता है।
  - पेपर पल्प उद्योग के लिए 60% कच्चा माल ,
  - हरे चारे की 9-11%
- **कृषि वानिकी** या **वृक्ष-आधारित खेती 2.5** से **3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड** के अतिरिक्त **कार्बन सिंक** के रूप में **कार्बन पृथक्करण** में सहायता कर सकती है।
- **सामान्य मिट्टी** की तुलना में **वन-प्रभावित मिट्टी में फसलों** की अधिक पैदावार देखी गई है।

कृषि वानिकी में सुधार के कदम -

- सभी **छोटे भूमिधारकों, किसान समूहों-सहकारिताओं**, **FPO** को **वित्तीय सहायता प्रदान** की जानी चाहिए।
- **भूमि उपयोग** और **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन** से संबंधित **सभी नीतियों** में **कृषि वानिकी** को शामिल करना।
- स्थान विशेष पर उगाए जाने वाले और अपनाए जाने वाले पेड़ों पर **वैज्ञानिक अनुसंधान** करना।

114. भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए स्थायी समाधान चाहता है- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व व्यापार संगठन
- कृषि पर समझौता

समाचार :

- **WTO** में भारत **MSP** जैसे **कार्यक्रमों को सुचारू** रूप से चलाने के लिए **सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग सब्सिडी** के लंबे समय से लंबित **स्थायी समाधान** पर काम करना चाहता था।
- अबू धाबी में हाल ही में हुआ **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन परिणाम** देने में विफल रहा।

मुख्य बिंदु

- WTO में **कृषि समिति (CoA)** की बैठक में , **नई दिल्ली** ने जोर देकर कहा कि **सदस्यों को सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग** पर **G33-अफ्रीकी समूह -ACP** समूह द्वारा दिए गए **संयुक्त** प्रस्ताव पर फिर से विचार करना चाहिए।
- **MC13** में **सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग** पर **स्थायी समाधान** पर सहमति नहीं बन सकी।
- **सदस्यों** को **वर्ष 2013 बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय** के बाद से लंबित मामले पर **जनादेश** का **तत्काल सम्मान** करना चाहिए
- शांति खंड **कठिन परिस्थितियों** और कठिन **अधिसूचना आवश्यकताओं** से ग्रस्त है।

पीस क्लॉज (शांति खंड)-

- ऐसा माना जाता है कि **उच्च सब्सिडी वैश्विक व्यापार** को विकृत कर रही है।
- **पीस क्लॉज (शांति खंड)** एक **विकासशील देश** के **खाद्य खरीद कार्यक्रमों** को **सब्सिडी सीमा** का उल्लंघन होने पर **WTO सदस्यों** की कार्रवाई से बचाता है।
- **भारत** और अन्य **विकासशील देशों** के मामले में यह **सीमा खाद्य उत्पादन** के **मूल्य का 10% (**जिसे D मिनिमिस कहा जाता है) आंकी गई है।

विश्व व्यापार संगठन-कृषि समझौता:

- यह **घरेलू सब्सिडी** में कटौती का आह्वान करता है जो कृषि उद्योग में **मुक्त व्यापार और उचित मूल्य** को विकृत करता है।
- समर्थन के **समग्र मापन (AMS)** को **6 वर्षों** की अवधि में **20%** और **विकासशील देशों** द्वारा **10 वर्षों** की अवधि में **13%** कम किया जाना है।

सब्सिडी को निम्न में वर्गीकृत किया गया है:

ग्रीन बॉक्स : ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती है, या अधिकतम न्यूनतम विरूपण का कारण बनती है।

- ये **सरकार** द्वारा **वित्त पोषित** हैं और उनमें **मूल्य समर्थन** शामिल नहीं होना चाहिए।

- **पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम** भी शामिल हैं ।
- इसलिए **ग्रीन बॉक्स सब्सिडी** बिना किसी सीमा के अनुमत है।

एम्बर बॉक्स:

- **उत्पादन और व्यापार** को विकृत करने वाले सभी **घरेलू समर्थन** उपाय **एम्बर बॉक्स** में आते हैं, उदाहरण के लिए भारत में **MSP** को **एम्बर बॉक्स** के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ब्लू बॉक्स:

- यह **शर्तों वाला एम्बर बॉक्स** है ऐसी स्थितियाँ **उत्पादन** को **सीमित** करके और निर्दिष्ट **कोटा रखकर विकृति** को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- वर्तमान में **ब्लू बॉक्स सब्सिडी** पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।

115. वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ने का अनुमान: UNCTAD - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNCTAD
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

समाचार:

- **संयुक्त राष्ट्र** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2024** में भारत की **अर्थव्यवस्था 6.5%** बढ़ने का अनुमान है

मुख्य बिंदु

- इसमें कहा गया है कि **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ** अपनी **आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता** लाने के लिए देश में अपनी **विनिर्माण प्रक्रियाओं** का विस्तार कर रही हैं, इससे **भारतीय निर्यात** पर **सकारात्मक प्रभाव** पड़ेगा।
- **वर्ष 2023** में विस्तार मजबूत **सार्वजनिक निवेश परिव्यय** के साथ-साथ **सेवा क्षेत्र** की जीवंतता से प्रेरित था
  - अंकटाड ने कहा, "उपभोक्ता सेवाओं के लिए मजबूत स्थानीय मांग और देश की व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के लिए मजबूत बाहरी मांग से लाभ हुआ।"

UNCTAD

- विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास-अनुकूल एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** (UNCTAD) की **स्थापना 1964 में की गई थी।**
- **UNCTAD** एक स्थायी **अंतरसरकारी निकाय** है जिसका **मुख्यालय स्विट्जरलैंड** के **जिनेवा** में है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टें हैं:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट
  - विश्व निवेश रिपोर्ट
  - सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट
  - सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट
  - वस्तुएँ और विकास रिपोर्ट

116. IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां खरीदने हेतु आयु सीमा को समाप्त किया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- IRDAI
- बीमा ट्रिनिटी

समाचार:

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDAI) ने **स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां** खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी है।

मुख्य बिंदु:

- **नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी** खरीदने के लिए **65 वर्ष** की **आयु सीमा** थी ।
- इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विस्तारित स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है
  - बच्चों और मातृत्व आवश्यकताओं सहित विविध जनसांख्यिकीय समूहों को पूरा करना है।

- **कंपनियों** को अधिक **समावेशी स्वास्थ्य** देखभाल **पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देने, **विशिष्ट आयु-संबंधित** आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप उत्पाद विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

IRDAI:

- यह **IRDA अधिनियम 1999** के तहत एक **वैधानिक निकाय** है और **वित्त मंत्रालय** के **अधिकार क्षेत्र** में है ।
- यह बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई एक **नियामक संस्था** भी है।
- **भारतीय बीमा विनियामक** और **विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने **वर्ष 2047** तक अपने 'सभी के लिए बीमा' के विज़न में , भारत में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए **प्रत्येक बीमाकर्ता को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** आवंटित किए हैं।
- **IRDAI बीमा गतिविधियों** को बेहतर बनाने के लिए **सामान्य** और **जीवन बीमा कंपनियों** के साथ मिलकर बीमा **ट्रिनिटी बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक लॉन्च** करने की भी योजना बना रहा है।
- **बीमा सुगम:** यह बीमाकर्ताओं और वितरकों के लिए एक एकीकृत मंच है। यह पॉलिसी खरीद, सेवा अनुरोध और दावों के निपटान को सरल बनाता है
- **बीमा विस्तार** : यह एक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है, त्वरित दावा भुगतान सुनिश्चित करती है।
- **बीमा वाहक:** यह ग्राम सभा स्तर पर कार्यरत एक महिला-केंद्रित कार्यबल है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23:

- **भारत** का **बीमा बाजार** आने वाले दशक में **वैश्विक स्तर** पर सबसे तेजी से बढ़ते **बाजारों** में से एक बनकर उभरने की ओर अग्रसर है।
- **IRDAI** के अनुसार**, भारत में बीमा प्रवेश वर्ष 2019-20** में **3.76%** से बढ़कर **वर्ष 2020-21** में **4.20%** हो गया, जिसमें **11.70%** की वृद्धि दर्ज की गई।

बीमा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

- पूर्ण डिजिटलीकरण की आवश्यकता
- लोगों में गोद (दतक) लेने की दर कम होना
- क्लेम्स प्रोसेस धीमी

117. FSSAI भारत में बिकने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेगा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे

- इथिलीन ऑक्साइड
- FSSAI

समाचार:

- **हांगकांग और सिंगापुर** में **अधिकारियों** द्वारा **एथिलीन ऑक्साइड** के **उच्च स्तर** का पता चलने के बाद भारत के **दो शीर्ष मसाला निर्माताओं** से **चार मसाला मिश्रण वापस** लेने का आदेश दिए जाने के बाद, **FSSAI** ने **राज्यों** से **ब्रांडेड मसालों** का **परीक्षण** करने को कहा है।

मुख्य बिंदु:

- **एथिलीन ऑक्साइड** की उपस्थिति के लिए सभी **ब्रांडों** के **मसाला मिश्रणों** के **नमूनों का परीक्षण** किया जाएगा, नियमों के अनुसार **खाद्य उत्पादों** में इस यौगिक की अनुमति नहीं है।
- **खाद्य नियामक** ने यह जांचने के लिए **शिशु फार्मूला के नमूने एकत्र करना भी शुरू कर दिया है** कि वे भारतीय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
    - यह बात तब सामने आई है जब एक **अंतरराष्ट्रीय संस्था** ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि **खाद्य** और **पेय पदार्थ** की **दिग्गज कंपनी नेस्ले दक्षिण एशियाई, अफ्रीकी** और **लैटिन अमेरिकी** देशों में **उच्च शुगर सामग्री वाला बेबी फॉर्मूला** बेच रही थी।
- **FSSAI** ने कहा था कि **भारत** से **नमूनों** की लैब रिपोर्ट मांगी जाएगी और जांच के लिए मौजूदा, **इन-हाउस** विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जाएगी।
    - अधिकारियों के मुताबिक, **मसालों** पर एक **समेकित रिपोर्ट 25 दिनों** में आने की संभावना है।

इथिलीन ऑक्साइड:

- एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है
- इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है।
- यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील गैस है।
- यह एक स्पष्ट रंगहीन गैस के रूप में दिखाई देती है
- यह पानी में आसानी से घुल सकता है।
- इसका उपयोग भंडारित कृषि उत्पादों में कीटनाशक के रूप में और चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज़ करने के लिए किया जाता है।
- इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) द्वारा एथिलीन ऑक्साइड को समूह -1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - एथिलीन ऑक्साइड के लगातार संपर्क से त्वचा, आंखों, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है।

FSSAI :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक **स्वायत्त वैधानिक निकाय** है।
- FSSAI **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** के अंतर्गत आता है और इसका **मुख्यालय दिल्ली** में है।
- FSSAI की जिम्मेदारी में **FSS अधिनियम, 2006** का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।
- **खाद्य सुरक्षा विभागों** के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली **निगरानी, निगरानी, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने** के आधार पर किया जाता है।

118. नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 का अनावरण किया- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- नाबार्ड
- ग्रीन क्रेडिट

समाचार:

- **राष्ट्रीय कृषि** और **ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** ने **पृथ्वी दिवस** के अवसर पर अपने **जलवायु रणनीति 2030** दस्तावेज़ का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य **भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग** की आवश्यकता को संबोधित करना है।
- भारत को **वर्ष 2030** तक **2.5 ट्रिलियन डॉलर** से अधिक की **कुल संचयी राशि** तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग **170 बिलियन डॉलर** की आवश्यकता है , वर्तमान **ग्रीन फाइनेंस** प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है।

मुख्य बिंदु:

- **वर्ष 2019-20** में, भारत ने **ग्रीन फाइनेंसिंग** में लगभग **49 बिलियन डॉलर** जुटाए, जो कि जरूरत का एक अंश मात्र है।
- **शमन** के लिए निर्धारित अधिकांश **धनराशि, अनुकूलन और लचीलेपन के** लिए केवल **$5 बिलियन** आवंटित की गई थी।
- **बैंक योग्यता** और **वाणिज्यिक व्यवहार्यता** में चुनौतियों के कारण इन क्षेत्रों में **निजी क्षेत्र** की भागीदारी न्यूनतम है।

नाबार्ड जलवायु रणनीति 2030:

- **नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030** में निम्नलिखित **चार प्रमुख स्तंभों** शामिल हैं:
    - सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना
    - व्यापक बाज़ार-निर्माण भूमिका निभाना
    - आंतरिक हरित परिवर्तन और
    - सामरिक संसाधन जुटाना।

नाबार्ड:

- यह **राष्ट्रीय कृषि** और **ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981** द्वारा अस्तित्व में आया।
- **बी शिवरामन समिति** के आधार पर, **नाबार्ड** ने **भारतीय रिजर्व बैंक** के **कृषि ऋण विभाग (ACD)** और **ग्रामीण योजना** और **क्रेडिट सेल (RPCC)** का स्थान ले लिया।
- नाबार्ड विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों (CB) की ग्रामीण विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है।
- **ईशक्ति : "ईशक्ति"** भारत में **स्वयं सहायता समूह (SHG)** के सभी सदस्यों के **डिजिटलीकरण** के लिए नाबार्ड द्वारा विकसित एक परियोजना है।

- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** नाबार्ड द्वारा किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **जनजातीय विकास कार्यक्रम:** एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसका लक्ष्य देश के जनजातीय परिवारों को स्थायी आजीविका प्रदान करना है।

नाबार्ड के कार्य:

- ऋण प्रवाह में छोटे बैंकों का पर्यवेक्षण करता है।
- **सतत विकास:** प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम जिसमें वाटरशेड विकास, जनजातीय विकास और फार्म नवाचार जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।
- **ग्रामीण नवाचार का समर्थन करना:** यह ग्रामीण नवाचार, अपरंपरागत कृषि पद्धतियों के लिए धन आकर्षित करने में कामयाब रहा है
- किसी **परियोजना** की **निगरानी और मूल्यांकन** करना इसकी जिम्मेदारी **ग्रामीण क्षेत्र** में होने वाली **परियोजना या गतिविधि** की **निगरानी और मूल्यांकन** करना है।
- **ग्रामीण अवसंरचना निधि:** ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- **वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (WIF)** : नाबार्ड की सुविधाओं का उपयोग करते हुए, देश में कृषि वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए ऋण दिया जाता है।

119. PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिली - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- UPI
- RBI

समाचार:

- **फिनटेक** फर्म **PayU** को **पेमेंट एग्रीगेटर** के रूप में काम करने के लिए **रिजर्व बैंक** से **सैद्धांतिक मंजूरी** मिल गई है।
- **सैद्धांतिक** मंजूरी के साथ, **PayU** अब नए **व्यापारियों** को **डिजिटल भुगतान** सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकता है।

पेमेंट एग्रीगेटर

- ऑनलाइन **पेमेंट एग्रीगेटर** ऐसी कंपनियां हैं जो **ग्राहक और व्यापारी** के बीच **मध्यस्थ** के रूप में कार्य करके **ऑनलाइन** भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।
- **RBI** ने **मार्च 2020** में **PA** और **पेमेंट गेटवे** को **विनियमित** करने के लिए **दिशानिर्देश** पेश किए।
- ये आम तौर पर **ग्राहकों** को **क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण** और **ई-वॉलेट** सहित कई प्रकार के भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं।
- **पेमेंट एग्रीगेटर भुगतान** जानकारी एकत्र और संसाधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेनदेन **सुरक्षित** और **विश्वसनीय** हैं।
- **पेमेंट एग्रीगेटर** का उपयोग करके, व्यवसाय अपने स्वयं के **भुगतान प्रसंस्करण सिस्टम** को स्थापित करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता से बच सकते हैं
  - जो जटिल और महंगा हो सकता है.
- **पेमेंट एग्रीगेटर्स** के कुछ उदाहरणों में **पेपाल, स्ट्राइप, स्क्वायर** और **अमेज़ॅन पे** शामिल हैं।

120. RBI डेटा: REITs, InvITs ने चार वर्षों में ₹1.3 लाख करोड़ जुटाए - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- REIT एवं INVIT
- SEBI

समाचार:

- **रियल्टी** और **आधारभूत संरचना** क्षेत्र **REITs** और **InvITs** के निवेश वाहनों ने पिछले **चार वर्षों** में **₹1.3 लाख** करोड़ जुटाए हैं।
- **RBI बुलेटिन** में **केंद्रीय बैंक** ने कहा कि उनसे अधिक **एकत्रित धन** की सुविधा की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- **REIT और InvIT** विशेष रूप से **उच्च निवल मूल्य** वाले **व्यक्तियों** के लिए **वैकल्पिक निवेश साधन** के रूप में उभर रहे हैं।

- **RBI ने 'स्टेट ऑफ इकोनॉमी'** में लिखा है की , ''भारत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को देर से अपनाने वाला देश रहा है।''

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(IIT):

- **InvITs म्यूचुअल फंड** के समान एक निवेश योजना है, जो **व्यक्तिगत** और **संस्थागत निवेशकों** से **इंफ्रास्ट्रक्चर** की **परियोजनाओं** में धन के सीधे निवेश को आय का एक **छोटा हिस्सा रिटर्न** के रूप में अर्जित करने में सक्षम बनाती है।
- **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)** के माध्यम से **स्टॉक** की तरह ही **InvIT** को **एक्सचेंजों** पर सूचीबद्ध किया जाता है ।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित।

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट:

- **निवेश योग्य निधियों** को **आय-उत्पादक अचल संपत्ति** के **संचालन**, **स्वामित्व या वित्तपोषण** में लगाने के लिए बनाई गई इकाई है।
- **REIT** को **म्यूचुअल फंड** की तर्ज पर तैयार किया गया है और यह **निवेशकों** को **रियल एस्टेट** में हिस्सेदारी पाने के लिए बेहद तरल तरीका प्रदान करता है।

REIT और INVIT सूचकांक:

- **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया** की सहायक कंपनी **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड** द्वारा लॉन्च किया गया है।
- सूचकांक का लक्ष्य **Reits** और **InvIT** के **प्रदर्शन** को **ट्रैक** करना है जो **NSE** पर **सार्वजनिक** रूप से सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं।
- **सूचकांक** के भीतर **प्रतिभूतियों** का भार उनके **फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण** पर आधारित होता है।

SEBI

- **भारतीय प्रतिभूति** और **विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992** के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया।
- समारोह:
  - प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना।

121. इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और कैसे काम करता है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे

- एस्टेट ड्यूटी
- आय असमानता

समाचार:

- **आय असमानता** को दूर करने के लिए **धन के पुनर्वितरण** के लिए एक **उपकरण** के रूप में **इनहेरिटेंस टैक्स** के **उपयोग** पर **व्यापक** रूप से **चर्चा** की गई है। पिछले कुछ वर्षों में, **भारत** ने **एस्टेट ड्यूटी, संपत्ति टैक्स** को समाप्त कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **आय असमानता** को दूर करने के लिए **धन के पुनर्वितरण** के एक **उपकरण** के रूप में **इनहेरिटेंस टैक्स** के उपयोग पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।
- **विश्व स्तर** पर अधिक **न्यायसंगत समाज** बनाने के लिए **अरबपतियों** पर टैक्स लगाने की मांग जोर-शोर से बढ़ रही है।
- अमेरिका **100 मिलियन डॉलर** से **अधिक संपत्ति** वाले **करदाताओं** पर **न्यूनतम 25% टैक्स** लगाएगा।
- **फ़्रांस और ब्राज़ील** ने **अत्यधिक अमीरों** पर **टैक्स** लगाने के लिए **G20 घोषणा** पर ज़ोर दिया है।

आय असमानता

- **ऑक्सफैम** द्वारा किए गए एक **सर्वेक्षण** के अनुसार, **भारत** की **कुल संपत्ति** का **58 प्रतिशत हिस्सा** इसकी एक **प्रतिशत आबादी** के भीतर केंद्रित है।
- यह **वैश्विक औसत** लगभग **50 प्रतिशत** से अधिक है ।
- इस **असमानता** को दूर करने के लिए, क्योंकि **भारत** एक **कल्याणकारी राज्य** है, और निचले तबके के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए **संवैधानिक** रूप से बाध्य है।

एस्टेट ड्यूटी:

- **भारत** में एक समय **विरासत** (या मृत्यु) कर था।
- **टैक्स** , जिसे **एस्टेट ड्यूटी** के रूप में जाना जाता था, **वर्ष 1953** में पेश किया गया था और **वर्ष 1985** में समाप्त कर दिया गया था।

- यह आर्थिक असमानता को कम करने का एक प्रयास था।
- आज, **अमेरिका**, **ब्रिटेन**, **फ्रांस**, **जापान** और **नीदरलैंड** जैसे कई **विकसित देशों** में **इनहेरिटेंस टैक्स कानून** लागू हैं।
- **इनहेरिटेंस टैक्स** की वसूली मुख्य रूप से **उद्यमशील मानव पूंजी** और **विदेश** जाने वाले **वित्तीय संसाधनों के बहिर्वाह** के बारे में आशंकाओं के इर्द-गिर्द है।

धन और गिफ्ट टैक्स

- **संपत्ति टैक्स** किसी **व्यक्ति** की पर लगाया जाता है में, **संपत्ति टैक्स अधिनियम 1957** में पेश किया गया था और **वर्ष 2015** में निरस्त कर दिया गया था।
- यह मूल रूप से उस वर्ग के लिए है जो एक **निश्चित सीमा (30 लाख)** से अधिक अमीर है और **सीमा** से अधिक राशि पर **संपत्ति टैक्स (1%)** के लिए पात्र है।
- इसी तरह, एक **वित्तीय वर्ष** में **50,000 रुपये** से अधिक प्राप्त उपहारों पर **गिफ्ट टैक्स** लगाया जाता है, जिसे अन्य स्रोतों से आपकी **आय** में जोड़ा जाएगा और आपके **स्लैब** के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

122. यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु SFB की कीमत 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए: RBI - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- SFB
- CRR और SLR

समाचार:

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने कहा है कि **यूनिवर्सल बैंक** बनने के लिए **स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB)** की **न्यूनतम नेटवर्थ 1,000 करोड़** रुपये होनी चाहिए।

मुख्य बिंदु:

- **SFB** के पास **न्यूनतम पांच वर्षों** की अवधि के लिए प्रदर्शन का **संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड** होना चाहिए।
- इन बैंक के शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त **स्टॉक एक्सचेंज** में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए
- **SFB** को पिछले **दो वित्तीय वर्षों** में **शुद्ध लाभ** भी होना चाहिए
- पिछले **दो वित्तीय वर्षों** में **सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA)** और शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति **(NNPA)** क्रमशः **तीन प्रतिशत** और **एक प्रतिशत** से कम या उसके बराबर है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB)

- **भारत** में **SFB** आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी **बैंकिंग सेवाएं** और **ऋण सुविधाएं** प्रदान करने के लिए स्थापित बैंकों की एक श्रेणी है।
- जिसमें छोटे व्यवसाय के मालिक, सूक्ष्म और लघु उद्योग, किसान और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं।
- RBI द्वारा विनियमित
- **CRR और SLR** के रखरखाव की आवश्यकता सहित मौजूदा **वाणिज्यिक बैंकों** पर लागू **RBI** के सभी विवेकपूर्ण **मानदंड** और **विनियम SFB** पर भी लागू होते हैं।
- **RBI** के अनुसार, यदि कोई **SFB** एक **सार्वभौमिक बैंक** में स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, तो उसके पास **न्यूनतम 5 वर्षों** की अवधि के लिए प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
- **SFBs** के लिए न्यूनतम चुकता **वोटिंग इक्विटी पूंजी 200 करोड़** रुपये होगी
- **स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB)** को अपने कुल शुद्ध ऋण का **75% प्राथमिकता क्षेत्र** को ऋण देने के लिए आवंटित करना होता है।
- उन्हें अपनी कम से कम **25% शाखाएँ बैंक** रहित **ग्रामीण क्षेत्रों** में रखनी होंगी।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम**, **1949** और **RBI अधिनियम, 1934** द्वारा शासित।

CRR और SLR:

- **CRR** -नकद आरक्षित अनुपात, और **SLR**-वैधानिक तरलता अनुपात।
- **CRR** और **SLR** दोनों ही **अर्थव्यवस्था** में **ऋण** की उपलब्धता को **विनियमित** और **नियंत्रित** करने के लिए **केंद्रीय बैंकों** के **मौद्रिक** नीति उपकरण हैं।
- CRR में, **वाणिज्यिक बैंकों** को **केंद्रीय बैंक** के पास एक **निश्चित न्यूनतम जमा राशि (NDTL)** आरक्षित रखनी होती है।
- **SLR जमा** का **न्यूनतम प्रतिशत** है जिसे एक **वाणिज्यिक बैंक** को **नकदी, सोना** या **अन्य प्रतिभूतियों** के रूप में बनाए रखना होता है

123. वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने से निर्यात पर असर पड़ सकता है: FIEO - द हिंदू

समाचार:

- **FIEO** ने कहा कि बढ़ते **भू-राजनीतिक तनाव** से वै**श्विक मांग** पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका **भारत के निर्यात** पर असर पड़ सकता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- **FIEO**
- ब्याज समानीकरण योजना

मुख्य बिंदु:

- **रूस और यूक्रेन** के बीच जारी युद्ध के कारण **उत्पन्न अनिश्चितताओं** ने **वर्ष 2023-24 में** भारत के **आउटबाउंड शिपमेंट** को प्रभावित किया, जो **3.11%** की गिरावट के साथ **437 बिलियन डॉलर** दर्ज किया गया। **आयात** भी **8%** से अधिक घटकर **$677.24 बिलियन** हो गया।
- मांग में कमी के कारण माल का उठाव कम होगा इसलिए **विदेशी खरीदारों** को भुगतान करने में भी अधिक समय लगेगा।
  - इसके लिए लंबी अवधि के लिए फंड की जरूरत होती है
  - निर्यातकों को ब्याज सहायता सहायता की भी आवश्यकता है

FIEO:

- **सरकार** की **सर्वोच्च संस्था** ने भारत में **निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों** और **निर्यात विकास** प्राधिकरणों को मान्यता दी है।
- देश से व्यापार को बढ़ावा देने में लगे सभी **हितधारकों** के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत **सरकार** के **वाणिज्य मंत्रालय** द्वारा **वर्ष 1965** में स्थापित किया गया।
- केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और **निर्यात व्यापार सुविधा** में लगे सभी लोगों के साथ **भारत** के **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय** के बीच महत्वपूर्ण **इंटरफ़ेस** प्रदान करता है।
- यह **प्रत्यक्ष** और **अप्रत्यक्ष** रूप से देश के **प्रत्येक उद्योग** और **सेवा क्षेत्र** के **200,000** से अधिक निर्यातकों के हितों की पूर्ति करता है।

ब्याज समकरण योजना:

- **भारत सरकार** ने **पात्र निर्यातकों** के लिए **प्री** और **पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट** पर **ब्याज समानीकरण** योजना की घोषणा की थी।
  - यह योजना **वर्ष 2015** में शुरू की गई थी और शुरू में यह **5 वर्षों** के लिए वैध थी।
  - इसके बाद भी इस योजना को जारी रखा गया है, जिसमें **कोविड** के दौरान एक साल का विस्तार और आगे के विस्तार और फंड आवंटन शामिल हैं।
- यह योजना चिन्हित क्षेत्रों के **निर्यातकों** और **MSME विनिर्माता निर्यातकों** को **शिपमेंट पूर्व** और **शिपमेंट पश्चात रुपया निर्यात ऋण** पर **प्रतिस्पर्धी दरों** का लाभ उठाने में मदद करती है।
- वर्तमान में यह योजना **2%** की दर से **ब्याज समकारी लाभ** प्रदान करती है।
- यह योजना निधि तक सीमित नहीं थी तथा इसका लाभ बिना किसी सीमा के सभी निर्यातकों को दिया गया।
- इस योजना को अब निधि सीमित कर दिया गया है, तथा व्यक्तिगत निर्यातकों को प्रति **IEC (आयात निर्यात** कोड) के तहत प्रति वर्ष **10 करोड़ रुपये** तक का लाभ दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, जो **बैंक निर्यातकों** को **रेपो + 4%** से अधिक की **औसत दर** पर ऋण देते हैं, उन्हें भी इस योजना के **अंतर्गत प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा।

INTERNATIONAL RELATION

124. IP: अमेरिका ने भारत को 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया -द हिंदू

समाचार:

- **अमेरिका** ने **भारत** को एक बार फिर **देशों** की '**प्रायोरिटी वॉच लिस्ट** ' में शामिल किया है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- ट्रिप्स (TRIPS)
- विशेष रिपोर्ट 301

- **आईपी सुरक्षा** और प्रवर्तन से संबंधित **कथित समस्याओं** के लिए **चीन, रूस, वेनेजुएला** और **तीन अन्य** के साथ, आने वाले वर्ष के दौरान इस मामले पर विशेष रूप से **गहन द्विपक्षीय भागीदारी** होगी।

मुख्य बिंदु:

- **ट्रेडमार्क उल्लंघन जांच** और **पूर्व-अनुदान विरोध कार्यवाही** के मुद्दों को संबोधित करने में **अमेरिका -भारत व्यापार नीति फोरम** के तहत प्रगति हुई है।
- **अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि** की विशेष **301 रिपोर्ट** के अनुसार, कई लंबे समय से चली आ रही चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **अपर्याप्त IP** प्रवर्तन, जिसमें **ऑनलाइन चोरी** की **उच्च दर** और व्यापार रहस्यों की रक्षा के लिए अपर्याप्त कानूनी साधन शामिल हैं।
- **भारत** ने कहा कि वह **ट्रिप्स (TRIPS)** के तहत उल्लिखित सभी **प्रोटोकॉल** का पालन करता है।

ट्रिप्स (TRIPS)

- **इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) अधिकारों** के **व्यापार-संबंधित** पहलू यह एक **अंतरराष्ट्रीय समझौता** है जो **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** रूपरेखा का हिस्सा है।
- **वैश्विक स्तर** पर **इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP)** अधिकारों के लिए **सुसंगत और मानकीकृत नियम स्थापित** करने के लिए **ट्रिप्स (TRIPS)** की स्थापना की गई थी।
- यह सुनिश्चित करना कि सदस्य देशों के पास **पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क** और **व्यापार** रहस्य सहित **इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा)** के **विभिन्न रूपों** की सुरक्षा के लिए एक सामान्य रूपरेखा है।

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) अधिकारों के प्रकार

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के मुख्य प्रकारों में शामिल हैं:

- **कॉपीराइट** :
  - कॉपीराइट मूल साहित्यिक, कलात्मक और रचनात्मक कार्यों, जैसे किताबें, संगीत, पेंटिंग, मूर्तियां, फिल्में और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है।
- **पेटेंट:**
  - पेटेंट आविष्कारों की रक्षा करते हैं और आविष्कारक को आविष्कार बनाने, उपयोग करने और बेचने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर 20 वर्ष) के लिए विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।
- **ट्रेडमार्क** :
  - ट्रेडमार्क किसी विशेष व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट संकेतों, प्रतीकों, नामों और लोगो की सुरक्षा करते हैं।
- **व्यापार के रहस्य** :
  - व्यापार रहस्य मूल्यवान और गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, जैसे कि सूत्र, प्रक्रियाएँ, विधियाँ, ग्राहक सूची और तकनीकी जानकारी की रक्षा करते हैं
- **औद्योगिक डिज़ाइन** :
  - औद्योगिक डिज़ाइन उत्पादों के दृश्य सजावटी पहलुओं, जैसे उनके आकार, रंग, बनावट और सौंदर्यशास्त्र की रक्षा करते हैं।
- **भौगोलिक संकेत (GI)** :
  - GI उन उत्पादों की रक्षा करते हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं।
- **पौधों की किस्में** :
  - पादप विविधता संरक्षण प्रजनकों को उनके द्वारा विकसित की जाने वाली नई पादप किस्मों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **सुई(Sui) जेनेरिस सिस्टम:**
  - कुछ देशों ने स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, लोककथाओं और आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अद्वितीय प्रणालियाँ स्थापित की हैं।

125. भारत अपने मध्य पूर्व संबंधों में वृद्धि हेतु ओमान के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार-द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- GCC
- भारत-ओमान संबंध

समाचार:
- **भारत और ओमान** आने वाले **महीनों** में एक **व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि **नई दिल्ली पश्चिम एशिया** में अपने **संबंधों** का विस्तार करना चाहता है, जहां बढ़ते तनाव **प्रमुख शिपिंग मार्गों** को खतरे में डाल रहे हैं।
- यह भारत को एक **सामरिक साझेदार** और में तक पहुंच बनाने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु:
- **भारत और ओमान** के बीच **वार्षिक व्यापार 13 अरब डॉलर** से भी कम है ।
- यह सम्बन्ध **नई दिल्ली** के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि **खाड़ी देश ओमान** और **ईरान** के बीच **होर्मुज** की **संकीर्ण जलडमरूमध्य** का प्रवेश द्वार है, जो वै**श्विक तेल शिपमेंट** के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है।
- **भारत** ने **ओमान** और **संयुक्त अरब अमीरात** जैसे **GCC**(खाड़ी सहयोग परिषद) के सदस्य देशों के साथ **द्विपक्षीय समझौते** की मांग की है।
- **ओमान** के साथ नियोजित सौदा "**प्रतिस्पर्धी** बढ़त भी देता है क्योंकि **GCC** पाकिस्तान और चीन के साथ **व्यापार समझौतों** पर बातचीत कर रहा है,

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
- **अरब प्रायद्वीप** में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात **छह देशों** का एक **राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन** है ।
- **वर्ष 1981** में स्थापित, GCC **छह राज्यों** के बीच **आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक** और **सामाजिक सहयोग** को बढ़ावा देता है और **सहयोग और क्षेत्रीय मामलों** पर चर्चा करने के लिए **हर साल** एक **शिखर सम्मेलन** आयोजित करता है।
- सभी मौजूदा **सदस्य देश राजतंत्र** हैं, जिनमें **तीन संवैधानिक राजतंत्र** (कतर, कुवैत और बहरीन), **दो पूर्ण** राजतंत्र (सऊदी अरब और ओमान), और एक **संघीय राजतंत्र** (संयुक्त अरब अमीरात) शामिल हैं।

भारत और GCC:
- खाड़ी भारत के 'विस्तारित पड़ोस' का एक अभिन्न अंग है,
- **भारत** अपने कुल **तेल आयात** के **42 प्रतिशत** के लिए **छह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** देशों पर निर्भर है, **भारत** के शीर्ष **पांच तेल आपूर्तिकर्ताओं** में से **तीन खाड़ी देश** हैं।
- **भारतीय** सबसे बड़ा श्रमिक समुदाय हैं, अनुमानित **7.6 मिलियन भारतीय नागरि**क इस क्षेत्र में विशेष रूप से **सऊदी अरब** और **संयुक्त अरब अमीरात** में रहते हैं और काम करते हैं।
- **GCC** भारत का सबसे बड़ा **क्षेत्रीय-ब्लॉक व्यापारिक** भागीदार है , जिसका **व्यापार $104 बिलियन** है

भारत ओमान संबंध
- **सैन्य उपयोग** और **रसद सहायता** के लिए **ओमान** में **डुक्म** के **प्रमुख बंदरगा**ह तक पहुंच हासिल कर ली है ।
- **सैन्य अभ्यास:**
  - सेना अभ्यास: अल नजाह
  - वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
  - नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह्र
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने ओमान में ढोफ़र विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन-हिंदी भाषा का एक अध्यक्ष स्थापित किया है।
- **वर्ष 2022** के लिए **ओमान** के **कच्चे तेल निर्यात** के लिए **चीन** के बाद **भारत** दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

126. भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
• ATS • तटरक्षक बल

समाचार:

- **भारतीय तट रक्षक (ICG**) ने एक **पाकिस्तानी नाव** से **602 करोड़** रुपये **मूल्य** की **86 किलोग्राम** संदिग्ध **हेरोइन** जब्त की, जो **गुजरात** में **पोरबंदर तट** से **तमिलनाडु** के रास्ते **श्रीलंका** जा रही थी।
- **आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS)** और **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के साथ एक **संयुक्त ICG ऑपरेशन** के दौरान दवाओं को जब्त किया गया था, जिसके दौरान **भारतीय पक्ष** ने गोलीबारी की थी, जिसमें **चालक दल** के सदस्यों में से एक घायल हो गया था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

- यह **भारत** में एक **सरकारी** एजेंसी है जिसका काम **अवैध नशीली दवाओं** के उपयोग और तस्करी से लड़ना है।
- **वर्ष 1986** में स्थापित, यह **स्वापक औषधि** और **मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम** को लागू करने के लिए **गृह मंत्रालय** के तहत काम करता है।
  - जो ऐसे पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण रखता है।
- यह अधिनियम **नशीले पदार्थों** के **नियंत्रण** पर **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों** को कायम रखने की **भारत** की **प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS)

- यह महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई राज्यों में एक विशेष पुलिस बल है।
- महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ द्वारा किया जाता है। इस दस्ते ने देश में कई आतंकवादी हमलों को रोका है।

उद्देश्य एवं कर्तव्य

- राष्ट्रविरोधी तत्वों के बारे में जानकारी जुटाना
- IB और RAW जैसी ख़ुफ़िया सेवाओं के साथ समन्वय और आदान-प्रदान।
- आतंकवादियों, माफियाओं और अन्य संगठित आपराधिक सिंडिकेटों की गतिविधियों और गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें खत्म करना।
- नकली नोटों और नशीले पदार्थों के घोटाले का पता लगाना और उसका खुलासा करना।

GEO IAS It's about quality

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

127. दक्षिण भारत में जल संकट से सम्बंधित मामला

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।
प्रसंग:

- **दक्षिण भारत** के सभी **जलाशयों** में केवल **23% जल धारण क्षमता भ**रने के लिए **पर्याप्त पानी** है
- विश्लेषण के अनुसार, यह **रोलिंग दशकीय** औसत से **नौ प्रतिशत अंक** कम है, जो **आसन्न संकट** की **निश्चितता और भयावहता** को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- आखिरी बार दक्षिण भारत को गर्मियों में जल संकट का सामना वर्ष 2017 में करना पड़ा था।
- इस वर्ष उसी क्षेत्र में संकट कुछ कारणों से अलग और बदतर होने की ओर अग्रसर है।
- सबसे पहले, मानसून इनके विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, अल नीनो घटनाएँ उन्हें और अधिक अनियमित बना देती हैं, भले ही उनके प्रभाव को अलग करना एक सरलीकरण है।
- वर्ष 2014-16 में अल नीनो घटना थी जबकि इस बार यह घटना चल रही है और यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास की पांच सबसे मजबूत घटनाओं में से एक है।
- दूसरा, मौसम विज्ञानियों द्वारा वर्ष 2023 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष दर्ज करने के बाद, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष 2024 और भी बदतर होगा।
- चौथा, यह संकट पहले भी आया है, जबकि नीतियों और पूर्वानुमानों में सुधार हुआ है, ज़मीन पर इन नीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन में सुधार नहीं हुआ है।
- अनियोजित शहरी विकास, भूजल का अत्यधिक दोहन, कम पानी के पुन: उपयोग की दक्षता, अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी और जलग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण और/या गिरावट सहित अन्य कारक कायम हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन एक साथ संकट पैदा करके भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर अधिक घातक लागत डालेगा।
- किसी भी जल संकट को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जहां यह अपने आप में एक संकट है और एक ऐसा कारक है जो दूसरे के प्रभावों को बढ़ाता है।
- लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों और नीति निर्माताओं को यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि यह और भविष्य का संकट न तो केवल पानी के बारे में होगा और न ही जलवायु परिवर्तन के कारण होगा।

128. अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के लिए भारत के प्रयास - द प्रिंट

प्रासंगिकता: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव।
प्रसंग

- **पूर्व** से **पश्चिम** तक, **भारत** आज प्रमुख **अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों** का नेतृत्व कर रहा है जो अंततः **अटलांटिक** को **एशिया** के माध्यम से **प्रशांत महासागर** से जोड़ देगा।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री इन गलियारों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं
  - अरब प्रायद्वीप के माध्यम से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पहल
  - पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) से दक्षिण पूर्व एशिया में त्रिपक्षीय राजमार्ग तक
  - पूर्व में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मार्ग।
- जबकि IMEC का लक्ष्य भारत को रेल और समुद्री संपर्क के माध्यम से अरब प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है
- दो दशक पहले INSTC की अवधारणा 7,200 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें जहाज, रेल और सड़क मार्ग शामिल हैं जो भारत को ईरान और मध्य एशिया से रूस तक जोड़ते हैं।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत की कनेक्टिविटी का वादा करता है।
- INSTC का शुरू में इरादा ईरान के माध्यम से भारत से रूस तक माल भेजने का था। माल का पहला सेट जुलाई 2022 में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
- INSTC को ईरान और रूस जैसे स्वीकृत देशों के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा गया है।
- विदेश मंत्री ने IMEC और एक अन्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना को भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग से जोड़ना शुरू कर दिया है।

आर्थिक गलियारों के लिए वैश्विक दबाव बढ़ रहा है

- त्रिपक्षीय राजमार्ग वर्ष 2001 से दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम का एक हिस्सा रहा है।
- यह कार्यक्रम सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और देशों के बीच तेजी से व्यापार कनेक्शन की सुविधा के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक साथ लाता है।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII)

- G7 ने 2021 में इस बुनियादी ढांचे की कमी को पहचाना जब उसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) की घोषणा की गई है।
- B3W का लक्ष्य विकासशील दुनिया में 40 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना और BRI का विकल्प पेश करना है।
- वर्ष 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर इन प्रयासों को अंततः ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का नाम दिया गया।
- IMEC भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त अरब अमीरात तक माल भेजेगा और रेल के माध्यम से सऊदी अरब और फिर संभवतः जॉर्डन के माध्यम से इज़राइल तक यात्रा करेगा।
  - मूल समझौता ज्ञापन पर न तो इज़राइल और न ही जॉर्डन ने हस्ताक्षर किए।

वैश्विक गठबंधनों की झलक

- BRI के एक भाग के रूप में, 2017 में, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पहले बेल्ट एंड रोड फोरम (BRI फोरम) की मेजबानी की है।
- इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ 29 राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों ने भाग लिया।
- भारत ने फोरम में भाग लेने से इनकार कर दिया और यहां तक कि इस पहल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया।
- वर्ष 2023 में आयोजित तीसरे फोरम में अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी के बावजूद तालिबान की उपस्थिति देखी गई, जो वर्ष 2021 से अफगानिस्तान में सत्ता में रहे संगठन के साथ बीजिंग के बढ़ते संबंधों को रेखांकित करता है।
- सितंबर 2023 में IMEC की घोषणा के ठीक बाद तुर्की ने अपना स्वयं का "इराक डेवलपमेंट रोड" प्रस्तावित किया।
- इस परियोजना के तहत माल को इराक के अंतिम छोर पर ग्रैंड फॉ बंदरगाह पर स्थानांतरित किया जाएगा और फिर यूरोप पहुंचने से पहले जमीन के रास्ते तुर्की ले जाया जाएगा।

129. भारत और श्रीलंका के बीच कच्चाथीवू द्वीप विवाद - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

समाचार:

- तमिलनाडु में **लोकसभा चुनाव** से कुछ हफ्ते पहले **प्रधानमंत्री** ने **कच्चाथीवू** का विवादित मामला फिर उठाया.

कच्चाथीवू श्रीलंका का हिस्सा कब बना?

- 26-28 जून, 1974 के दौरान, भारत और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, इंदिरा गांधी और सिरिमा आरडी भंडारनायके ने पाक जलडमरूमध्य से एडम ब्रिज तक ऐतिहासिक जल में दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसमें यह भी बताया गया है कि "यह सीमा निर्जन कच्चाथीवू के पश्चिमी तट से एक मील दूर पड़ती है।"
- इस समझौते के कारण अक्टूबर 1921 से दोनों पक्षों के बीच चल रही वार्ता समाप्त हो गई। प्रारंभ में, वार्ता तत्कालीन मद्रास और सीलोन की सरकारों के बीच आयोजित की गई थी।

मछुआरों के लिए कचातीवू कितना महत्वपूर्ण रहा है?

- दोनों देशों के मछुआरे परंपरागत रूप से मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप का उपयोग करते रहे हैं।
- हालाँकि इस फ़ीचर को वर्ष 1974 के समझौते में स्वीकार किया गया था, मार्च 1976 में पूरक समझौते ने इसे स्पष्ट कर दिया
  - दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे "श्रीलंका या भारत की स्पष्ट अनुमति के बिना" किसी भी देश के ऐतिहासिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और विशेष क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में "शामिल नहीं होंगे"।

भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत की शुरुआत किस वजह से हुई?

- श्रीलंका ने इस आधार पर काचाथिवु पर संप्रभुता का दावा किया कि वर्ष 1505-1658 ई. के दौरान द्वीप पर कब्जा करने वाले पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था।
- भारत का तर्क यह था कि रामनाड [रामनाथपुरम] के तत्कालीन राजा ने अपनी जमीन के हिस्से के रूप में इस पर कब्जा कर लिया था।

वर्ष 1974 का समझौता कैसे प्राप्त हुआ?

- कच्चाथीवू पुनर्प्राप्ति की वर्तमान मांग की उत्पत्ति 1974 में उत्पन्न संधि के विरोध से हुई है।

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है?

- अगस्त 2013 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि **टापू ब्रिटिश भारत और सीलोन** (अब श्रीलंका) के बीच विवाद का मामला था और इसकी कोई सहमत सीमा नहीं थी, जिसका मामला **वर्ष 1974** और **वर्ष 1976** के समझौतों के माध्यम से सुलझाया गया था।
- **दिसंबर 2022** में, **केंद्र सरकार** ने **दो समझौतों** का जिक्र करते हुए, **राज्यसभा** में अपने जवाब में बताया कि कच्चातिवु "**भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री** सीमा रेखा के श्रीलंकाई पक्ष पर स्थित है।
- इसमें कहा गया कि मामला **उच्चतम न्यायालय** में विचाराधीन है।

130. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।

समाचार:

- **केरल सरकार** ने राज्य **उधार लेने की शक्ति** के मुद्दे पर समाधान के लिए **सुप्रीम कोर्ट** का दरवाजा खटखटाया है

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य की उधारी राज्य की आय या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% तक सीमित होनी चाहिए।
- केरल राज्य का तर्क है कि उसकी उधार लेने की शक्तियों में कटौती करके, केंद्र राज्य की कुछ बुनियादी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को कम कर रहा है और संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है।
- संविधान भारत की संघीय सरकार (संघ) और राज्य सरकारों के बीच व्यय जिम्मेदारियों को विभाजित करता है।
- **टैक्स में वृद्धि** : अधिकतर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **स्पेंडिंग** : अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है (संघ के ₹2,230 बिलियन की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹19,182 बिलियन)।

सामाजिक सेवाओं बनाम अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दें:

- केंद्र सरकार रक्षा (सामाजिक सेवाओं से लगभग दोगुना) और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा (सामाजिक सेवाओं से 2.4 गुना) पर अधिक खर्च करती है।
- राज्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में सामाजिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस खर्च से धीमी ग्रामीण आय वृद्धि को संबोधित करने में मदद मिली है।

केरल: केस स्टडी

- उन्होंने अपने बजट का 40-50% सामाजिक क्षेत्रों (1960-2000) को समर्पित किया, जिससे महत्वपूर्ण विकास हुआ।
- हालाँकि, उनका सामाजिक व्यय अनुपात हाल ही में स्थिर हो गया है, जबकि अन्य राज्यों ने अपना बढ़ा दिया है।
- केरल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय सरकारों को सौंपता है, जो उन्हें अभी भी सामाजिक खर्च में राष्ट्रीय औसत से ऊपर रख सकता है।

चुनौतियाँ और विचार:

- राज्यों को तीन स्रोतों करों, संघ हस्तांतरण और उधार से धन मिलता है।
- केरल ने आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए महामारी के दौरान भारी उधार लिया।
- कम केंद्रीय हस्तांतरण और स्थिर कर राजस्व ने केरल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर किया।

केरल द्वारा बढ़ती उधारी के लिए तर्क:

- उच्च सामाजिक व्यय ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- केरल की उच्च बचत दर के साथ घरेलू संस्थानों से उधार लेना लाभदायक हो सकता है।
- उधार ली गई धनराशि का प्रभावी उपयोग विकास का एक अच्छा चक्र बना सकता है।

केरल के खर्च को लेकर चिंताएं:

- सामाजिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जिससे संभावित रूप से नई पहल के लिए धन सीमित हो जाता है।
- कम पूंजीगत व्यय (बुनियादी ढांचा) भविष्य की वृद्धि में बाधा बन सकता है।

आगे की राह:

- **केरल** का तर्क है कि उधार लेने पर **प्रतिबंध संघवाद** का उल्लंघन करता है और **वित्तीय प्रतिबद्धताओं** को पूरा करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- बढ़ती **आबादी और युवाओं** के बाहर प्रवास के कारण अन्य राज्यों को भी जल्द ही इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इन मुद्दों के समाधान के लिए **केंद्र और राज्य सरकारों** को सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **केरल को संघ** को यह समझाने की जरूरत है कि उनकी उधारी एक **दीर्घकालिक निवेश** है, न कि केवल त्वरित समाधान।

131. उत्तराखंड सरकार GLOF के जोखिम का मूल्यांकन करेगी -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

समाचार:

- **उत्तराखंड सरकार** ने क्षेत्र में **पांच संभावित खतरनाक हिमनद झीलों** से उत्पन्न खतरे का **मूल्यांकन** करने के लिए **विशेषज्ञों की दो टीमों** का गठन किया है।
- ये झीलें **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** से ग्रस्त हैं, जिस तरह की **घटनाओं के परिणामस्वरूप** हाल के वर्षों में **हिमालयी राज्यों** में कई आपदाएँ हुई हैं।

मुख्य बिंदु

- जोखिम मूल्यांकन अभ्यास का लक्ष्य GLOF घटना की संभावना को कम करना और उल्लंघन की स्थिति में राहत और निकासी के लिए अधिक समय प्रदान करना है।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)

- **ग्लेशियर रिट्रीट,लेक फॉर्मेशन** :जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं, वे अपने पीछे अवसाद छोड़ जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है और हिमनद झीलें बन जाती हैं।
- ये झीलें ऊंचे पहाड़ों और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे आम हैं।
- **झीलें के प्रकार:** दो मुख्य प्रकार हैं: बर्फ-संपर्क झीलें (ग्लेशियर को छूने वाली) और दूरस्थ झीलें (अधिक दूर लेकिन फिर भी ग्लेशियरों से प्रभावित)।
- **GLOF खतरा:** अधिकांश हिमनदी झीलें बर्फ या ढीली चट्टान के अस्थिर बांधों द्वारा अनिश्चित रूप से रोकी जाती हैं।
- यदि ये बांध टूट जाते हैं, तो GLOF नामक एक विशाल बाढ़ पहाड़ों से नीचे गिरती है, जिससे विनाशकारी क्षति होती है।

GLOF को क्या ट्रिगर करता है?

- **आइस कैल्विंग:** बर्फ के बड़े टुकड़े ग्लेशियरों को तोड़कर झील में गिर सकते हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
- **भूस्खलन और हिमस्खलन:** ये घटनाएँ झील को बनाए रखने वाले बांध को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे अचानक पानी छोड़ा जा सकता है।

GLOFs का विनाशकारी प्रभाव

- **फ्लड ऑफ़ फरी :** GLOF भारी मात्रा में पानी, तलछट और मलबा छोड़ते हैं, जिससे पूरी घाटियाँ अविश्वसनीय तरीके से नष्ट हो जाती हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर ऑबलिटेरटेड:** सड़कों, पुलों और इमारतों का इन बाढ़ों से कोई मुकाबला नहीं है, जिससे व्यापक विनाश हुआ।
- **जीवन और आजीविका की हानि:** GLOF जीवन की दुखद हानि और समुदायों को तबाह कर सकता है।

बढ़ता हुआ ख़तरा: जलवायु परिवर्तन और विकास

- **मेल्टिंग ऑन द राइज़** : बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे विशेष रूप से हिमालय में अधिक और बड़ी हिमनद झीलें बन रही हैं।
- **खतरनाक स्थानों में डेवलपमेंट** : उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण से GLOF के खतरे और बढ़ जाते हैं।

भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग जोखिम में

- एक हालिया अध्ययन नेचर में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग GLOF खतरों का सामना करते हैं, बावजूद इसके कि इन क्षेत्रों में अन्य स्थानों की तुलना में कम हिमनद झीलें हैं।
- इन क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अधिक GLOF -प्रवण क्षेत्रों में से एक बनाता है।

जोखिम मूल्यांकन: खतरे को कम करना

- **शीघ्र चेतावनी सिस्टम:** भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) GLOF जोखिमों को कम करने और उल्लंघन होने पर तेजी से निकासी की अनुमति देने के लिए संभावित खतरनाक हिमनद झीलों की पहचान कर रहा है।
- **हाई अलर्ट पर उत्तराखंड:** हिमालयी राज्यों में 188 संभावित जोखिम भरी हिमनद झीलों की पहचान की गई है, जिनमें से 13 उत्तराखंड में हैं।
- GLOF जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न एक गंभीर खतरा है।
- जोखिमों को समझकर और निवारक उपाय करके, हम उम्मीद से उनके कारण होने वाली तबाही को कम कर सकते हैं।

132. भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वाहन परियोजना -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- हाल ही में, **सरकार** ने **दो बसों** के **परीक्षण** के साथ **भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब** बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो इस **स्वच्छ ईंधन** पर चलेंगी।
- इसकी साल के अंत तक ऐसी **15** और बसें शुरू करने की योजना है।

मुख्य बिंदु	चुनौतियाँ
• इन वाहनों में वस्तुतः शून्य उत्सर्जन होता है और उनके ईंधन सेल आंतरिक दहन इंजन की तुलना में बहुत अधिक कुशल होते हैं। • स्वच्छ प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को सौर या पवन ऊर्जा की अनिश्चितताओं के बिना अधिक भरोसेमंद ईंधन के रूप में देखा जाता है। • भारत का एक महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसका लक्ष्य ग्रीन 2030 से सालाना 5 मिलियन टन ईंधन का उत्पादन करना है। • इस परियोजना का लक्ष्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर 1 लाख करोड़ रुपये की निर्भरता कम करना और 50 मिलियन मीट्रिक टन जीएचजी उत्सर्जन को रोकना है। • हालाँकि, इस ग्रीन ईंधन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने से पहले कई बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। • पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन खींचने के लिए बिजली का उपयोग करने की तकनीक 1800 के दशक से ही मौजूद है। • नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग इस प्रक्रिया को ग्रीन बनाता है।	• यहीं पर पहली चुनौती सामने आती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को अपने ग्रीन हाइड्रोजन-संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले सात वर्षों तक हर साल लगभग 100 गीगावॉट RE क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। ○ चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, पिछले साल इसमें लगभग 16 गीगावॉट RE जोड़ा गया। • इसके अलावा, इस स्वच्छ ईंधन के 1 किलोग्राम उत्पादन के लिए आठ से नौ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ○ देश के बड़े हिस्से में जल संकट को देखते हुए, हाइड्रोजन उत्पादन को कम जल-गहन बनाना देश के स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रोलाइज़र की वैश्विक विनिर्माण क्षमता जिस इकाई में इलेक्ट्रोलिसिस होती है वह लगभग 10 गीगावॉट है। • अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को दुनिया की वर्तमान इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन क्षमता से छह से 10 गुना अधिक की आवश्यकता हो सकती है • चीन के वर्चस्व वाले बाजार में रेयर अर्थ मिनिरल्स तक पहुंच इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। • अत्यधिक ज्वलनशील ग्रीन ईंधन के परिवहन और भंडारण में तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता होगी, सुरक्षा चिंता एक कारण है कि बसें शुरू में यात्रियों को नहीं ले जाएंगी।

निष्कर्ष

- **सरकार** ने देश की पहली **ग्रीन हाइड्रोजन वाहन परियोजना** के लिए **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन** की सिद्ध क्षमताओं का उपयोग करके सही काम किया है।
- **बाज़ारों** तक पहुंच बनाने के लिए अब उसे अधिक **विशेषज्ञता विकसित** करने और **अन्य देशों** के साथ साझेदारी बनाने की आवश्यकता होगी।

133. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

समाचार:

- उन प्रवासियों को **नागरिकता प्रदान** करना जो **उत्पीड़न के कारण** अपने **मूल देश** से भाग गए हैं और अपने गोद लिए गए देश में पर्याप्त समय तक रहे हैं, किसी भी **राष्ट्र-राज्य** द्वारा एक **मानवीय प्रयास** है और आम तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु	शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
• लेकिन इस उपाय को केवल पड़ोसी देशों के एक मनमाने समूह के प्रवासियों तक सीमित करके और परिभाषा को केवल "धार्मिक उत्पीड़न" तक सीमित कर दिया गया। ○ और इसे और अधिक सीमित करने के लिए इसमें मुसलमानों, नास्तिकों और अज्ञेयवादियों को शामिल नहीं किया जाएगा • यह सुझाव दिया जाएगा कि इस नागरिकता प्रदान करने का तर्क मानवतावाद से कम और भारतीय नागरिकता की विकृत और विकृत समझ से अधिक है। • अपने मूल इरादे से, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, जिसके नियमों को पिछले महीने गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था ○ संसद में अधिनियम पारित होने के चार साल बाद, यह भारतीय संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। • यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्पीड़न अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे हाल के वर्षों में श्रीलंका के मामले में भाषाई भेदभाव और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जहां से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। • इसके अलावा, जैसा कि म्यांमार के रोहिंग्या के मामले से पता चलता है, मुसलमानों को भी हाल के वर्षों में भेदभाव के सबसे गंभीर रूप का सामना करना पड़ा है • हजारों लोग मारे गए, उनमें से दस लाख से अधिक राज्यविहीन हो गए और लाखों लोग भारत सहित अन्य देशों में भाग गए • यहां तक कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम-बहुल देशों और इस्लाम को राज्य धर्म मानने वाले देशों में भी, अहमदिया जैसे अल्पसंख्यक इस्लामी संप्रदाय उत्पीड़न और उत्पीड़न के अधीन रहे हैं।	• शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में शरणार्थी संरक्षण से संबंधित है, इसे वर्ष 1951 में अपनाया गया और वर्ष 1954 में लागू हुआ। • वर्ष 1967 प्रोटोकॉल के रूप में सम्मेलन में एक संशोधन किया गया है। • जबकि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। • उनके पास ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो केवल अपने धर्म के अलावा विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के अधीन हैं।

134. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विनियमन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण - द हिन्दू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

समाचार:

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** क्षेत्र में हाल के वर्षों में इसके विनियमन के लिए महत्वपूर्ण कुछ विकास हुए हैं जैसे **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, **यूरोपीय संसद** द्वारा AI अधिनियम, यूके और चीन में AI पर पेश किए गए कानून और भारत में **AI मिशन** का शुभारंभ आदि।
- वैश्विक स्तर पर AI नियमों को औपचारिक बनाने के ये प्रयास अन्य सभी देशों में शासन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

मुख्य बिंदु

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पारित होने के साथ, AI के विनियमन पर आवश्यकता और संबंधित चर्चा एक नए चरण में प्रवेश कर गई है।
- यह माना गया कि एआई सिस्टम का अनैतिक और अनुचित उपयोग 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धि में बाधा बनेगा
  - जिससे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक तीनों आयामों में चल रहे प्रयास कमजोर होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में उल्लिखित एक और विवादास्पद पहलू कार्यबल पर AI का संभावित प्रतिकूल प्रभाव है।
- इस प्रकार, अपनी तरह का पहला होने के नाते, संकल्प ने AI सिस्टम के भविष्य के निहितार्थ और सहयोगात्मक कार्रवाई को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण

- यूरोपीय संघ ने हाल ही में AI अधिनियम पारित किया है, जो AI सिस्टम को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। अपने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के साथ, अधिनियम सिस्टम को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और न्यूनतम जोखिम, प्रत्येक के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- अधिनियम उन अनुप्रयोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों के अधिकारों को जोखिम में डालते हैं, जिसमें मानव व्यवहार में हेरफेर, भावना पहचान, सामूहिक निगरानी आदि शामिल हैं।

AI पर चीन का रुख

- देश ने चरणों में, निम्नलिखित तीन मुद्दों को संबोधित करते हुए एक नियामक ढांचा जारी किया
- सामग्री मॉडरेशन, जिसमें किसी भी AI सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न सामग्री की पहचान शामिल है
- व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं के डेटा और एल्गोरिथम प्रशासन तक पहुंचने और संसाधित करने से पहले उनकी सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने के साथ
  - किसी भी एकत्रित डेटासेट पर एल्गोरिदम विकसित करने और चलाने के दौरान सुरक्षा और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करना।

भारत की स्थिति

- AI सिस्टम को विनियमित करने की दिशा में वैश्विक आंदोलन के बीच, भारत की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश वर्तमान में प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़े उपभोक्ता आधार और श्रम बलों में से एक को पूरा कर रहा है।
- भारत वर्ष 2030 तक 10,000 से अधिक डीप टेक स्टार्ट-अप का घर होगा। इस दिशा में, अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत AI मिशन के लिए ₹10,300 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी गई थी।
  - बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- अन्य पहलों के अलावा, आवंटन का उपयोग 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग इकाइयों, बड़े मल्टी-मॉडल (LMM) और अन्य एआई-आधारित अनुसंधान सहयोग और कुशल और अभिनव परियोजनाओं को तैनात करने के लिए किया जाएगा।

निष्कर्ष

- अपनी **अर्थव्यवस्था** के विस्तार के साथ, **भारत** की प्रतिक्रिया **SDG** के प्रति उसकी **प्रतिबद्धता** के अनुरूप होनी चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि **आर्थिक विकास** बना रहे।
- इसके लिए ऐसे **समाधान** पेश करने के लिए **AI सिस्टम** के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होगी जो इसके जोखिमों को कम करते हुए **नवाचार** को आगे बढ़ा सके।
- एक निष्पक्ष और समावेशी **AI प्रणाली** की दिशा में भारत के प्रयासों के लिए **क्रमिक चरण-आधारित** दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है

135. जलवायु परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को बढ़ाता - द हिन्दू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- **जलवायु संकट** पहले से ही मौजूद है और इसका **प्रभाव सभी पर समान** रूप से नहीं पड़ता है।
- **महिलाओं और लड़कियों** को विशेष रूप से गरीबी की स्थितियों में और **मौजूदा भूमिकाओं, जिम्मेदारियों** और **सांस्कृतिक मानदंडों** के कारण अ**त्यधिक स्वास्थ्य जोखिमों** का सामना करना पड़ता है।

मुख्य बिंदु
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, किसी आपदा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बच्चों के मरने की संभावना 14 गुना अधिक होती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी फैसला सुनाया है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है,
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार पहले से ही जीवन के अधिकार के दायरे में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

महिलाओं पर जलवायु का असर
- जलवायु-प्रेरित फसल उपज में कमी से खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, जिससे गरीब परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो पहले से ही उच्च पोषण संबंधी कमी से पीड़ित हैं।
- छोटे और सीमांत भूमिधारक परिवारों में, जबकि पुरुषों को अवैतनिक ऋण के कारण सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है (जिसके कारण प्रवासन, भावनात्मक संकट और कभी-कभी आत्महत्या भी होती है),
- महिलाओं को अधिक घरेलू काम का बोझ, ख़राब स्वास्थ्य और अधिक अंतरंग साथी हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 4 और 5 के आंकड़ों से पता चला है कि सूखाग्रस्त जिलों में रहने वाली महिलाओं का वजन अधिक था
  - अधिक अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया और लड़की विवाह का प्रचलन अधिक था।
  - बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर भी प्रभाव डालता है।

एक्सट्रीम इवेंट्स और लैंगिक आधारित हिंसा
- 2021 में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 75% भारतीय जिले हाइड्रोमेट आपदाओं (बाढ़, सूखा और चक्रवात) के प्रति संवेदनशील हैं।
- NFHS 5 डेटा से पता चला कि इन जिलों में रहने वाली आधी से अधिक महिलाएं और बच्चे जोखिम में थे।

जलवायु कार्रवाई के लिए महिलाओं की आवश्यकता क्यों है?
- जब पुरुषों के समान संसाधनों तक पहुंच प्रदान की गई, तो महिलाओं ने अपनी कृषि उपज में 20% से 30% की वृद्धि की है।
- विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रही हैं।
- महिलाओं और महिला समूहों (स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों) को ज्ञान, उपकरण और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने से स्थानीय समाधान उभरने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

क्या करने की आवश्यकता है
- सभी संवेदनशील जिलों में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों और जिला अधिकारियों को एक योजना बनाने और प्रमुख कार्यान्वयनकर्ताओं को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- वृक्षों के आवरण को बेहतर बनाने, कंक्रीट को कम करने, हरे-नीले स्थानों को बढ़ाने और गर्मी को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम आवास डिजाइन करने की शहरी योजना दीर्घकालिक कार्य हैं।
- क्षमताओं और वित्त का हस्तांतरण और पंचायत की क्षमता के निर्माण में निवेश करना।

केस स्टडी
- उदयपुर में महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने दिखाया कि कम आय वाले घरों की छतों को परावर्तक सफेद रंग से रंगने से घर के अंदर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष
- **जलवायु परिवर्तन** पर **राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** और **जलवायु परिवर्तन** पर राज्य कार्य योजना **(SAPCC) महिलाओं** पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालती है।
- **SAPCC** के चल रहे संशोधन की **सिफ़ारिशें रूढ़िवादिता** से आगे बढ़ने, सभी **जेंडर वल्नरबिलिटी** को पहचानने की आवश्यकता पर जोर देती हैं।
- जलवायु अनुकूलन के लिए एक व्यापक और **न्यायसंगत दृष्टिकोण** सुनिश्चित करते हुए, लैंगिक-परिवर्तनकारी रणनीतियों को लागू करें।
- पीड़ित के रूप में लेबल किए जाने के बजाय, महिलाएं जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व कर सकती हैं।

136. सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का भारत का विनियमन- द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

समाचार:
- भारत के **नवीकरणीय विनिर्माण पारिस्थितिकी** तंत्र का समर्थन करने के लिए **सौर मॉड्यूल** की **स्थानीय सोर्सिंग** बढ़ाने के प्रयासों पर हाल के **सरकारी आदेशों** को व्यापक रूप से '**आयात प्रतिबंध**' के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- **सरकार** ने '**सौर फोटोवोल्टिक [PV] मॉड्यूल** के **मॉडल और निर्माताओं** की स्वीकृत लिस्ट', जिसे **ALMM लिस्ट** भी कहा जाता है, की अपनी **वर्ष 2021 अधिसूचना** को फिर से लागू करने का आदेश दिया है।

ALMM लिस्ट
- इस सूची में वे निर्माता शामिल हैं जो "केंद्र और राज्य सरकारों को बिजली की बिक्री के लिए स्थापित परियोजनाओं सहित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सरकारी परियोजनाओं/सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/परियोजनाओं में उपयोग के लिए पात्र हैं।"
- हालाँकि, यह अधिसूचना जारी होने के दो साल बाद पिछले वित्तीय वर्ष के लिए "स्थगित" रखी गई थी।
- हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन यह उन चिंताओं से उपजा है कि सौर मॉड्यूल और सेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर चीन से आयात किए गए थे।
- यह एक आयात प्रतिस्थापन प्रयास है और आयात को प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं है।

क्या भारत सौर PV आयात पर निर्भर है?
- भारत सौर सेल और मॉड्यूल की अपनी मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक आयात पर निर्भर है और चीन और वियतनाम देश के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
- इसकी तुलना में, भारत में विनिर्माण क्षमता अपेक्षाकृत कम है और काफी हद तक अंतिम विनिर्माण चरण तक ही सीमित है ।
  - ICRA ने अपनी नवंबर 2023 की रिपोर्ट में कहा कि PLI योजना से इसमें बदलाव की उम्मीद है, अगले 2-3 वर्षों में भारत में एकीकृत मॉड्यूल इकाइयां आने की उम्मीद है।
- सरकार ने पीवी मॉड्यूल पर 40% और PV सेल पर 25% का भारी सीमा शुल्क भी लगाया है।

भारत में सोलर संभावनाएं
- **वर्ष 2030** तक **गैर-जीवाश्म ईंधन** से **500 गीगावॉट स्थापित क्षमता** का **सरकार का महत्वाकांक्षी** लक्ष्य **भारत** में **सौर ऊर्जा** को बढ़ाने का मुख्य चालक है।
- **IEA** के अनुसार, **प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं** में **वर्ष 2026** तक **बिजली की मांग** में **भारत की वृद्धि** दर सबसे तेज़ रहेगी।

- देश में अनुमानित **सौर ऊर्जा क्षमता 748.99 गीगावॉट** है, इसलिए, अब तक **सौर ऊर्जा** की क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है।
- सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध क्षमता का दोहन करने का प्रयास कर रही है

137. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।
समाचार:

- जब **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता (2018)** और **जलवायु** कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** ने अपने **21 दिवसीय जलवायु** उपवास की घोषणा की है।

मुख्य बिन्दु

- हिमालय क्षेत्र को बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का भी सामना करना पड़ता है।
- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह हिमालय के ग्लेशियरों के भी पिघलने का खतरा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि

- वर्ष 2008 में, केंद्र ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशन शुरू किए गए थे ।
- इनमें से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE) के अधीन था।
- "NMSHE का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करने की क्षमता विकसित करना है"।

NMSHE अपनी भूमिका

- जैसे ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से शुरू की गईं है ।
- इनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुलों का निर्माण, सड़कों, सुरंगों, रेलवे लाइनों का चौड़ीकरण, मेगा सौर परियोजनाएं, एक अत्याधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल और सड़क के किनारे सुविधाएं शामिल हैं।
- वर्ष 2023 की लद्दाख (UT) औद्योगिक भूमि आवंटन नीति का लक्ष्य "UT लद्दाख को निवेश के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बनाना" है।
- वर्ष 2021-22 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने अपना दृष्टिकोण निम्नलिखित बताया है:
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाना है।

हिमालय संवेदनशील क्षेत्र

- वर्ष 2010 के बाद से, हिमालय क्षेत्र में कई आपदाएँ आई हैं, जिनमें जीवन और आजीविका की हानि हुई है।
- वर्ष 2013 में, हिमालय के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से केदारनाथ में अचानक बाढ़ आ गई।
- जनवरी 2023 में, जोशीमठ में आपदा आई, जब पानी पहाड़ की निचली ढलान से नीचे की ओर बह गया, जिससे शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए।
- नवंबर 2023 में, हिमालय में ध्वस्त सिल्क्यारा सुरंग परियोजना में फंसे 41 श्रमिकों के बचाव ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

समिति का सुझाव

- भूवैज्ञानिकों और पारिस्थितिकीविदों की सख्त चेतावनियों के बावजूद यह जारी है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने यहां तक सुझाव दिया कि अधिकारियों को चार बांध हिमालयी मंदिरों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को वहन क्षमता तक सीमित करना चाहिए।
- कुछ विशेषज्ञ समितियों ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि पैरा-ग्लेशियल क्षेत्र में कोई जलविद्युत परियोजना स्थापित नहीं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- विकास के नाम पर, **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र** और इसकी **जैव विविधता** में **नाजुक संतुलन** को बिगाड़ना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है कि हिमालय और इसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहें।

138. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडो-पैसिफिक हेतु महत्वपूर्ण -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।
प्रसंग:

- **वर्ष 1857** के **स्वतंत्रता संग्राम** के बाद **अंग्रेजों** ने **अंडमान और निकोबार (A&N)** द्वीप समूह में एक **दंडात्मक कॉलोनी** स्थापित की, जहां कई **भारतीय क्रांतिकारियों** और **स्वतंत्रता सेनानियों** को जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया।
- इन **सामरिक द्वीपों** पर सरकार के बढ़े हुए **सुरक्षा फोकस** के बारे में **हालिया रिपोर्टों** का स्वागत किया जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अतीत में, ये द्वीप भारत की पकड़ से लगभग जा चुके थे ।

INA द्वारा मुक्त कराया गया	थिएटर कमांड

• फरवरी 1942 में, सिंगापुर के पतन के ठीक एक महीने बाद, भारत पर आक्रमण के लिए संभावित स्प्रिंगबोर्ड के रूप में जापानियों ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया।
• वर्ष 1943 के अंत में, वे ब्रिटिश शासन से "मुक्त" होने वाले भारत के पहले हिस्से बन गए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया और INA का झंडा फहराया।
• हालाँकि, यह महज प्रतीकवाद था क्योंकि वर्ष 1945 में जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों ने A&N पर फिर से कब्जा कर लिया था।
• आजादी के बाद यह द्वीप भारत के हिस्से में आ गया
कारगिल युद्ध के बाद
• वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद की सुरक्षा समीक्षा में पोर्ट ब्लेयर में भारत की पहली संयुक्त/एकीकृत परिचालन कमान अंडमान निकोबार कमांड (ANC) की स्थापना की गई।
• द्वीपसमूह के 836 द्वीपों और टापुओं में से केवल 31 में ही निवास है।
• इसका मतलब यह है कि एक पड़ोसी देश द्वारा "कारगिल की पहाड़ियों" पर गुप्त रूप से कब्ज़ा करने की संभावना है।
	• राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा घुसपैठ की संभावना को खत्म करने के लिए, ANC को रडार, विमान, उपग्रहों और मानव रहित वाहनों सहित नेटवर्क संपत्तियों के माध्यम से त्रि-आयामी समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
	• लाल सागर में हौथी हमलों के कारण हुए जहाजरानी के गंभीर व्यवधान और पुनः मार्ग के संदर्भ में
	  ○ मलक्का जलडमरूमध्य - दुनिया का लगभग 30 प्रतिशत व्यापार माल ले जाने वाले 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज हर साल इससे होकर गुजरते हैं
	  ○ यह भारत के लिए एक चुनौती के साथ-साथ एक गुप्त अवसर भी प्रस्तुत करता है।
	द्वीपों की श्रृंखला का महत्व
	• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अत्यधिक सामरिक महत्व का है क्योंकि वे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक हैं।
	• यह भारत को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से अंडमान सागर (हिंद महासागर) तक यातायात के प्रवाह की निगरानी करने की सुविधा देता है जो भारत-प्रशांत में व्यापार और तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है।
	• हालाँकि इन द्वीपों का सतह क्षेत्र केवल 8,300 वर्ग किमी है, ये समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार के वादे के साथ भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 300,000 वर्ग किमी जोड़ते हैं।

निष्कर्ष

- एक उम्मीद है कि रिपोर्ट की गई **सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर** का **उन्नयन** एक **सामंजस्यपूर्ण रणनीति** का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य **अंडमान और निकोबार द्वीपों** को एक **दुर्जेय समुद्री गढ़ में** परिवर्तित करना है जो न केवल **भारत** की **रक्षात्मक परिधि** का विस्तार करेगा बल्कि **समुद्री पड़ोसियों** को शक्ति दिखाने या दोस्ती का हाथ बढ़ाने की क्षमता भी प्रदान करेगा।

139. भारत - चीन के बीच सीमा विवाद - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रसंग:

- लद्दाख निश्चित रूप से एक गंभीर टकराव बिंदु रहा है और बना रहेगा।
- **1,597 किमी** लंबी **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** के अलावा यहां कोई सीमा नहीं है, जो **वर्ष 1962** से **भारत और चीन** को अलग करने वाली एक **काल्पनिक सीमा** है। यहां तक कि **LAC** भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है।

मुख्य बिंदु	चांग चेन्मो घाटी

• सीमा को लेकर दोनों देशों की धारणाएं अलग-अलग हैं।।
• काराकोरम से चुमुर तक फैले 65 निर्धारित गश्ती बिंदुओं (PP) तक गश्त की जाती है।
• हालिया विवाद बिंदु देपसांग में PP9, 10, 11, 12, 12A और 13, गलवान में PP14, हॉट स्प्रिंग्स/चांग चेनमो में PP15 और PP16, और गोगरा में PP17 और 17A पर हुए।
चुशुल-पैंगोंग सेक्टर
• चुशूल पैंगोंग सेक्टर में, पैंगोंग के उत्तरी तट पर सिरिजाप रेंज में जहां फिंगर सीरीज 1 से 8 तक स्थिति स्थिर है।
• मई 2020 में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोकने के लिए फिंगर 3-4 क्षेत्र में प्रवेश किया।
• फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल की जा रही है।
कैलाश रेंज
• कैलाश रेंज में पैंगोंग त्सो और स्पैंगगुर गैप के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्यानलुंग योकमा गोंगमा /कैलाश हाइट्स पर कब्जा करने के लिए PLA ने सितंबर 2020 की शुरुआत में उत्तेजक कदम उठाया था।
  ○ भारतीय सेना द्वारा एक प्रमुख सामरिक युद्धाभ्यास में इसे विफल कर दिया गया।
	• गलवान घाटी, चांगलुंग घाटी हॉट स्प्रिंग्स और चांग चेन्मो घाटी के कोंगरुंग घाटी में PLA की घुसपैठ, जहां उसने भारतीय सैनिकों के लिए क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया था, अब अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है।
	• गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में स्थिति 8 सितंबर, 2022 तक अस्थिर रही, जब दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत हुए।
	देपसांग और डेमचोक
	• वर्तमान में, केवल डेपसांग और डेमचोक ही वर्ष 2020 के गतिरोध से पहले से ही टकराव के बिंदु बने हुए हैं।
	• अगस्त 2013 की श्याम सरन रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि PLA द्वारा "क्षेत्र इनकार" के कारण भारत ने 640 वर्ग किमी क्षेत्र खो दिया है।
	• विशेषज्ञों का सुझाव है कि देपसांग मैदान के दक्षिणी आधे हिस्से के 600-800 वर्ग किमी पर चीनियों का नियंत्रण है।
	  ○ पूर्णतः पृथक्करण अप्राप्य रहा है।
	इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड
	• इससे पहले, चीन ने भारत के ढीले रवैये के कारण उसे धमकाया और मजबूर किया और वर्ष 1960 और वर्ष 1990 के दशक के बीच लद्दाख क्षेत्र का एक हिस्सा हड़प लिया।
	• सरकार ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया है, जिसमें 260 किलोमीटर लंबी श्योक-DBO सड़क भी शामिल है, जिसे युद्धस्तर पर पूरा किया गया।
	• अब डोरबुक से DBO आठ घंटे में पहुंचा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों को कठिन इलाके में एक बड़ा फायदा मिलता है।

निष्कर्ष

- **तकनीकी** रूप से, **LAC** के **भारतीय क्षेत्र** में कोई घुसपैठ नहीं हुई है।
- **LAC** की धारणा में **अंतर** के कारण **विसंगतियां** केवल **ग्रे-जोन गश्त** वाले क्षेत्रों में हुई हैं।
- **नई दिल्ली** में **नई सरकार** बनने के बाद **LAC** को स्पष्ट करने की रुकी हुई **प्रक्रिया को पुनर्जीवित** करने के लिए **दोनों पक्षों** को नए **अवसरों का लाभ** उठाना चाहिए।

140. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफ़ारी से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- मार्च में अपने फैसले में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **उत्तराखंड** में **जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क** में **6,000 पेड़ों** की कटाई के लिए जिम्मेदार **राजनेताओं, वन अधिकारियों** और **स्थानीय ठेकेदारों** की **नापाक सांठगांठ** को उजागर किया।

मुख्य बिंदु	कोर्ट से चूक
• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, प्रोजेक्ट टाइगर और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 सहित नीतियों और कानूनों के माध्यम से संरक्षण लक्ष्यों को प्राथमिकता मिलने के बावजूद राज्य का मुख्य हित राजस्व बढ़ाना है। • जिम कॉर्बेट में पेड़ों के अवैध विनाश को ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1983 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन में देखा जा सकता है। ○ जिसमें कहा गया था कि "पर्यावरण विनाश और लोगों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की कीमत पर आर्थिक विकास हासिल नहीं किया जा सकता है।" • राष्ट्रीय और राज्य वन प्राधिकरण एक साथ संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने, राजस्व बढ़ाने और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए इकोटूरिज्म पर निर्भर हो गए हैं। • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दृष्टिकोण पर्यावरण-केंद्रित होना चाहिए न कि मानव-केंद्रित होना चाहिए। • अदालत ने मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगाने और न केवल जिम कॉर्बेट, बल्कि पूरे भारत में परिधीय क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति देने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। • यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2019 के दिशानिर्देशों से भी असहमत है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान में चिड़ियाघर की तर्ज पर बाघ सफारी की अनुमति देता है। • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बाघों को उसी परिदृश्य से लाया जाना चाहिए जहां सफारी संचालित की जा रही है, न कि बाघ अभयारण्य के बाहर से है । • सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अपने चार जैव विविधता हॉटस्पॉट के तहत 90% क्षेत्र खो दिया है।	• पुनर्स्थापन की लागत वसूलने का मतलब सामान और सेवाएँ प्रदान करने की पर्यावरण की क्षमता के नुकसान की भरपाई करना नहीं है। • भारत में, मूल्यांकन की रूपरेखा, जो टीएन गोदावर्मन मामले (1996) से पहले की थी, का उद्देश्य खोए हुए प्राकृतिक वनों को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के साथ बदलना था। • दो विकल्प जो कानूनी और संस्थागत रूप से समर्थित हैं और भारत में वन भूमि के मूल्यांकन के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं, वे अब प्रतिपूरक वनीकरण लेवी और शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हैं।

निष्कर्ष

- न्यायालय यह कहकर एक मिसाल कायम कर सकता था कि **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ** अधिक महत्वपूर्ण हैं और **पर्यावरण-पर्यटन** की तुलना में अधिक **राजस्व उत्पन्न** करती हैं या **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं** से संबंधित एक सटीक कानून और नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दे सकती थी।
- **कोस्टा रिका बनाम निकारागुआ (2018)** में अं**तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** द्वारा दिए गए तर्क का उपयोग **पर्यावरण** को होने वाले नुकसान के **मूल्यांकन** के तरीकों को समझने के लिए किया जा सकता था।

141. भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष से सम्बंधित मामला- डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।
प्रसंग:

- **भारत**, अपनी **समृद्ध जैव विविधता** और बढ़ती **मानव आबादी** के साथ, **मानव-पशु संघर्ष** की एक महत्वपूर्ण चुनौती से जूझ रहा है।
- जैसे-जैसे आवास सिकुड़ते जा रहे हैं और **मानवीय गतिविधियाँ वन्यजीव क्षेत्रों** पर अतिक्रमण कर रही हैं, **मनुष्यों और जानवरों**, मुख्य रूप से **बाघों और हाथियों** के बीच टकराव बढ़ गया है, जिससे **दोनों समुदायों** के लिए खतरा पैदा हो गया है।
- **लोकसभा चुनाव** से पहले **केरल** जैसे **राज्यों** में यह एक **प्रमुख मुद्दा** बनकर उभरा है। सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने और **भारत की प्राकृतिक विरासत** को **संरक्षित** करने के लिए इस **संघर्ष** को समझना और कम करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

- **जनसंख्या स्थिति**: भारत में जंगली हाथियों और बाघों की बड़ी आबादी रहती है, जिससे अक्सर मनुष्यों के साथ मुठभेड़ होती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों तरफ मौतें होती हैं।
- **पर्यावास विखंडन:** शहरीकरण, कृषि विस्तार और ढांचागत विकास ने प्राकृतिक आवासों को खंडित कर दिया है, जिससे वन्यजीवों को मानव बस्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- **आर्थिक प्रभाव:** फसल की बर्बादी और पशुधन के शिकार से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे समुदायों और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ जाता है।

आयाम - प्रभाव एवं चुनौतियाँ

- **आर्थिक कठिनाइयाँ**: फसल क्षति और पशुधन की हानि वन्यजीव आवासों के पास रहने वाले समुदायों की आजीविका को प्रभावित करती है।
- **मनोवैज्ञानिक संकट:** प्रभावित समुदायों में भय और चिंता व्याप्त है, जिससे वन्यजीवों के प्रति शत्रुता कायम है।
- **संरक्षण दुविधा** : मानव आजीविका आवश्यकताओं के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करना एक जटिल दुविधा प्रस्तुत करता है, जिससे अक्सर हितों का टकराव होता है।

आयाम - आवश्यक रणनीतियाँ

- **व्यापक दृष्टिकोण:** मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सक्रिय उपायों और सामुदायिक भागीदारी से युक्त एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है।
- **स्थायी समाधान** : बिजली की बाड़ और मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ जैसी नवीन निवारक विधियाँ वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाए बिना संघर्ष को कम कर सकती हैं।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण** : समुदाय-आधारित संरक्षण पहल और वैकल्पिक आजीविका विकल्पों में निवेश करने से वन्यजीवों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक-आर्थिक बोझ कम हो सकता है।

HWC प्रबंधन के छह तत्व

- **संघर्ष को समझना:** किसी भी स्थिति में संघर्ष के संदर्भ को समझने के लिए संघर्ष प्रोफ़ाइल के सभी पहलुओं पर शोध करना, HWC के घटित होने के बाद उसके प्रभावों को कम करना (मुआवजा, बीमा, वैकल्पिक आजीविका, आदि)
- **प्रतिक्रिया:** चल रही HWC घटना को संबोधित करना (प्रतिक्रिया दल, रिपोर्टिंग तंत्र, मानक संचालन प्रक्रियाएं, आदि)
- **रोकथाम** : HWC को घटित होने से पहले रोकना या रोकना (बाड़, शीघ्र पता लगाने वाले उपकरण, सुरक्षित कार्य वातावरण, आदि)
- **नीति** : प्रोटोकॉल, सिद्धांतों, प्रावधानों और कानून में निर्धारित और अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के माध्यम से HWC प्रबंधन को सक्षम करना (अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय और स्थानीय एचडब्ल्यूसी प्रबंधन योजनाएं, स्थानिक योजनाएं, आदि)
- **निगरानी** : समय के साथ HWC प्रबंधन हस्तक्षेपों के प्रदर्शन और प्रभावशीलता को मापना (डेटा संग्रह, सूचना साझा करना, अनुकूली प्रबंधन, आदि)

142. हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, निष्कर्षण विधियां- द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव
समाचार:

- सबसे आम रूप जिसमें ये **हाइड्रोकार्बन भूमिगत चट्टान** संरचनाओं में मौजूद हैं ये **प्राकृतिक गैस, कोयला**, **कच्चा तेल** और **पेट्रोलियम** हैं।
- ये आम तौर पर **भूमिगत जलाशयों** में पाए जाते हैं, जब अधिक **प्रतिरोधी चट्टान** का प्रकार कम प्रतिरोधी चट्टान पर हावी हो जाता है,

- वास्तव में एक ढक्कन बनाना जिसके कारण उसके नीचे **हाइड्रोकार्बन** जमा हो जाता है।

हाइड्रोकार्बन का स्रोत	**रॉक स्रोत**
• ऐसी संरचनाएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अन्यथा, हाइड्रोकार्बन सतह पर तैरेंगे और नष्ट हो जायेंगे। • इस चट्टानी भूमिगत में हाइड्रोकार्बन के प्राथमिक स्रोत को कार्बनिक पदार्थ के केरोजेन लुम्प्स कहा जाता है। • केरोजेन को तीन संभावित स्रोतों से जमा किया जा सकता है जैसे झील (लैक्स्ट्रिन), बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेष है । • केरोजेन के आसपास की चट्टानें समय के साथ गर्म हो सकती हैं, अधिक सघन हो सकती हैं, जिससे केरोजेन पर बल पड़ता है जिससे यह टूट जाता है। • लैकस्ट्रिन केरोजेन से मोमी तेल समुद्री केरोजेन, तेल और गैस और स्थलीय केरोजेन, हल्के तेल, गैस और कोयला प्राप्त होता है।	• केरोजेन युक्त चट्टान को स्रोत चट्टान कहा जाता है, और पेट्रोलियम भूवैज्ञानिकों को इसकी तलाश करने का काम सौंपा जाता है ○ इसकी भूभौतिकीय और थर्मल विशेषताओं को समझना, और हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को चिह्नित करना। • वे अवलोकन डेटा द्वारा सूचित मॉडलिंग गतिविधियाँ भी करते हैं और वहां हाइड्रोकार्बन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए छोटे अन्वेषण कुओं की खुदाई करते हैं, और संबंधित नियामक निकाय को इसकी रिपोर्ट करते हैं। • एक बार जब कोई विशेष स्थान हाइड्रोकार्बन का लाभदायक स्रोत निर्धारित हो जाता है, तो ड्रिलिंग शुरू हो सकती है

143. भारत के हितों के लिए आर्कटिक क्षेत्र का महत्व - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रसंग :

- **नॉर्वे** के **स्वालबार्ड** में **अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक रिसर्च** बेस में **भारत का अनुसंधान स्टेशन हिमाद्रि**, तब तक केवल गर्मियों में मिशन की मेजबानी करता था।
- एक शीतकालीन अभियान में कठोर अनुकूलन की अवधि के बाद तीव्र ठंड (-15 डिग्री सेल्सियस से कम) में रहना शामिल है।

आर्कटिक में बढ़ती रुचि	**सहयोग की संभावना**
• एक दशक से भी अधिक समय से, भारत के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र को आर्कटिक में शीतकालीन मिशन का कोई कारण नजर नहीं आया। • जाहिर तौर पर भारतीय नीति में जो बदलाव आया, वह वैज्ञानिक डेटा था जो दर्शाता है कि आर्कटिक पहले की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। • नई दिल्ली आर्कटिक समुद्री मार्गों, मुख्य रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग, के खुलने से उत्साहित है और इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय व्यापार को आगे बढ़ाना चाहेगी। • इससे भारत को माल भेजने में समय, ईंधन और सुरक्षा लागत के साथ-साथ शिपिंग कंपनियों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। • आर्कटिक में चीन के बढ़ते निवेश ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। • चीन को उत्तरी समुद्री मार्ग तक विस्तारित पहुंच प्रदान करने के रूस के फैसले ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। • इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ वर्ष 1920 से चली आ रही है। • वर्ष 2007 में, भारत ने आर्कटिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूविज्ञान की जांच के लिए अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू किया। • एक साल बाद, चीन के अलावा भारत आर्कटिक अनुसंधान आधार स्थापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन गया। • वर्ष 2013 में आर्कटिक काउंसिल द्वारा 'पर्यवेक्षक' का दर्जा दिए जाने के बाद, भारत ने वर्ष 2014 में स्वालबार्ड में एक मल्टी-सेंसर मूर्ड वेधशाला और वर्ष 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला शुरू की है। • इन स्टेशनों पर काम आर्कटिक बर्फ प्रणालियों और ग्लेशियरों और हिमालय और भारतीय मानसून पर आर्कटिक पिघल के परिणामों की जांच पर केंद्रित है।	• आर्कटिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष नॉर्वे के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। • वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, दोनों देशों ने आर्कटिक और अंटार्कटिक में बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ दक्षिण एशिया पर उनके प्रभाव की जांच के लिए सहयोग किया है। • भारत की वर्तमान नीति अपने 'जिम्मेदार हितधारक' की साख को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में हरित ऊर्जा, और हरित और स्वच्छ उद्योगों में आर्कटिक देशों के साथ सहयोग करना है। • उदाहरण के लिए, डेनमार्क और फ़िनलैंड के साथ, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय सहयोग आया है। • जबकि भारत सरकार आर्कटिक में समुद्री खनन और संसाधन दोहन से लाभ उठाने की इच्छुक है, उसे स्पष्ट रूप से निष्कर्षण के एक स्थायी तरीके का समर्थन करना चाहिए। • ये उन छह स्तंभों (अन्य चार हैं आर्थिक और मानव विकास; परिवहन और कनेक्टिविटी; शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण)। में से दो हैं जिनमें भारत की आर्कटिक नीति शामिल है

निष्कर्ष

- भारत शायद अब भी आर्कटिक में आर्थिक अवसर तलाशेगा।
- ऐसे में नॉर्वे भारत को एक ऐसी स्थायी नीति तैयार करने में मदद कर सकता है जो वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग दोनों की जरूरतों को पूरा करती हो।
- चूंकि आर्कटिक में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है, इसलिए दबाव कम करने के लिए रचनात्मक और गैर-संवेदनशील तरीके खोजना भारत और नॉर्वे दोनों के हित में होगा।

144. एशियाई देशों में प्रजनन क्षमता का स्तर - द हिन्दू

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

समाचार:

- **पूर्वी** और **दक्षिण पूर्व एशिया** के कई **देश जनसंख्या संकट** के बीच में हैं, हर साल **कम जन्म** और **रिकॉर्ड-कम प्रजनन दर** है।

श्रिंकिंग फैमिलीज़ : एक उभरती चुनौती	**गिरावट क्यों? इसके कई कारण हैं:**
• **समस्या** : पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में जन्म दर कम हो रही है, जिससे जनसंख्या संकट पैदा हो गया है। • मांग की कमी के कारण अस्पताल प्रसूति वार्ड भी बंद कर रहे हैं। **बदलाव** • वर्ष 1950 के दशक में, इस क्षेत्र के परिवारों में कई बच्चे थे। • अब, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में प्रजनन दर प्रति महिला 1 बच्चे से कम है, जिसका अर्थ है कि लोगों के पास अपनी जगह लेने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हैं।	• **बदलती प्राथमिकताएँ** : लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, या बिल्कुल भी बच्चे नहीं पैदा करना पसंद कर रहे हैं। बच्चों का पालन-पोषण करना महंगा है! • **नीतिगत गूँज:** पिछली परिवार नियोजन नीतियों ने बड़े परिवारों को हतोत्साहित किया होगा, और वे दृष्टिकोण अभी भी बने हुए हैं। • **आर्थिक दबाव:** महिलाओं के पास कैरियर के अधिक अवसर हैं, लेकिन विवाह दर में गिरावट आ रही है। बच्चों के पालन-पोषण की लागत तनाव की एक और परत जोड़ती है। • **प्रभाव:** यह घटती जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। • बुजुर्गों की बढ़ती संख्या का समर्थन करने के लिए कम युवा लोग होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ तनावपूर्ण हो जाएंगी। • सरकारें लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी खर्च कर रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं।

आगे की राह

- **स्मार्टर पॉलिसियां:** सरकारों को कम जन्म दर के मूल कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है।
- **सपोर्ट सिस्टम्स:** किफायती बाल देखभाल, माता-पिता की छुट्टी और वित्तीय सहायता बच्चों के पालन-पोषण के बोझ को कम कर सकती है।
- **वर्क लाइफ बैलेंस:** लचीले कार्य विकल्प और एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन लोगों को करियर और परिवार दोनों का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन**: हमें बदलती सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को अपनाते हुए परिवारों को महत्व देने के तरीके खोजने की जरूरत है।
- इस स्थिति में इन एशियाई देशों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है

145. तमिलनाडु का विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण मॉडल- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग :

- **तमिलनाडु, जो 19** अप्रैल को मतदान करता है, **आर्थिक जटिलता** के मामले में **भारत** का **नंबर 1 राज्य** है, जिसे उसके **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** और **रोजगार प्रोफ़ाइल की विविधता** से मापा जाता है।

मुख्य बिंदु	तमिलनाडु की आर्थिक तेजी के दो प्रमुख तत्व हैं:
• कृषि पर तमिलनाडु की कम निर्भरता अखिल भारतीय की तुलना में इसकी अर्थव्यवस्था में उद्योग, सेवाओं और निर्माण की उच्च हिस्सेदारी से मेल खाती है। • TN के फार्म GVA का लगभग 45.3% पशुधन उपक्षेत्र (सर्वोच्च) से आता है जो अखिल भारतीय औसत 30.2% से अधिक है। • यह भारत की सबसे बड़ी निजी डेयरी कंपनी (हैटसन एग्रो प्रोडक्ट), ब्रॉयलर एंटरप्राइज (सुगुना फूड्स), एग प्रोसेसर (SKM ग्रुप) और "एग कैपिटल" (नमक्कल) का घर है।	• **क्लस्टर पावर:** विशाल कारखानों के बजाय, राज्य ने विशिष्ट उद्योगों में विशेषज्ञता वाले छोटे व्यवसायों के क्लस्टर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। • **टीम एफर्ट** - तिरुपुर (बुना हुआ कपड़ा के लिए प्रसिद्ध) जैसे क्लस्टर में कंपनियां एक-दूसरे के विकास का समर्थन करती हैं। • इस दृष्टिकोण ने छोटे शहरों और गांवों में नौकरियां पैदा की हैं, जिससे लोगों को खेती के अलावा अन्य विकल्प भी मिले हैं। • उदाहरण के लिए, तिरुपुर का फलता-फूलता बुना हुआ कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, जो अन्य राज्यों से भी श्रमिकों को आकर्षित करता है। • **घरेलू ऊधम** : इसके पीछे प्रेरक शक्ति बड़े निगम नहीं, बल्कि स्थानीय उद्यमी हैं। • कई लोग खेती या छोटे व्यवसाय की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो हैटसन (अरुण आइसक्रीम और अरोक्या दूध के लिए जाना जाता है) जैसे सफल ब्रांड बनाते हैं। • शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में राज्य के निवेश के साथ मिलकर इस "जमीनी स्तर की उद्यमिता" ने संभवतः कृषि से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में तमिलनाडु की सफलता को बढ़ावा दिया है।

SECTOR-WISE SHARES OF GVA & WORKFORCE: 2022-23 (%)

	Gross Value Added*		Workforce	
	All-India	Tamil Nadu	All-India	Tamil Nadu
Agriculture	18.19	12.55	45.76	28.87
Industry**	18.80	22.69	12.27	17.88
Construction	8.84	11.70	13.03	18.04
Services	54.18	53.05	28.94	35.21

*At Basic Prices; ** Includes manufacturing, mining, electricity and utilities. GVA is GDP net of product taxes and subsidies. Source: National Accounts Statistics and Periodic Labour Force Survey.*

146. मतदान प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता- द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रसंग :

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** के अनुसार वोट गणना के साथ **वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** पर्चियों के **100% क्रॉस-सत्यापन** की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

मतदान प्रक्रिया का इतिहास

- वर्ष 1952 और वर्ष 1957 के पहले दो आम चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उनके चुनाव चिन्ह के साथ एक अलग बॉक्स रखा गया था।
- इसके बाद तीसरे चुनाव से, उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों के साथ मतपत्र पेश किया गया जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मुहर लगाते थे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)को 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर पेश किया गया था।
- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग (2013) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- वर्ष 2019 के चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में EVM 100% VVPAT के साथ समर्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

- कई पश्चिमी लोकतंत्रों में चुनावों के लिए कागजी मतपत्र जारी हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों ने पिछले दो दशकों में परीक्षणों के बाद, राष्ट्रीय या संघीय चुनावों के लिए EVM का उपयोग बंद कर दिया है।
- जर्मनी में, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में चुनावों में EVM के इस्तेमाल को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- हालाँकि, ब्राज़ील जैसे कुछ देश अपने चुनावों के लिए EVM का उपयोग करते हैं।

EVM के फायदे

- EVM ने वोट डालने की दर को प्रति मिनट चार वोट तक सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को लगभग समाप्त कर दिया है और इस प्रकार झूठे वोट भरने के लिए आवश्यक समय में काफी वृद्धि हुई है।
- अवैध वोट, जो कागजी मतपत्रों का अभिशाप थे और मतगणना प्रक्रिया के दौरान विवाद का कारण भी थे, उन्हें EVM के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
- हमारे मतदाताओं की संख्या, जो एक अरब के करीब है, को ध्यान में रखते हुए, EVM का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल है क्योंकि इससे कागज की खपत कम हो जाती है।
- अंततः, यह मतदान के दिन मतदान अधिकारियों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है और मतगणना प्रक्रिया को तेज़ और त्रुटि मुक्त बनाता है।

EVM की अखंडता कैसे बरकरार रखें?

- इनमें मतदान से पहले बूथों पर EVM का यादृच्छिक आवंटन शामिल है
- वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले EVM और VVPAT की शुद्धता प्रदर्शित करने के लिए मॉक पोल का आयोजन होता है।
- वोकुल डाले गए वोटों के साथ EVM की क्रम संख्या को वोटों की गिनती के समय सत्यापित करने के लिए उम्मीदवारों के एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

आरोप

- सबसे बार दोहराया जाने वाला आरोप यह है कि EVM हैकिंग के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
- वर्तमान में VVPAT पर्चियों के साथ EVM की गिनती के मिलान के लिए नमूना आकार प्रति विधानसभा क्षेत्र/खंड पांच है।
- यह किसी भी वैज्ञानिक मानदंड पर आधारित नहीं है और गिनती के दौरान दोषपूर्ण EVM का पता लगाने में विफल हो सकता है।

आगे की राह

- विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार प्रत्येक **राज्य को बड़े क्षेत्रों** में विभाजित करके **EVM गणना** और **VVPAT पर्चियों** के मिलान के लिए नमूना वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाना चाहिए।
- एक भी त्रुटि के मामले में**, VVPAT** पर्चियों को संबंधित क्षेत्र के लिए पूरी तरह से गिना जाना चाहिए और परिणामों के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।
- इससे मतगणना प्रक्रिया में **सांख्यिकीय रूप** से महत्वपूर्ण विश्वास पैदा होगा।
- इसके अलावा, बूथ स्तर पर मतदाताओं को कवर की एक डिग्री प्रदान करने के लिए, **'टोटलाइज़र' मशीनें** पेश की जा सकती हैं जो उम्मीदवार-वार गिनती का खुलासा करने से पहले **15-20 EVM** में वोटों को एकत्रित करेंगी।

147. दुबई में मूसलाधार बारिश का कारण क्या है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** में हाल ही में आए **भीषण तूफान** के बाद अब तक की सबसे भारी **बारिश** दर्ज की गई।
- **सरकारी WAM** समाचार एजेंसी के अनुसार**, बारिश** "**एक ऐतिहासिक मौसम घटना**" थी, जो **वर्ष 1949** में **डेटा संग्रह** की शुरुआत के बाद से दर्ज की गई किसी भी चीज़ से अधिक थी, जो कि **वर्ष 1971** में **संयुक्त अरब अमीरात** की स्थापना से पहले थी।

मुख्य बिंदु
- संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश असामान्य है, जो एक शुष्क, अरब प्रायद्वीप देश है, हालांकि, वे कभी-कभी ठंडे सर्दियों के महीनों के दौरान इस क्षेत्र में होते हैं।
- बारिश असामान्य है, हालाँकि यह ठंडी सर्दियों के दौरान भी हो सकती है।
- पूरे क्षेत्र में चलने वाली तूफान प्रणाली मुख्य जिम्मेदार है।
- इसमें चांस क्लाउड सीडिंग की भी भूमिका हो सकती है, जो बारिश वाले बादलों को अधिक पानी छोड़ने की तकनीक है।

क्या जलवायु परिवर्तन शामिल हो सकता है?
- दुनिया भर में बढ़ते तापमान से वातावरण में अधिक नमी हो सकती है, जिससे अधिक तीव्र तूफान आ सकते हैं।
- लेकिन किसी एक मौसम घटना को जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर जोड़ना कठिन है क्योंकि अल नीनो और ला नीना जैसी अन्य चीजें भी मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
- जहां वर्ष 1850 के बाद से पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 60 वर्षों में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है।
- तापमान में वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से हीट-ट्रैपिंग ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में वृद्धि के कारण हुई है।

IPCC रिपोर्ट
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई है।
  - रिपोर्ट में कहा कि ग्रीनहाउस गैसों में मानव-जनित वृद्धि ने चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की है।
- खाड़ी के कई हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण भी जलवायु पैटर्न में बदलाव के पीछे एक कारण है

क्लाउड सीडिंग
- बादलों को बारिश कराने के लिए छोटी पानी या बर्फ की बूंदों की आवश्यकता होती है जिन्हें नाभिक कहा जाता है।
- मौसम संशोधन विधि में अधिक नाभिक बनाने वाले बादलों में कणों को मारने के लिए विमानों और जमीन-आधारित तोपों का उपयोग किया जाता है
  - नमी को आकर्षित करना जो बर्फ और बारिश के रूप में गिरती है।
- आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह सूखी बर्फ और अन्य सामग्री भी हो सकती है।
- यह विधि, जो पहली बार वर्ष 1940 के दशक में शुरू की गई थी, यह विधि 1960 के दशक में मुख्य रूप से बर्फ के लिए अमेरिकी पश्चिम में लोकप्रिय हो गई।
- यह साफ आसमान से पानी नहीं बना सकता है, कणों को एक तूफानी बादल में फेंकना होगा जो पहले से ही नमी रखता है ताकि वह गिर सके या स्वाभाविक रूप से उससे अधिक गिर सके।

148. दक्षिण चीन सागर में भारत का दृष्टिकोण - द हिन्दू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
समाचार:
- हाल ही में, **भारत** के **विदेश मंत्री** ने **मनीला** की अपनी यात्रा के दौरान एक **संयुक्त बयान** में, अपनी **राष्ट्रीय** संप्रभुता को बनाए रखने में **फिलीपींस** को **भारत का पूर्ण समर्थन** व्यक्त किया।

मुख्य बिंदु
- वर्ष 2023 में नई दिल्ली और मनीला के बीच एक संयुक्त बयान में भी चीन से नियम-आधारित समुद्री आदेश का पालन करने और मनीला के पक्ष में वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने का आह्वान किया गया था।
- हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर पर नई दिल्ली की स्थिति में काफी बदलाव आया है।

नीति विकास
- इस क्षेत्र के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव शुरू में मुख्य रूप से आर्थिक था, जो उसकी पूर्व की ओर देखो नीति से प्रेरित था
  - जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना और इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने की अनिवार्यता है।
- प्रधानमंत्री प्रशासन के तहत लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक भारत की नीति अभिविन्यास में परिवर्तन ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ अधिक रणनीतिक और सक्रिय जुड़ाव की ओर बदलाव को चिह्नित किया है।
- यह नीति विकास बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के प्रति भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है
- भारत ने साथ ही आगे की स्थिति, मिशन-आधारित तैनाती, सुदृढ़ समुद्री डोमेन जागरूकता और गहरे पानी की समुद्री सुविधाओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं को भी मजबूत किया है।

चीन के साथ भारत के जटिल संबंध
- दोनों देशों के बीच सीमा विवादों का एक लंबा इतिहास है जो वर्ष 2020 की गलवान घाटी घटना के बाद से और भी गहरा गया है
  - बीजिंग द्वारा समय-समय पर भारत के क्षेत्र में घुसपैठ और, हाल ही में, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय गांवों का नाम बदलने के के बाद से तेज हो गया है।
- असममित निरोध के लिए भारत की क्षमता के प्रदर्शन में भारत दक्षिण चीन सागर में एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत भेज रहा है।
- नियमित नौसैनिक अभ्यास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने सहित भारत की रणनीतिक गतिविधियां दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं:
  - ये क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं
  - चीन के गैरकानूनी दावों के प्रतिकार के रूप में कार्य करें।

आसियान फैक्टर
- दक्षिण चीन सागर में विवादों में मुख्य रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के कई देश शामिल हैं
- इंडो-पैसिफिक में एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में, भारत अब ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामलों पर स्पष्ट रुख अपनाने से नहीं कतरा सकता है।
- भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका भी भारत के लिए आसियान की स्थिति को मजबूत करना अनिवार्य बनाती है

निष्कर्ष

- इसलिए, **दक्षिण चीन सागर** में **भारत** का **सूक्ष्म दृष्टिकोण** उसकी **व्यापक रणनीति** का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य **भारत-प्रशांत क्षेत्र** में **शांति, स्थिरता** और **अंतरराष्ट्रीय कानून** के सम्मान को बनाए रखने के **सामूहिक** प्रयास में योगदान करते हुए अपने **हितों** की रक्षा करना है।

149. निजी निवेश में गिरावट से सम्बंधित मामला - द हिन्दू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- **सकल स्थिर** पूंजी निर्माण द्वारा मापा गया **निजी निवेश** गति नहीं पकड़ पा रहा है और **वर्ष 2011-12** से इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था** इस मुद्दे से त्रस्त है और **सरकार** को उम्मीद है कि **बड़े भारतीय निगम** इसमें कदम बढ़ाएंगे और निवेश बढ़ाएंगे।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1980 के दशक के अंत और वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों के कारण निजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के विश्वास में सुधार हुआ।
- इस बीच, निजी निवेश मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से थोड़ा नीचे या ऊपर बना हुआ है।
- दूसरी ओर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक निवेश,वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद के 3% से भी कम से बढ़कर वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश से आगे निकल गया।
- हालाँकि, उदारीकरण के बाद निजी निवेश के स्थिर पूंजी निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ इसमें गिरावट शुरू हो गई।
- निजी निवेश में वृद्धि वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट तक जारी रही।
- यह वर्ष 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% से बढ़कर वर्ष 2007-08 में लगभग 27% हो गया।
- हालाँकि,वर्ष 2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई और वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 19.6% के निचले स्तर पर पहुँच गया।

निजी निवेश में लगातार गिरावट के कारण:

- कई अर्थशास्त्री विशेष रूप से महामारी के बाद निजी निवेश में वृद्धि में विफलता के लिए कम निजी उपभोग व्यय को जिम्मेदार मानते हैं।
  - उनका कहना है कि व्यवसायों को विश्वास दिलाने के लिए मजबूत उपभोग व्यय की आवश्यकता है।
  - एक बार जब वे निश्चित पूंजी के निर्माण में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो आउटपुट की पर्याप्त मांग जुटाई जा सकती है।
- हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से, भारत में निजी उपभोग और निजी निवेश के बीच विपरीत संबंध के प्रमाण मिले हैं।
- उपभोग और निवेश के बीच विपरीत संबंध होने की संभावना है क्योंकि बचत और निवेश के लिए सरकार या निजी व्यवसायों द्वारा जो पैसा आवंटित किया जाता है, वह कम उपभोग व्यय की कीमत पर आता है।
- अन्य अर्थशास्त्री भी मानते हैं, पिछले दशक में, प्रतिकूल सरकारी नीति और नीतिगत अनिश्चितता जैसी संरचनात्मक समस्याओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश में गिरावट आई है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF):

- GFCF किसी अर्थव्यवस्था में स्थिर पूंजी के आकार में वृद्धि को संदर्भित करता है।
- स्थिर पूंजी में भवन और मशीनरी जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिन्हें बनाने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है
- निजी GFCF किसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र कितना निवेश करने को तैयार है, इसका अनुमानित मूल्य दर्शाने का काम कर सकता है।
- GFCF में सरकार द्वारा निवेश के परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण भी शामिल है।
- GFCF महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित पूंजी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद कर सकती है।

150. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से रोका - द हिंदू

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, जनादेश।

प्रसंग:

- **संयुक्त राष्ट्र** में **फ़िलिस्तीन** को **पूर्ण सदस्य** का दर्जा देने पर **अल्जीरिया** द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा **वीटो** कर दिया गया था।
- भले ही **फ़िलिस्तीन राज्य** को **वर्ष 2012** में स्थायी **संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक** का दर्जा और **वर्ष 2019** में पूर्ण सदस्य की **अस्थायी शक्तियाँ** प्राप्त हुईं, फिर भी इसे **पूर्ण सदस्य** के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- इज़राइल **वर्ष 1949** में **संयुक्त राष्ट्र** का पूर्ण सदस्य बन गया।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष:

- वर्तमान संघर्ष की जड़ें **20वीं** सदी में हैं।
- **वर्ष 1917** की **बाल्फोर घोषणा** में ब्रिटिश सरकार ने "**फिलिस्तीन** में **यहूदी** लोगों के लिए एक **राष्ट्रीय घर** की स्थापना" की घोषणा की है ।
  - यह घोषणा **प्रथम विश्व युद्ध** के लिए **यहूदी समर्थन** हासिल करने की आशा में थी।
- **फ़िलिस्तीन** में **अरबों** ने **फ़िलिस्तीनियों** की **अधीनता** की **चिंताओं** पर इस **घोषणा** का विरोध किया।
- **प्रथम विश्व युद्ध** के बाद **फ़िलिस्तीन** में **ब्रिटिशों** द्वारा एक **उपनिवेश स्थापित** किया गया था ताकि इस क्षेत्र पर शासन किया जा सके जब तक कि **फ़िलिस्तीनी स्वयं शासन** करने के लिए तैयार न हो जाएँ।
  - इसे अनिवार्य **फ़िलिस्तीन** कहा गया क्योंकि यह **राष्ट्र संघ** के आदेश के अनुसार था।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान, कई **यहूदी नरसंहार** से बचकर यूरोप भाग गए और उन्हें **फ़िलिस्तीन** लाया गया।
- वर्षों से **इज़राइल और फ़िलिस्तीन** के बीच तनाव बना हुआ है और कुछ देश **दो-राज्य समाधान** का पक्ष ले रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** ने **संयुक्त राष्ट्र** के **छह प्रमुख अंगों** की स्थापना की, जिनमें से एक **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा** परिषद थी।
- **UNSC** के पास **अंतर्राष्ट्रीय शांति** और **सुरक्षा** बनाए रखने का प्रभार है।
- परिषद में **15 सदस्य** हैं:
  - **पांच स्थायी सदस्य** - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
  - भारत सहित दस गैर-स्थायी सदस्य (दो साल के लिए निर्वाचित)।
- परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं।

151. पर्यावरण और उद्योग के बीच संतुलन - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** का अनुमान है कि **अप्रैल** से **जून** तक भीषण गर्मी होगी और लंबी लू चलेगी। **भारत** को **जल संकट** के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
- यह **पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल)** एक सचेतक आह्वान होना चाहिए।

मुख्य बिंदु

- पृथ्वी के 2.4% क्षेत्रफल पर विश्व की 18% आबादी भारत में निवास करती है और वैश्विक मीठे जल संसाधनों का मात्र 4% भारत के पास है।
- इसकी लगभग आधी नदियाँ प्रदूषित हैं, और इसके 150 प्राथमिक जलाशय वर्तमान में उनकी कुल भंडारण क्षमता का केवल 38% हैं।
- इसके अलावा, यह दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- और भारत के तीन-चौथाई जिले चरम जलवायु घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट हैं।
- इस पृष्ठभूमि में, भारत ने आपदा तैयारियों में भारी निवेश किया है, लेकिन जलवायु संबंधी प्रभावओं की प्रकृति बदलती रहेगी।

अर्थव्यवस्था में पानी का महत्व

- पानी हमारे जल विज्ञान, भोजन और ऊर्जा प्रणालियों को जोड़ता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
- लेकिन सबसे अधिक रोजगार देने वाला यह क्षेत्र तेजी से जलवायु के प्रति संवेदनशील है।
- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि कृषि अभी भी लगभग 45% आबादी को रोजगार देती है और देश की अधिकांश श्रम शक्ति को अवशोषित करती है।
- उसी समय, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में मानसूनी वर्षा का पैटर्न बदल रहा है।
- लेकिन यह बढ़ी हुई वर्षा अक्सर कम अवधि की, भारी वर्षा के कारण होती है, जिससे फसल की बुआई, सिंचाई और कटाई प्रभावित होती है।
- कृषि क्षेत्र को जलवायु और जल तनाव के प्रति अधिक रेसिलिएंट बनाना नौकरियों, विकास और स्थिरता के लिए मायने रखता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे डीकार्बोनाइजिंग उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त पानी और बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।

आपदा

- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, पिछले दो दशकों में लगभग 75% प्राकृतिक आपदाएँ पानी से संबंधित थीं।
- CEEW विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1970 से वर्ष 2019 के बीच भारत में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं (जैसे भूस्खलन, तूफान और बादल फटना) की संख्या 20 गुना तक बढ़ गई है।
- मीठे पानी, नौ ग्रहों की सीमाओं में से एक का उल्लंघन (2023 अध्ययन) किया गया है ।

जल सुरक्षा के तत्व

- इस जल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए सही नीतियों, शहरी अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग सहित पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और बदलती दुनिया को अपनाने के लिए वित्त के मिश्रण की आवश्यकता होगी।
- सबसे पहले, प्रभावी जल प्रशासन को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो भोजन और ऊर्जा प्रणालियों के साथ इसकी अंतःक्रिया को पहचानें।
- हालाँकि, CEEW और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) के विश्लेषण से पता चलता है कि हालाँकि भारत ने कई नीतियां अपनाई हैं, लेकिन अधिकांश योजना बनाते समय या कार्यान्वयन चरण में इस गठजोड़ को नहीं पहचानते हैं।
- राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है।
- इसी तरह, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन पर अटल मिशन (अमृत) 2.0 में शहरी स्थानीय निकायों में गैर-राजस्व पानी को 20% से कम करने का आह्वान किया गया है, जो अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है।
- भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे बाज़ार नवाचारों में अपशिष्ट जल उपचार में निवेश को प्रोत्साहित करके अनुकूलन निधि अंतर को आंशिक रूप से पाटने की क्षमता है।
  - अलवणीकरण संयंत्र, और कृषि विस्तार सेवाएँ।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (2014-15 और 2020-21 के बीच) के तहत भारत में निवेश को ध्यान में रखते हुए, हर साल लगभग ₹12,000 करोड़ के निवेश का लाभ उठाने की संभावना है।

निष्कर्ष

- जल, ऊर्जा और जलवायु नीतियों में अधिक सामंजस्य स्थापित करके, जल बचत बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित आधार रेखाएं बनाकर और अनुकूलन निवेश के लिए नए वित्तीय उपकरणों और बाजारों को सक्षम करके शुरुआत करना संभव है।जल-सुरक्षित अर्थव्यवस्था क्लाइमेट -रेसिलिएंट अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला कदम है।

152. ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भूकंप जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ

समाचार:

- हाल ही में **ताइवान में 7.4 तीव्रता** का भूकंप आया था ।
- पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया, जापान, चीन, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इक्वाडोर, मैक्सिको, मोरक्को और तुर्की-सीरिया सीमा सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़े भूकंप आए हैं।

मुख्य बिंदु:

- भूकंपों के स्थानिक वितरण को प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत द्वारा समझाया गया है,
  - जो बताता है कि कैसे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, स्थलमंडल, 15 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है जो लगातार एक दूसरे के सापेक्ष घूम रही हैं।
  - यही कारण है कि शक्तिशाली भूकंप हिमालय जैसी अभिसरण प्लेट सीमाओं पर केंद्रित होते हैं , जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण का एक टेक्टोनिक उत्पाद है।
- वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने मध्य नेपाल में भारी तबाही मचाई, लेकिन भारत इससे बच गया। हिमाचल प्रदेश में मनाली के आसपास के क्षेत्र में हाल ही में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था।
- ताइवान जो कि तेज़ भूकंपों वाला देश है।
- इसका निर्माण पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपीन और यूरेशियन प्लेटों की अभिसरण सीमा पर हुआ था।
  - फिलीपीन सागर प्लेट उत्तर-पश्चिम में यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जो भारतीय प्लेट की गति से भी तेज है।
- आज, ताइवान की भूकंप संबंधी तैयारियां दुनिया में सबसे उन्नत हैं।
  - ताइवान के पास सबसे उन्नत भूकंप-निगरानी नेटवर्क और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
  - व्यापक जागरूकता अभियान और सुरक्षा अभ्यास के साथ-साथ भूकंप सुरक्षा आवश्यकताओं पर सरकार के निरंतर अद्यतन ने भूकंप के जोखिमों के बारे में जनता की समझ में सुधार किया है।
- प्रत्येक स्थान पर कंपन कितना गंभीर होगा, इसके आधार पर ताइवान ठोस वैज्ञानिक निर्णय तक पहुंचने में सक्षम है ।
  - ताइवान की सबसे प्रतिष्ठित इमारत, ताइपे 101 , नवीनतम भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त होने से बच गई।

भारत में भूकंप बचाव संबंधी प्रयास :

- आधारभूत संरचना के विस्तार के एक बड़े चरण से गुजर रहा है , इसलिए भूकंप सुरक्षा विशेष चिंता का विषय होनी चाहिए। सभी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भूकंपीय सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
- ताइवान का भूकंप भारत के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।
  - इनमें भूकंपीय कोड का पालन करना , सुरक्षित इंजीनियर संरचनाओं का निर्माण करना, और भूकंपीय कोड के प्रवर्तन और गैर-अनुपालन में अपर्याप्तताओं पर काबू पाना शामिल है।
  - भारत के कुछ हिस्सों में, भूकंप प्रतिरोधकता रखने वाली पारंपरिक वास्तुकला शैलियों को फिर से खोजा और प्रोत्साहित किया जा सकता है।

153. जलवायु परिवर्तन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान- द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- **यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय** ने **स्विट्जरलैंड सरकार** को **स्विस नागरिक समाज** समूह की **महिला वरिष्ठ नागरिकों** के एक **समूह के अधिकारों** का उल्लंघन करने का दोषी पाया है ।

- इसमें कहा गया है कि **उत्सर्जन** पर अंकुश लगाने के लिए **सरकार की कार्रवाई** अपर्याप्त थी और **जलवायु परिवर्तन** के प्रभावों से **महिलाओं की रक्षा** करने में विफल रही थी।

मुख्य बिंदु:	जलवायु संकट से बचने के उपाय:

• यह निर्णय, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे जलवायु संकट तेजी से मानवाधिकार संकट बनता जा रहा है।
• एक महीने पहले भारत में भी ऐसा ही एक संकटपूर्ण क्षण आया था, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था कि लोगों को 'जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने' का अधिकार है।
• विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की नवीनतम स्थिति से पता चला है कि अधिकांश जलवायु परिवर्तन संकेतक 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
  ○ इसने पुष्टि की कि तापमान की वैश्विक रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद से 2023 सबसे गर्म वर्ष होगा।
  ○ समुद्र की गर्मी, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की कमी और ग्लेशियर के पीछे हटने के रिकॉर्ड भी टूट गए है।
• ग्रह का स्वास्थ्य अत्यधिक टेंशन में है, जिससे लोगों के स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है।
• भारत ने आर्थिक विकास से उत्सर्जन को अलग करने की दिशा में तेजी से प्रगति की है। इसने अपने दो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य भी हासिल कर लिए हैं ,
  ○ अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33% घटाकर 35% करना।
  ○ लक्ष्य वर्ष 2030 से काफी पहले, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
• हालाँकि, देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। इसकी 80% से अधिक आबादी उन जिलों में रहती है जो जलवायु-प्रेरित आपदाओं के जोखिम में हैं।
	• जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक विनियमन को अपनाना जबकि भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई कानून और नियम हैं, एक रूपरेखा कानून जलवायु शासन को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
	• सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए भारत के स्थानीयकरण मॉडल ने SDG को बहु-स्तरीय और बहु-हितधारक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर की योजना में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
	  ○ एक अन्य मार्ग एक स्वास्थ्य पहल की तरह ही अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है।
	• पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई पर अधिकार-आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समूहों और नागरिक समाज संगठनों को सशक्त बनाना।

154. भारत में आय और धन असमानता - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
समाचार:

- मार्च में, **असमानता** और **सार्वजनिक नीतियों** पर केंद्रित एक **वैश्विक अनुसंधान केंद्र, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब** ने 'भारत में आय और धन असमानता, 1**922-2023: द राइज़ ऑफ़ द बिलियनेयर राज**' शीर्षक से एक **वर्किंग पेपर** प्रकाशित किया।

मुख्य बिंदु **आय और धन असमानता**	**मानव विकास**
• रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष2022-23 तक, भारत की राष्ट्रीय आय का 22.6% देश के शीर्ष 1% लोगों के पास चला गया, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक है। • और केवल शीर्ष 0.1% आबादी ने भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग 10% अर्जित किया। • शीर्ष 10% के बीच संपत्ति का हिस्सा 1961 में 45% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 65% हो गया। • भारत की धन असमानता ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जितनी चरम नहीं है, जहां शीर्ष 10% लोगों के पास क्रमशः 85.6% और 79.7% राष्ट्रीय संपत्ति है। • हालाँकि, वर्ष 1961 और वर्ष 2023 के बीच इसकी संपत्ति का संकेन्द्रण तीन गुना बढ़ गया है । • इसके अतिरिक्त, चूँकि भारत की आय असमानता दुनिया में सबसे अधिक है, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से भी अधिक, यह केवल धन असमानता को बढ़ाएगी। • वर्ष 1980 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही असमानता बढ़ने लगी और भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यह तेजी से बढ़ने लगी है। • यहां, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि उच्च आर्थिक विकास और असमानता में कमी के दोहरे उद्देश्य केवल मानव विकास में सुधार और गरीबी में कमी के साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं। • राष्ट्रीय स्तर पर, जिन राज्यों ने तीन दशकों तक उच्च विकास दर (प्रति वर्ष 7% GSDP से अधिक) कायम रखी, ये मानव विकास में अपेक्षाकृत उन्नत थे। • इनमें दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात और उत्तर में पंजाब और दिल्ली शामिल हैं। • मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। • उदारीकरण के बाद ये राज्य केवल 5% प्रति वर्ष से कम की विकास दर दर्ज करने में सक्षम थे।	• मानव विकास रिपोर्ट (HDR) वर्ष 2023-2024 में भारत को 193 देशों में से 134वां स्थान दिया गया। • भारत अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन मानव विकास में यह अभी भी श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से नीचे है। • इसकी आर्थिक वृद्धि मानव विकास में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है। • गरीबों को आर्थिक विकास के लाभों के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, मानव विकास को समावेशी विकास को बढ़ावा देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। • HDR 2023-2024 के अनुसार, अगर हम आर्थिक असमानता को ध्यान में रखें तो भारत का स्कोर 31.1% कम हो जाता है। • आर्थिक असमानता की सीमा ऐसी है कि इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से दूर नहीं किया जा सकता है, जो लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कुछ किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। • नौकरियों के बिना रियायतें निरंतर और समावेशी विकास का आधार नहीं हो सकतीं। • जैसा कि पेपर कहता है, "यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की असमानता का स्तर बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बिना कितने समय तक बना रह सकता है"।

155. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी(PMAY-U) - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रसंग :

चूंकि वर्तमान **केंद्र सरकार** ने **दो कार्यकाल** पूरे कर लिए हैं, इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक **वर्ष 2015** में **PMAY** (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजना के तहत **शहरी और ग्रामीण** दोनों क्षेत्रों में **वर्ष 2022** तक सभी के लिए आवास (HfA) था।

PMAY योजना	**PMAY में समस्याएँ**

• योजना के घोषित उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  ○ निजी डेवलपर्स की भागीदारी से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों का पुनर्वास
  ○ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं (CLSS) के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना
  ○ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास
  ○ लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के लिए सब्सिडी।
योजना किस प्रकार फलीभूत हुई?
• भले ही योजना के पूरा होने में दो साल और बीत चुके हैं, HfA एक दूर की वास्तविकता बनी हुई है।
• अगस्त 2022 में, सरकार ने PMAY-शहरी (PMAY-U) को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।
  ○ पहले से स्वीकृत आवासों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश।
• ICRIER के एक अध्ययन के अनुसार, शहरी आवास की कमी 54% बढ़ गई, वर्ष 2012 में 1.88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018 में 2.9 करोड़ हो गई है।
• इसका मतलब यह है कि जिस वर्टिकल को सबसे बड़ी मांग को पूरा करना चाहिए, जिसे इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) कहा जाता है, वह विफल हो गया है।
• PIB प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ISSR के तहत, जो शहरों में सबसे बड़ी जरूरत है, पात्र लाभार्थियों के लिए केवल 2,10,552 घर स्वीकृत किए गए हैं।
	• यह योजना सामाजिक आवास में सार्वजनिक निवेश के अंतर को पाटने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्साहित है।
	• ज़मीन भी एक बड़ा मुद्दा था.
	• हवाई अड्डों, रेलवे, वनों आदि के तहत पंजीकृत भूमि ISSR के लिए असंभव थी। इसके अलावा, ISSR की योजनाएं समुदाय की किसी भी भूमिका के बिना, सलाहकारों द्वारा तैयार की गईं है।
	• एक और बड़ी बाधा शहर के मास्टर प्लान और PMAY-U के बीच मौजूद विरोधाभास है।
	• अधिकांश शहरों की योजनाएँ अब बड़े सलाहकारों द्वारा तय की जा रही हैं जो बड़े पूंजी-गहन तकनीकी समाधानों के पक्षधर हैं।
	• उदाहरण के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने 2041 मास्टर प्लान में पारगमन-उन्मुख विकास मॉडल की वकालत की जा रही है।
	• यह सामाजिक आवास के बारे में बात नहीं करता है और कहता है कि यह बाजार शक्तियों से आना चाहिए। ऐसे में PMAY के लगभग सभी वर्टिकल फेल हो जाते हैं.
	• PMAY की वास्तुकला भूमिहीनों और गरीबों को संबोधित नहीं करती है। स्वीकृत घरों में से लगभग 62% BLC वर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, जहां सरकार की भूमिका केवल लाभार्थियों के साथ लागत साझा करने तक सीमित है।
	• CLSS लाभार्थियों की संख्या 21% मानी जाती है। उपरोक्त दोनों में, सरकार की सीमित भूमिका है और इसमें केवल ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि भूमि का स्वामित्व लाभार्थियों के पास है।
	• जिन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों का ISSR के तहत पुनर्वास किया जाना है, ये कुल लाभार्थियों का लगभग 2.5% हैं।
	• जबकि PMAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें वित्तीय योगदान देना होता है।
	• ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत कुल निवेश व्यय में केंद्र का योगदान लगभग 25% या ₹2.03 लाख करोड़ है।
	• धनराशि का बड़ा हिस्सा लाभार्थी परिवारों द्वारा स्वयं खर्च किया जाता है, जो कि 60% या ₹4.95 लाख करोड़ है।

156. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रसंग:

- जब **भारत सरकार** ने **वर्ष 2019** में **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** शुरू किया, तो उसे **वर्ष 2017** के स्तर से **वर्ष 2024** तक **वायुमंडलीय पार्टिकुलेट मैटर (PM)** की एकाग्रता में **20-30%** की कटौती करनी थी।
- इसे बाद में **वर्ष 2026** तक संशोधित कर **40%** कर दिया गया।

मुख्य बिंदु	NCAP की फंडिंग और प्रोग्रेस:
• वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए NCAP की योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई, NCAP शहर-विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ हवा का लक्ष्य रखता है। • लगातार उच्च प्रदूषण स्तर वाले शहरों को ये योजनाएँ बनानी और क्रियान्वित करनी चाहिए। **NCAP के लक्ष्य:** • सख्त नियंत्रण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करें • संपूर्ण भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार लाना • वायु प्रदूषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना	• कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। • वायु गुणवत्ता सूचना केंद्र और पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करने में देरी हुई है। • आवंटित धनराशि का केवल एक हिस्सा ही अब तक उपयोग किया गया है। • हालांकि निरंतर वायु निगरानी स्टेशनों पर अच्छी प्रगति हुई है, नियमित निगरानी नेटवर्क का विस्तार पिछड़ रहा है। **NCAP के सामने चुनौतियाँ:** • राज्यों ने योजनाओं को लगातार क्रियान्वित नहीं किया है। • अस्पष्ट प्रक्रियाओं और समय-सीमा की कमी के कारण विलंब। • अन्य बाधाओं में नौकरशाही और कुछ उपायों की प्रभावशीलता पर संदेह शामिल हैं।

NCAP के लिए आगे की राह:

- प्रदूषण स्रोतों को इंगित करने के लिए अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।
- वायु गुणवत्ता मॉडलिंग से दूर के स्रोतों से प्रदूषण के प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है।
- इसका धरातल पर तेजी से कार्यान्वयन जरूरी है।
- कुल मिलाकर, स्वच्छ हवा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक होगा।
- NCAP की सफलता मजबूत विज्ञान, धन के स्मार्ट उपयोग और प्रभावी निष्पादन पर निर्भर करती है।

157. महिलाओं के लिए चाइल्डकैअर अवकाश एक संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

समाचार:

- **CJI** ने टिप्पणी की **कार्यबल** में **महिलाओं** की **भागीदारी** सिर्फ **विशेषाधिकार** का मामला नहीं है बल्कि एक **संवैधानिक अधिकार** है।

मुख्य बिंदु:	महिला कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति:

• संविधान का अनुच्छेद 15 न केवल लैंगिकता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है बल्कि राज्यों को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में भी सक्षम बनाता है।
• यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी दर के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और राज्य और केंद्र सरकारों ने भुगतान किए गए कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया है।
• IMF ने श्रम बल भागीदारी में महिलाओं की समान भागीदारी के माध्यम से भारत की GDP में 27 प्रतिशत के संभावित विचलन की भविष्यवाणी की है।
महिलाओं की श्रम शक्ति में गिरती भागीदारी:
• भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी बमुश्किल 37 प्रतिशत है।
• PLFS 2022 में कहा गया है कि 60 प्रतिशत महिलाएं स्व-रोज़गार हैं और 53 प्रतिशत स्व-रोज़गार महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक सहायक के रूप में काम करती हैं।
• ये श्रम बाजार में अवसरों की कमी और दोनों को संतुलित करने के लिए घर के पास या घर पर लचीले रोजगार का विकल्प चुनने के परस्पर जुड़े हुए परिणाम हैं।
• दीर्घकालिक रुझानों से पता चलता है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर हैरान करने वाली रही है और भागीदारी दर में व्यापक लैंगिक अंतर भी बना हुआ है।
	• महिलाओं के पास घर के काम, देखभाल के काम और वैतनिक कार्यों का भार अकेले ही संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
	• सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं पर अधिक भार होता है।
	  ○ कामकाजी महिलाओं को अक्सर विवाह और मातृत्व के रूप में दंड का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके कारण उन्हें अक्सर अस्थायी रूप से कार्यबल से हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
	• संविधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है।
	  ○ सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता, 2020 ने क्रेच को लैंगिक-तटस्थ अधिकार बना दिया।
	  ○ यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लैंगिक-तटस्थ प्रावधान ने देखभाल को "माता-पिता" की जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया।
	  ○ हालाँकि, यह पात्रता 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तक ही सीमित थी।
	• इसके अलावा, राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत क्रेच कम वित्तपोषित और संख्या तथा उपयोग में सीमित रहे।
	• मिशन शक्ति परियोजना के तहत, "पालना योजना" शुरू की गई, इसने राज्य सरकारों को स्टैंडअलोन क्रेच खोलने या आंगनवाड़ी केंद्रों को क्रेच में बदलने का विकल्प प्रदान किया।
	  ○ हालाँकि, एक प्रतिबद्ध बजट के साथ पहल को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

- चाइल्डकैअर को राज्य, नियोक्ताओं और समुदायों की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।
  - **श्रम बाजारों** को **महिलाओं** को **प्राथमिक** कमाने वाला मानने और उन्हें **पूर्ण रोजगार** लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
  - उन देशों में **उच्च महिला श्रम बल भागीदारी** का प्रमाण है जहां **अवैतनिक देखभाल कार्य** जिम्मेदारियां समान रूप से साझा की जाती हैं।
  - **महिलाओं** के **अवैतनिक देखभाल कार्य** में कमी **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी** दर में **10 प्रतिशत अंक** की वृद्धि से संबंधित है।

158. वैश्विक शिपिंग उद्योग में भारतीय नाविकों की भूमिका - द हिंदू

प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।

प्रसंग:

- **भारत** ने **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** की **कानूनी समिति (LEG)** के **111वें** सत्र में **तीन दस्तावेज़** प्रस्तुत किए गए है।

मुख्य बिंदु	अधिकारों पर एक भारतीय पहल

• ये प्रस्तुतियाँ नाविकों की सुरक्षा, अनुबंध की शर्तों और व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती हैं।
• समुद्री खतरों से निपटने के लिए IMO के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, भारत ने विभिन्न समुद्री खतरों से निपटने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है
  ○ समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, चरमपंथी हमले, क्षेत्रीय संघर्ष, और ड्रोन हमले और समुद्री हथियारों के उपयोग जैसे उभरते जोखिम आदि जिसमें शामिल हैं
समुद्री डकैती
• अपहरण सहित सोमालिया के तट पर हाल के समुद्री डाकू हमले, समुद्री डकैती के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं।
• भारत ने नाविकों के हित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अवैध भर्ती गतिविधियों के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है।
• वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री उद्योग काफी हद तक नाविकों पर निर्भर करता है, जिन्हें अक्सर चुनौतियों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
	• जवाब में, भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'समुद्र में मानवाधिकार' पहल शुरू की है।
	• रिपोर्टों से नाविकों को विदेशी जेलों में बंद किए जाने, विदेशी जलक्षेत्र में फंसे होने और अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले सामने आए हैं।
	• 'ह्यूमन राइट्स एट सी' ने भारतीय नाविकों के खिलाफ दुर्व्यवहार को उजागर किया है, जिनमें 200 विदेशी जेलों में बंद हैं और 65 इंडोनेशिया में 151 दिनों से फंसे हुए हैं।
	• NHRC ने विदेशी पंजीकरण के तहत काम करने वाले भारतीय नाविकों के खिलाफ उल्लंघन के लिए जहाज मालिकों को जिम्मेदार ठहराने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है
	  ○ टैक्स से बचने के लिए और समुद्री उद्योग में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हितधारकों और तंत्रों के बीच सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।
	• वाणिज्यिक जहाजों पर हाल के हमलों ने भारतीय नाविकों के बीच सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, कुछ लोग सुरक्षा भय के कारण अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यह सरकारी समर्थन और उन्नत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

159. इसरो ने हिमनद झीलों का विश्लेषण करने हेतु उपग्रह रिमोट-सेंसिंग का उपयोग किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।
प्रसंग:

- इस सप्ताह की शुरुआत में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** ने **भारतीय हिमालयी नदी घाटियों** के **जलग्रहण क्षेत्र** में **हिमनद झीलों** के विस्तार पर उ**पग्रह-डेटा-आधारित विश्लेषण** जारी किया।
- यह **हिमनद झीलों** पर किए गए अध्ययनों में से **नवीनतम** है जिसने **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** के **जोखिमों और प्रभाव** को उजागर किया है।

इसरो का विश्लेषण	हिमनद झील (ग्लेशियल लेक)
• इसरो के विश्लेषण में हिमाच्छादित वातावरण में परिवर्तन का आकलन करने के लिए पिछले चार दशकों के उपग्रह डेटा अभिलेखागार को देखा गया। • भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान में फैले भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 2023 तक उपलब्ध है। • इसरो के आंकड़ों से हिमनद झीलों के आकार में उल्लेखनीय विस्तार का संकेत मिला है। • इसरो ने कहा कि 676 झीलों में से 130 भारत में सिंधु (65), गंगा (7) और ब्रह्मपुत्र (58) नदी बेसिन में स्थित हैं। • इन झीलों का विस्तार हुआ है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से घट रहे हैं।	• ग्लेशियरों की गति से क्षरण होता है और आसपास की स्थलाकृति में अवसाद पैदा होता है। • जब ये पिघलते है तो पिघला हुआ पानी ऐसे गड्ढों में जमा होने लगता है, जिससे ग्लेशियर झीलों का निर्माण होता है। • इसरो ने हिमनद झीलों को उनके निर्माण के आधार पर हिमोढ़-बांधित, बर्फ-बांधित, अपरदन-आधारित, और 'अन्य' चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है । • कटाव-आधारित झीलें तब बनती हैं जब पानी कटाव-निर्मित अवसादों द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। • "GLOF तब होता है जब प्राकृतिक बांध के टूटने के कारण ग्लेशियल झीलें बड़ी मात्रा में पिघले पानी को छोड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीचे की ओर अचानक और गंभीर बाढ़ आ जाती है। **हिमानी झीलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट-सेंसिंग तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है?** • ऊबड़-खाबड़ इलाका होने के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमनदी झीलों और उनके विस्तार की निगरानी चुनौतीपूर्ण है। • इसरो के अनुसार, यहीं पर उपग्रह रिमोट-सेंसिंग तकनीक "अपनी व्यापक कवरेज और पुनरीक्षण क्षमता के कारण निगरानी के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण साबित होती है"।

हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरों को कैसे कम किया जा सकता है?

- **वर्ष 2023** में, **जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित** एक अध्ययन ने **हिमाचल प्रदेश** में **4,068** मीटर की ऊंचाई पर स्थित **घेपन गाथ झील** से **लाहौल घाटी** के **सिस्सू** तक उत्पन्न खतरों की जांच की, और झील में जल स्तर कम होने के प्रभावों का मॉडल तैयार किया।
- इसमें पाया गया कि **झील** के स्तर को **10 से 30 मीटर** तक कम करने से **सिस्सु शहर** पर प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, हालांकि **GLOM** घटना से उत्पन्न **जोखिम** पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं।

160. वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।
प्रसंग:

- **माउंट एवरेस्ट** की चोटी से लेकर **प्रशांत महासागर** के तल तक, **जानवरों** और **पक्षियों** के शरीर के अंदर, और **मानव रक्त** और **दूध** में, **प्लास्टिक कचरा** हर जगह है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण** पर अंकुश लगाने के लिए पहली **वैश्विक संधि** के संबंध में बातचीत शुरू करने के लिए **175 देशों** के **हजारों वार्ताकार** और **पर्यवेक्षक** कनाडा के ओटावा पहुंचे।
- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2024** के अंत तक **प्लास्टिक प्रदूषण** पर कानूनी रूप से **बाध्यकारी संधि** विकसित करने पर सहमत हुई।

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता

- वर्ष 1950 के दशक के बाद से, दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छू गया है।
- यदि अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो उत्पादन वर्ष 2050 तक दोगुना और वर्ष 2060 तक तिगुना हो जाएगा।
- हालाँकि प्लास्टिक एक सस्ती और बहुमुखी सामग्री है, जिसके कई प्रकार के अनुप्रयोग हैं, लेकिन इसके व्यापक उपयोग ने संकट पैदा कर दिया है।
- इस प्लास्टिक कचरे का अधिकांश भाग पर्यावरण में लीक हो जाता है, विशेषकर नदियों और महासागरों में, जहाँ यह छोटे कणों (माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक) में टूट जाता है।
- प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में लीक हो जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र में चला जाता है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में, प्लास्टिक ने 1.8 बिलियन टन GHG उत्सर्जन उत्पन्न किया जो वैश्विक उत्सर्जन का 3.4% है।

संधि में क्या शामिल हो सकता है?

- हालाँकि संधि के किसी भी विवरण को फिलहाल अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में प्लास्टिक उत्पादन पर रोक लगाने से भी आगे बढ़ सकती है।
- यह संधि प्लास्टिक में कुछ रसायनों के परीक्षण को अनिवार्य कर सकती है।

संधि में बाधाएँ

- नवंबर 2022 में उरुग्वे में पहले दौर की वार्ता के बाद से, सऊदी अरब, रूस और ईरान जैसे तेल उत्पादक देशों ने प्लास्टिक उत्पादन की सीमा का विरोध किया है, और रचनात्मक बातचीत को पटरी से उतारने के लिए असंख्य विलंब रणनीति (जैसे प्रक्रियात्मक मामलों पर बहस) का उपयोग कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, देशों को अभी यह तय करना बाकी है कि प्लास्टिक संधि पर आम सहमति से सहमति होगी या बहुमत से होगा ।
- अमेरिका HAC में शामिल नहीं हुआ है
- "99% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, और जीवाश्म ईंधन उद्योग प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स को जीवन रेखा के रूप में रखता है।
- विश्लेषण में कहा गया है कि रासायनिक और जीवाश्म ईंधन उद्योग प्लास्टिक उत्पादन में कटौती का विरोध करते हैं, यह झूठा दावा करते हैं कि प्लास्टिक संकट प्लास्टिक समस्या नहीं है, बल्कि अपशिष्ट समस्या है।
- ऐसी बाधाओं के कारण ही पिछले तीन दौर की वार्ताएँ संधि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति करने में विफल रही हैं।

161. उत्तराखंड में दावानल से सम्बंधित मामला - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : आपदा एवं आपदा प्रबंधन।
समाचार:

- **उत्तराखंड** के **नैनीताल** जिले में **जंगल** की **आग** के बीच, **भारतीय वायु सेना अग्निशमन अभियान** में लगी हुई थी।

मुख्य बिंदु:

- सबसे अधिक नुकसान **नैनीताल**, **हलद्वानी** और **रामनगर वन प्रभागों** को हुआ।
- कुछ क्षेत्रों में, **बांबी बाल्टी** की मदद से **आग बुझाई** गई, जिसका उपयोग **अपेक्षाकृत त्वरित अंतराल** में आग की **लपटों** पर बड़ी मात्रा में पानी डालने के लिए किया जाता था।

जंगल की आग(दावानल):	वनों की आग को रोकना:
• जंगल, घास के मैदान, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसी प्राकृतिक सेटिंग में पौधों का अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या जलाना। • प्राकृतिक ईंधन का उपभोग करता है और हवा, स्थलाकृति, नमी, वनस्पति आदि स्थितियों के आधार पर फैलता है। • कई प्रकार के वनों में, विशेषकर शुष्क पर्णपाती वनों में भीषण आग लगती है, जबकि सदाबहार, अर्ध-सदाबहार और पर्वतीय समशीतोष्ण वनों में तुलनात्मक रूप से कम खतरा होता है। • सूखी पत्तियाँ जंगल की आग का ईंधन होती हैं। • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की वेबसाइट बताती है कि भारत के लगभग 36 प्रतिशत जंगलों में अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। • भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में यह भी पाया गया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जंगल की आग की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। **वनों में आग लगने के कारण:** • ऐसा माना जाता है कि कृषि में बदलाव और अनियंत्रित भूमि-उपयोग पैटर्न के कारण अधिकांश आग मानव निर्मित होती हैं। • वन विभाग ने पहले जंगल की आग के स्थानीय लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगाना, लापरवाही, खेती से संबंधित गतिविधियाँ और प्राकृतिक कारण जैसे चार कारण बताए हैं।	• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों की सूची बनाई है: ○ शीघ्र पता लगाने के लिए निगरानी टावरों का निर्माण; ○ अग्नि निगरानीकर्ताओं की तैनाती; ○ स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ○ अग्नि लाइनों का निर्माण और रखरखाव। • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की वेबसाइट के अनुसार, दो प्रकार की फायर लाइनें प्रचलन में हैं - ○ कच्छ या ढकी हुई अग्नि रेखाएँ और ○ पक्की या खुली अग्नि रेखाएँ। • कच्ची अग्नि लाइनों में, घास और झाड़ियों को हटा दिया जाता है जबकि ईंधन भार को कम करने के लिए पेड़ों को रखा जाता है। • संभावित आग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पक्की आग एक जंगल/डिब्बे/ब्लॉक को दूसरे से अलग करती है।

162. भारत में असमानता और धन का संकेंद्रण से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: समावेशी विकास

समाचार:

- कांग्रेस पार्टी के **चुनाव घोषणाप**त्र ने **असमानता**, **धन का संकेंद्रण** और इन **मुद्दों के समाधान** के उपायों पर बहस शुरू कर दी है।

मुख्य बिंदु:	असमानता का समाधान:
• **विश्व असमानता डेटाबेस** में पाया गया कि **वर्ष 2022-23** में, **राष्ट्रीय आय** का **22.6% शीर्ष 1%** के पास चला गया, जो **वर्ष 1922** के बाद से सबसे अधिक है। ○ धन की असमानता और भी गंभीर है, **शीर्ष 1% आबादी के पास** धन में 40.1% हिस्सेदारी है। • अन्य मध्यम आय वाले देशों की तुलना में भारत का टैक्स -GDP अनुपात कम है • इसकी कराधान संरचना भी प्रतिगामी है, अप्रत्यक्ष टैक्स सभी कर राजस्व संग्रह में लगभग दो-तिहाई योगदान करते हैं। • इसके अलावा, प्रत्यक्ष टैक्स भी बहुत प्रगतिशील नहीं हैं। ○ रसीद बजट 2023-24 के अनुसार उन कंपनियों के लिए प्रभावी टैक्स दर (टैक्स से लाभ अनुपात) 19.14% थी, जिनका टैक्स पूर्व लाभ ₹500 करोड़ से अधिक था। इस बीच, 0-₹1 करोड़ लाभ समूह की कंपनियों के लिए प्रभावी टैक्स दर 24.82% थी • कल्याण और सामाजिक क्षेत्र पर भारत का खर्च अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ○ उदाहरण के लिए स्वास्थ्य व्यय अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3% है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% प्राप्त करना है।	• हमने बेरोजगारी के साथ-साथ विकास का भी सामना किया है। इसलिए, चर्चा रोजगार पैदा करने पर होनी चाहिए। ○ इसके लिए हमें लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ अधिक न्यायसंगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ○ सरकारें नरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों पर खर्च करके इसमें भूमिका निभा सकती हैं। • सरकारें सभी मौजूदा रिक्तियों को भरने और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में बहुत आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करके सीधे नौकरियां पैदा करने में भी योगदान दे सकती हैं। • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं जैसी नौकरियों की गुणवत्ता में भी पर्याप्त वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के साथ सुधार की आवश्यकता है। • प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के ये प्रयास कई लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। ○ मानव विकास परिणामों को बेहतर बनाने और महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य के भर को कम करने और उन्हें अन्य रोजगार के लिए मुक्त करने में भी योगदान देंगे।

फैक्ट फटाफट

1. व्हाइट रैबिट (WR)

- यह CERN में संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित एक तकनीक है, जो एक्सेलेरेटर में उपकरणों को उप-नैनोसेकंड तक सिंक्रनाइज़ करने और नेटवर्क में समय की एक आम धारणा स्थापित करने की चुनौती को हल करने के लिए है।
- व्हाइट रैबिट स्विच उप-नैनोसेकंड सिंक्रनाइज़ेशन सटीकता प्रदान करता है, जिसके लिए पहले वास्तविक समय ईथरनेट नेटवर्क के लचीलेपन और मॉड्यूलरिटी के साथ समर्पित हार्ड-वायर्ड टाइमिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह ईथरनेट आधारित नेटवर्क में उप-नैनोसेकंड सटीकता प्राप्त करता है।
- व्हाइट रैबिट नेटवर्क का उपयोग केवल वितरित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समय और सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करने के लिए, या समय और वास्तविक समय डेटा ट्रांसफर दोनों प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

2. लम्पी स्किन डिजीज

- यह मवेशियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है।
- यह लम्पी स्किन डिजीज वायरस (LSDV) के कारण होता है, जो कैप्रिपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है, जो पॉक्सविरिडे परिवार का एक हिस्सा है (चेचक और मंकीपॉक्स वायरस भी उसी परिवार का हिस्सा हैं)।
- LSDV एक ज़ूनोटिक वायरस नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैल सकती है।
- भौगोलिक वितरण:
- LSD वर्तमान में अधिकांश अफ्रीका, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों और तुर्की में स्थानिक है।
- वर्ष 2015 के बाद से यह बीमारी अधिकांश बाल्कन देशों, काकेशस और रूसी संघ में फैल गई है।
- वर्ष 2019 के बाद से, एशिया (बांग्लादेश, भारत, चीन, चीनी ताइपे, वियतनाम, भूटान, हांगकांग (SAR-RPC), नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड) के देशों में LSD के कई प्रकोप सामने आए हैं।

3. न्यायालय की अवमानना

- संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 'रिकॉर्ड न्यायालय' होगा और इसमें ऐसी अदालतों की सभी शक्तियाँ हैं जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को तदनुरूपी शक्ति प्रदान की गई है।
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना या तो सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना हो सकती है।
- सिविल अवमानना का अर्थ है अदालत के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।
- दूसरी ओर, आपराधिक अवमानना का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कि:
  - किसी न्यायालय के अधिकार को लांछित करता है या लांछित करता है या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है
  - किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है
  - किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।

4. जापान सागर

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है।
- यह पूर्वी एशिया में स्थित है और पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप से और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा है।
- दोहोकू सीमाउंट, एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी, इसका सबसे गहरा बिंदु है।
- समुद्र स्वयं एक गहरे बेसिन में स्थित है, जो पूर्वी चीन सागर से दक्षिण में त्सुशिमा और कोरिया जलडमरूमध्य द्वारा और उत्तर में ओखोटस्क सागर से ला पेरोस (या सोया) और तातार जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है।
- पूर्व में, यह कानमोन जलडमरूमध्य द्वारा जापान के अंतर्देशीय सागर और त्सुगारू जलडमरूमध्य द्वारा प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है।
- यह अपने अपेक्षाकृत गर्म पानी के कारण जापान की जलवायु को प्रभावित करता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी धाराओं और दक्षिण से आने वाली गर्म धाराओं के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

5. पुनेट स्क्वायर

- इसका नाम ब्रिटिश आनुवंशिकीविद् रेजिनाल्ड पुनेट के नाम पर रखा गया है।
- ग्रिड के शीर्ष और किनारे पर, एक तरफ एक माता-पिता और दूसरी तरफ दूसरे माता-पिता के संभावित आनुवंशिक लक्षण सूचीबद्ध हैं।
- फिर, आप प्रत्येक माता-पिता के गुणों को मिलाकर वर्गों को भरें।
- प्रत्येक वर्ग प्रभावी रूप से उन लक्षणों के संभावित संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है जो उनकी संतानों को विरासत में मिल सकते हैं।
- यह संतानों में दिखने वाले विभिन्न लक्षणों की संभावनाओं की कल्पना करने का एक सरल तरीका है।
- इनका उपयोग आमतौर पर जीव विज्ञान में वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है, जैसे जब आप स्कूल में प्रमुख और अप्रभावी जीन के बारे में सीखते हैं।
- यह एक उपयोगी उपकरण है जो क्रॉस-ब्रीडिंग के परिणामस्वरूप होने वाली विविधताओं और संभावनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।

6. पैरा फसल प्रणाली

- उटेरा/पैरा एक प्रकार की फसल है जो आमतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रचलित है।
- यह बुआई की एक प्रकार की रिले विधि है जिसमें धान की खड़ी फसल में कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर/लथीरस/उर्दबीन/मूंग के बीज डाले जाते हैं।
- यह प्रणाली जुताई, निराई, सिंचाई और उर्वरक जैसे कृषि संबंधी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देती है, हालांकि, चावल की किस्म इस प्रणाली में दालों की उत्पादकता तय करती है।
- यह अभ्यास हमें चावल की फसल की कटाई के समय उपलब्ध बेहतर मिट्टी की नमी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जो अन्यथा जल्दी ही नष्ट हो सकती है।
- प्रायोगिक साक्ष्यों से पता चला है कि चावल की फसल की कटाई के बाद जुताई के साथ बुआई करने की तुलना में जोड़ीदार फसल से मसूर की अधिक पैदावार होती है।
- यह टिकाऊ फसल गहनता और भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका है।

7. स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH)

- स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH) एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप है, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ है।
- इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, स्वास्थ्य के अपने अधिकारों का एहसास कराने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना है।
- इसे स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है
- इसमें कैंसर, हृदय रोग सहित दुनिया में मृत्यु के कुछ प्रमुख कारणों के जोखिम कारकों की बेहतर समझ विकसित करने में लोगों की सहायता करने की क्षमता है।
- यह लोगों को तंबाकू छोड़ने, सक्रिय रहने, स्वस्थ आहार खाने और अन्य चीजों के अलावा तनावमुक्त होने के बारे में नवीनतम जानकारी तक पहुंचने में मदद कर सकता है।

8. पर्पल स्ट्राइप्ड जेलिफ़िश

- यह आमतौर पर नीले बैंगनी (मौवे) रंग में दिखाई देता है, जिसमें ग्लोब के आकार की छतरी होती है जो नारंगी भूरे रंग के मस्सों से ढकी होती है।
- यह मुख्य रूप से पेलजिक या खुले महासागर में है, हालांकि, यह प्रजाति बेंटिक और समशीतोष्ण तटीय आवासों में जीवित रह सकती है।
- यह दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और गर्म तापमान वाले समुद्रों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में पाया जाता है।
- अन्य जेलीफ़िश प्रजातियों के विपरीत, इसमें न केवल टेंटेकल्स पर, बल्कि बेल पर भी डंक होते हैं। ये बायोलुमिनसेंट होते हैं, जिनमें अंधेरे में प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है।

9. वाशिंगटन संधि

- वाशिंगटन संधि, या उत्तरी अटलांटिक संधि, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का आधार बनती है।
- इस पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन डीसी में 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करती है।
- सामूहिक रक्षा संधि के केंद्र में है और अनुच्छेद 5 में निहित है। यह सदस्यों को एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और गठबंधन के भीतर एकजुटता की भावना स्थापित करता है।
- यह संधि छोटी है, इसमें केवल 14 अनुच्छेद हैं और यह सभी मोर्चों पर अंतर्निहित लचीलेपन का प्रावधान करती है।
- बदलते सुरक्षा परिवेश के बावजूद, मूल संधि को कभी भी संशोधित नहीं करना पड़ा है और प्रत्येक सहयोगी को अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार पाठ को लागू करने की संभावना है।

10. वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA)

- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में डोपिंग-मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी।
- इसका प्रशासन और वित्तपोषण खेल आंदोलन और दुनिया की सरकारों के बीच समान साझेदारी पर आधारित है।
- इसकी प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को विकसित करना, सामंजस्य बनाना और समन्वय करना है।
- इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास और विश्व डोपिंग रोधी संहिता (कोड) की निगरानी, सभी खेलों और सभी देशों में डोपिंग रोधी नीतियों को सुसंगत बनाने वाला दस्तावेज़ शामिल है।

11. मंगल पांडे

- उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक माना जाता है, जिसे वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।
- उनका जन्म 19 जुलाई, 1827 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के पास हुआ था।
- वर्ष 1849 में, पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 6वीं कंपनी में एक सिपाही के रूप में कार्य किया।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह:
- उन्होंने जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों को पेश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं।
- विद्रोहियों का यह आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों तक पहुंच गया और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ

12. सतपुला बांध

- सतपुला ('सत्' का अर्थ है सात और 'पुल' का अर्थ है पुल का खुलना) का निर्माण सुल्तान मुहम्मद शाह तुगलक (1325-1351) के शासनकाल के दौरान किया गया था।
- इसे अरावली में पाए जाने वाले दिल्ली क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था।
- इसे दिल्ली के चौथे शहर जहांपनाह की रक्षा दीवार के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया गया था।बांध ने दो उद्देश्यों को पूरा किया: सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना, और संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में कार्य करना।
- इसे उपयुक्त स्थलाकृति की पहचान करके विकसित किया गया था, यानी, एक बड़ा खुला मैदान जहां बड़ी समतल भूमि की सिंचाई के लिए पानी जमा किया जा सकता है। इसलिए, स्लुइस गेट और जलाशय वाली यह संरचना विकसित की गई।
- चूंकि सूफी संत नसीरुद्दीन महमूद (जिन्हें चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है) पास में रहते थे, लोगों का मानना था कि नहर के पानी में उपचार गुण हैं।

13. ओशनिक नीनो इंडेक्स

- यह मौसमी जलवायु पैटर्न के समुद्री हिस्से की निगरानी के लिए प्राथमिक संकेतक है जिसे अल नीनो-दक्षिणी दोलन या "ENSO" कहा जाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट, पूर्व-मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में 120°-170°W के बीच चल रहे 3 महीने के औसत समुद्री सतह तापमान को ट्रैक करता है, और क्या वे औसत से अधिक गर्म या ठंडे हैं।
- +0.5 या उससे अधिक का सूचकांक मान अल नीनो को दर्शाता है और -0.5 या उससे कम का मान ला नीना को दर्शाता है।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

14. टीसैट (TSAT)-1A

- यह एक ऑप्टिकल सब-मीटर-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- इसे वर्ष 2023 के अंत में दोनों कंपनियों के बीच एक सहयोग समझौते के बाद, लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलॉजिक इंक के सहयोग से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा बनाया गया था।
- TSAT-1A को कर्नाटक में इसकी वेमागल सुविधा में TASL के असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग (AIT) प्लांट में असेंबल किया गया था।
- इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था।

15. जेनु कुरुबा समुदाय

- कन्नड़ में जेनु का अर्थ शहद होता है और कुरुबा जाति है जैसा कि नाम से पता चलता है जेनु कुरुबा शहद इकट्ठा करने वाले होते हैं।
- ये पारंपरिक शहद इकट्ठा करने वाली जनजाति हैं और तीन राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैले पश्चिमी घाट के जंगलों के मूल निवासियों में से हैं।
- ये हादी नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं।
- व्यवसाय: मुख्य व्यवसाय जंगलों में भोजन इकट्ठा करना, जंगलों में लघु वन उपज का संग्रह करना, शहद सहित लघु वन उपज का संग्रह करना होता था।
- ये स्थानान्तरित खेती करते हैं, जिससे खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं।

16. रम्फिकार्पा फिस्टुलोसा

- यह एक वैकल्पिक, परजीवी खरपतवार है जो चावल पर उगता है जिसे राइस वैम्पायरवीड के नाम से भी जाना जाता है।
- यह ज्वार और मक्का और संभावित रूप से अन्य अनाज फसलों को भी प्रभावित करता है।
- खरपतवार स्वतंत्र रूप से अंकुरित और विकसित हो सकता है लेकिन एक उपयुक्त मेजबान पर परजीवी होने पर इसके प्रजनन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- यह उर्वरकों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।
- यह अफ्रीका के कम से कम 35 देशों में पाया जाता है, जिनमें से 28 देशों में वर्षा आधारित तराई वाले चावल के क्षेत्र पाए जाते हैं।
- उच्चतम अनुमानित संक्रमण दर वाले देश गाम्बिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, टोगो और कुछ हद तक मॉरिटानिया, गिनी-बिसाऊ, बेनिन, मलावी और तंजानिया थे।

17. राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट

- यह नवीनतम सार्वजनिक वित्त विकास का अवलोकन प्रदान करता है, मध्यम अवधि के राजकोषीय दृष्टिकोण को अद्यतन करता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतियों के राजकोषीय निहितार्थ का आकलन करता है। इसे IMF के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।
- इसके अनुमान विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR) के लिए उपयोग किए गए समान डेटाबेस पर आधारित हैं।
- अलग-अलग देशों के लिए राजकोषीय अनुमान IMF डेस्क अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए हैं, और, WEO दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

18. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF)

- यह एक फंड मैनेजर है जो भारत में बुनियादी ढांचे और संबंधित क्षेत्रों में निवेश करता है। यह भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) है, जिसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था।
- यह घरेलू बुनियादी ढांचे में इक्विटी पूंजी निवेश करने के जनादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच है।
- यह अपने निवेशकों के लिए आकर्षक जोखिम-समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत में बुनियादी ढांचे, निजी इक्विटी और अन्य विविध क्षेत्रों जैसे परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करता है।
- यह ग्रीनफील्ड (नए), ब्राउनफील्ड (मौजूदा) और रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश करता है।

- NIIF का 49% स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसके प्रबंधन के तहत 4.9 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जो इसे देश का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा कोष बनाती है।
- यह सरकार के साथ अपने सहयोग से लाभान्वित होता है फिर भी अपने निवेश निर्णयों में स्वतंत्र है।

19. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत

- क़ानूनों की व्याख्या के लिए यह एक आवश्यक नियम है। इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक क़ानूनों के बीच या किसी क़ानून के विभिन्न भागों या प्रावधानों के बीच कोई टकराव होता है, तो हमें उनकी व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए कि उनमें सामंजस्य हो।
- इसका अर्थ यह है कि जब विसंगतियाँ हों तो हमें परस्पर विरोधी भागों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक भाग दूसरे के उद्देश्य को अस्वीकार न कर दे।
- यह मौलिक कानूनी सिद्धांत में निहित है कि प्रत्येक क़ानून एक विशिष्ट उद्देश्य और इरादे से बनाया गया है, इसलिए इसे समग्र रूप से समझा जाना चाहिए।
- लेकिन जब दो प्रावधान विरोधाभासी होते हैं, तो उन दोनों को लागू करना संभव नहीं हो सकता है, और परिणामस्वरूप, 'यूट रेस मैगिस वलेट क़ौम पेरेट' (कि एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझा जाता है कि उसे उस से वंचित किया जाना चाहिए) के स्थापित बुनियादी सिद्धांत के विपरीत एक को निरर्थक बना दिया जाएगा।

20. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (WWS)

- स्थान: यह केरल के वायनाड में पश्चिमी घाट की दक्षिणी खाइयों में स्थित है। यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- इसकी सीमा उत्तरपूर्वी तरफ कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर और दक्षिणपूर्वी तरफ तमिलनाडु में मुदुमलाई के संरक्षित क्षेत्रों से लगती है।
- इन जंगलों में रहने वाली जनजातियों में कुछ अनुसूचित आदिवासी जैसे पनियास, कट्टुनैक्कन, कुरुमास, ओरालिस, अदियान और कुरिचियास शामिल हैं।

21. सनग्राज़िंग धूमकेतु

- सनग्राज़िंग धूमकेतु धूमकेतुओं का एक विशेष वर्ग है जो अपने निकटतम दृष्टिकोण पर सूर्य के बहुत करीब आते हैं, एक बिंदु जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है।
- सनग्रेज़र माने जाने के लिए, एक धूमकेतु को पेरीहेलियन पर सूर्य से लगभग 850,000 मील के भीतर आने की आवश्यकता होती है, कई तो इससे भी करीब आते हैं, यहां तक कि कुछ हज़ार मील के भीतर भी होती है ।
- धूमकेतुओं का सूर्य के इतने करीब रहना कई कारणों से बहुत कठिन है।
- ये बहुत अधिक सौर विकिरण के अधीन होते हैं, जिससे उनका पानी या अन्य वाष्पशील पदार्थ उबल जाते हैं।
- विकिरण और सौर हवा का भौतिक धक्का भी पूंछ बनाने में मदद करता है।
- जैसे-जैसे वे सूर्य के करीब आते हैं, धूमकेतु अत्यधिक तीव्र ज्वारीय बल या गुरुत्वाकर्षण तनाव का अनुभव करते हैं।
- इस प्रतिकूल वातावरण में, कई सूर्यग्राही सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा से बच नहीं पाते हैं।

22. फ्रैक्टल

- यह एक कभी न ख़त्म होने वाला पैटर्न है जो असीम रूप से जटिल है और विभिन्न पैमानों पर स्वयं-समान है। ये एक चालू फीडबैक लूप में एक सरल प्रक्रिया को बार-बार दोहराकर बनाए जाते हैं।
- संक्षेप में, फ्रैक्टल एक पैटर्न है जो हमेशा के लिए दोहराया जाता है, और फ्रैक्टल का प्रत्येक भाग, चाहे आप कितना भी ज़ूम इन या ज़ूम आउट करें, यह पूरी छवि के समान दिखता है।
- फ्रैक्टल शास्त्रीय, या यूक्लिडियन, ज्यामिति - वर्ग, वृत्त, गोले आदि की सरल आकृतियों से भिन्न होते हैं।

23. खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क

- यह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है।
- यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के खावड़ा में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित 45 गीगावॉट की प्रभावशाली क्षमता है।
- इस क्षेत्र में लद्दाख के बाद देश में दूसरा सबसे अच्छा सौर विकिरण है और हवा की गति मैदानी इलाकों की तुलना में पांच गुना अधिक है।
- पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ऊर्जा पार्क सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा संचालित एक बफर जोन बनाए रखता है।
- मूल रूप से हवाई यातायात नियंत्रण के बिना केवल एक मामूली हवाई पट्टी द्वारा पहुंच योग्य, यह साइट अब एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उद्यम के लिए तैयार है। यह 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पेरिस के आकार का लगभग पांच गुना है।

24. फोर्ट इमैनुएल

- यह केरल के कोच्चि में फोर्ट कोच्चि बीच पर स्थित एक खंडहर किला है, इसे मूल रूप से वर्ष 1503 में बनाया गया था और वर्ष 1538 में इसे सुदृढ़ किया गया था।
- यह कोच्चि के महाराजा और पुर्तगाल के सम्राट के बीच रणनीतिक गठबंधन का प्रतीक था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था।
- यह एक विशाल संरचना थी और पूरी बस्ती इसके दायरे में थी। इससे क्षेत्र पर पुर्तगाली कब्जे को मजबूत करने में काफी मदद मिली।
- फोर्ट कोच्चि वर्ष 1683 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जब डच औपनिवेशिक सैनिकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली संस्थानों को नष्ट कर दिया।
- वर्ष 1795 तक डचों ने किले को अपने कब्जे में रखा, जब अंग्रेजों ने डचों को हराकर इस पर कब्ज़ा कर लिया। वर्ष 1806 तक, डच और बाद में अंग्रेजों ने किले की अधिकांश दीवारों और उसके गढ़ों को नष्ट कर दिया था।

25. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB)

- यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है।
- FSIB की प्राथमिक भूमिका जनशक्ति क्षमताओं की पहचान करना और सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ पदों के लिए प्रतिभा का उचित चयन सुनिश्चित करना है।
- इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान ले लिया, जिसे एक अक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया था।
- एफएसआईबी का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होगा।
- बोर्ड में DFSके सचिव, IRDAI के अध्यक्ष और RBI के एक डिप्टी गवर्नर शामिल होंगे।
- इसके अतिरिक्त, इसमें तीन अंशकालिक सदस्य होंगे जो बैंकिंग के विशेषज्ञ होंगे और तीन अन्य बीमा क्षेत्र से होंगे।

26. जियाधल नदी

- यह ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदी है।
- यह अरुणाचल प्रदेश के उप-हिमालयी पहाड़ों से 1247 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। नदी की कुल लंबाई 187 किमी है।
- अरुणाचल प्रदेश में एक संकीर्ण घाटी से गुजरने के बाद, नदी धेमाजी जिले में असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जहां यह लटके हुए चैनलों में बहती है।
- नदी अंततः लखीमपुर जिले के सेलामुख के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
- लेकिन ब्रह्मपुत्र के खेरकुटिया सुति पर तटबंध के निर्माण के बाद, नदी का संगम सुबनसिरी नदी से हो जाता है।

27. ऑपरेशन मेघदूत

- यह उत्तरी लद्दाख पर हावी होने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल के ऑपरेशन का कोड-नाम था।
- वर्ष 1949 के कराची समझौते के बाद से ही सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है
  - जब शत्रुतापूर्ण भूभाग और अत्यधिक खराब मौसम के कारण क्षेत्र को अविभाजित छोड़ दिया गया था।
- ऑपरेशन मेघदूत भारत की साहसिक सैन्य प्रतिक्रिया थी, जिसे नई दिल्ली मानचित्र संदर्भ NJ9842 के उत्तर में लद्दाख के अज्ञात क्षेत्र में पाकिस्तान की "कार्टोग्राफ़िक आक्रामकता" कहती है।
  - जहां नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर सहमति जताई थी।
- इस ऑपरेशन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तानी सेना द्वारा सिया ला और बिलाफोंड ला दर्रों पर कब्ज़ा करने से पहले रोकना था।

28. प्रीकोशनरी सिद्धांत

- यह नीति निर्धारण का एक दृष्टिकोण है जो निवारक उपायों को अपनाने को वैध बनाता है
  - कुछ गतिविधियों या नीतियों से जुड़े जनता या पर्यावरण के लिए संभावित जोखिमों का समाधान करना।
- सिद्धांत कहता है, "जहां गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो, वहां पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी को ऐसे पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"
- यह निर्णय लेने वालों को एहतियाती उपाय अपनाने में सक्षम बनाता है जब किसी पर्यावरणीय या मानव स्वास्थ्य खतरे के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण अनिश्चित होते हैं और जोखिम ऊंचे होते हैं।
- इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी संभावित नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, भले ही ऐसी संभावना हो कि ऐसा नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे सुरक्षित रखें।

29. कुदसिया बाग

- इसका निर्माण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी कुदसिया बेगम (1748 में) ने करवाया था, जिन्होंने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया था।
- यह उत्तरी दिल्ली में स्थित है, इसे फ़ारसी चार-बाग शैली में बनाया गया था।
- बाग के एकमात्र अवशेष इसके भव्य पश्चिमी प्रवेश द्वार, कुदसिया मस्जिद और नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर से बने कुछ मंडप हैं।
- यह सम्राट और उनकी पत्नी की निजी मस्जिद थी और इसे तीन मंजिला ऊंची दीवारों के ऊपर बहुत ही सरल शैली में बनाया गया था।
- मस्जिद एक ASI संरक्षित स्मारक है और इसे लाखौरी ईंटों से बनाया गया है।
- बाग में लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित कई प्रवेश द्वार थे, दीवारों पर चूना पत्थर से प्लास्टर किया गया था, दीवारों पर प्लास्टर का काम किया गया था, ऊपर पुष्प पैटर्न के साथ घुमावदार मेहराब थे।

30. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

- यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में तीन राज्यों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रि-जंक्शन पर स्थित है।
- यह नीलगिरि पहाड़ियों के उत्तरपूर्वी और उत्तरपश्चिमी ढलानों पर स्थित है, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है।
- यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है।
- इसकी पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व (कर्नाटक), दक्षिण और पूर्व में नीलगिरी उत्तरी डिवीजन और दक्षिण-पश्चिम में गुडलूर वन डिवीजन के साथ एक आम सीमा है।

31. करिबा झील

- यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है।
- यह ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है।
- यह विक्टोरिया फॉल्स से 200 किलोमीटर नीचे की ओर है।
- उत्तरपूर्वी छोर पर करिबा बांध की दीवार के पूरा होने के बाद झील भर गई, जिससे ज़म्बेजी नदी पर करिबा कण्ठ में बाढ़ आ गई।
- करिबा बांध में दोहरी मेहराबदार दीवार है।
- यह दीवार करिबा कण्ठ तक फैली हुई है, जो ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बीच एक सीमा बनाती है।
- यह ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे दोनों को पर्याप्त विद्युत शक्ति प्रदान करता है और एक संपन्न वाणिज्यिक मछली पकड़ने के उद्योग का समर्थन करता है।

32. यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज (UNPFII)

- इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के एक सलाहकार निकाय के रूप में आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था।
- अपने अधिदेश के अनुसार, स्थायी फोरम यह करेगा
- परिषद के माध्यम से परिषद के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों, निधियों और एजेंसियों को विशेषज्ञ सलाह और सिफारिशें प्रदान करना।
- जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर स्वदेशी मुद्दों से संबंधित गतिविधियों के एकीकरण और समन्वय को बढ़ावा देना।
- स्वदेशी मुद्दों पर जानकारी तैयार करना और उसका प्रसार करना।

33. कवच सिस्टम

- कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली है।
- यह सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 (SIL-4) मानकों वाला एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है।
- यह उच्च आवृत्ति रेडियो संचार का उपयोग करता है और टकराव को रोकने के लिए आंदोलन के निरंतर अद्यतन के सिद्धांत पर काम करता है
- यह मूवमेंट अथॉरिटी के निरंतर अद्यतन के सिद्धांत पर काम करता है।
- यह किसी भी प्रकार की दुर्घटना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय रूप से एसओएस का उपयोग करता है।

34. वीरानम झील

- वीरानम झील चेन्नई के लिए एक महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करती है।
- यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है।
- इसे 14 किमी की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित झीलों में से एक माना जाता था।
- इसका निर्माण 907-955 ईस्वी के बीच ग्रेटर चोलों की अवधि के दौरान, चोल राजकुमार-राजादित्य चोल द्वारा किया गया था, जो परांतक प्रथम के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की उपाधि-वीरनारायणन के नाम पर इस जलाशय का नाम रखा था।
- कल्कि द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास पोन्नियिन सेलवन में इस झील का उपयोग संदर्भ के रूप में किया गया था।
- वीरानम का स्रोत कोल्लीदम नदी है
  - जो कावेरी नदी की उत्तरी सहायक नदी है, जहाँ वदावरु नदी वीरनम और कोल्लीदम दोनों को जोड़ती है।

35. वोस्त्रो अकाउंट

- यह वह अकाउंट है जो घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपनी घरेलू मुद्रा, इस मामले में, रुपये में रखते हैं।
- घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए करते हैं जिनकी वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताएँ हैं।
- यह संवाददाता बैंकिंग की एक अभिन्न शाखा है जिसमें एक बैंक (या एक मध्यस्थ) शामिल होता है जो वायर ट्रांसफर की सुविधा देता है, व्यावसायिक लेनदेन करता है, जमा स्वीकार करता है और दूसरे बैंक की ओर से दस्तावेज़ इकट्ठा करता है।
- यह घरेलू बैंकों को विदेशी वित्तीय बाजारों तक व्यापक पहुंच प्राप्त करने और विदेश में भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा करने में मदद करता है।

36. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs)

- विश्व बैंक के अनुसार, ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो जलवायु-संबंधित या पर्यावरण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी की जाती है।
- ऐसी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए सरकारों द्वारा SGB जारी किए जाते हैं।
- भारत में, केंद्रीय बजट 2022-23 में SGrBs जारी करने की घोषणा की गई।
- सरकार का फ्रेमवर्क ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) के सूचीबद्ध सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके चार घटक हैं:
  - आय का उपयोग, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन और रिपोर्टिंग

37. लीफ लिटर फ्रॉग

- यह वन समुदाय में मेंढकों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है।
- यह जीवित रहने की रणनीति के रूप में अपनी उच्च-आवृत्ति चीखों का उपयोग करता है।
- यह प्राथमिक और द्वितीयक वनों और वन किनारों पर निवास करता है।
- यह आमतौर पर जंगल के फर्श पर पत्तों के कूड़े में, या जंगल के अंदर कम वनस्पति में पत्तियों पर पाया जाता है।
- ये बहुत छोटे होते हैं और इस प्रजाति में सबसे बड़ी मादा होती है। आकार में, ये बमुश्किल 64 मिलीमीटर (2.5 इंच) लंबे होते हैं।
- यह ब्राजील के अटलांटिक वर्षावन में पाई जाने वाली मेंढक की एक प्रजाति है।
- इस प्रजाति को IUCN संरक्षण स्थिति के तहत कम से कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है

38. मैनिंजाइटिस

- यह एक गंभीर संक्रमण है जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली और सुरक्षित रखने वाली झिल्लियों (मेनिन्जेस) में सूजन आ जाती है।
- मेनिनजाइटिस के कई कारण हैं, जिनमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और परजीवी रोगजनक शामिल हैं।
- बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस, जो विशेष रूप से मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है, अफ्रीका में एक विशेष चिंता का विषय है और इसके परिणामस्वरूप सेप्टिसीमिया (रक्त विषाक्तता) भी हो सकता है।
  - जो लोग इसके संपर्क में आते हैं उन्हें 24 घंटों के भीतर गंभीर रूप से अक्षम या मार डाला जा सकता है।
- इसमें अक्सर सिरदर्द, बुखार और गर्दन में अकड़न शामिल होती है।
- 26 देशों का एक क्षेत्र जिसे "अफ्रीकी मेनिनजाइटिस बेल्ट" के रूप में जाना जाता है, नाइजीरिया सहित पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है

39. शोम्पेन जनजाति

- ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है।
- ये अंडमान और निकोबार द्वीप में पाँच PVTGs में से एक हैं।
- जनगणना (2011) में उनकी अनुमानित जनसंख्या 229 बताई गई है
- उनमें से अधिकांश संपर्क रहित हैं और अपनी भाषा बोलते हैं, हालाँकि, बोलियाँ भिन्न हो सकती हैं।
- अर्ध खानाबदोश जनजाति होने के कारण इनकी आजीविका के मुख्य स्रोत शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना हैं।
- शोम्पेन जनजाति का मुख्य भोजन पैंडनस फल है, जिसे वे लारोप कहते हैं।

40. वासुकी इंडिकस

- इस सांप के जीवाश्म गुजरात के कच्छ स्थित पनांद्रो लिग्नाइट खदान में पाए गए थे।
- यह अब तक अस्तित्व में आए सबसे बड़े सांपों में से एक है।
- यह संभवतः 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इओसीन काल में रहता था
- पाया गया जीवाश्म अब विलुप्त हो चुके मडत्सोइदे साँप परिवार का था। हालाँकि, यह भारत की एक अद्वितीय वंशावली का प्रतिनिधित्व करता है।
- ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसका शरीर बेलनाकार, मजबूत और शक्तिशाली संरचना वाला था,
- यह टाइटेनोबोआ जितना बड़ा था, एक और विशाल सांप जो कथित तौर पर अब तक ज्ञात सबसे लंबा सांप था।

41. माउंट रुआंग

- सुदूर इंडोनेशियाई ज्वालामुखी से आसमान में राख उगलने लगी है ,
- इस सप्ताह की शुरुआत में लगभग आधा दर्जन विस्फोटों के बाद जब पिघली हुई चट्टानों की बारिश उनके गांवों पर हुई तो हजारों लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- देश की ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने कहा कि विस्फोट से शिखर से 400 मीटर ऊपर धुएं का गुबार फैल गया।

42. माउंट अपो

- सबसे ऊंची चोटी, और फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है ।
- फिलीपींस में साल भर उच्च तापमान और आर्द्रता के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसमें नम और शुष्क मौसम का अनुभव होता है।
- फिलीपींस को दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है।
- फिलीपींस भी प्रशांत रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है, जो इसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय बनाता है। इसमें 20 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें मेयोन (हाल ही में 2023 में विस्फोट हुआ), ताल और माउंट पिनातुबो (1991 में विस्फोट हुआ) शामिल हैं।

43. पन्हाला दुर्ग

- यह महाराष्ट्र में स्थित है और इस राज्य के इतिहास में इसका प्रमुख स्थान है।
- स्थानीय रूप से, यह स्थान नागों के निवास के रूप में जाना जाता था और पारंपरिक रूप से ऋषि पराशर से जुड़ा हुआ था।
- यह रणनीतिक रूप से सह्याद्रि पर्वत, दक्कन पठार और कोंकण तट को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, यह किला कई राजवंशों के लिए रुचि का केंद्र बन गया।
- किले की प्राचीनता 11वीं शताब्दी के शिलाहारा वंश के शासक भोज के समय से चली आ रही है।

44. बिटकॉइन हाल्विंग

- हाल्विंग का तात्पर्य बिटकॉइन की मूलभूत ब्लॉकचेन तकनीक में बदलाव से है, जिसका उद्देश्य नए बिटकॉइन बनाने की गति को कम करना है।
- छद्मनाम व्यक्ति सातोशी नाकामोटो द्वारा इसके निर्माण के बाद से, बिटकॉइन को 21 मिलियन टोकन की सीमित आपूर्ति के लिए संरचित किया गया है।
- हाल्विंग की प्रक्रिया वर्ष 2041 तक जारी रहेगी, उस समय तक सभी बिटकॉइन का खनन किया जा चुका होगा।

45. दीर्घायु भारत पहल

- यह मानव 'स्वास्थ्य अवधि' को बढ़ाने और उम्र बढ़ने से संबंधित चुनौतियों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित एक परियोजना है।
- इसने बड़े पैमाने पर नैदानिक अध्ययन भी शुरू किया है जिसमें कई ।IS विभागों, चिकित्सक, उद्योग, परोपकारी और नागरिक समाज के शोधकर्ता शामिल होंगे।
- यह मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान दोनों के माध्यम से उम्र बढ़ने की समझ को बढ़ाने और ऐसे समाधान विकसित करने का प्रयास करता है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
- यह ऐसे हस्तक्षेप विकसित करने के लिए उन्नत अनुसंधान का लाभ उठाएगा जो पूरे भारत में स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ उम्र से संबंधित बीमारियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।

46. रैम्पेज मिसाइल

- यह लंबी दूरी की, सुपरसोनिक, हवा से जमीन पर मार करने वाली, खोज रहित, सटीक मार करने वाली मिसाइल है।
- इसे इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इज़राइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था।
- इसे संचार और कमांड सेंटर, वायु सेना अड्डों, रखरखाव केंद्रों और बुनियादी ढांचे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी तरह से संरक्षित लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से मिशन में उपयोग के लिए विकसित किया गया है।
- यह सुपरसोनिक गति से यात्रा कर सकता है, जिससे वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इसकी पहचान करना और अवरोधन करना मुश्किल हो जाता है।
- इसकी मारक क्षमता 190 मील से अधिक है।
- यह 150 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है।
- इसमें विस्फोट विखंडन या सामान्य प्रयोजन वारहेड है।

47. आर्टेमिस समझौते

- ये 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर-बाध्यकारी सेट हैं।
- ये सिद्धांत एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित बाहरी अंतरिक्ष वातावरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
- नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के सह-नेतृत्व में, आर्टेमिस समझौते की स्थापना 2020 में सात अन्य संस्थापक सदस्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम) के साथ की गई थी।
- अप्रैल 2024 तक, भारत सहित 38 हस्ताक्षरकर्ता थे।

48. माउंट एरेबस

- यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है यह रॉस द्वीप, अंटार्कटिका पर स्थित है।
- यह एक स्ट्रैटोवोलकानो है, जिसकी विशेषता शंक्वाकार आकार और कठोर लावा, टेफ्रा और ज्वालामुखीय राख की परतें हैं।
- माउंट एरेबस अपनी सतत लावा झील के लिए जाना जाता है।
- झील कम से कम वर्ष 1972 से सक्रिय है और पृथ्वी पर केवल कुछ लंबे समय तक जीवित रहने वाली लावा झीलों में से एक है।
- यह लगातार मंथन करता है और कभी-कभी स्ट्रोमबोलियन विस्फोटों में पिघली हुई चट्टान के बम उगलता है।
- चूँकि ज्वालामुखी एक दूरस्थ स्थान पर है, शोधकर्ता उपग्रहों का उपयोग करके इसकी निगरानी करते हैं।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

49. राष्ट्रीय बायोमटेरियल सेंटर (राष्ट्रीय ऊतक बैंक)

- मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 में ऊतक दान और ऊतक बैंकों के पंजीकरण के घटक को शामिल किया गया है।
- केंद्र की स्थापना का मुख्य जोर और उद्देश्य 'मांग' और 'आपूर्ति' के साथ-साथ विभिन्न ऊतकों की उपलब्धता में 'गुणवत्ता आश्वासन' के बीच के अंतर को भरना है।
- कार्य: ऊतक खरीद और वितरण के लिए समन्वय; दाता ऊतक स्क्रीनिंग; ऊतकों को हटाना और भंडारण करना; ऊतक का संरक्षण; ऊतकों की प्रयोगशाला जांच; ऊतक ट्रैकिंग; बंध्याकरण, अभिलेख रखरखाव; डेटा सुरक्षा

50. हेडलाइन इन्फ्लेशन

- हेडलाइन इन्फ्लेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कच्चा इन्फ्लेशन आंकड़ा है
- यह श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है।
- व्यापक अर्थव्यवस्था में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है यह निर्धारित करने के लिए CPI माल की एक निश्चित टोकरी खरीदने की लागत की गणना करता है।
- CPI एक आधार वर्ष का उपयोग करता है और आधार वर्ष के मूल्यों के अनुसार चालू वर्ष की कीमतों को अनुक्रमित करता है।

51. कोर इन्फ्लेशन

- कोर इन्फ्लेशन CPI घटकों को हटा देती है जो महीने-दर-महीने बड़ी मात्रा में अस्थिरता प्रदर्शित कर सकते हैं
- जो शीर्षक चित्र में अवांछित विकृति पैदा कर सकता है।
- सबसे आम तौर पर हटाए जाने वाले कारक भोजन और ऊर्जा की लागत से संबंधित हैं।
- खाद्य पदार्थों की कीमतें अर्थव्यवस्था से जुड़े कारकों के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हो सकती हैं
  - जैसे पर्यावरणीय बदलाव जो फसलों की वृद्धि में समस्याएँ पैदा करते हैं।
- ऊर्जा लागत, जैसे तेल उत्पादन, पारंपरिक आपूर्ति और मांग से बाहर की ताकतों, जैसे राजनीतिक असंतोष, से प्रभावित हो सकती है।

52. बैंडेड क्रेट

- यह एलैपिड सांपों की बड़ी प्रजाति है
- एलैपिड सांप- सांपों का परिवार जो मुंह के सामने अपने स्थायी रूप से उभरे हुए नुकीले दांतों से पहचाना जाता है
- इसमें उच्च न्यूरोटॉक्सिक विष है
- IUCN स्थिति- कम से कम चिंता का विषय
- विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है

53. वोयाजर 1 अंतरिक्ष यान

- यह नासा द्वारा बाहरी सौर मंडल और उससे आगे का अध्ययन करने के लिए अपने ट्विन वोयाजर 2 के लगभग दो सप्ताह बाद 5 सितंबर, 1977 को लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है।
- इसके मिशन में बृहस्पति और शनि की उड़ान को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य उनके चंद्रमाओं, छल्लों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है।
- यह वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है।
- यह हेलियोस्फीयर को पार करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, वह सीमा जहां हमारे सौर मंडल के बाहर के प्रभाव हमारे सूर्य से अधिक मजबूत होते हैं।
- इसने बृहस्पति के चारों ओर एक पतली रिंग और दो नए जोवियन चंद्रमाओं थेबे और मेटिस की खोज की है ।
- शनि पर, वोयाजर 1 को पांच नए चंद्रमा और एक नया वलय मिला, जिसे जी-रिंग कहा जाता है।

- वॉयेजर 1 के पास एक स्वर्णिम रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता को चित्रित करने के लिए चुनी गई ध्वनियाँ और चित्र शामिल हैं, इस घटना में कि यह कभी भी अलौकिक जीवन का सामना करता है।

54. क्रिस्टल मेज़ 2

- इसे ROCKS के रूप में भी जाना जाता है, यह एक हवा से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह इजरायली मूल का है।
- इसे संभावित विरोधियों की उच्च-मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य संपत्तियों, जैसे लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अपने पूर्ववर्ती क्रिस्टल मेज़ 1 से अलग, जिसे पहले इज़राइल से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, क्रिस्टल मेज़ 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में विस्तारित स्टैंड-ऑफ रेंज क्षमताओं का दावा करती है।
- यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भेदन या विस्फोट विखंडन वारहेड के विकल्पों के साथ, यह मिसाइल जमीन के ऊपर या अच्छी तरह से संरक्षित भूमिगत लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।
- यह GPS-अस्वीकृत वातावरण में विशेष रूप से प्रभावी है।

55. टीना (TINA) फैक्टर

- इसका अर्थ है कोई विकल्प नहीं है, यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां निवेशक मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए किसी विशेष परिसंपत्ति वर्ग या निवेश को सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखते हैं।
- यह धारणा तब उत्पन्न होती है जब कम रिटर्न, उच्च अस्थिरता या आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारकों के कारण अन्य निवेश विकल्प अनाकर्षक समझे जाते हैं।
- मूलतः, भविष्य में संभावित अनिश्चितताओं से भयभीत लोग सबसे सुरक्षित निवेश साधन में निवेश करने पर विचार करते हैं।
- यानी, उचित विकल्पों की कमी के कारण कीमतें अवास्तविक ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं।
- टीना (TINA) ऐतिहासिक रूप से कुछ आर्थिक स्थितियों की प्रतिक्रिया रही है जहां आम तौर पर सुरक्षित माने जाने वाले निवेश कम अनुकूल हो गए हैं।

56. मारबर्ग वायरस डिजीज (MVD)

- यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो लोगों और गैर-मानव प्राइमेट्स दोनों को प्रभावित करता है।
- यह मारबर्ग वायरस के कारण होता है, जो फ़िलोवायरस परिवार का आनुवंशिक रूप से अद्वितीय ज़ूनोटिक (या, पशु-जनित) RNA वायरस है।
- यह उसी परिवार का वायरस है जो इबोला वायरस का कारण बनता है
- MVD के साथ मानव संक्रमण शुरू में रूसेटस चमगादड़ों द्वारा बसाई गई खानों या गुफाओं में लंबे समय तक रहने के परिणामस्वरूप होता है।
- एक बार जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो मारबर्ग मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से फैल सकता है
  - संक्रमित लोगों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से (टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से)फैल सकता है
  - इन तरल पदार्थों से दूषित सतहों और सामग्रियों (जैसे, बिस्तर, कपड़े) के साथ फैल सकता है

57. बैथिमेट्री

- यह महासागरों, नदियों, झीलों और झरनों में पानी की गहराई का अध्ययन और मानचित्रण है।
- बाथमीट्रिक मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्रों के समान होते हैं, जो भूमि की विशेषताओं के आकार और ऊंचाई को दिखाने के लिए रेखाओं का उपयोग करते हैं।
- बाथिमेट्रिक मानचित्रों पर, रेखाएँ समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ती हैं।

- बैथिमेट्री हाइड्रोग्राफी विज्ञान की नींव है, जो जल निकाय की भौतिक विशेषताओं को मापता है।
- हाइड्रोग्राफी में न केवल बाथमीट्री शामिल है, बल्कि तटरेखा का आकार और विशेषताएं भी शामिल हैं
  - जैसे ज्वार, धारा और लहरों की विशेषताएँ; और पानी के भौतिक और रासायनिक गुण आदि

58. Phi-3-Mini

- माइक्रोसॉफ्ट ने Phi-3 को खुले AI मॉडल के एक परिवार के रूप में वर्णित किया है जो उपलब्ध सबसे सक्षम और लागत प्रभावी छोटे भाषा मॉडल (SLM) हैं।
- माना जाता है कि Phi-3 -मिनी उन तीन छोटे मॉडलों में पहला है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट जारी करने की योजना बना रहा है।
- कथित तौर पर इसने भाषा, तर्क, कोडिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में समान आकार के मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

59. ATACMS

- ATACMS अमेरिका स्थित हथियार निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली तोपखाने हथियार प्रणाली है। इसकी सबसे बड़ी ताकत हमले की लंबी दूरी, क्लस्टर युद्ध सामग्री को फायर करने की क्षमता और हथियार प्रणाली की गतिशीलता है।
- ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए 300 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज का हिस्सा थीं।
- ATACMS का एक मध्य-श्रेणी संस्करण है, जिसे ब्लॉक 1 कहा जाता है, और एक लंबी दूरी का संस्करण ब्लॉक 1A है।
- ATACMS ब्लॉक 1 की रेंज 165 किमी है और यूक्रेन को ये सिस्टम पिछले साल ATACMS ब्लॉक 1A प्रदान किया गया था
  - दूसरी ओर, आपके पास अधिकतम 300 किमी की सीमा है जो मौजूदा सेना के तोपों, रॉकेट और अन्य मिसाइलों की सीमा से कहीं अधिक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है।

60. इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन

- वर्ष **2022** में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के पांचवें सत्र में, समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण (**ILBI**) विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया गया था।
- प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (**UNEP**) के कार्यकारी निदेशक से "उपकरण" विकसित करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (**INC**) पर सहमति देने का अनुरोध किया गया।
  - जो एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है जो प्लास्टिक के उत्पादन, डिजाइन और निपटान सहित उसके पूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करता है।
- वैश्विक प्लास्टिक संधि का उद्देश्य जवाबदेही, जिम्मेदारियों, वित्तपोषण, सामग्री/रासायनिक मानकों, आयात/निर्यात प्रतिबंधों, लक्ष्यों के आसपास मानकों का एक वैश्विक ढांचा स्थापित करना है।

61. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (GRFC) 2024

- यह खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क (FSIN) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा लॉन्च किया जाता है
  - एक बहुहितधारक पहल जिसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी और खाद्य संकट से निपटने के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।
- इसमें 59 देशों में 2023 में 1.3 बिलियन की आबादी का विश्लेषण किया गया, लगभग 282 मिलियन लोगों को उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।

- वर्ष 2023 तीव्र खाद्य असुरक्षा से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि का लगातार पाँचवाँ वर्ष था
  - इसे तब परिभाषित किया जाता है जब आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है जिससे जीवन या आजीविका को खतरा होता है, भले ही कारण या समय की अवधि कुछ भी हो।

62. बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्थान(NIEPID)

- NIEPID (पूर्व में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान), वर्ष 1984 में स्थापित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह राष्ट्रीय हित में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है।
- यह देश में बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, नवी मुंबई और नोएडा में हैं।

63. नेफ्रोटिक सिंड्रोम

- यह एक किडनी विकार है जिसके कारण आपका शरीर आपके मूत्र में बहुत अधिक प्रोटीन उत्सर्जित करता है।
- यह आमतौर पर आपके गुर्दे के फिल्टर (ग्लोमेरुली) की समस्या के कारण होता है।
- गुर्दे नेफ्रॉन नामक फ़िल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटा देते हैं।
- प्रत्येक नेफ्रॉन में एक फिल्टर (ग्लोमेरुलस) होता है, जो आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालता है और उन्हें मूत्र के रूप में आपके मूत्राशय में भेजता है।
- सामान्य अपशिष्ट उत्पादों में नाइट्रोजन अपशिष्ट (यूरिया), मांसपेशी अपशिष्ट (क्रिएटिनिन), और एसिड शामिल हैं।
- स्वस्थ किडनी में, ग्लोमेरुली अपशिष्ट उत्पादों को फ़िल्टर करता है।
- ये आपके रक्त को उन कोशिकाओं और प्रोटीन को बनाए रखने की अनुमति देते हैं जिनकी आपके शरीर को नियमित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है।

64. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क (CTCN)

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी तंत्र की परिचालन शाखा है।
- इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UNEP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से और जलवायु प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखने वाले 11 स्वतंत्र संगठनों के सहयोग से की जाती है।
- इसकी स्थापना विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए की गई थी।
- यह प्रौद्योगिकी कंपनियों और संस्थानों के वैश्विक नेटवर्क की विशेषज्ञता का उपयोग करके व्यक्तिगत देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी समाधान, क्षमता निर्माण और नीति, कानूनी और नियामक ढांचे पर सलाह प्रदान करता है।

65. Chang'e-6

- Chang'e-6 मिशन एक नियोजित लैंडर है जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर उतरना, चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। यह प्रक्रिया चंद्रमा के भूवैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए महत्वपूर्ण डेटा का योगदान देगी।
- चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से नमूने प्राप्त करने के प्रथम प्रयास के रूप में, Chang'e-6 दो किलोग्राम तक चंद्र नमूने वापस लाने के लिए तैयार है, तथा इसका विन्यास सफल Chang'e-5 मिशन के समान होगा।

- इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के पेलोड शामिल हैं।

66. बांबी बकेट

- यह एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका प्रयोग 1980 के दशक से किया जा रहा है।
- यह मूलतः एक हल्का, बंधनेवाला कंटेनर है जो पायलट-नियंत्रित वाल्व का उपयोग करके हेलीकॉप्टर के नीचे से लक्षित क्षेत्रों में पानी छोड़ता है।
- इसे झीलों और स्विमिंग पूल सहित विभिन्न स्रोतों से जल्दी और आसानी से भरा जा सकता है, जिससे अग्निशामकों को इसे तेजी से फिर से भरने और लक्ष्य क्षेत्र में लौटने की अनुमति मिलती है।
- यह 270 से 9,840 लीटर तक की क्षमता के साथ विभिन्न आकारों और मॉडलों में उपलब्ध है।

67. ग्रीन टैक्सयोनोमय

- ग्रीन टैक्सयोनोमय पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ निवेश कहलाने के लिए एक रूपरेखा है।
- यह एक वर्गीकरण प्रणाली है जो परिभाषित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ और संपत्तियाँ "ग्रीन " या पर्यावरणीय रूप से सतत हैं।
- यह एक उपयोगी उपकरण है और इसके कई पूरक उद्देश्य हैं:
- ग्रीनवाशिंग को रोकने में मदद;
- निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सहायता करना; और
- निवेश को स्थायी या हरित आर्थिक गतिविधियों और परिसंपत्तियों की ओर निर्देशित करें।

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com